



LK ACADEMY®
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

जुलाई 2026

करेंट अफेयर्स
मैगजीन





LK ACADEMY[®]
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

जुलाई- 2026

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
इतिहास एवं संस्कृति	1-11
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक चापेकर ब्रदर्स राखीगढ़ी - हड़प्पा स्थल सुश्रुत पैट्रिस लुमुम्बा की जीवित मूर्ति: उपनिवेशवाद-विरोधी प्रतिरोध के लिए एक कांगो प्रशंसक की श्रद्धांजलि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 3 जून की घोषणा मौलाना बरकतउल्लाह भोपाली झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला	
राज्यवस्था	12-28
दलबदल विरोधी कानून भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है सुधार 3.0 - भारत विकास दर की ओर ऑपरेशन शेरवाली स्वतः संज्ञान और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं ईएसआईसी की केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली महा जल मिशन भूल जाने का अधिकार लैंड पूलिंग अधिग्रहण की समस्याओं को कैसे हल करती है? सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सीट विस्तार: संवैधानिक प्रश्न और संस्थागत जोखिम राज्यसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA)	
भूगोल	29-36
रास लाफान गैस सुविधा भारत का खराब मानसून और तैयारी भारत की कम प्रजनन क्षमता वाली संरचना विकसित हो रही है लिपुलेख दर्रा	

उत्तर पश्चिमी भारतीय धूल भरी आंधी
अल नीनो
सुपर अल नीनो

पर्यावरण

37-49

बायोचार
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)
नागालैंड कैस्केड मेंढक
फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026
भारत के जलवायु भविष्य का वित्तपोषण
भारत ने जलवायु वित्त पर बातचीत का आह्वान किया
पेरिस समझौते के तहत पहला कार्बन क्रेडिट
एआई डेटा केंद्र और पर्यावरणीय घर्षण
पैराक्वाट शाकनाशी
भारत गरीबी के खिलाफ युद्ध जीतकर अपने जंगलों को बचा सकता है
स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

50-71

भारत की विकसित अंतरिक्ष वास्तुकला
प्रोजेक्ट निंबस
अमोनिया गैस
फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन
केंद्र ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा पर प्रतिबंध लगाया
प्रीलिम्स इन फोकस : सरकारी विधेयक और अधिनियम
परमाणु ऊष्मा-आधारित Cu-Cl हाइड्रोजन सुविधा
ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली
ब्लू माइक्रोमून
कोयला गैसीकरण
आरटीएक्स स्पार्क चिप
फोकस में प्रारंभिक परीक्षा: पर्यावरण
टायलोसॉरस रेक्स
भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर व्हीकल
मावेन मंगल मिशन
एक्सोप्लैनेट WASP-94A b
E85 ईंधन
नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी)
जापान का H3 रॉकेट
इरॉप शिपिंग
मेमोरी चिप्स
उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (एचईएमसीपी)
बीजीपी अपहरण
डाउनब्लेंडिंग प्रक्रिया

अर्थव्यवस्था

72-83

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
भारत 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज रीसाइक्लिंग राष्ट्र बना
चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है
ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी)

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

अनुसूचित इंडियन एयरलाइंस के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: भारत के व्यापार ढांचे को मजबूत करना

ब्रूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स

10 वर्षों में भारत के रोजगार की एक शारीरिक रचना

केंद्रीय बैंक का अधिशेष हस्तांतरण ढांचा

पीआईबी

84-106

एकीकृत वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीतियां

सिकल सेल रोग

कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना

हरित यूरिया उत्पादन को वास्तविकता बनाने का रोडमैप

सुमन रोडमैप 2030

द गार्जियन ऑफ द ब्रू होराइजन अवार्ड

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

प्रोजेक्ट उदयक

मिशन सेनेहजोरी

नवाचार मंत्र पहल

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित होकर 2022-23 किया गया

पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026

MUC1-लक्षित सिलिका नैनोकैरियर (MPPPM)

ई-जागृति प्लेटफॉर्म

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र

एलपीएमएस - विनिमे सिस्टम

तिलहन किसान मित्र

वर्या एआई मॉडल

सशक्त युवा, मजबूत राष्ट्र: विकसित भारत @ 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण

भारत-फ्रांस एटीएल ब्रिज

औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी)

प्रोलिम्स इन फोकस : अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कादियान-ब्यास रेलवे लाइन परियोजना

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

107-121

रिटर्न रेगुलेशन

ऑपरेशन अमिस्ताद

हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का एक महासागर

भूल जाने का अधिकार

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS)

भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाइ चेन ऑब्जर्वेटरी

मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

भारत-नेपाल सीमा मुद्दा

भारतीय चालक दल के साथ जहाजों पर अमेरिका का हमला

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

ब्रिक्स इंदौर घोषणा

संयुक्त क्रेडिट तंत्र (जेसीएम)
यूएस पैसिफिक कमांड (USPACOM)
संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 14-खंड समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विवादेक 2026

सामाजिक मुद्दे

122-136

आयुष्मान सारथी चैटबॉट
प्रोजेक्ट ब्रह्मांक
ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल
प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना 2026
भव्या पोर्टल
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)
गर्भनिरोधक उपयोग और प्रजनन एजेंसी
FCRA विधेयक - नागरिक समाज पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार
विकलांग व्यक्तियों के लिए उपचार की समानता
अवैतनिक घरेलू श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का आदेश
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69(ए)
यूपीएससी ईडब्ल्यूएस कोटा जांच

रक्षा

137-146

एयर कुशन वाहन (ACVs)s
आईएनएस टूनागिरी, आईएनएस शोधक और आईएनएस अग्रे को त्रि-कमीशन
भारत के परमाणु त्रय में रणनीतिक बदलाव
ब्रह्मोस मिसाइल
एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
रुद्रएम-II मिसाइल
भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस)
नेत्र एयरबोर्न अली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली
रक्षा दशक परिवर्तन (2014-2026)

आपदा

147-148

भारत और शहरी अग्निकांड: मालवीय नगर घटना

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

संदर्भ:

भारत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि को चिह्नित किया, जो 1858 में ग्वालियर के पास ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए थे।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में:

वह कौन है?

- रानी लक्ष्मीबाई झांसी रियासत की रानी और 1857 के भारतीय विद्रोह की एक प्रतिष्ठित नेता थीं।
- "भारत की सबसे बड़ी नायिका" और महिला नेताओं के बीच एक अग्रणी के रूप में जानी जाने वाली उनकी ऐतिहासिक विरासत को अक्सर छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसी हस्तियों के साथ साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।



शुरुआती दिन और विलय संकट:

- रानी पत्नी: उनका विवाह झांसी रियासत के शासक महाराजा गंगाधर राव से हुआ था।
- उत्तराधिकार संकट: महाराजा की असामयिक मृत्यु ने शाही वंश को प्राकृतिक रूप से जन्मे उत्तराधिकारी के बिना छोड़ दिया। उनके निधन से पहले, शाही जोड़े ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए एक युवा राजकुमार को गोद लिया था।

व्यपगत का सिद्धांत:

- विस्तारवादी नीतियों से प्रेरित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी (ईआईसी) ने गोद लिए गए राजकुमार की वैधता को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
- विवादास्पद व्यपगत का सिद्धांत का उपयोग करते हुए - जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य के तहत किसी भी रियासत को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाएगा यदि शासक एक प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है - ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा कर लिया।

1857 के विद्रोह में प्रमुख योगदान:

- लगाम संभालना: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए अपनी संप्रभुता को सौंपने से इनकार करते हुए, रानी ने राज्य का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।
- सैन्य नेतृत्व: उन्होंने झांसी के सशस्त्र बलों का पुनर्गठन किया, स्थानीय सैनिकों को एकजुट किया, और व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बलों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में उनका नेतृत्व किया।
- अथक प्रतिरोध का प्रतीक: कई पड़ोसी रियासतों के विपरीत, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने का विकल्प चुना, लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक रैली स्थल बन गई, जो विदेशी शासन के खिलाफ पूर्ण बलिदान और अवज्ञा का प्रतीक थीं।

अंतिम दिन और शहादत:

- एक तीव्र ब्रिटिश हमले का सामना करते हुए, रानी ने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी।
- झांसी के पतन के बाद, वह विद्रोह को जीवित रखने के लिए ग्वालियर की ओर पीछे हट गई। 18 जून, 1858 को, वह ग्वालियर के पास ब्रिटिश घुड़सवार इकाइयों से लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे।
- इतिहासकारों का कहना है कि वह हार के रूप में मर गई, लेकिन हार के नहीं, भारतीय इतिहास में एक महान शहीद के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया।

सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और विरासत:

- मौखिक परंपराएं और प्रारंभिक साहित्य: औपनिवेशिक सेंसरशिप के बीच, उनकी विरासत लोक परंपराओं के माध्यम से जीवित रही, जिसने रवींद्रनाथ टैगोर की झांसीर रानी (1877) को प्रेरित किया।
- चौहान की आइकॉनिक कविता: सुभद्रा कुमारी चौहान की 1930 की कविता 'झांसी की रानी' ने उनकी बहादुरी को अमर कर दिया, "खूब लाड़ी मर्दानी..."।

- सबाल्टर्न और मॉडर्न रीटेलिंग्स: वृंदावन ताल वर्मा (1946) ने उन्हें एक आदर्श राष्ट्रवादी नायिका के रूप में चित्रित किया, जबकि महाश्वेता देवी (1956) ने लोक और सबाल्टर्न कथाओं पर प्रकाश डाला।
- झांसी रेजिमेंट की आईएनए रानी: उनकी विरासत से प्रेरित होकर, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आईएनए की महिला लड़ाकू इकाई का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा।

सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक

संदर्भ:

18 से 22 जून, 1940 तक नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के पहले पूर्ण सम्मेलन की वर्षगांठ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक अध्याय पर प्रकाश डालती है।

सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक

सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में:

यह क्या है?

- ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मई 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित एक कट्टरपंथी राजनीतिक दल था, जो शुरू में इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) मैट्रिक्स और कांग्रेस के इंडियन नेशनल एक्स्प्रेस लांचे के भीतर एक वामपंथी गुट के रूप में काम कर रहा था।
- वामपंथी और कट्टरपंथी राष्ट्रवादी तत्वों को एकजुट करने के लिए बनाई गई इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के पुराने नेता को चुनौती देना था।
- जून 1940 तक, नागपुर प्लेनरी ने फॉरवर्ड ब्लॉक को एक स्वतंत्र समाजवादी राजनीतिक ताकत में बदल दिया, जो एक उग्रवादी, साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- जनवरी 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने कट्टरपंथी, वामपंथी युवा समूहों की बढ़ती आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करके कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सफलतापूर्वक चुनाव जीता।
- हालांकि, उनकी जीत ने पार्टी के भीतर गहरे वैचारिक दरार को उबलते हुए बिंदु पर ला दिया।
- बोस का मानना था कि जनता ब्रिटिश राज के खिलाफ एक तत्काल, समझौता न करने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जबकि महात्मा गांधी और प्रमुख नेतृत्व ने महसूस किया कि समय समय से पहले था। इस गतिरोध ने बोस को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने और अपना राजनीतिक वाहन स्थापित करने के लिए मजबूर किया।

सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ी?

- दक्षिणपंथी समझौते के आरोप: बोस ने सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं की खुले तौर पर आलोचना की, उन्हें दक्षिणपंथी के रूप में पेश किया और उन पर ब्रिटिश सरकार के साथ सक्रिय रूप से एक प्रति-उत्पादक समझौते की मांग करने का आरोप लगाया।
- सामूहिक इस्तीफे का संकट: बोस के आक्रामक राजनीतिक दावों ने गांधीवादी हलकों के भीतर भारी असंतोष पैदा कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस कार्य समिति के 12 सदस्यों को नाटकीय रूप से इस्तीफा देना पड़ा।
- त्रिपुरी सत्र के अल्टीमेटम: मार्च 1939 के त्रिपुरी सत्र में, बोस ने मांग की कि कांग्रेस अंग्रेजों को स्वतंत्रता देने के लिए छह महीने का सख्त अल्टीमेटम दे, एक उग्रवादी रणनीति जिसे महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।
- गोविंद बल्लभ पंत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव ने बोस को गांधी की इच्छा के अनुसार सख्ती से एक कार्य समिति नामित करने के लिए मजबूर किया। गांधी की रणनीति से बंधे एक प्रमुख राष्ट्रपति बने रहने से इनकार करते हुए, बोस ने इस्तीफा दे दिया।

फॉरवर्ड ब्लॉक: लक्ष्य और प्रमुख विचार

- वैश्विक भू-राजनीति का लाभ उठाना: नेताजी ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिद्वंद्वी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच एक साम्राज्यवादी संघर्ष के रूप में देखा और भारत से तत्काल स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने के लिए ब्रिटेन की कमजोरी का फायदा उठाने का आग्रह किया।
- एक वैकल्पिक नेतृत्व का निर्माण: प्राथमिक लक्ष्य कांग्रेस के झिझकने वाले पुराने गार्ड के लिए एक कट्टरपंथी, वामपंथी विकल्प की पेशकश करना था, जिससे राष्ट्रीय ध्यान जन आंदोलन की ओर बढ़ सके।
- स्वतंत्रता के बाद समाजवादी ब्लूप्रिंट की स्थापना: नेताजी ने एक दोहरे चरण की कल्पना की जहां पार्टी युद्ध के दौरान एक समझौता न करने वाले साम्राज्यवाद विरोधी अभियान को लागू करेगी और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समाजवाद पर आधारित एक नए भारत के निर्माण के लिए संक्रमण करेगी।
- पूर्ण संप्रभुता का आक्रोश: नागपुर सम्मेलन में, नेताजी ने देश को एक शक्तिशाली नई रैली की पेशकश करने के लिए मानक संवैधानिक मांगों को आगे बढ़ाया: भारतीय लोगों को सारी शक्ति।



भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में फॉरवर्ड ब्लॉक का योगदान:

- कट्टरपंथी वामपंथी तत्वों को जुटाना: पार्टी ने एक साम्राज्यवाद विरोधी बैनर के नीचे बिखरे हुए समाजवादी, युवा और कट्टरपंथी राष्ट्रवादी समूहों को सफलतापूर्वक एकजुट किया।
- जन जागरूकता को बढ़ावा देना: मई और जुलाई 1939 के बीच, नेताजी ने बंगाल, पंजाब और संयुक्त प्रांत में बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी दौरे शुरू किए, भारी भीड़ को आकर्षित किया और जनता को गतिशील प्रतिरोध के लिए तैयार किया।
- कांग्रेस को आंदोलन की ओर ले जाना: बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा लागू किए गए निरंतर राजनीतिक दबाव ने प्रभावी रूप से मुख्यधारा की कांग्रेस को समझौता वार्ता छोड़ने और अंततः ब्रिटेन के प्रति अधिक टकराव की मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर किया।
- सशस्त्र मुक्ति के लिए एक नींव बनाना: फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा निर्मित कट्टरपंथी वैचारिक ढांचे ने सीधे तौर पर नेताजी के बाद में भारत से भागने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) को संगठित करने और विदेशों से सशस्त्र संघर्ष शुरू करने के लिए मंच तैयार किया।

कांग्रेस से नेताजी के टूटने का महत्व:

- वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ की बौद्धिक पुनर्परिभाषा: विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के भीतर एक कठोर बहस को मजबूर कर दिया, जो कि वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं का गठन करता है, जैसा कि नेताजी और जवाहरलाल नेहरू के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों में दर्शाया गया है।
- विचार की राजशाही को चुनौती देना: इसने प्रदर्शित किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अखंड नहीं था, यह साबित करता है कि स्वतंत्रता के लिए वैकल्पिक राजनीतिक रास्ते प्रमुख गांधीवादी दर्शन को चुनौती दे सकते हैं।
- गुट से स्वतंत्र बल में संक्रमण: नागपुर के पूर्ण सत्र में उस क्षण को चिह्नित किया गया जब फॉरवर्ड ब्लॉक ने केवल एक आंतरिक कांग्रेस दबाव समूह के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में उभरा।
- राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए एक प्रारंभिक खाका: इसने राज्य योजना और धन वितरण पर संरचित विचारों को पेश किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय स्वतंत्रता का मतलब श्रमिक वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक मुक्ति होगा।

निष्कर्ष:

द्वितीय विश्व युद्ध को कार्रवाई में देरी करने के कारण के बजाय मुक्ति के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखकर, नेताजी ने भारत के साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण, जुझारू ऊर्जा लाई। अंततः, जबकि उनके बाहर निकलने ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर गहरे वैचारिक विभाजन को उजागर किया, फॉरवर्ड ब्लॉक ने भारत के राजनीतिक क्षितिज में पूर्ण संप्रभुता और समाजवादी भविष्य के आह्वान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।

चापेकर ब्रदर्स

संदर्भ:

22 जून, 1897 को तीन चापेकर भाइयों ने बुबोनिक प्लेग के दौरान किए गए औपनिवेशिक अत्याचारों का बदला लेने के लिए पुणे में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड की हत्या कर दी।

चापेकर ब्रदर्स

चापेकर ब्रदर्स के बारे में:

वे कौन हैं?

- चापेकर बंधु - दामोदर हरि चापेकर (28), बालकृष्ण हरि चापेकर (24), और वासुदेव हरि चापेकर (18) - 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का बीड़ा उठाया था। कोंकण क्षेत्र से आने वाले उन्होंने एकमात्र उदाहरण के रूप में ऐतिहासिक प्रमुखता हासिल की, जहां भारत की स्वतंत्रता की सेवा में तीन जैविक भाइयों को फांसी दी गई थी।

प्रारंभिक दिन और वैचारिक जड़ें:

- धार्मिक पालन-पोषण: भाइयों का जन्म हरिपंत चापेकर के घर हुआ था, जो एक प्रसिद्ध कीर्तनकार (शास्त्रों के गायक-कहानीकार) थे। बाद में परिवार अपने भक्तों के करीब रहने के लिए पुणे के सदाशिव पेठ में स्थानांतरित हो गया।
- पौराणिक प्रेरणा: धर्मग्रंथों के पाठ पर पले-बढ़े दामोदर चापेकर ने सवाल किया कि उनकी पीढ़ी ब्रिटिश उत्पीड़कों द्वारा सन्नद्ध समकालीन रावण और कंस के खिलाफ क्यों नहीं उठ सकती है।
- देशभक्तिपूर्ण प्रभाव: दोनों भाई क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र संघर्ष से गहराई से प्रभावित थे और राष्ट्रवादी नेता लोकमान्य तिलक के प्रबल अनुयायी थे, जो नियमित रूप से समाचार पत्र केसरी में उनकी उग्र सामाजिक-राजनीतिक आलोचनाओं को पढ़ते थे।

1897 पुणे प्लेग और हत्या:

- प्लेग संकट: अक्टूबर 1896 में, बुबोनिक प्लेग पुणे में फैल गया। प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए, बॉम्बे गवर्नर सैंडहर्स्ट ने वाल्टर चार्ल्स रैंड को पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया।



- औपनिवेशिक उत्पीड़न: रैंड ने ब्रिटिश सैनिकों को तैनात किया जिन्होंने अत्यधिक असंवेदनशील उपायों को लागू किया। सैनिकों ने घरेलू रसोई और घर के मंदिरों की पवित्रता का उल्लंघन करते हुए चमड़े के जूते के साथ निजी आवासों में प्रवेश किया।
- हत्या योजना: इन कृत्यों से क्रोधित होकर, भाइयों ने 22 जून, 1897 को रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह के दौरान रैंड की हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने रैंड को हमले की चेतावनी देते हुए एक पूर्वव्यापी पत्र भी भेजा।
- द एक्जीक्यूशन एंड गोंड्या आला रे: मुथा नदी के पुल के पास इंतजार करते हुए, भाइयों ने अपने गुप्त कोड गोंड्या आला रे का इस्तेमाल किया (मूल रूप से एक वाक्यांश जो उनके सरकारी नियोजित चाचा के कमरे में प्रवेश करते थे, तो विषय को सुरक्षित रूप से बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था)।
- घातक गलती: अंधेरे में भ्रम के कारण, सबसे छोटे भाई वासुदेव ने गलत कोच पर हमले का संकेत दिया, जिससे बालकृष्ण ने गोली मार दी और तुरंत लेफ्टिनेंट चार्ल्स आयरस्ट की हत्या कर दी। गलती का एहसास करते हुए, दामोदर दूसरी गाड़ी पर कूद गया और रैंड को गोली मार दी, जिसने 3 जुलाई को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और महत्व:

- सशस्त्र क्रांतिकारी उत्साह को प्रज्वलित करना: चापेकर बंधु संगठित क्रांतिकारी समूहों के मुख्यधारा बनने से पहले के युग में काम करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों पर उनके निडर हमले ने औपनिवेशिक प्रशासन को हिलाकर रख दिया और ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया।
- राष्ट्र के लिए शहादत: मुखबिर गणेश और रामचंद्र द्रविड़ द्वारा पुलिस को धोखा देकर तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर मौत की सजा सुनाई गई। दामोदर को 18 अप्रैल, 1898 को, वासुदेव को 8 मई को और बालकृष्ण को 12 मई, 1898 को फांसी दी गई थी। उनकी अटूट देशभक्ति को दामोदर के संस्मरण, म्यूजिंग्स फ्रॉम द फालोउ में प्रलेखित किया गया था।
- बाद के क्रांतिकारियों के प्रेरक: चापेकरों के सर्वोच्च बलिदान ने पूरे भारत में एक लहर पैदा की। नासिक में एक युवा विनायक दामोदर सावरकर उनकी फांसी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत की मुक्ति के लिए अपने अधूरे क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार देवता, आठ भुजाओं वाली दुर्गा के सामने एक गंभीर शपथ ली।

राखीगढ़ी - हड़प्पा स्थल

संदर्भ:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने औपचारिक रूप से हरियाणा में राखीगढ़ी स्थल से खुदाई किए गए मानव कंकाल के अवशेषों को भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (एएनएसआई) को सौंप दिया है।

राखीगढ़ी - हड़प्पा स्थल

राखीगढ़ी - हड़प्पा साइट के बारे में:

यह क्या है?

- राखीगढ़ी एक प्राचीन कांस्य युग का महानगर है जो सिंधु-सरस्वती (हड़प्पा) सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात शहरी बस्ती के रूप में खड़ा है। यह स्थल हजारों वर्षों के निरंतर मानव निवास का दस्तावेजीकरण करता है, जो प्रारंभिक (पूर्व-हड़प्पा) से लेकर परिपक्व हड़प्पा काल तक एक पूर्ण विकासवादी स्ट्रैटिग्राफी को प्रदर्शित करता है।

स्थान:

- भौगोलिक मैट्रिक्स: हरियाणा के हिसार जिले की नारनौद तहसील में स्थित है, जो नई दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है।
- नदी का मैदान बेसिन: उपजाऊ घग्गर-हकरा नदी के मैदान के भीतर, मौसमी सरस्वती नदी के शुष्क पैलियो-बेड के साथ स्थित है।

खोज और खुदाई:

- प्रारंभिक खोज: इस स्थल की पहचान पहली बार 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा की गई थी, जिसमें 1969 में प्रोफेसर सूरज भान द्वारा किए गए अग्रणी दस्तावेज थे।

प्रमुख खुदाई:

- डॉ. अमरेंद्र नाथ (एएसआई): 1997 और 2000 के बीच ऐतिहासिक व्यापक खुदाई का नेतृत्व किया, जिससे बस्ती के वास्तविक महानगरीय पैमाने की पुष्टि हुई और शुरुआती कब्रिस्तानों की खोज हुई।
- प्रोफेसर वसंत शिंदे (डेक्कन कॉलेज): 2012 से 2016 तक बड़े पैमाने पर संरचनात्मक और कंकाल खुदाई का नेतृत्व किया, टीले की संख्या का विस्तार किया और प्राचीन डीएनए को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया।
- डॉ. संजय मंजुल (पुरातत्व संस्थान): 2022 से 2026 तक आधुनिक क्षेत्र के मौसमों का आयोजन किया, टीले नंबर 7 में अभूतपूर्व कब्रिस्तान कलाकृतियों का पता लगाया।



साइट की मुख्य विशेषताएं:

- उन्नत ब्रिड सिटी योजना: 1.92 मीटर चौड़ी पक्की सार्वजनिक सड़कों के साथ मानकीकृत जली हुई और मिट्टी की टेराकोटा ईंटों का उपयोग करके घरों का निर्माण किया गया था।
- परिष्कृतजल निकासी वास्तुकला: व्यक्तिगत घरों से सीधे मुख्य सड़क सीवेज चैनलों में चलने वाले जटिल, ईंट-पंक्तिबद्ध अपशिष्ट जल नालियों की सुविधा है।
- बड़े सार्वजनिक अन्न भंडार: परिपक्व हड़प्पा परतों में खोजे गए, इस सार्वजनिक अन्न भंडार में मिट्टी-ईंट निर्माण और सात बड़े आयताकार कक्ष हैं। निचली दीवारें नमी को दूर करने के लिए चूने और विघटित घास के निशान बनाए रखती हैं।
- औद्योगिक विनिर्माण केंद्र: टीला नंबर 1 एक प्राचीन विनिर्माण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें कपड़े-रंगाई प्रतिष्ठान, टेराकोटा फायरिंग भट्टे, और एक विशेष सोने की फाउंड्री होती है जिसमें एक भट्टी और 3,000 से अधिक अपरिष्कृत अर्ध-कीमती रत्न होते हैं।
- टीला नंबर 7 कब्रिस्तान और समृद्ध दफन प्रसाद: प्राथमिक कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है।
- हाल ही में 2025-26 की खुदाई से अभूतपूर्व अंत्येष्टि रीति-रिवाजों का पता चला, जिसमें कुछ कब्रों में उत्त्व सामाजिक स्थिति का संकेत देने के लिए मृतक के पास 40 अलग-अलग मिट्टी के बर्तनों की पेशकश की गई थी। कंकाल पारंपरिक रूप से उत्तर-दक्षिण संरेखण में रखे जाते हैं।
- वाणिज्यिक और अनुष्ठान कलाकृतियां: उत्खनन से मानकीकृत चर्ट व्यापार वजन, तांबे की मछली के हुक, जानवरों की मूर्तियाँ, नागरिक अनुष्ठानों के लिए ईंट-पंक्तिबद्ध आग की वेदियाँ, और हड़प्पा लिपि प्रतीकों और मगरमच्छ रूपांकनों के साथ उकेरी गई अद्वितीय स्टीटाइट सिलेंडर सील प्राप्त हुई।

सुश्रुत

संदर्भ:

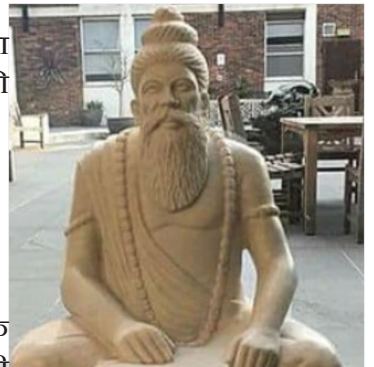
स्कॉटलैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग, जिसे व्यापक रूप से दुनिया का सबसे पुराना सर्जिकल कॉलेज माना जाता है, ने प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

सुश्रुत

सुश्रुत के बारे में:

वह कौन था?

- सुश्रुत एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक और सर्जन हैं, जिन्हें दुनिया भर में "प्लास्टिक सर्जरी के पिता" और "सर्जरी के पिता" के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया में इसी तरह की प्रथाओं की स्थापना से पहले जटिल ऑपरेटिव प्रक्रियाओं, संरचनात्मक शारीरिक विच्छेदन और संरचित चिकित्सा शिक्षा सहस्राब्दियों का बीड़ा उठाया।



इतिहास और युग:

- कालक्रम: माना जाता है कि वह लगभग 2,600 साल पहले (लगभग 600 ईसा पूर्व) रहते थे और अभ्यास करते थे।
- ऐतिहासिक समयरेखा: सुश्रुत ने हिप्पोक्रेट्स से एक सहस्राब्दी पहले और सेल्सस और गैलेन जैसे प्रमुख यूरोपीय चिकित्सा दिग्गजों के उभरने से दो सहस्राब्दी पहले उन्नत, गणना की गई शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया।

साहित्यिक कृतियाँ: सुश्रुत संहिता

- सुश्रुत ने अपने चिकित्सा और शल्य चिकित्सा ज्ञान को सुश्रुत संहिता में संकलित किया, जो आज जीवित प्राचीन दुनिया के सबसे विस्तृत और मूलभूत चिकित्सा संकलनों में से एक है।
- संरचनात्मक विभाजन: संग्रह को दो प्राथमिक खंडों में विभाजित किया गया है: पूर्वा-तंत्र (जो उन्नत सर्जरी, आंतरिक चिकित्सा, बाल रोग, शरीर रचना विज्ञान और विष विज्ञान से संबंधित है) और उत्तर-तंत्र (जिसमें मनोचिकित्सा, बुजुर्गों की देखभाल और आंख, कान, नाक और गले के रोगों को शामिल किया गया है)।
- पाठ का दायरा: ग्रंथ एक विशाल चिकित्सा शब्दकोष का दस्तावेजीकरण करता है जिसमें शामिल हैं:
 - 1,120 अलग-अलग बीमारियाँ और चिकित्सा स्थितियाँ।
 - 700 से अधिक औषधीय पौधे और पशु और खनिज स्रोतों से प्राप्त सैकड़ों उपचार।
 - 300 से अधिक जटिल चिकित्सा और ऑपरेटिव प्रक्रियाएं।
 - लगभग 120 अद्वितीय, अत्यधिक विशिष्ट सर्जिकल उपकरण।

चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान

- अब्रणी राइनोप्लास्टी और प्लास्टिक पुनर्निर्माण: उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान राइनोप्लास्टी (कटी हुई नाक का सर्जिकल पुनर्निर्माण) का विकास है, जिसमें माथे या गाल (पेडिकल फ्लैप) से काटी गई त्वचा के फ्लैप का उपयोग किया जाता है।
- अष्टविधा शास्त्र (सर्जरी की आठ श्रेणियाँ): उन्होंने सभी सर्जिकल हस्तक्षेपों को आठ मौलिक संरचनात्मक विधियों में वर्गीकृत

किया: छेदना (छांटना), भेदना (चीरा), लेखा (स्कैपिंग), व्याध (पंचर), ईशाना (जांच), अहर्था (निष्कर्षण), विश्रवण (जल निकासी), और सेवाना (टांके)।

- उन्नत थर्मल ट्रॉमा फ्रेमवर्क: उन्होंने जलने, हीट स्ट्रोक, शीतदंश और बिजली के हमलों के लिए एक आधुनिक शैली की वर्गीकरण प्रणाली बनाई, पश्चिमी चिकित्सा द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाने से बहुत पहले थर्मल चोटों के विभिन्न रूपों को एक एकीकृत नैदानिक ढांचे में समूहित किया।
- जीवनशैली और व्यापक चिकित्सा: उन्होंने आधुनिक मधुमेह, मोटापा और हृदय संबंधी विकारों से मिलती-जुलती जीवनशैली-सहसंबद्ध स्थितियों की पहचान की।
- संरचित हैंड्स-ऑन मेडिकल एजुकेशन: सुश्रुत ने अनिवार्य किया कि छात्रों को मानव रोगियों पर ऑपरेशन करने से पहले सटीकता में महारत हासिल करने के लिए निर्जीव वस्तुओं पर व्यावहारिक मॉक सर्जरी करनी चाहिए।

पैट्रिस लुमुम्बा की जीवित मूर्ति: उपनिवेशवाद-विरोधी प्रतिरोध के लिए एक कांगो प्रशंसक की श्रद्धांजलि

संदर्भ:

मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में फीफा विश्व कप 2026 के दौरान, डीआर कांगो के सुपरफैन मिशेल नकुका म्बोलाडिंगा ने स्वतंत्रता नायक पैट्रिस लुमुम्बा का सम्मान करते हुए एक जीवित मूर्ति के रूप में गतिहीन खड़े होकर वैश्वक ध्यान आकर्षित किया।

पैट्रिस लुमुम्बा की जीवित प्रतिमा

पैट्रिस लुमुम्बा की जीवित मूर्ति के बारे में: उपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध के लिए एक कांगो प्रशंसक की श्रद्धांजलि:

यह क्या है?

- मिशेल नकुका म्बोलाडिंगा, जिन्हें स्टेडियमों में लुमुम्बा वीया के नाम से जाना जाता है, ने साधारण फुटबॉल स्टैंड को ऐतिहासिक स्मृति और राजनीतिक एकजुटता के लिए एक सक्रिय स्थान में बदल दिया है।
- उनकी मुद्रा किंशासा में प्रतिष्ठित पैट्रिस लुमुम्बा प्रतिमा को प्रतिबिंबित करती है। पूरे मैच के दौरान गतिहीन खड़े रहकर, म्बोलाडिंगा 2026 फीफा विश्व कप का उपयोग राष्ट्रीय संप्रभुता, उपनिवेशवाद से मुक्ति और अफ्रीकी गौरव के प्रतीक के रूप में करता है।

पैट्रिस लुमुम्बा का इतिहास और पृष्ठभूमि:

- प्रारंभिक व्यावसायिक पृष्ठभूमि: 2 जुलाई, 1925 को कसाई प्रांत में एक जातीय अल्पसंख्यक जनजाति में जन्मे, लुमुम्बा ने डाक वर्क बनने की दुर्लभ औपनिवेशिक उपलब्धि हासिल की। वह वोल्टेयर और विक्टर ह्यूगो के ज्ञानोदय और रोमांटिक साहित्य से गहराई से प्रेरित थे।
- राजनीतिक जागृति: शुरू में एवोलुएस (पश्चिमी-शिक्षित अफ्रीकियों का एक समूह) में भाग लेते हुए, 1956 में एक संक्षिप्त जेल की सजा के बाद उनके राजनीतिक विचारों में काफी तेजी आई। रिहा होने पर, उन्होंने मूवमेंट नेशनल कांगोलिस (एमएनसी) की सह-स्थापना की, जो देश की पहली सही मायने में ट्रांस-जातीय, राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है।
- सत्ता में उदय: घाना में क्वामे नक्रुमा की उपनिवेशवाद-विरोधी सफलता से प्रेरित होकर, लुमुम्बा की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बेल्जियम शासन के खिलाफ अत्यधिक सफल बहिष्कार और जन आंदोलन आयोजित किए। मई 1960 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद, 34 वर्षीय लुमुम्बा को लोकतांत्रिक रूप से डीआरसी के पहले प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था।
- 1960 का अपरीक्षित भाषण: स्वतंत्रता दिवस (30 जून, 1960) पर, बेल्जियम के राजा बॉडोइन और बेल्जियम समर्थक कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कासा-वुबू की उपस्थिति में, लुमुम्बा ने एक पौराणिक, अपरीक्षित भाषण दिया जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया:
- "सुबह, दोपहर और रात, हमें उपहास, अपमान और मारपीट का सामना करना पड़ा क्योंकि हम 'नीग्रो' थे। कोई भी कांगो कभी नहीं भूलेगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में जीती गई थी।
- विश्वासघात, निष्पादन और संशोधन: अपने कार्यकाल के सात महीने बाद, एक पश्चिमी-भड़काए गए गृहयुद्ध और मोइस त्शोम्बे के तहत खनिज समृद्ध कटंगा प्रांत के अलगाव के बीच, लुमुम्बा को कासा-वुबू द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और सेना प्रमुख कर्नल जोसेफ मोबुतु के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में पकड़ लिया गया था।
- जनवरी 1961 में, अमेरिकी आइजनाहवर प्रशासन, सीआईए और बेल्जियम की खुफिया जानकारी के सक्रिय प्राधिकरण के साथ, लुमुम्बा को प्रताड़ित किया गया, एक फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया, और उनके अवशेषों को सल्फ्यूरिक एसिड के एक बर्तन में भंग कर दिया गया। 2022 में, बेल्जियम के एक अधिकारी द्वारा रखा गया एक सुनहरा दांत अंततः प्रतीकात्मक दफन के लिए उसके परिवार को वापस कर दिया गया।

कांगो इंपीरियल इतिहास:

- कांगो का इतिहास यूरोपीय साम्राज्यवाद के सबसे कूर अध्यायों में से एक है। फरवरी 1885 में, बर्लिन सम्मेलन ने कांगो फ्री स्टेट को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय की निजी, व्यक्तिगत जागीर के रूप में मान्यता दी।



- मानवीय सभ्यता और ईसाई धर्म के प्रसार के झूठे बहाने के तहत, लियोपोल्ड ने खनिज समृद्ध क्षेत्र को जंगली खबर, निकल, सोना, हीरे, कोबाल्ट और यूरेनियम निकालने के लिए एक बड़े पैमाने पर मजबूर-श्रम शिविर में बदल दिया।
- 1908 में जब तक बेल्जियम राज्य ने प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण ले लिया, तब तक अनुमानित 10 मिलियन कांगो नागरिक भुखमरी, बीमारी और गणना किए गए कॉर्पोरेट निष्पादन के कारण मर गए थे।
- अगली आधी सदी के लिए, बेल्जियम राज्य ने सख्त अलग-अलग बनाए रखा, जिससे आबादी पूरी तरह से अशिक्षित रही; 1960 में स्वतंत्रता के समय, 30 से कम कांगो के नागरिकों के पास विश्वविद्यालय की डिग्री थी।

पैट्रिस लुमुम्बा का मुख्य योगदान:

- एक गहरे खंडित राष्ट्र को एकजुट करना: लुमुम्बा ने क्षेत्रीय जनजातीयता को सख्ती से खारिज कर दिया, मूवमेंट नेशनल कांगोलिस की विलक्षण पहचान के तहत दो सौ से अधिक अलग-अलग जातीय समूहों को सफलतापूर्वक एकजुट किया।
- अग्रणी कट्टरपंथी पैन-अफ्रीकीवाद: ववामे नक्रुमाह और फ्रांज़ फैनन जैसे वैश्विक आइकन के साथ, लुमुम्बा ने पूर्ण अफ्रीकी आर्थिक मुक्ति का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि राजनीतिक स्वतंत्रता पूरी तरह से अर्थहीन थी यदि पश्चिमी निगम अभी भी महाद्वीप की उप-भूमि संपत्ति को नियंत्रित करते हैं।
- सच्ची पूर्ण संप्रभुता की मांग: कठपुतली-राज्य व्यवस्था को स्वीकार करने से उनके इनकार ने सदियों के प्रत्यक्ष यूरोपीय शासन को तेजी से समाप्त करने के लिए मजबूर किया, जिसने दुनिया भर में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के लिए एक साहसिक उदाहरण स्थापित किया।
- भविष्य के क्रांतिकारी नेताओं को प्रेरक बनाना: उनका जीवन और लेखन बाद की पीढ़ी के अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतीकों के लिए एक मूलभूत खाका बन गया, जिसमें थॉमस संकरा और नेल्सन मंडेला शामिल थे।

श्रद्धांजलि और विरासत का महत्व:

- भू-राजनीतिक स्थानों की विडंबना: संयुक्त राज्य अमेरिका में मैचों के दौरान अपनी जीवित प्रतिमा की दिनचर्या का प्रदर्शन करने का मबोलाडिंगा का निर्णय अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिससे लुमुम्बा की छवि उसी देश में वापस आ जाती है जिसकी खुफिया एजेंसियों ने उसे हटाने की योजना बनाई थी।
- आधुनिक उथल-पुथल में आशा की किरण: जैसे-जैसे आधुनिक डीआरसी क्षेत्रीय सुरक्षा संघर्षों और संसाधन शोषण को नेविगेट करना जारी रखता है, लुमुम्बा की दृष्टि अटूट राष्ट्रीय लचीलेपन के एकीकृत प्रतीक के रूप में कार्य करती है।
- समकालीन राजनीति से आगे बढ़ना: स्टैडियम श्रद्धांजलि साबित करती है कि लुमुम्बा केवल इतिहास की किताबों में बंद एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि उपनिवेशवाद-विरोधी गरिमा का एक जीवित मानक-वाहक हैं।
- स्वतंत्रता का अविनाशी प्रतीक: जैसा कि दार्शनिक फ्रांज़ फैनन द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लुमुम्बा को अफ्रीका में बेच दिया गया था - एक अडिग चैंपियन जिसे बाहरी वैश्विक शक्तियों द्वारा खरीदा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।

निष्कर्ष:

पैट्रिस लुमुम्बा की मुद्रा को मूर्त रूप देकर, प्रशंसक ऐतिहासिक औपनिवेशिक पीड़ा और पूर्ण संप्रभुता के लिए आधुनिक कांगो संघर्ष के बीच की खाई को पाटता है। अंततः, हालांकि 1961 में लुमुम्बा के भौतिक शरीर को दुखद रूप से नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके साम्राज्यवाद-विरोधी आदर्श पूरी तरह से अपराजित हैं, जो फुटबॉल स्टेड के दिल से वैश्विक अफ्रीकी प्रवासियों को प्रेरित करते हैं।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में:

वह कौन था?

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय (जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है) भारत के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों, कवियों, निबंधकारों और पत्रकारों में से एक थे। एक महान साहित्यिक दिग्गज के रूप में पहचाने जाने वाले, उनके बौद्धिक और रचनात्मक आउटपुट ने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शुरुआती दिन:

- उनका जन्म 27 जून, 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में एक पारंपरिक बंगाली परिवार में हुआ था।
- शिक्षा: वह एक शानदार विद्वान थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले दो स्नातकों में से एक बन गए।
- सिविल सेवा: अपनी शिक्षा के बाद, वह एक डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के रूप में औपनिवेशिक प्रशासन में शामिल हुए, सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त होने से पहले तीस वर्षों से अधिक समय तक सरकार की सेवा की।



साहित्यिक कृतियाँ:

- दुर्गेशनंदिनी (1865): उनका पहला प्रमुख बंगाली रोमांस उपन्यास, जिसने इस क्षेत्र के साहित्यिक परिदृश्य में क्रांति ला दी।
- आनंदमठ (1882): 18वीं सदी के संन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक उपन्यास। इस पुस्तक को व्यापक रूप से उनके सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- देवी चौधरी: एक और प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास दमनकारी ब्रिटिश कर संग्रह प्रणालियों के खिलाफ महिलाओं की ताकत और सक्रिय प्रतिरोध पर जोर देता है।
- बंगदर्शन: एक कट्टरपंथी साहित्यिक मासिक पत्रिका जिसकी स्थापना उन्होंने 1872 में की थी। इसने बंगाली पुनर्जागरण के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में कार्य किया, विज्ञान, इतिहास और सामाजिक दर्शन पर निबंधों को जनता के सामने पेश किया।

स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान:

- वंदे मातरम का उपहार: अपने उपन्यास आनंदमठ में, उन्होंने भजन वंदे मातरम का परिचय दिया। मूल रूप से संस्कृत और बंगाली के सुंदर मिश्रण में लिखी गई इस कविता ने भारत को एक पोषित लेकिन शक्तिशाली मातृ देवी के रूप में चित्रित किया।
- स्वतंत्रता आंदोलन का गान: वंदे मातरम तेजी से पूरे देश में फैल गया, जो एक साधारण कविता से भारतीय राष्ट्रवादियों के आधिकारिक युद्ध घोष में बदल गया।
- देशभक्ति के विचार को विकसित करना: अपने पात्रों के माध्यम से, बंकिम चंद्र ने क्रांतिकारी विचार सिखाया कि मातृभूमि की मुक्ति के लिए काम करना सर्वोच्च आध्यात्मिक कर्तव्य था, जो बंगाल और उसके बाहर भूमिगत राष्ट्रवादी समूहों को सीधे प्रेरित करता था।

अंतिम दिन:

- अपने अंतिम वर्षों में, बंकिम चंद्र ने आधिकारिक सार्वजनिक भूमिकाओं से पूरी तरह से धार्मिक, दार्शनिक और साहित्यिक लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीछे हट गए, जिसमें भगवद गीता पर विस्तृत टिप्पणियां भी शामिल थीं।
- जीवन भर सेवा और साहित्य के लिए समर्पित रहने के बाद, 8 अप्रैल, 1894 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया।

3 जून की घोषणा**संदर्भ:**

3 जून, 2026, 1947 की ऐतिहासिक 3 जून की घोषणा (जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है) की 79वीं वर्षगांठ है।

3 जून की घोषणा**3 जून की घोषणा के बारे में:****यह क्या है?**

- 3 जून की घोषणा भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन द्वारा जारी किया गया आधिकारिक स्वाका था, जिसमें ब्रिटिश भारत के विभाजन और भारतीय हाथों में राजनीतिक संप्रभुता के हस्तांतरण के लिए संरचनात्मक विधि, राजनीतिक तर्क और त्वरित समयरेखा का विवरण दिया गया था।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

- इस घोषणा की अवधारणा गहरे राजनीतिक गतिरोध और बढ़ती सामाजिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि के खिलाफ की गई थी:
- सांप्रदायिक गतिरोध: 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के पतन के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध टूट गए। अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के लिए लीग के आह्वान ने ब्रेट कलकत्ता हत्याओं को ट्रिगर किया, जो जल्दी से नोआखली, बिहार और पंजाब जिलों (अमृतसर, रावलपिंडी) में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया।
- जब मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पदभार संभाला, तो ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली ने उन्हें 30 जून, 1948 के बाद सत्ता हस्तांतरित करने के लिए एक सख्त समय सीमा दी।
- बाल्कन योजना को छोड़ना: माउंटबेटन ने मूल रूप से एक वैकल्पिक योजना (प्लान बाल्कन) का मसौदा तैयार किया था जिसने अलग-अलग प्रांतों को स्वतंत्रता की घोषणा करने या अपनी विधानसभाओं को चुनने की अनुमति दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे जमकर खारिज कर दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि इससे भारत का पूर्ण विखंडन होगा। यह महसूस करते हुए कि पाकिस्तान की मांग अब अपरिहार्य थी, माउंटबेटन ने शेष भारत के लिए एक मजबूत, एकीकृत केंद्रीय ब्लॉक को संरक्षित करने के लिए 3 जून की योजना तैयार की।

3 जून की योजना की मुख्य विशेषताएं:

- विभाजन का सिद्धांत: ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया। दो अलग-अलग संप्रभु प्रभुत्व- भारत का अधिराज्य और पाकिस्तान का अधिराज्य- स्थापित किया जाना था।

प्रांतीय आत्मनिर्णय:

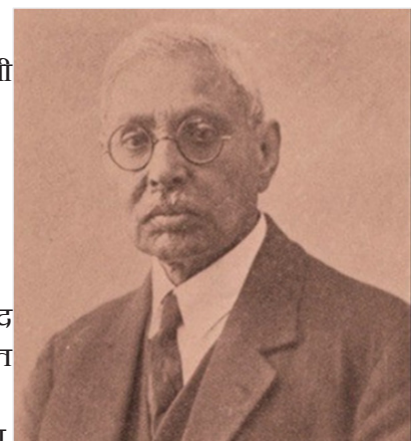
- बंगाल और पंजाब: इन दो विशाल प्रांतों की विधानसभाओं को विभाजन पर अलग-अलग मतदान करने के लिए दो वर्गों (मुस्लिम बहुल और गैर-मुस्लिम बहुल जिले) में विभाजित किया गया था। यदि किसी भी वर्ग में साधारण बहुमत ने विभाजन के लिए मतदान किया, तो प्रांत का विभाजन हो जाएगा।
- सिंध: सिंध विधानसभा को यह जनादेश दिया गया था कि वह किस संविधान सभा में शामिल हो, इस पर मतदान करे।
- उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी) और सिलहट: वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत संग्रह मतदाताओं को भारत और पाकिस्तान के बीच वयन करने की अनुमति देने के लिए निर्धारित किया गया था। बाद में सिलहट ने पूर्वी बंगाल में विलय के लिए मतदान किया।
- सीमा आयोग: इस योजना ने प्रांतीय विभाजन की स्थिति में सटीक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का नक्शा तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र सीमा आयोग (बाद में सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में) के निर्माण को अनिवार्य किया।
- रियासतों की दुविधा: इस योजना ने 560+ रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। उनसे स्वतंत्र रहने का विकल्प छीन लिया गया था और भौगोलिक निकटता के आधार पर उन्हें भारतीय या पाकिस्तानी प्रभुत्व में शामिल होने की आवश्यकता थी।
- त्वरित स्वतंत्रता तिथि: बढ़ती हिंसा के बीच एक पूर्ण प्रशासनिक पतन को रोकने के लिए, माउंटबेटन ने नाटकीय रूप से मूल जून 1948 की समय सीमा से 15 अगस्त, 1947 तक सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण को आगे बढ़ाया।

मौलाना बरकतउल्लाह भोपाली**संदर्भ:**

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने संस्थान का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया है।

मौलाना बरकतउल्लाह भोपाली**मौलाना बरकतउल्लाह भोपाली के बारे में:****वह कौन था?**

- मौलाना बरकतउल्ला भोपाली (7 जुलाई, 1854 - सितंबर 1927) एक महान उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी, विद्वान और उग्र पत्रकार थे, जिन्होंने 1915 में स्थापित निर्वासन में भारत की पहली सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने अपने वयस्क जीवन का पूरा समय अंतरराष्ट्रीय धरती से संचालित होने में बिताया, ब्रिटिश शासन से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक साम्राज्यवाद-विरोधी नेटवर्क का निर्माण किया।

**प्रारंभिक जीवन और वैचारिक विकास:**

- जन्म और शिक्षा: भोपाल, मध्य प्रदेश में जन्मे, वह एक अत्यधिक मेधावी छात्र थे, जिन्होंने कई भाषाओं में महारत हासिल की। वह उन्नत अध्ययन के लिए बॉम्बे और बाद में लंदन चले गए।
- कट्टरपंथ की विंगारी: इंग्लैंड के लिवरपूल में अरबी और फारसी पढ़ाते समय, उन्होंने सक्रिय भारतीय क्रांतिकारियों के साथ रास्ते पार किए। उनके नियमित ब्रिटिश विरोधी लेखों और उग्र सार्वजनिक भाषणों ने उन्हें ब्रिटिश खुफिया के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया, जिससे उन्हें 1899 में संयुक्त राज्य अमेरिका भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- कोर यूनिटी का दृष्टिकोण: बरकतुल्लाह पूर्ण हिंदू-मुस्लिम एकजुटता में दृढ़ विश्वास रखते थे। साथी स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी को लिखे अपने व्यक्तिगत पत्रों में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूर अकाल और आर्थिक भुखमरी ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से कुचल दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भारत कभी भी सच्ची संप्रभुता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि सभी धार्मिक समुदाय फूट डालो और राज करो की रणनीति के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं लड़ते।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख योगदान:

- बरकतुल्लाह के उपनिवेशवाद-विरोधी अभियानों ने गठबंधनों के एक जटिल, वैश्विक नेटवर्क को फैलाया:

काबुल निर्वासन सरकार का नेतृत्व (1915):

- 1 दिसंबर 1915 को, बरकतुल्लाह ने काबुल में भारत की अंतिम सरकार की सह-स्थापना की, जो स्वतंत्रता के लिए अंतराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश नियंत्रण के बाहर स्थापित पहली भारतीय सरकार थी।
- राजा महेंद्र प्रताप ने राष्ट्रपति के रूप में, मौलाना बरकतुल्ला ने प्रधान मंत्री के रूप में और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया, जो एक संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चे का प्रतीक है।

गदर पार्टी में भूमिका:

- बरकतुल्लाह गदर पार्टी (1913) के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, जिसने सशस्त्र क्रांति की वकालत की और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को खारिज कर दिया।

- पार्टी का उद्देश्य ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर बड़े पैमाने पर विद्रोह को शुरू करना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विद्रोह को प्रेरित करना था।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन धुरी योजना:

- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने जर्मनी के साथ मिलकर काम किया, ब्रिटेन के दुश्मनों को भारत के मुक्ति संग्राम में संभावित सहयोगियों के रूप में देखा।
- उन्होंने यूरोप में भारतीय युद्धबंदी शिविरों का दौरा किया , पकड़े गए सैनिकों से एक क्रांतिकारी बल में शामिल होने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया।

व्लादिमीर लेनिन से मुलाकात (1919):

- 1919 में, बरकतुल्लाह ने भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के लिए समर्थन मांगने के लिए मास्को में व्लादिमीर लेनिन से मुलाकात की।

अंतिम दिन और निधन:

- गिरते स्वास्थ्य और निरंतर ब्रिटिश निगरानी के बावजूद, बरकतुल्लाह विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहे।
- सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की सभा में भाग लेने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें कैलिफोर्निया में दफनाया गया।

मुख्य उपलब्धियां:

- भारत की निर्वासित सरकार के प्रधान मंत्री: काबुल सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने एक स्वतंत्र भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व किया।
- स्वतंत्रता संग्राम का वैश्वीकरण: बरकतुल्लाह ने एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सक्रियता के माध्यम से भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन को एक अंतरराष्ट्रीय अभियान में बदल दिया।
- भविष्य के क्रांतिकारी प्रयासों की नींव रखना: इन प्रयासों ने बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों और इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के गठन को प्रभावित और प्रेरित किया।

झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला

संदर्भ:

आदिवासी शिल्प कौशल के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर में, झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों- भूँया रेशम, कुचाई रेशम, मुंडा आभूषण और बांस शिल्प को आधिकारिक तौर पर प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है।

झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला

झारखंड के चार पारंपरिक उत्पादों के बारे में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त होता है:

यह क्या है?

- भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग एक आधिकारिक बौद्धिक संपदा संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और गुण, विशेषताएं या प्रतिष्ठा होती है जो अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान के कारण होती हैं। भारत में, जीआई पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होते हैं।

जीआई टैग की मुख्य विशेषताएं:

- दोहराव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा: किसी उत्पाद के नाम के अनधिकृत उपयोग, नकल या जालसाजी को उसके अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र के बाहर रोकता है।
- प्रीमियम गुणवत्ता का आश्वासन: प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है और उपभोक्ताओं को आश्वस्त करता है कि उत्पाद अपने मूल स्थान से जुड़े पारंपरिक तरीकों का पालन करता है।
- आजीविका और सामुदायिक सशक्तिकरण: अधिक बाजार मान्यता और मूल्यवर्धन सुनिश्चित करके स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों की आय बढ़ाता है।
- वैश्विक ब्रांडिंग और निर्यात मूल्य: सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करते हुए निर्यात, ग्रामीण पर्यटन और अंतराष्ट्रीय दृश्यता को बढ़ावा देता है।
- झारखंड के नए जीआई-टैग किए गए खजाने:



भगैया सिल्क और कुचाई सिल्क:

- पारंपरिक झारखंड रेशम अपनी प्राकृतिक सुनहरी चमक, स्थायित्व और पर्यावरण के अनुकूल जंगली टसर रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है।
- स्वदेशी हाथ से रीलिंग तकनीकों के माध्यम से उत्पादित, जो राज्य की समृद्ध हथकरघा विरासत को दर्शाता है।

मुंडा आभूषण:

- पारंपरिक आदिवासी आभूषण मुंडा समुदाय के अद्वितीय ज्यामितीय पैटर्न और प्रकृति से प्रेरित रूपांकनों के साथ दस्तकारी की गई हैं।
- सदियों पुरानी स्वदेशी धातुशिल्प परंपराओं को संरक्षित करते हुए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है।

झारखंड बांस शिल्प:

- टोकरी, मैट, उपयोगिता उत्पाद और सजावटी सामान बनाने के लिए स्थानीय बांस का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल शिल्प।
- स्थायी आजीविका का समर्थन करता है और ग्रामीण वन क्षेत्रों में बांस आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देता है।



LK ACADEMY[®]
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

दलबदल विरोधी कानून

संदर्भ:

शिवसेना गुट के नौ में से छह लोकसभा सांसद कथित तौर पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट में शामिल होने की योजना बना रहे हैं।

दलबदल विरोधी कानून

दलबदल विरोधी कानून के बारे में:

यह क्या है?

- दलबदल विरोधी कानून भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के भीतर निहित एक व्यापक संवैधानिक ढांचा है। यह निर्वाचित विधायकों (सांसदों और विधायकों) को दंडित करता है जो अपनी राजनीतिक निष्ठा बदलते हैं या उस पार्टी के जनादेश को धोखा देते हैं जिसके टिकट पर वे कार्यालय के लिए चुने गए थे।
- उद्देश्य: राजनीतिक दलबदल को रोकना, सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करना और अवसरवादी पार्टी स्विचिंग को हतोत्साहित करके विधायी जनादेश की अखंडता की रक्षा करना।



दलबदल और अयोग्यता के लिए मानदंड:

एक राजनीतिक दल के सदस्य:

- स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दें (इस्तीफे या प्रस्थान का संकेत देने वाले आचरण के माध्यम से)।
- बिना अनुमोदन के पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करके/अनुपस्थित रहकर पार्टी विधि की अवहेलना करें, जब तक कि 15 दिनों के भीतर माफ न किया जाए।
- स्वतंत्र सदस्य: चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हों, जिससे तत्काल अयोग्यता हो सकती है।
- मनोनीत सदस्य: विधायिका में अपनी सीट लेने के छह महीने बाद एक राजनीतिक दल में शामिल हों। (वे केवल पहले छह महीनों के भीतर एक पार्टी में शामिल हो सकते हैं)।

मुख्य विशेषताएं और छूट:

- दो-तिहाई विलय नियम (पैरा 4): यदि कोई विधायक दल का दो-तिहाई किसी अन्य पार्टी के साथ विलय का समर्थन करता है तो कोई अयोग्यता नहीं।
- विभाजन प्रावधान का उन्मूलन: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने एक तिहाई विभाजन के लिए पहले की सुरक्षा को हटा दिया।
- पीठासीन अधिकारी छूट: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तटस्थता बनाए रखने के लिए कार्यकाल के दौरान अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं।

महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं:

- राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007): दलबदल का अनुमान किसी सदस्य के आचरण से लगाया जा सकता है; औपचारिक इस्तीफा आवश्यक नहीं है।
- गिरीश चोडनकर बनाम स्पीकर, गोवा विधानसभा (2022): किसी अन्य पार्टी में शामिल होने वाले दो-तिहाई समूह को वैध विलय के रूप में माना जा सकता है।
- सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र (2023): पैरा 3 को हटाने के बाद, विभाजन कोई बचाव नहीं है; वास्तविक राजनीतिक दल उसके संविधान और नेतृत्व से निर्धारित होता है, न कि केवल विधायी बहुमत से।

भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है

संदर्भ:

14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एक संरचनात्मक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें कहा गया था कि एक भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक कानूनी यात्रा दस्तावेज है और इसे नागरिकता के स्टैंडअलोन प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।



भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है

भारतीय पासपोर्ट के बारे में नागरिकता का प्रमाण नहीं है:

यह क्या है?

- भारतीय पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक राष्ट्रीय पारगमन दस्तावेज है। हालांकि यह विदेश में धारक की राष्ट्रियता स्थापित करने के लिए कई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सख्त पृष्ठभूमि की जांच और सत्यापन के बाद ही दिया जाता है, इसका प्राथमिक कानूनी उद्देश्य नागरिकता के एक निश्चित, स्टैंडअलोन प्रमाण के रूप में कार्य करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना और कांसुलर सुरक्षा प्रदान करना है।

उन्नत पासपोर्ट प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

- उन्नतआरएफआईडी माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी: नए जारी किए गए भारतीय पासपोर्ट चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) माइक्रोचिप्स और सुरक्षित बायोमेट्रिक डेटा स्टोरेज के साथ एम्बेडेड हैं।
- जालसाजी विरोधी और पहचान सुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया, बायोमेट्रिक आर्किटेक्चर पहचान धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और पासपोर्ट जालसाजी के जोखिम को काफी कम करता है।
- त्वरित वैश्विक मंजूरी: स्वचालित चिप कॉन्फिगरेशन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तेज़, निर्बाध इलेक्ट्रॉनिक आव्रजन मंजूरी की अनुमति देता है। इस आधुनिक ढांचे के तहत 14.7 मिलियन से अधिक ई-पासपोर्ट पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
- विस्तारित अंतराष्ट्रीय गतिशीलता: हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से प्रेरित, भारतीय पासपोर्ट धारक अब इसका आनंद ले रहे हैं:
- 27 देश पूरी तरह से वीज़ा-मुक्त प्रवेश की पेशकश कर रहे हैं (16 में 2019 से ऊपर)।
- 47 देश सुविधाजनक वीजा-ऑन-अराइवल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
- 66 देश सुलभ ई-वीजा प्रवेश चैनल प्रदान करते हैं।

भारत में निश्चित नागरिकता दस्तावेज:

- चूंकि पासपोर्ट को कानूनी रूप से एक पारगमन दस्तावेज के रूप में परिभाषित किया गया है, इसलिए निश्चित भारतीय नागरिकता को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत प्रबंधित विशिष्ट वैधानिक नागरिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाता है :
- प्राकृतिक नागरिकता प्रमाण: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सक्षम नगरपालिका या स्थानीय रजिस्ट्रार निकायों द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिनके माता-पिता भारतीय मूल के आधारभूत मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी): आधिकारिक राज्य नागरिक रजिस्टर के भीतर एक प्रमाणित समावेशन नागरिकता की स्थिति के निश्चित प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

- प्राकृतिककरण या पंजीकरण के प्रमाण पत्र: औपचारिक कानूनी चैनलों के माध्यम से सफलतापूर्वक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सीधे जारी किए गए आधिकारिक पंजीकरण प्रमाण पत्र।

सुधार 3.0 - भारत विकास दर की ओर

संदर्भ:

विशेषज्ञों ने एक महत्वाकांक्षी सुधार 3.0 रोडमैप का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले दशक में 8% से अधिक की विकास दर में परिवर्तित करना है।

सुधार 3.0 - भारत विकास दर की ओर

सुधार 3.0 के बारे में- भारत विकास दर की ओर:

यह क्या है?

- सुधार 3.0 एक व्यापक नीतिगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को न केवल एक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर उपकरण के रूप में, बल्कि राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए मुख्य बुनियादी ढांचे के रूप में देखता है।
- 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण की तरह, यह वास्तुकला मूलभूत बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) को ओपन-सोर्स बनाकर और भारत के शीर्ष अनुसंधान संस्थानों को मुफ्त प्रसंस्करण टोकन प्रदान करके पुरानी कंप्यूटिंग सीमाओं को पार करना चाहता है।

भारत के तकनीकी और विकास क्षेत्रों पर प्रमुख डेटा और आंकड़े:

- अल्पR&D व्युत्क्रम आधार रेखा: भारत वर्तमान में अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.65% अनुसंधान और विकास (R&D) पर खर्च करता है, जो चीन (2.4%), संयुक्त राज्य अमेरिका (3.5%), दक्षिण कोरिया (4.9%), और इज़राइल (5.4%) जैसे अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से काफी पीछे है।
- टोकन सब्सिडी लागत: भारत के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और 5,000 उच्च विद्यालयों को मुफ्त, असीमित एआई टोकन प्रदान करने के लिए आवश्यक संपूर्ण वार्षिक बजट का अनुमान 2 बिलियन डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.06%) है।
- कल्याण व्यय अनुपात: 2 बिलियन डॉलर का यह प्रस्तावित बजट भारत की वार्षिक खाद्य सब्सिडी (49 बिलियन डॉलर छाता) का केवल चौदहवां हिस्सा है और इसकी उर्वरक सब्सिडी का दसवां हिस्सा है।
- मोनोपोलिस्टिक कंप्यूट रियलिटी: ग्राफिक प्रोसेसर दिग्गज NVIDIA वर्तमान में वैश्विक AI प्रशिक्षण हार्डवेयर बाजार के 80% से अधिक पर नियंत्रण रखता है, जिससे संप्रभु परियोजनाओं के लिए विकास लागत बढ़ जाती है।

भारत के विकास के अवसर 3.0 प्रतिमान:

- 8% से अधिक जीडीपी ग्रोथ ट्रैक में परिवर्तन: एक संज्ञानात्मक बल गुणक के रूप में एआई का उपयोग व्यवस्थित रूप से दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार को ऐतिहासिक आधार रेखा से लक्षित भारत विकास दर तक बढ़ा सकता है।
- पुराने मेट्रिक्स पर अनुभूति को सब्सिडी देना: देश की 49 बिलियन डॉलर की विशाल ऊर्जा और भौतिक सब्सिडी के एक अंश को मुफ्त एआई टोकन की ओर फिर से आवंटित करने से देश के युवाओं को उच्च तकनीक वाले कार्यबल में बदल दिया जा सकता है।
- बेजोड़ बाजार पैमाने का लाभ उठाना: संरचनात्मक बातचीत के लाभ के रूप में भारत के विलक्षण 1.4 बिलियन उपयोगकर्ता बाजार का उपयोग करने से राज्य को भूमि और बिजली पहुंच के बदले में वैश्विक हाइपरस्केलर्स से बड़े पैमाने पर क्लाउड क्षमता सुरक्षित करने की अनुमति मिलती है।
- पूर्ण एआई डेटा संप्रभुता प्राप्त करना: घरेलू धरती पर होस्ट किए गए पूरी तरह से ओपन-सोर्स मॉडल (जैसे लामा या डीपसीक) का उपयोग करके, देश अचानक विदेशी एपीआई शटडाउन के जोखिम को समाप्त करता है।
- एंटरप्राइज़ स्तरों के माध्यम से सार्वजनिक प्रगति को क्रॉस-सब्सिडी देना: कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान किए गए उद्यम स्तरों की स्थापना स्कूलों और विकित्सा केंद्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त पहुंच के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न कर सकती है।

अब तक की गई प्रमुख पहलें:

- सॉफ्टवेयर आइडेंटिटी फाउंडेशन: बायोमेट्रिक आइडेंटिटी मेट्रिक्स के ऐतिहासिक रोलआउट ने 1.38 बिलियन नागरिकों को सुरक्षित रूप से नामांकित किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सार्वजनिक उपयोगिता का निर्माण कर रहा है।
- एकीकृत भुगतान वृद्धि: स्थानीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण अब 3.4 ट्रिलियन डॉलर के 250 बिलियन वार्षिक लेनदेन को निर्बाध रूप से संसाधित करता है, जो ग्रह के वास्तविक समय भुगतान की मात्रा के आधे हिस्से को संभालता है।
- मास डेटा क्रांति: 2016 के बाद से हाई-स्पीड नेटवर्क विस्तार के लिए नीति समर्थन ने राष्ट्रीय मोबाइल डेटा की कीमतों को \$3 प्रति जीबी से घटाकर \$0.10 प्रति जीबी कर दिया, जिससे मुफ्त एआई टोकन के लिए संरचनात्मक प्लेबुक स्थापित हो गई।
- अग्रणी स्थानीयकृत बड़े भाषा मॉडल: सर्वम जैसे स्वदेशी कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की सफल तैनाती ने साबित कर दिया है कि फ्रंटियर एआई सिस्टम को क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का उपयोग करके भारतीय धरती पर प्रशिक्षित और ठीक किया जा सकता है।

एआई रोडमैप से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- विदेशी सिलिकॉन की असाधारण पूंजीगत लागत: पूरी तरह से एकाधिकारवादी कंप्यूटिंग विक्रेताओं पर भरोसा करना उच्च GPU मूल्य निर्धारण के कारण एक राष्ट्रव्यापी 1.4-बिलियन-उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बनाता है।
- जटिल तकनीकी-वाणिज्यिक वैश्विक वार्ता: विशाल वैश्विक हाइपरस्केलर्स के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी को अंतिम रूप देने के लिए गहन भू-राजनीतिक क्रॉस-दबाव और डेटा रेजीडेंसी नियमों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- पैमाने की कठोर तकनीकी मांगें: राष्ट्रीय स्तर के एलएलएम की मेजबानी करने के लिए टियर-2/3 शहरों में 99.99% सिस्टम अपटाइम और अंडर-200ms विलंबता को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
- कमजोरियों को रोकने के लिए लगातार भेद्यता: सार्वजनिक क्षेत्र के एआई उपकरणों को बढ़ाने से सिस्टम को त्वरित इंजेक्शन और एल्गोरिथम मतिभ्रम जैसे संरचनात्मक डिजिटल खतरों के लिए खोलता है।
- विषम बजट प्राथमिकता को संबोधित करना: राज्य के विभागों को दीर्घकालिक डिजिटल उपकरणों को निधि देने के लिए उर्वरक जैसे भौतिक क्षेत्रों में आधारभूत सब्सिडी वृद्धि को स्थिर करने के लिए राजी करना अत्यधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की मांग करता है।

आगे की राह:

- हार्डवेयर मिक्स में विविधता लाना (40:30:30 स्प्लिट): एक अनुकूलित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को तैनात करके एकल-विक्रेता निर्भरता को तोड़ें: लागत प्रभावी AWS ट्रेनियम/AMD चिप्स पर 40%, अकादमिक अनुसंधान के लिए Google TPU पर 30%, और विरासत प्रशिक्षण के लिए NVIDIA पर 30%।
- एक राष्ट्रीय एआई टोकन नीति की घोषणा: प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ साझेदारी में एक बहु-विक्रेता संप्रभु गणना मेट्रिक्स बनाने के लिए एक औपचारिक 24 महीने की नीति ढांचा लागू करना।
- प्रारंभिक शैक्षणिक टोकन पायलट की तैनाती: 500 तकनीकी स्टार्टअप के लिए तुरंत एक एपीआई सैंडबॉक्स लॉन्च करें और प्रारंभिक शोध को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष 20 आईआईटी और आईआईएससी को असीमित मुफ्त टोकन प्रदान करें।
- स्थानीयकृत इंडिक बेंचमार्क को अनिवार्य करना: स्थानीय न्यायपालिकाओं, वलीनिकों और खेतों में एआई क्षमताओं को इंजेक्ट करने के लिए सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में अनुकूलित सार्वजनिक, फाइन-ट्यून मूलभूत मॉडल बनाएं।
- एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में मानना: कंप्यूट क्लस्टर को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मानने के लिए बुनियादी कंटेनर होस्टिंग को आगे बढ़ाएं, जो अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों के लिए उपयोग किए जाने वाले दीर्घकालिक निवेश मॉडल से मेल खाता है।

निष्कर्ष:

अनुकूलित 40:30:30 कंप्यूट ब्रिड और मुफ्त शोध टोकन के साथ अपने विशाल 1.4-बिलियन-उपयोगकर्ता बाजार उत्तोलन का मिलान करके, राष्ट्र विदेशी एकाधिकार और कम प्रौद्योगिकी लागत को सफलतापूर्वक तोड़ सकता है। अंततः, जैसा कि राज्य अगले दो दशकों में अपनी राष्ट्रीय एआई टोकन नीति को अंतिम रूप देने के लिए काम करता है, संज्ञानात्मक क्रांति को देश की आर्थिक संप्रभुता के स्थायी स्तंभ में बदलने के लिए कंप्यूट पावर को एक बुनियादी सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में मानना आवश्यक रहेगा।

ऑपरेशन शेरुवाली

संदर्भ:

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शेरुवाली जारी रखा और आतंकवाद विरोधी अभियान अपने सातवें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें डोरीमाल-गंभीर मुगल वन क्षेत्र में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाया गया।

ऑपरेशन शेरुवाली

ऑपरेशन शेरुवाली के बारे में:

यह क्या है?

- ऑपरेशन शेरुवाली एक बड़े पैमाने पर, बहु-एजेंसी आतंकवाद विरोधी अभियान है जो जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के घने जंगल वाले क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों को बेअसर करने और उनके समर्थन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है।
- द्वारा लॉन्च किया गया: भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस (विशेष अभियान समूह), और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।

उद्देश्य:

- राजौरी-पुंछ वन क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को ट्रैक करें, अलग-थलग करें और उनका सफाया करें।
- घुसपैठ को रोकना, आतंकी नेटवर्क को बाधित करना और पीर पंजाल क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करना।



प्रमुख विशेषताएँ:

- बहु-एजेंसी समन्वय: एकीकृत अभियानों के लिए सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, खुफिया ब्यूरो और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को शामिल किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी: वास्तविक समय की निगरानी और लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए ड्रोन, हेलीकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग सिस्टम और रिमफर डोंग का उपयोग करता है।
- घेराबंदी और तलाशी अभियान: सुरक्षा बलों ने स्तरित घेराबंदी स्थापित की है और घने जंगल वाले इलाकों में भागने के संभावित मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है।
- आतंकी बुनियादी ढांचे को लक्षित करना: दूरदराज के वन क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों, आपूर्ति डंप और रसद नेटवर्क को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

महत्व:

- यह कठिन पहाड़ी और जंगली इलाकों में निरंतर, खुफिया-आधारित अभियान चलाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र राजौरी-पुंछ में आतंकवादी गतिविधियों के हालिया पुनरुत्थान को रोकने में मदद करता है।

स्वतः संज्ञान और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं**संदर्भ:**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान के बार-बार उपयोग ने न्यायिक अतिरेक, निचली अदालतों की संरचनात्मक उपेक्षा और शीर्ष अदालत के मामले के चयन पर प्राइमटाइम मीडिया आख्यानों के बढ़ते प्रभाव के बारे में गहन बहस शुरू कर दी है।

स्वतः संज्ञान और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं**स्वतः संज्ञान और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में:****यह क्या है?**

- स्वतः संज्ञान एक विशेष कानूनी क्षेत्राधिकार है जो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को पूरी तरह से अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता है, बिना किसी औपचारिक याचिका या पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा दायर किए।
- ऐतिहासिक रूप से जनहित याचिका (पीआईएल) के विकास में निहित और संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 142 की विस्तृत शक्तियों के तहत स्थापित, यह एक शक्तिशाली संवैधानिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है जिसे मानवाधिकारों की रक्षा करने, न्याय के गंभीर गर्भपात को संबोधित करने या राज्य की निष्क्रियता की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- हालाँकि, इस हस्तक्षेप की सीमाएँ स्वाभाविक रूप से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और न्यायपालिका के संरचनात्मक लेआउट से बंधी हुई हैं।
- स्वतः प्रेरण शक्तियों का संवैधानिक रूप से एक अवशिष्ट, सहायक उपकरण होने का इरादा है जिसका उपयोग व्यक्तिगत आपराधिक मामलों को सूक्ष्म प्रबंधन करने के बजाय मैक्रो-सिस्टमिक वैक्युम को संबोधित करने के लिए किया जाता है जो पहले से ही सक्षम निचली सुनवाई अदालतों द्वारा सक्रिय रूप से संसाधित किए जा रहे हैं।

स्वतः संज्ञान का उदय:

- एक बार कानूनी विद्वानों मार्क गैलेंटर और वसुजीत राम द्वारा एक दुर्लभ लेकिन अत्यधिक दृश्यमान तंत्र के रूप में वर्णित होने के बाद, स्वतः संज्ञान संबंधी कार्यवाहियाँ एक अवशिष्ट क्षेत्राधिकार से एक आवर्ती साधन में स्थानांतरित हो गई हैं। डेटा स्पष्ट रूप से इस तीव्र वृद्धि को उजागर करता है:
- ऐतिहासिक बनाम हालिया खंड: सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 से 2024 तक पांच साल की अवधि में 35 स्वतः संज्ञान मामले शुरू किए, जो पिछले पंद्रह वर्षों की अवधि में दर्ज किए गए कुल 31 मामलों को पीछे छोड़ दिया।
- वार्षिक रुझानों में तेजी: अवमानना और स्थानांतरण मामलों को छोड़कर, अदालत ने 2020 में 10, 2021 में 8, 2022 में 1, 2023 में 4 और 2024 में 12 मामले दर्ज किए। यह प्रक्षेपवक्र 2025 में 10 सिविल और 3 आपराधिक स्वतः संज्ञान रिट के साथ जारी रहा।
- वर्तमान उछाल: मई 2026 के अंत तक, शीर्ष अदालत पहले ही 4 सिविल और 4 आपराधिक स्वतः संज्ञान मामले दर्ज कर चुकी है। अकेले इन कुछ महीनों के लिए आपराधिक गिनती ने पिछले पूरे वर्ष के आपराधिक योग से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो इस तंत्र पर तीव्र निर्भरता का संकेत देता है।

स्वतः प्रेरणा सक्रियता बनाम संस्थागत सुधार

- स्वतः संज्ञान हस्तक्षेपों में वृद्धि स्थानीयकृत न्यायिक सक्रियता और स्थायी संरचनात्मक सुधार के बीच एक स्पष्ट द्वंद्व को उजागर करती है:



- सक्रियता का आसान मार्ग: स्वतः प्रेरणा सूची के लिए व्यक्तिगत, हार्ड-प्रोफाइल आपराधिक मामलों का चयन करने के लिए न्यूनतम संस्थागत प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यह तत्काल, अत्यधिक दृश्यमान सार्वजनिक सत्यापन प्रदान करता है लेकिन केवल गहरे मुद्दों पर एक अस्थायी बैंड-सहायता के रूप में कार्य करता है।
- प्रणालीगत सुधार का कठिन मार्ग: सच्चा संरचनात्मक सुधार निरंतर, अस्पष्ट प्रशासनिक सहयोग की मांग करता है। इसमें अधीनस्थ अदालतों के पर्यवेक्षण के लिए अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालयों के साथ साझेदारी करना, गिरते ट्रायल-कोर्ट के बुनियादी ढांचे को निधि देने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करना, बड़े पैमाने पर न्यायिक रिक्तियों को भरना और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण मॉड्यूल का आधुनिकीकरण करना शामिल है।
- निचली न्यायपालिका के लिए तिरस्कार: स्थापित स्थानीय कानूनी चैनलों को दरकिनार करना अक्सर एक अंतर्निहित संगठनात्मक तिरस्कार का संकेत देता है, इस कथा को मजबूत करता है कि निचली सुनवाई अदालतें जटिल मामलों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए व्यवस्थित रूप से सशक्त बनाने के बजाय बीमार हैं।

पिछले स्वतः संज्ञान मामलों से सबक:

- एक पूर्वव्यापी विश्लेषण से पता चलता है कि शीर्ष-स्तरीय निगरानी शायद ही कभी ट्रायल अदालतों के आधारभूत प्रयासों की तुलना में न्याय के मुख्य वितरण को तेज करती है:
- आरजी कर मामला (2024): सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त, 2024 को स्वतः संज्ञान निगरानी शुरू की। हालाँकि, परिचालन कार्य पूरी तरह से स्थानीय सियालदह ट्रायल कोर्ट द्वारा संचालित किया गया था, जिसने स्वतंत्र रूप से सबूतों का मूल्यांकन किया, मुकदमा चलाया और जनवरी 2025 तक दोषसिद्धि और आजीवन कारावास सुनाया।
- लखीमपुर खीरी (2021): शीर्ष अदालत के गहन फोकस और जमानत के आदेशों को रद्द करने के बावजूद, मुकदमे की संरचनात्मक बाधाएं अपरिवर्तित रहीं। 2026 की शुरुआत तक, ट्रायल कोर्ट 44 सूचीबद्ध गवाहों में से केवल 131 से ही पूछताछ करने में कामयाब रहा था।
- मणिपुर (2023): जुलाई 2023 से वायरल जातीय हिंसा वीडियो के संबंध में अत्यधिक प्रचारित स्वतः संज्ञान हस्तक्षेप अभी तक अंतिम दोषसिद्धि में परिणत नहीं हुआ है, यह दर्शाता है कि ऊपर से नीचे न्यायिक पर्यवेक्षण स्वचालित रूप से स्थानीय प्रणालीगत गतिरोध को दूर नहीं करता है।
- हाथरस सिद्धांत: अक्टूबर 2020 हाथरस मामले जैसे पिछले उदाहरणों में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्धिमानी से संरचनात्मक सीमाओं को मान्यता दी और निगरानी कर्तव्यों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लौटा दिया। इसने इस सिद्धांत को बनाए रखा कि स्थानीय उच्च न्यायालय क्षेत्रीय मुद्दों की निगरानी के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं।

स्वतः संज्ञान से जुड़ी चुनौतियाँ:

- मीडिया-संचालित ट्रिगर अनुक्रम: केस चयन तेजी से एक अस्थायी, मीडिया-संचालित चक्र के लिए अनुकूलित हो गया है। निरंतर प्राइमटाइम मीडिया का ध्यान और टेलीविजन रिपोर्ट अक्सर मामले के पंजीकरण के लिए प्राथमिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं, जिससे न्यायपालिका एक ही प्रेस रिपोर्ट के उपभोक्ता और आलोचक दोनों में बदल जाती है।
- नामकरण के माध्यम से पूर्वाग्रह: किसी भी औपचारिक न्यायिक जांच से पहले अनुमानित वाक्यांशों के साथ मामलों को सूचीबद्ध करना - संस्थागत तटस्थता के मूल सिद्धांत से समझौता करता है।
- दुर्लभ ध्यान का गलत आवंटन: सालाना होने वाले हजारों वैधानिक अपराधों (उदाहरण के लिए, एनसीआरबी द्वारा एक ही वर्ष में दर्ज 6,450 से अधिक दहेज हत्याएं), अदालत के पास केवल कुछ मुद्दे भर लोगों को अपने तत्काल दृष्टिकोण में स्वीचने की कार्यात्मक क्षमता है। वस्तुनिष्ठ कानूनी बेंचमार्क के बजाय मीडिया की दृश्यता के आधार पर मामलों का चयन करना न्याय का एक मनमाना स्तर बनाता है।
- निचली अदालतों पर शीतलक प्रभाव: शीर्ष अदालत का लगातार हस्तक्षेप स्थानीय मजिस्ट्रेटों और उच्च न्यायालयों के मनोबल और कानूनी अधिकार को बाधित करता है, जो अक्सर पहले से ही आंदोलन में होते हैं और अभियुक्तों के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठा रहे होते हैं।

आगे की राह:

- सब्सिडी का सख्त पालन: सर्वोच्च न्यायालय को संस्थागत आत्म-संयम का अभ्यास करना चाहिए, स्थानीय आपराधिक मामलों को संबंधित राज्य उच्च न्यायालयों और स्थानीय ट्रायल मजिस्ट्रेटों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए जब तक कि एक स्पष्ट संवैधानिक टूटन न हो।
- वास्तुशिल्प पथ पर ध्यान केंद्रित करना: शीर्ष अदालत को अपनी दुर्लभ संस्थागत ऊर्जा को टेलीविजन पर मामले-निगरानी से दूर और दीर्घकालिक प्रशासनिक सुधारों की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिए, जैसे कि उप-जिला अदालत के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, मामले के प्रबंधन को मानकीकृत करना और न्यायिक रिक्तियों को भरना।
- चयन के लिए उद्देश्य सीमा: स्वतः संज्ञान कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट, पारदर्शी और कड़ाई से कानूनी मापदंडों को तैयार किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि उपकरण मीडिया की गति के बजाय संरचनात्मक गंभीरता से ट्रिगर हो।

निष्कर्ष:

प्रणालीगत विफलताओं को ठीक करने के लिए स्वतः संज्ञान एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन बना हुआ है, लेकिन इसके अति-उपयोग

से शीर्ष अदालत को एक अंतिम पर्यवेक्षक से एक विस्तृत, मीडिया-उत्तरदायी नौकरशाही में बदलने का जोखिम है। निचली न्यायपालिका को दरकिनारा करने वाले एकवचन, टेलीविज़न हस्तक्षेपों के माध्यम से सच्चा न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संस्थागत सुधार के कठोर, शांत कार्य के साथ अपनी ऊर्जावान सार्वजनिक सक्रियता को संतुलित करना चाहिए, जिससे मूलभूत विचारण अदालतें अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

ईएसआईसी की केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली

संदर्भ:

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपने सभी अस्पतालों और औषधालयों में एक राष्ट्रव्यापी, केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की।

ईएसआईसी की केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली

ESIC के केंद्रीकृत डिजिटल रोगी प्रतिक्रिया प्रणाली के बारे में:

यह क्या है?

- यह एक उन्नत, सर्वव्यापी डिजिटल सार्वजनिक शिकायत और गुणवत्ता-आश्वासन मंच है। यह प्रणाली लाभार्थियों को उनके स्वास्थ्य देखभाल अनुभव को तुरंत रेट करने की अनुमति देती है, जिससे प्रशासन को सेवा बेंचमार्क को ट्रैक करने और स्थानीय परिचालन कमियों को तुरंत दूर करने में मदद मिलती है।
- शामिल संगठन: इस प्लेटफॉर्म को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा शुरू किया गया है।

यह कैसे काम करता है और प्रमुख विशेषताएं:

- ओमनीचैनल फीडबैक ट्रिगर: एक बार जब कोई मरीज केंद्रीकृत ईएसआईसी स्वास्थ्य सूचना प्रणाली (धनवंतरि मॉड्यूल) के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाता है, तो एक स्वचालित प्रणाली एसएमएस के माध्यम से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सीधा फीडबैक लिंक भेजती है। वैकल्पिक रूप से, रोगी आउट-पेशेंट विभागों (ओपीडी) में बहुभाषी पोस्टरों पर प्रदर्शित स्थानीयकृत क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं।
- सुरक्षित ओटीपी सत्यापन: डेटा प्रामाणिकता बनाए रखने और धोखाधड़ी या डुप्लिकेट प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए, रोगी अपना बीमित व्यक्ति (आईपी) नंबर दर्ज करते हैं, जो वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) सत्यापन ढांचे को ट्रिगर करता है।
- दानेदार मेट्रिक्स मूल्यांकन: मरीज सेकंड के भीतर अपना मूल्यांकन पूरा कर सकते हैं, अस्पताल की सफाई, चिकित्सा कर्मचारियों के व्यवहार और संरचित पैमाने पर निर्धारित दवाओं की तत्काल उपलब्धता जैसे मुख्य मापदंडों की रेटिंग कर सकते हैं।
- स्वचालित वृद्धि मेट्रिक्स: यह प्रणाली एक डिजिटल ट्रिपवायर के रूप में कार्य करती है; कोई भी सेवा रेटिंग जो 5 में से 3 से नीचे आती है, उसे स्वचालित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में चिह्नित किया जाता है और त्वरित सुधारात्मक हस्तक्षेप के लिए स्थानीय प्रशासनिक डैशबोर्ड पर भेज दिया जाता है।
- भूमिका-आधारित निगरानी डैशबोर्ड: दैनिक संतुष्टि रुझानों पर निगरानी बनाए रखने के लिए संस्थागत, क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तरों पर पहुंच योग्य स्तरीय, वास्तविक समय विश्लेषण डैशबोर्ड को शामिल करता है।
- बहुभाषी इंटरफ़ेस: भाषा की बाधाओं को खत्म करने और विविध श्रमिक वर्ग के लाभार्थी पूल के बीच व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण बहुभाषी समर्थन की सुविधा देता है।
- महत्व:
 - रोगी की प्रतिक्रिया को तत्काल डिजिटल अलर्ट में परिवर्तित करता है, जिससे अस्पताल के अधिकारियों को सेवा अंतराल और परिचालन संबंधी मुद्दों को जल्दी से संबोधित करने में मदद मिलती है।
 - निरंतर रोगी संतुष्टि डेटा उत्पन्न करता है, ईएसआई अस्पतालों को रैंक करने में मदद करता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण को प्रोत्साहित करता है।

महा जल मिशन

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री ने जल क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए 200 करोड़ रुपये के महा जल मिशन का शुभारंभ किया।

महा जल मिशन

महा जल मिशन के बारे में:

यह क्या है?

- MAHA (उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन) जल मिशन एक उच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे मौलिक



अनुसंधान और क्षेत्र परिनियोजन के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उत्त्व प्रभाव वाले जल समाधानों के प्रौद्योगिकी विकास, सत्यापन और व्यावसायीकरण के लिए एक एकीकृत मार्ग के रूप में कार्य करता है।

शामिल संगठन:

मिशन निम्नलिखित के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है:

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ): भारत में अनुसंधान वित्त पोषण के लोकतंत्रीकरण और सुव्यवस्थित करने के लिए प्राथमिक निकाय।
- जल शक्ति मंत्रालय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के लिए नोडल मंत्रालय।
- अंतरिक्ष विभाग/इसरो: जल मानचित्रण और मूल्यांकन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकियां और भू-स्थानिक डेटा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वित्तीय सहायता: पांच वर्षों में ₹200 करोड़ का अनुमानित परिव्यय। वयनित बहु-विषयक संघ ₹20 करोड़ तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- बहु-विषयक संघ: भागीदारी विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संगठनों, स्टार्टअप, एमएसएमई और उद्योग भागीदारों के मिश्रण के लिए खुली है।
- प्रस्तावों के लिए ओपन कॉल: मिशन में विशेष रूप से उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास के लिए स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए एक समर्पित ओपन कॉल की सुविधा है।

पांच प्राथमिकता विषय:

- जल संसाधन मूल्यांकन और सतत प्रबंधन।
- पीने का पानी (गुणवत्ता और पहुंच)।
- पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य।
- जल उपयोग दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था।
- जलवायु लचीलापन और अनुकूलन।
- डिजिटल एकीकरण: वास्तविक समय की निगरानी और सार्वजनिक भागीदारी के लिए जल संवय जनभागीदारी, नागरिक ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग (JSJB-CTR) पोर्टल और ऐप के शुभारंभ से पूर्ण।

महत्त्व:

- देश भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थानों से परे विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप और युवा शोधकर्ताओं को वित्त पोषण प्रदान करता है।
- भूजल मानचित्रण और सिंचाई योजना के लिए इसरो के उपग्रह डेटा का उपयोग करता है, वैज्ञानिक और जलवायु-लचीला जल प्रबंधन का समर्थन करता है।

भूल जाने का अधिकार

संदर्भ:

दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उत्त्व न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में 'भूल जाने के अधिकार' को मान्यता दी।

भूल जाने का अधिकार

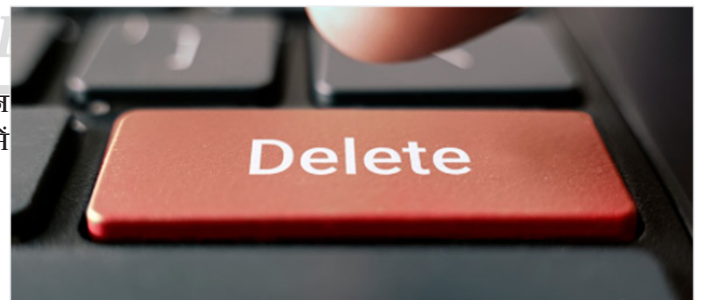
भूल जाने के अधिकार के बारे में:

यह क्या है?

- भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पिछले आपराधिक रिकॉर्ड या निजी विवाद, को विशिष्ट परिस्थितियों में इंटरनेट खोजों और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों से हटा दे।
- यह सूचनात्मक आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है, जो लोगों को पिछली घटनाओं से आगे बढ़ने की अनुमति देता है जो अब प्रासंगिक नहीं हैं या जहां जानकारी जानने में सार्वजनिक हित व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार से अधिक है।

इतिहास और विकास:

- यूरोपीय जड़ें: इस अवधारणा को 2014 के यूरोपीय न्यायालय के फैसले (Google Spain बनाम AEPD) के बाद वैश्विक प्रमुखता मिली, जिसने स्थापित किया कि खोज इंजनों को व्यक्तिगत डेटा के लिंक को हटाना होगा जो अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अत्यधिक हैं। इसे अब यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) में संहिताबद्ध किया गया है।
- भारतीय संदर्भ: संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2017 के केएस पुट्टास्वामी फैसले ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, जिससे आरटीबीएफ का मार्ग प्रशस्त हुआ।



- विधायी स्थिति: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 में व्यक्तिगत डेटा के सुधार, पूर्णता और मिटाने के प्रावधान शामिल हैं, जो भारत में इस अधिकार के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला:

- न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने जनता के जानने के अधिकार के साथ निजी गरिमा को संतुलित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया:
- डी-इंडेक्सिंग जनादेश: प्लेटफॉर्म को विशिष्ट मामलों के लिए नाम-आधारित खोज कार्यक्षमता को अक्षम करना होगा। इसका मतलब है कि निर्णय ऑनलाइन रहता है, लेकिन व्यक्ति का नाम खोजकर इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

राहत का दायरा: सुरक्षा मुख्य रूप से इन तक बढ़ाई गई है:

- आपराधिक आरोपों से बरी किए गए व्यक्ति
- वैवाहिक या निजी नागरिक विवादों में शामिल पक्ष
- ऐसे व्यक्ति जिनके नाम मामले में पक्षकार नहीं होने के बावजूद रिकॉर्ड में संयोग से दिखाई देते हैं।
- मास्किंग प्रोटोकॉल: अदालत ने आदेश दिया कि व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं (नाम, पते) को नकाबपोश/संशोधित किया जाए, जबकि न्यायिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कानूनी तर्क और निर्णय के निष्कर्ष सार्वजनिक रहते हैं।
- मध्यस्थ जिम्मेदारी: अदालत ने स्पष्ट किया कि खोज इंजन स्वचालित एल्गोरिदम के माध्यम से काम करते हैं और किसी व्यक्ति के सूचनात्मक गोपनीयता के मौलिक अधिकार को ओवरसाइड नहीं कर सकते हैं। आईटी नियम 2021 के तहत, वे ऐसे निष्कासन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

महत्व:

- यह डिजिटल कलंक को रोकता है, जहां व्यक्तियों को अदालतों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी पिछले कानूनी मुद्दों के कारण आजीवन पेशेवर या सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।
- सत्तारूढ़ स्वीकार करता है कि एक डिजिटल युग में जहां रिकॉर्ड लगभग अमिट हैं, पिछले डेटा को किसी व्यक्ति के भविष्य को प्रेरान करने से रोकने के लिए कानून विकसित होना चाहिए।
- पूर्ण विलोपन के बजाय मास्किंग की वकालत करके, अदालत यह सुनिश्चित करती है कि कानून अनुसंधान और मिसाल के लिए सुलभ बना रहे, लेकिन व्यक्तिगत उत्पीड़न के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं।

लैंड पूलिंग अधिग्रहण की समस्याओं को कैसे हल करती है?

संदर्भ:

राजस्थान ने आधिकारिक तौर पर सड़कों और सार्वजनिक कार्यों जैसी विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे की भूमि संयोजन को आसान बनाने के लिए अपनी पहली लैंड पूलिंग योजना की घोषणा की है।

लैंड पूलिंग अधिग्रहण की समस्याओं को कैसे हल करती है?

इस बारे में कि भूमि पूलिंग अधिग्रहण की समस्याओं को कैसे हल करती है?

भूमि अधिग्रहण क्या है?

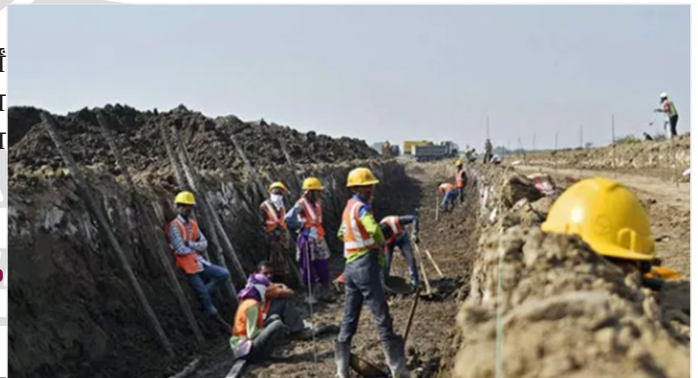
- भूमि अधिग्रहण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संप्रभु राज्य या एक सरकारी एजेंसी सार्वजनिक कल्याण, औद्योगिक बुनियादी ढांचे या शहरी विस्तार के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि को अनिवार्य रूप से अपने कब्जे में ले लेती है।
- इस पारंपरिक मॉडल के तहत, संपत्ति पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व अधिकार स्थायी रूप से राज्य द्वारा निर्धारित एकमुश्त मौद्रिक मुआवजे और निर्दिष्ट पुनर्वास भत्ते के बदले में सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

लैंड पूलिंग क्या है?

- लैंड पूलिंग एक प्रगतिशील, जन-केंद्रित सार्वजनिक सभा मॉडल है जहां आसन्न निजी भूमि मालिकों का एक समूह स्वेच्छा से अपने भूमि पारसल को पूल करता है और उन्हें शहरी बुनियादी ढांचे के लिए एक सरकारी विकास प्राधिकरण को सौंप देता है।
- नकदी लेआउट के लिए अपनी संपत्ति को स्थायी रूप से खोने के बजाय, सरकार सड़कों, खुले हरे सार्वजनिक स्थानों और सामाजिक आवास के लिए एक विशिष्ट हिस्से (आमतौर पर 25-45%) का उपयोग करती है, शेष 55-75% मूल मालिकों को एक छोटे, अत्यधिक पुनर्गठित, पूरी तरह से सेवित भूखंड के रूप में वापस कर देती है।

भारत में भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानून और उनकी विशेषताएं:

- इस स्थान को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:
- अनिवार्य सहमति खंड: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए कम से कम 70% प्रभावित परिवारों और विशुद्ध रूप से निजी औद्योगिक विकास के लिए 80% की पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता होती है।



- अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA): किसी भी आधिकारिक अधिसूचना से पहले स्थानीय सामुदायिक आजीविका और सामाजिक गतिशीलता पर बुनियादी ढांचा परियोजना के कारण होने वाले पूर्ण व्यवधान को मापने के लिए एक कठोर, बहु-हितधारक मूल्यांकन का आदेश देता है।
- उन्नत उचितबाजार मूल्य गुणक: पुराने औपनिवेशिक मूल्यांकन को प्रतिस्थापित करता है, शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य के दो गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के चार गुना तक की गणना की गई नकद मुआवजा प्रदान करता है, जिसे अनिवार्य 100% सोलेटियम कर द्वारा बल दिया जाता है।
- वैधानिक पुनर्वास और पुनर्वास (R&R) अधिकार: कानूनी रूप से न केवल प्राथमिक परिसंपत्ति शीर्षक धारकों को बल्कि भूमिहीन कृषि मजदूरों और आश्रित कारीगरों को भी राज्य समर्थित आजीविका लाभ, आवास या वार्षिकी पैकेज का अधिकार देता है।
- बहु-फसल सिंचित उपजाऊ भूमि का संरक्षण: दीर्घकालिक घरेलू खाद्य सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए बहु-फसल कृषि भूमि के बेलगाम अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है, केवल सख्त, सीमित असाधारण परिस्थितियों में अधिग्रहण की अनुमति देता है।

भारत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे:

- कॉर्पोरेट वित्तीय और पूंजीगत बोझ में गंभीर वृद्धि: आधुनिक कानून द्वारा अनिवार्य व्यापक कल्याणकारी दिशानिर्देशों ने आधारभूत बुनियादी ढांचा परियोजना लागत को काफी बढ़ा दिया है।
- उदाहरण: 2013 के बाद के आर एंड आर नियमों ने समग्र वित्तीय दायित्वों में काफी वृद्धि की है, जिससे अक्सर सार्वजनिक शहरी बुनियादी ढांचे के लिए बड़े पैमाने पर अनिवार्य अधिग्रहण आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गए हैं।
- प्रक्रियात्मक विलंब तंत्रों को पंगु बनाना महत्वपूर्ण परिसंपत्ति निष्पादन को रोकना: जटिल, बहु-चरण अनुमोदन वर्कफ्लो के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर निष्पादन अंतराल होते हैं, जिससे ब्लूप्रिंट लक्ष्य कागज पर फंसे रहते हैं।
- उदाहरण: एसआईए को पूरा करने, सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने और विवादों को निपटाने की लंबी प्रक्रिया अक्सर कई वर्षों तक महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को रोकती है, जिससे निष्पादन अंतराल का विस्तार होता है।
- व्यापक सामाजिक विस्थापन और सामुदायिक विखंडन: अनिवार्य बेदखली लंबे समय से चले आ रहे सामुदायिक नेटवर्क को तोड़ देती है, जिससे ग्रामीण आबादी को उनके पैतृक घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- उदाहरण: विशाल हिस्सों का स्थायी अधिग्रहण बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवासन का कारण बनता है और पड़ोस के नेटवर्क को विभाजित करता है, जिससे समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के बिना छोड़ दिया जाता है।
- असंतुष्ट भूस्वामियों द्वारा लगातार और तीव्र मुकदमेबाजी प्रतिस्पर्धा: मनमाने बेंचमार्क मूल्यांकन समुदायों को मुकदमे दायर करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे क्षेत्रीय अदालतों में बड़े पैमाने पर गतिरोध पैदा होता है।
- उदाहरण: स्थानीय जमीनी वास्तविकताओं और आधिकारिक स्टाम्प-ड्यूटी रिकॉर्ड के बीच बेमेल व्यापक कानूनी नाकेबंदी और अदालती विवादों को जन्म देते हैं, जिससे बुनियादी ढांचे का काम पूरी तरह से रुक जाता है।

लैंड पूलिंग के अनुकरणीय राज्य मॉडल:

- गुजरात टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) प्रतिमान: गुजरात टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के तहत औपचारिक, इस सदी पुराने मॉडल ने अहमदाबाद, सूरात, राजकोट, वडोदरा और गांधीनगर जैसे प्रमुख शहरी समूहों में 1,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
- गुवाहाटी व्यावहारिक अनुकूलन मॉडल: मैनुअल, गैर-डिजिटल रिकॉर्ड और जमीनी डेटा विविधताओं का सामना करते हुए, गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण ने मौजूदा मानचित्रों को बनाए रखकर समय बचाया और विशेष रूप से सड़क बुनियादी ढांचे के लिए व्यक्तिगत भूमि योगदान को मानक 40% से घटाकर अत्यधिक स्वीकृत 12-15% कर दिया।

भूमि पूलिंग भूमि अधिग्रहण के संकट को कैसे हल करती है:

- स्वैच्छिक भागीदारी के लिए अनिवार्य राज्य जबरदस्ती की अदला-बदली: यह मॉडल सामाजिक घर्षण से बचते हुए, जबरन सरकारी अधिग्रहण को सहभागी लेआउट के साथ बदल देता है।
- उदाहरण: क्योंकि भागीदारी सहकारी है, भूमि पूलिंग मॉडल विकास लाभों को समान रूप से वितरित करते हैं, लंबे समय तक कानूनी नाकाबंदी के जोखिम को काफी कम करते हैं।
- वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा इंजन बनाना: मॉडल भारी अभ्रिम लागत में कटौती करता है, समय के साथ मूल्य बढ़ने पर अपने स्वयं के धन का उत्पादन करता है।
- उदाहरण: अधिकारियों को शुरू में बड़े पैमाने पर नकदी भंडार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्नत भूखंडों पर वृद्धिशील शुल्क के माध्यम से भूमि मालिकों से समय के साथ विकास लागत वसूल की जाती है।
- कट्टरपंथी शारीरिक विस्थापन और पुनर्वास संकट को दूर करना: भूस्वामियों को स्थानीय सामुदायिक संबंधों को संरक्षित करते हुए अपने पड़ोस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
- उदाहरण: बाहर धकेलने के बजाय, परिवार अपने पारंपरिक सामाजिक दायरे से जुड़े रहते हुए, अपने मूल स्थान का 60-75% स्थानीय रूप से रखते हैं।
- छोटे धारकों के लिए परिसंपत्ति मूल्य सृजन में तेजी लाना: पुनर्गठित भूखंड बड़े पैमाने पर संरचनात्मक मूल्य वृद्धि को सुरक्षित करते हैं, कच्ची भूमि के छोटे टुकड़ों को अत्यधिक उपयोगी अवल संपत्ति में बदल देते हैं।
- उदाहरण: एक किसान कच्ची भूमि सौंपता है और थोड़ा छोटा लेकिन अत्यधिक मूल्यवान, अच्छी तरह से आकार का भूखंड प्राप्त करता है जो पूरी तरह से आधुनिक बिजली, पानी और सड़कों से जुड़ा हुआ है।

आगे की राह:

- व्यापक जीआईएस-आधारित भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में तेजी लाना: राज्यों को डेटा त्रुटियों से बचने के लिए योजनाओं को शुरू करने से पहले ड्रोन सर्वेक्षणों के माध्यम से भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट और मिलान करना चाहिए।
- पारदर्शी, बहु-स्तरीय वित्तीय रिटर्न मेट्रिक्स का मानकीकरण: भूमि योगदान पर स्पष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करके विश्वास का निर्माण करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि भूस्वामी यह समझें कि उन्हें क्या वापस मिलेगा।
- भूमिहीन और किरायेदार श्रमिकों के लिए समावेशी ढांचे को डिजाइन करना: नए भूखंडों के भीतर छोटे व्यवसाय स्थानों को शामिल करने के लिए मॉडल का विस्तार करना, स्थानीय किरायेदार श्रमिकों और मजदूरों की आजीविका की रक्षा करना।
- स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों के लिए कानूनी स्वतंत्रता प्रदान करना: स्थानीय नगरपालिका टीमों को स्वतंत्र रूप से योजनाओं को साफ करने और निष्पादित करने के लिए आवश्यक वित्तीय और कानूनी दांत देने के लिए पुराने शहरी नियोजन कानूनों को अपडेट करें।
- विकास चरणों के दौरान अस्थायी वार्षिकी सुरक्षा जाल का उपयोग करना: छोटे किसानों को वार्षिक वित्तीय भत्ते का भुगतान करें, जबकि उनके भूखंडों को उनके घरेलू खर्चों का समर्थन करने के लिए विकसित किया जा रहा है जब तक कि भूमि वापस नहीं आ जाती।

निष्कर्ष:

लैंड पूलिंग मॉडल की ओर परिवर्तन भारत के बदलते आर्थिक परिदृश्य में सतत शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विकासवादी कदम है। पारंपरिक जबरन अधिग्रहण को स्वैच्छिक भागीदारी में बदलकर, नगर नियोजन योजनाएं उच्च वित्तीय लागतों और लंबी कानूनी देरी को सफलतापूर्वक बायपास करती हैं, जबकि यह सुनिश्चित करती हैं कि समुदायों को नए बुनियादी ढांचे द्वारा बनाए गए मूल्य में हिस्सा मिले।

सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता**संदर्भ:**

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के जल्दबाजी में कार्यान्वयन ने गंभीर तकनीकी गड़बड़ियों, धुंधली स्क्रिप्ट स्कैन और असंगत अंकन पैटर्न के बाद गहन नैतिक बहस छेड़ दी है।

सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता**सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के बारे में:****पारदर्शिता क्या है?**

- लोक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में, पारदर्शिता एक संस्था का नैतिक दायित्व है कि वह खुले तौर पर, अनुमानित रूप से और समझ में आए। यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के पास सूचना, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और निर्णय लेने वाले वर्कफ्लो तक निरंकुश, निर्बाध पहुंच है जो संस्थागत कार्यों को नियंत्रित करते हैं।
- एक शैक्षिक संदर्भ में, यह एक छात्र के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है कि वह अपने बौद्धिक कार्य का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सटीक मानदंड, कार्यप्रणाली और चरणों को देखे।

यह विश्वसनीयता क्या है?

- विश्वसनीयता वह नैतिक पूंजी है जो एक संस्था समय के साथ अर्जित करती है, जो विश्वसनीयता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता और स्थिरता की नींव पर बनी होती है। यह पूर्वाग्रह, त्रुटि या प्रणालीगत विफलता के बिना अपने जनादेश को पूरा करने के लिए संस्था की क्षमता में सार्वजनिक स्थानों पर विश्वास के स्तर को दर्शाता है।
- जब एक सार्वजनिक संस्थान के पास उच्च विश्वसनीयता होती है, तो उसके प्रमाण पत्र, मूल्यांकन और निर्णय समाज द्वारा मानव प्रगति के लिए वैध और न्यायसंगत बेंचमार्क के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता का महत्व

- वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखना: खुले और विश्वसनीय मूल्यांकन ढांचे यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक पुरस्कार, जैसे कि कॉलेज प्रवेश और छात्रवृत्ति, मनमाने ढंग से त्रुटियों के बजाय पूरी तरह से योग्यता के आधार पर वितरित किए जाते हैं।
- उदाहरण: बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए, सटीक मूल्यांकन सीधे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय प्लेसमेंट का निर्णय लेता है, जिससे संस्थागत निष्पक्षता सामाजिक समानता के लिए एक पूर्ण शर्त बन जाती है।
- प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना: सार्वजनिक जांच के तहत काम करना संस्थानों को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकता है और नौकरशाही उदासीनता को व्यक्तिगत नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है।



- उदाहरण: एक सप्ताह के भीतर व्यापक विषय अंकन योजनाएं जारी करने से परीक्षकों को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह लागू करने से रोका जा सकता है, जिससे उन्हें समान दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- नागरिक विश्वास और संस्थागत वैधता को बढ़ावा देना: जब सार्वजनिक निकाय पूर्ण स्पष्टता के साथ काम करते हैं, तो यह सामाजिक सद्भाव का निर्माण करता है और राज्य प्रणालियों में जनता के विश्वास को मजबूत करता है।
- उदाहरण: सभी छात्रों को सक्रिय रूप से स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं मुफ्त में प्रदान करने से सार्वजनिक संदेह समाप्त हो जाता है और ब्रेडिंग पर कानूनी विवाद कम हो जाता है।
- निरंतर संगठनात्मक सुधार को बढ़ावा देना: ओपन ट्रेकिंग नेटवर्क संरचनात्मक स्वामियों को जल्दी उजागर करते हैं, जिससे सार्वजनिक संस्थानों को तकनीकी और परिचालन मुद्दों को बढ़ने से पहले ठीक करने की अनुमति मिलती है।
- उदाहरण: डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स और विसंगति-पहचान प्रणालियों का उपयोग करने से पर्यवेक्षकों को मूल्यांकन त्रुटियों को तुरंत पकड़ने की अनुमति मिलती है, जिससे लगातार ब्रेडिंग मानक सुनिश्चित होते हैं।

लोक शासन से जुड़े नैतिक सिद्धांत:

- Deontological नैतिकता (कर्तव्य और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता): इमैनुएल कांट के deontological ढांचे के तहत, सार्वजनिक संस्थानों के पास व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक पूर्ण, गैर-परक्राम्य नैतिक कर्तव्य है, चाहे लागत या प्रशासनिक प्रयास कुछ भी हो। परीक्षा बोर्डों के लिए, इसका मतलब है कि छात्रों को अपने आप में अंत के रूप में माना जाता है - उन्हें यह सत्यापित करने के लिए अधिकृत करना कि उनकी स्क्रिप्ट पूर्ण, पठनीय और स्थापित नियमों के अनुसार सख्ती से मूल्यांकन की जाती है।
- उपयोगितावाद (सार्वजनिक कल्याण को अधिकतम करना): जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल के उपयोगितावादी फोकस की मांग है कि सार्वजनिक प्रणालियां "सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी" का अनुकूलन करें। जल्दबाजी में डिजिटल रोलआउट जो सर्वर त्रुटियां और ब्रेडिंग विसंगतियों को पैदा करते हैं, लाखों छात्रों और परिवारों के बीच व्यापक संकट पैदा करके इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। सच्चा उपयोगितावादी मूल्य केवल तभी प्राप्त होता है जब मजबूत, पूरी तरह से नकली बुनियादी ढांचा सटीक परिणाम प्रदान करता है, विश्वास और सिस्टम स्थिरता को अधिकतम करता है।
- रॉल्लियन जस्टिस (द वेल ऑफ इग्नोरेंस): जॉन रॉल्लस का निष्पक्षता के रूप में न्याय का सिद्धांत कहता है कि संस्थागत नियमों को सबसे कमजोर हितधारकों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। डिजिटल उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंचने के लिए उच्च शुल्क लेना एक अनुचित वित्तीय बाधा पैदा करता है जो कम आय वाले परिवारों के खिलाफ भेदभाव करता है। सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायपूर्ण प्रणाली को इन लिपियों तक मुफ्त, समान पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

संस्थानों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए चुनौतियाँ:

- पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना जल्दबाजी में सिस्टम रोलआउट: परीक्षण के बिना जटिल सॉफ्टवेयर टूल तैनात करने से तकनीकी भ्रम पैदा होता है, जिससे सार्वजनिक मूल्यांकन की सटीकता कम हो जाती है।
- उदाहरण: उचित पायलट परीक्षण के बिना OSM रोलआउट में जल्दबाजी करने से गंभीर अंकन त्रुटियां, असमान चरण-ब्रेडिंग और उत्तर अनियंत्रित हो गए।
- सार्वजनिक रिकॉर्ड और डेटा एक्सेस का व्यावसायीकरण: नागरिकों से अपने स्वयं के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उच्च शुल्क लेना एक वित्तीय बाधा के रूप में कार्य करता है जो जवाबदेही को अवरुद्ध करता है।
- उदाहरण: छात्रों को अपनी स्वयं की डिजिटल उत्तर पुस्तिकाओं को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर करना कम आय वाले आवेदकों को दंडित करते हुए खराब मूल्यांकन की रक्षा करता है।
- कमजोर बुनियादी ढांचा परिचालन विफलता की ओर ले जाता है: कम-शक्ति वाले सर्वर या निम्न-गुणवत्ता वाले हार्डवेयर का उपयोग करने से डेटा त्रुटियां आती हैं जो संस्थागत सटीकता से समझौता करती हैं।
- उदाहरण: खराब गुणवत्ता वाले स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करने से धुंधली और अपूर्ण डिजिटल फाइलें उत्पन्न हुईं, जिससे मूल्यांकनकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रूप से ग्रेड करना असंभव हो गया।
- बाहरी गुणवत्ता ऑडिट और निरीक्षण की कमी: अलग-अलग नौकरशाही साइलो के भीतर काम करने से त्रुटियों का पता नहीं चल पाया जाता है, जिससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता को नुकसान होता है।
- उदाहरण: वास्तविक समय के स्वतंत्र मॉडरेशन की अनुपस्थिति ने मनमाने ढंग से अंकन विविधताओं को फिसलने की अनुमति दी, जिससे सार्वजनिक विवाद छिड़ गया।

आगे की राह:

- डिजिटल उत्तर पुस्तिकाओं तक मुफ्त और खुली पहुंच को अनिवार्य करना: पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्रों को उनकी परीक्षा के दो सप्ताह के भीतर सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनक्रिप्टेड, स्कैन की गई उत्तर प्रतियां मुफ्त प्रदान करें।
- व्यापक प्री-बोर्ड तनाव परीक्षण को लागू करना: राष्ट्रीय रोलआउट से पहले पोर्टल बग को ठीक करने के लिए स्थानीय स्कूल परीक्षाओं के दौरान डिजिटल सर्वर पर पूर्ण पैमाने पर मॉक सिमुलेशन और लोड परीक्षण की आवश्यकता होती है।
- मानकीकृत स्टेप-मार्किंग दिशानिर्देशों को लागू करना: मूल्यांकनकर्ता व्यक्तिपरकता को खत्म करने के लिए परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर विषयवार ब्रेडिंग चुंजी और स्वीकार्य वैकल्पिक समाधान ऑनलाइन जारी करें।
- स्वचालित डिजिटल ऑडिट नियंत्रण तैनात करना: ब्रेडिंग स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के भीतर एआई-संचालित टोटलिंग चेक, रीयल-टाइम ऑनलाइन मॉडरेशन और विसंगति-पहचान ट्रैकर्स को एम्बेड करें।

- कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नैतिकता और डिजिटल प्रशिक्षण की संरचना: रिफ्रैश की समीक्षा करने से पहले सभी मूल्यांकनकर्ताओं, स्कैनिंग ऑपरेटरों और सिस्टम प्रबंधकों को डिजिटल हैंडलिंग और नैतिक ब्रेडिंग प्रथाओं में औपचारिक प्रशिक्षण पूरा करने की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

मूल्यांकन ढांचा शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र का नैतिक आधार है, जो युवा नागरिकों के भविष्य के अवसरों और शैक्षणिक यात्राओं को सीधे आकार देता है। ऑन-स्क्रीन मार्किंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के दौरान आधुनिकीकरण के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करता है, उचित बुनियादी ढांचे या कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बिना रोलआउट में जल्दबाजी करने से जनता के विश्वास को कम करने और प्रणालीगत अनुचितता पैदा होने का जोखिम होता है।

अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सीट विस्तार: संवैधानिक प्रश्न और संस्थागत जोखिम

संदर्भ:

राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अदालत की स्वीकृत न्यायिक शक्ति को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है।

अध्यादेश के माध्यम से कोर्ट सीट विस्तार

अध्यादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सीट विस्तार के बारे में: संवैधानिक प्रश्न और संस्थागत जोखिम:

क्या हुआ?

- मई में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू होने के बाद पांच नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई गई।
- जबकि इनमें से दो नियुक्तियों ने मूल 34-न्यायाधीशों की आधार रेखा के भीतर मौजूदा, वैध रिक्तियों को निर्बाध रूप से भर दिया, शेष तीन नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यकारी डिफ्री द्वारा बनाई गई अस्थायी सीटों पर टिकी हुई हैं।

इसमें शामिल संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 124 (1): स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संरचना और अंतिम संख्या कानून द्वारा निर्धारित करने के लिए संसद के लिए छोड़ दिया गया मामला है।
- अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति को संसदीय अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जबकि एक अध्यादेश एक अधिनियम के समान बल रखता है, यह अल्पकालिक होता है; यह संसद के पुनः संयोजन के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है जब तक कि आधिकारिक तौर पर एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है या एक वैधानिक प्रस्ताव द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है।

परिचित जोखिम: कॉलेजियम का रणनीतिक गणित

- सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 37 सक्रिय न्यायाधीश बैठते हैं। कानूनी विशेषज्ञों से पता चलता है कि कॉलेजियम ने जानबूझकर 38 वीं सीट को खाली छोड़ दिया और अस्थायी न्यायाधीशों को स्थायी सीटों में बदलने के लिए न्यायिक सेवानिवृत्ति कैलेंडर के आधार पर नियुक्तियों को सावधानीपूर्वक मैप किया।
- पहले दो अध्यादेश न्यायाधीशों को अवशोषित करना: न्यायमूर्ति पंकज मित्तल 16 जून, 2026 को सेवानिवृत्त होंगे और न्यायमूर्ति जेके माहेस्वरी 28 जून, 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके प्रस्थान से दो स्थायी संरचनात्मक सीटों को फिर से खोलना संभव हो गया है, जिससे तीन नवनिर्वाचित अध्यादेश न्यायाधीशों में से दो को स्वचालित रूप से स्थायी पदों पर जाने की अनुमति मिलती है।
- सबसे जूनियर जज की कमजोर स्थिति: बार से सीधे नियुक्त जस्टिस वी. मोहना अनिश्चित स्थिति में अकेले बैठते हैं। वह 22 अगस्त, 2026 को न्यायमूर्ति संजय करोल के सेवानिवृत्त होने तक स्थायी, वैध सीट पर नहीं जा सकती।
- रणनीतिक दांव: न्यायमूर्ति करोल की सेवानिवृत्ति लगभग ठीक उसी समय के साथ मेल खाती है जब संसदीय मानसून सत्र के दौरान अध्यादेश के समाप्त होने की उम्मीद है। कॉलेजियम शर्त लगा रहा है कि 22 अगस्त से पहले एक प्रतिस्थापन अधिनियम पारित किया जाएगा, या यह कि अध्यादेश समाप्त होने पर न्यायमूर्ति करोल की रिक्ति उन्हें अवशोषित करने के लिए समय पर खुल जाएगी।

प्रमुख वैचारिक और संस्थागत चुनौतियाँ:

- कार्यकारी कानून बनाने के खिलाफ बसे हुए न्यायशास्त्र को कमजोर करना: अदालत का विस्तार करने के लिए एक अध्यादेश को स्वीकार करना विधायिका को दरकिनार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अपनी ऐतिहासिक चेतावनियों के सामने उड़ता है।
- उदाहरण: डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) में, अदालत ने फैसला सुनाया कि पुनः प्रस्थापित अध्यादेशों के माध्यम से शासन करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है, जो समानांतर कार्यकारी कानून के खिलाफ 2017 के कृष्ण कुमार सिंह के फैसले द्वारा समर्थित एक सिद्धांत है।
- शक्तियों के पृथक्करण के महत्वपूर्ण बाहरी स्वरूप से समझौता: एक अस्थायी डिफ्री द्वारा बनाई गई सीटों को धारण करने वाले न्यायाधीशों को सरकार से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करते समय हितों के अंतर्निहित टकराव का सामना करना पड़ता है।



- उदाहरण: क्योंकि सत्तारूढ़ राजनीतिक बहुमत को अपनी नौकरियों को नियमित करने के लिए विधेयक पारित करना चाहिए, अदालत की आवश्यक टुकड़ी से समझौता किया जाता है जब वही केंद्र सरकार प्राथमिक वादी के रूप में उनके सामने आती है।
- यदि अध्यादेश विफल हो जाता है तो अभूतपूर्व परिचालन विसंगतियां: यदि संसद विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो समाप्त हो चुके पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय न्यायाधीश की कानूनी स्थिति भारतीय इतिहास में पूरी तरह से अपरीक्षित रहती है।
- उदाहरण: जबकि गोकाराजू रंगराजू (1981) जैसे पिछले फैसले वास्तविक सिद्धांत के तहत अपने फैसलों की रक्षा करते हैं, एक चूक एक न्यायाधीश को एक ऐसे पद पर छोड़ देगी जिसे कानून अब मान्यता नहीं देता है।
- दूसरे न्यायाधीशों के मामले में कड़ी मेहनत से जीती गई प्रधानता का क्षय: कार्यपालिका को अस्थायी सनक पर अदालत के आकार को निर्धारित करने की अनुमति देकर, न्यायपालिका उस स्वतंत्रता को खोने का जोखिम उठाती है जिसकी रक्षा के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी।
- उदाहरण: 2015 के एनजेएसी मामले में, अदालत ने नियुक्तियों में अपनी प्राथमिक भूमिका को बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को खारिज कर दिया, फिर भी अब इसने अपनी बेंच की ताकत को कार्यकारी सद्भावना पर निर्भर छोड़ दिया है।

आगे की राह:

- तत्काल संसदीय नियमितीकरण को प्राथमिकता देना: संसद को संवैधानिक विसंगति को समाप्त करने के लिए मानसून सत्र की शुरुआत में प्रतिस्थापन विधेयक को पेश करने और पारित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- बेंच विस्तार अध्यादेशों पर वैधानिक सीमा स्थापित करना: एक स्पष्ट कानूनी नियम पेश करें जिसमें कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट के आकार में भविष्य में कोई भी बदलाव केवल नियमित संसदीय संशोधनों के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है, अस्थायी अध्यादेशों के माध्यम से नहीं।
- भविष्य के शपथ ग्रहण प्रोटोकॉल को स्थायी रिक्रियों तक सीमित करना: कॉलेजियम को एक आंतरिक दिशानिर्देश स्थापित करना चाहिए जो न्यायाधीशों को अस्थायी, अध्यादेश-निर्मित सीटों पर नियुक्त करने या शपथ लेने से इनकार करता है, जब तक कि वे कानून द्वारा स्थायी रूप से औपचारिक नहीं हो जाते।
- अध्यादेश-निर्भर न्यायाधीशों को उत्त्व-दांव नीति समीक्षा से अलग करना: संस्थागत अखंडता की रक्षा के लिए, अस्थायी सीटों पर कब्जा करने वाले न्यायाधीशों को संघ कार्यपालिका से जुड़े हार्ड-प्रोफाइल संवैधानिक मामलों से खुद को अलग करना चाहिए जब तक कि उनके पद पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाएं।

निष्कर्ष:

अपनी न्यायिक नियुक्तियों को संसदीय सत्रों और आगामी सेवानिवृत्ति की टिक-टिक घड़ी से मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्त्व गणना संस्थागत जोखिम लिया है। जबकि राजनीतिक आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार सीटों को नियमित करेगी, गहरा मुद्दा यह है कि न्यायपालिका ने राजनीतिक शाखा की सद्भावना पर अपने कार्यकाल की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। सच्ची न्यायिक स्वतंत्रता के लिए कार्यकारी शक्ति की जांच करने के अधिकार से अधिक की आवश्यकता होती है - यह इससे अपने स्वयं के अलगाव की रक्षा के लिए एक अडिग संस्थागत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।

राज्यसभा चुनाव

संदर्भ:

भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने की तिथि की बंद कर दी है, जिससे 27 सीटों पर लड़े गए राज्यसभा चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है।

राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा चुनाव के बारे में:

यह क्या है?

- राज्यसभा (भारत की संसद का ऊपरी सदन) एक स्थायी विधायी निकाय है जिसके सदस्य छह साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के विपरीत, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है।
- प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए, एक रोलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है जहां कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष स्वचालित रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनकी रिक्तियों को द्विवार्षिक चुनावों के माध्यम से भरा जाता है।
- नियमित द्विवार्षिक चक्रों के माध्यम से चुने गए सदस्य पूरे छह साल के कार्यकाल की सेवा करते हैं, जबकि उप-चुनावों के माध्यम से नियुक्त सदस्य केवल उस व्यक्ति के शेष, असमाप्त कार्यकाल की सेवा करते हैं जिसकी सीट खाली हो गई थी।

चुनाव की प्रक्रिया:

- अप्रत्यक्ष निर्वाचित: राज्यसभा के सांसदों को प्रत्यक्ष सार्वजनिक मतदान के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वे संबंधित राज्यों की विधान सभाओं (विधायकों) के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, प्रतिनिधियों को एक नामित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है (वर्तमान में, केवल दिल्ली और पुडुचेरी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं)।



- मतदान प्रणाली: चुनाव एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक ही नाम चुनने के बजाय, विधायक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में रैंकिंग करके अपना वोट डालते हैं।
- विजेता कोटा फॉर्मूला: एक सीट सुरक्षित करने के लिए, एक उम्मीदवार को वैध प्रथम-वरीयता वोटों की गणितीय रूप से गणना की गई न्यूनतम सीमा को पार करना होगा। इस कोटा को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\text{Required votes} = \left[\frac{\text{Total valid votes}}{\text{Number of Rajya Sabha seats} + 1} \right] + 1$$

जीतने का कोटा फॉर्मूला

- ओपन बैलेट सिस्टम: मतदान एक खुले मतपत्र के माध्यम से आयोजित किया जाता है। क्रॉस-वोटिंग, हॉर्स-ट्रेडिंग या अमान्यता को रोकने के लिए, एक विधायक को चुनाव नियमों के अनुसार अपने चिह्नित मतपत्र को मतपेटी में डालने से पहले अपनी संबंधित पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना आवश्यक है। एजेंट को मतपत्र प्रदर्शित करने में विफल रहने से वोट अमान्य हो जाता है।
- निर्विरोध चुनाव: वास्तविक मतदान तभी होता है जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या राज्यसभा की रिक्त सीटों की कुल संख्या से अधिक हो। यदि नामांकित उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों की सटीक संख्या से मेल खाती है, तो उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है।

राज्य सभा के कार्य और महत्व:

- गैर-धन विधेयकों को पारित करना: राज्यसभा गैर-धन विधेयकों की समीक्षा और पारित करके भारतीय विधायी पाइपलाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानून बनने के लिए एक विधेयक को उच्च सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- विधायी जांच और बहस: जब सत्तारूढ़ गठबंधन राज्यसभा में एक प्रमुख उपस्थिति रखता है, तो गैर-धन विधेयकों का पारित होना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, यदि विपक्ष एक मजबूत स्थिति रखता है, तो इससे गहन बहस, संशोधन निर्माण या गहन जांच के लिए प्रस्तावित कानून को संसदीय समितियों को भेजने की संभावना बढ़ जाती है।
- गठबंधन प्रबंधन और विधानसभा अंकगणित: राज्यसभा चुनाव राजनीतिक गठबंधनों के लिए विधानसभा अंकगणित और गठबंधन प्रबंधन की परीक्षा के रूप में काम करते हैं।
- क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी की शक्ति: क्योंकि राज्यसभा की सीटें संकीर्ण अंतर से जीती जा सकती हैं और क्रॉस-वोटिंग द्वारा परिणामों को बदला जा सकता है, क्षेत्रीय ब्लॉक कड़े विधायी वोटों के दौरान महत्वपूर्ण सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे संसदीय ताकत का समग्र संतुलन बदल जाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने:

यह क्या है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली थी और उनके कार्यकाल के लगातार 4,399 दिन पूरे हो गए हैं।
- इस संख्या को हिट करके, उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारतीय इतिहास में एक निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक निर्बाध कार्यकाल के लिए लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

अन्य भारतीय प्रधान मंत्री और शर्तें:

प्रधानमंत्री	समग्र नियम और युग	ऐतिहासिक मील का पत्थर संदर्भ	कार्यालय में लगातार दिन
नरेंद्र मोदी	3 लगातार शर्तें (मई 26, 2014 - वर्तमान)	2026 में केंद्रीय शासन के 12 साल पूरे हुए। वह आजादी के बाद इस पद को संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं।	4,399 दिन (10 जून 2026 तक)



जवाहरलाल नेहरू	3 चुनाव के बाद की शर्तें (13 मई, 1952 - 27 मई, 1964)	भारत के पहले आम चुनावों के बाद पिछला निर्बाध रिकॉर्ड बनाया। नोट: उनका संवयी कार्यकाल 6,131 दिन था, लेकिन इसमें उनका 1952 से पहले का अंतरिम, गैर-निर्वाचित प्रशासन शामिल है।	4,398 दिन
इंदिरा गांधी	अखंड प्रारंभिक युग (24 जनवरी, 1966 - 24 मार्च, 1977)	1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के दौरान लगातार सेवा की, इससे पहले कि उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। बाद में वह 1980 से 1984 तक एक अलग कार्यकाल के लिए लौट आई।	4,077 दिन

महत्व:

- लगातार तीन चुनावी जनादेश और 4,300 से अधिक दिनों के कार्यकाल ने नीतिगत स्थिरता, शासन निरंतरता और निर्णय लेने में अधिक पूर्वानुमान प्रदान किया है।
- जेएएम ढांचे के माध्यम से संचालित कल्याणकारी पहलों ने वित्तीय समावेशन और लक्षित लाभ वितरण का विस्तार किया, जिससे गरीबी में उल्लेखनीय कमी और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान हुआ।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968**संदर्भ:**

व्यंग्यात्मक युवा दबाव समूह, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना पहला शारीरिक विरोध प्रदर्शन किया।

चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश**चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के बारे में:****यह क्या है?**

- चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रतीकों को निर्दिष्ट करने, आरक्षित करने, पसंद आवंटित करने और विनियमित करने का अधिकार देता है। यह सभी विधानसभाओं और संसदीय चुनावों में राजनीतिक प्रतियोगियों की दृश्य पहचान के प्रबंधन के लिए शासी नियम पुस्तिका के रूप में कार्य करता है।
- इस आदेश को आधिकारिक तौर पर 31 अगस्त, 1968 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के माध्यम से निहित शक्तियों के तहत प्रख्यापित किया गया था, जिसे चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10 के साथ पढ़ा जाता है।

आदेश की मुख्य विशेषताएं:

- राजनीतिक दलों का वर्गीकरण: यह आदेश राजनीतिक समूहों को उनके पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर दो स्पष्ट प्रशासनिक स्तरों में विभाजित करता है: मान्यता प्राप्त दल और गैर-मान्यता प्राप्त दल।
- आरक्षित चुनाव चिह्न पूल: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों को स्वचालित रूप से उनकी पार्टी का अनन्य, स्थायी रूप से आरक्षित चुनाव चिह्न आवंटित किया जाता है। इन प्रतीकों का उपयोग देश या राज्य में किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- फ्रीसिंबल रोस्टर: गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए, ईसीआई मुफ्त प्रतीकों की एक गतिशील सूची बनाए रखता है और समय-समय पर अपडेट करता है। इनमें फल, सब्जियां और रोजमर्रा के घरेलू सामान जैसे एयर कंडीशनर, गुब्बारा, कटहल या टीवी रिमोट शामिल हैं।
- इन प्रतीकों को गारंटी देने के बजाय एक तरल, पहले आओ-पहले पाओ आवेदन के आधार पर वितरित किया जाता है।
- पूर्ण पशु निषेध: 1989 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के दौरान जीवित मुर्गों पर की गई अत्यधिक क्रूरता के बारे में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं के भारी प्रतिनिधित्व के बाद, चुनाव आयोग ने 1990 के दशक में प्रतीकों के रूप में जीवित प्राणियों के आवंटन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया।
- विरासत अपवाद: जिन पार्टियों को 1990 के दशक के निर्देश से पहले औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी और पशु प्रतीक प्रदान किया गया था - विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपने हाथी प्रतीक के साथ - को कानूनी रूप से नियम के दुर्लभ अपवाद के रूप में अपने विरासत प्रतीकों को बनाए रखने की अनुमति है।



सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को पूरी तरह से वापस लेना है, क्योंकि 80 प्रतिशत क्षेत्र पहले से ही अधिनियम से मुक्त है।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA)

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के बारे में:

यह क्या है?

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) भारतीय संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है जो केंद्रीय सशस्त्र बलों के सदस्यों को असाधारण विशेष परिचालन शक्तियां प्रदान करता है।
- यह विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर तैनात किया जाता है जहां स्थानीय राज्य प्रशासन को विद्रोह या नागरिक अशांति के खिलाफ आंतरिक सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ माना जाता है।

उत्पत्ति और इतिहास:

- राष्ट्रपति अध्यादेश (1958): बढ़ते विद्रोह और आंतरिक अशांति का सामना करते हुए, राष्ट्रपति ने 22 मई 1958 को सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश जारी किए। इसने प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को आपातकालीन शक्तियां प्रदान कीं।
- वैधानिक अधिनियमन: संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन के बाद, विधेयक को 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। यह सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 28) बन गया।
- AFSPA का उद्देश्य: AFSPA सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में नागरिक अधिकारियों का समर्थन करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य उग्रवाद पर अंकुश लगाना, आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना और सामान्य शासन को बहाल करना है।

AFSPA की मुख्य विशेषताएं:

- आग खोलने की शक्ति [धारा 4 (ए)]: सुरक्षा कर्मी उचित चेतावनी देने के बाद घातक बल सहित बल का उपयोग कर सकते हैं। यह नैरकानूनी सभाओं या निषिद्ध हथियार रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लागू होता है।
- गढ़वाले शिविरों का विनाश [धारा 4 (बी)]: सशस्त्र बल आतंकवादी शिविरों, ठिकानों, हथियारों के ढेर और प्रशिक्षण सुविधाओं को नष्ट कर सकते हैं। यह प्रावधान विद्रोही परिचालन क्षमताओं को कमजोर करने का प्रयास करता है।
- वारंट रहित गिरफ्तारी [धारा 4 (सी)]: कार्मिक व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं यदि उन्हें संज्ञेय अपराध करने का संदेह है। हिरासत को सुरक्षित करने के लिए उचित बल का उपयोग किया जा सकता है।
- वारंट रहित खोजें [धारा 4 (डी)]: बल पूर्व न्यायिक अनुमोदन के बिना परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। इससे हथियार, विस्फोटक, चोरी की संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने या संदिग्धों को पकड़ने में मदद मिलती है।
- हिरासत सुरक्षित-प्रबंधन प्रोटोकॉल [धारा 5]: गिरफ्तार व्यक्तियों को कम से कम संभव देरी के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की परिस्थितियों की व्याख्या करने वाली एक रिपोर्ट उनके साथ होनी चाहिए।
- पूर्ण न्यायिक प्रतिरक्षा [धारा 6]: केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कोई अभियोजन या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। इस सुरक्षा का उद्देश्य परिचालन प्रभावशीलता का समर्थन करना है।
- एक अशांत क्षेत्र की घोषणा [धारा 3]
- घोषणा करने का अधिकार: यदि सुरक्षा स्थितियों को खतरनाक माना जाता है तो किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है।

वर्तमान स्थिति (2026):

- पूर्वोत्तर का लगभग 80% हिस्सा अब AFSPA से मुक्त है। सुरक्षा आकलन के आधार पर यह अधिनियम केवल असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में ही लागू रहता है।



रास लाफान गैस सुविधा

संदर्भ:

कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बरज़ान गैस आपूर्ति सुविधा में एक विस्फोट और बड़ी आग लग गई, जिसमें कम से कम 54 लोग घायल हो गए और 18 कर्मचारी लापता हो गए।

रास लाफान गैस सुविधा

रास लाफान गैस सुविधा के बारे में:

यह क्या है?

- रास लाफान गैस सुविधा - मुख्य रूप से बरज़ान गैस परियोजना और कतर एनर्जी एलएनजी जैसे संचालन के आसपास केंद्रित है - दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) निर्यात केंद्र है और दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम बंदरगाह का घर है। यह एक उत्त्-सुरक्षा, अल्ट्रा-स्केल औद्योगिक बुनियादी ढांचा नोड के रूप में कार्य करता है जिसे प्राकृतिक गैस को संसाधित करने, परिष्कृत करने और निर्यात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्थान:

- भौगोलिक अक्ष: कतर की अल खोर नगर पालिका में स्थित है, जो राजधानी शहर दोहा से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) उत्तर में है।

इतिहास और संदर्भ:

- संस्थापक जनादेश: कतर एनर्जी के प्रशासन के तहत 1996 में कमीशन किया गया, औद्योगिक शहर विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र से टैप की गई प्राकृतिक गैस के लिए पेट्रोकेमिकल और रिफाइनिंग सुविधाओं की मेजबानी के लिए बनाया गया था।
- नॉर्थ फ़िल्ड कोर: यह सुविधा दुनिया के सबसे बड़े गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस क्षेत्र से गैस को संसाधित करती है, जिसमें 900 ट्रिलियन से अधिक मानक क्यूबिक फीट पुनर्प्राप्त करने योग्य गैस है।
- भू-राजनीतिक कमजोरियाँ (2026 संघर्ष): मार्च 2026 में, क्षेत्रीय शत्रुता के दौरान यह सुविधा एक लक्ष्य बन गई। 18 मार्च, 2026 को मिसाइल हमलों ने संपत्ति पर हमला करने के लिए रक्षा नेटवर्क को दरकिनार कर दिया, जिससे इसकी चौदह उत्पादन इकाइयों में से दो को व्यापक नुकसान हुआ, अस्थायी रूप से इसकी एलएनजी क्षमता का 17% खत्म हो गया, और \$ 20 बिलियन का वार्षिक राजस्व जोखिम शुरू हो गया।

इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स की मुख्य विशेषताएं:

- बरज़ान गैस प्लांट: एवसॉनमोबिल के साथ \$ 10.4 बिलियन के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित एक मुख्य घटक है, जो प्रति दिन 4 बिलियन मानक क्यूबिक फीट बिक्री गैस का उत्पादन करने में सक्षम है।
- विविध रिफाइनिंग प्लान्ट्स: पर्ल जीटीएल और ओआरवाईएक्स जीटीएल (गैस-टू-लिक्विड) प्रसंस्करण संयंत्रों, डॉल्फिन गैस प्रसंस्करण केंद्र और लाफान रिफाइनरी सहित प्रमुख डाउनस्ट्रीम संचालन की मेजबानी करता है।
- एकीकृत जल और विद्युत अवसंरचना: बिजली और ताजा पानी प्रदान करने के लिए तीन बड़े पैमाने पर एकीकृत बिजली उत्पादन और अलवणीकरण सुविधाओं (रास लाफान ए, बी, और सी/रास गिरतस) को समायोजित करता है।
- विश्व स्तरीय निर्यात बंदरगाह: प्रति वर्ष 15 मिलियन टन तरल उत्पादों के निर्यात की क्षमता के साथ सालाना 10,000 से अधिक जहाज लोडिंग को संभालने में सक्षम एक समर्पित 56 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल बंदरगाह संचालित करता है।
- समर्पित संकट सहायता: सहायता सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हार्डवेयर मरम्मत क्षेत्र के साथ-साथ रास लाफान आपातकालीन और सुरक्षा कॉलेज के माध्यम से अपनी विशेष आपातकालीन पाइपलाइन की सुविधा है।

भारत का खराब मानसून और तैयारी

संदर्भ:

जून 2026 के अंत में वर्षा गतिविधि में हल्के सुधार के बावजूद, मानसून के शुरुआती मौसम के कवरेज में गंभीर संरचनात्मक कमी ने लंबे समय तक शुष्क मौसम पर व्यापक चिंताएं पैदा कर दी हैं।

- आईएमडी की रिपोर्ट है कि भारत के लगभग 75% भूभाग में वर्तमान में 20% से अधिक वर्षा की कमी है।



भारत का खराब मानसून और तैयारी

भारत के खराब मानसून और तैयारियों के बारे में:

यह क्या है?

- पिछले एक दशक में, जलवायु परिवर्तन ने इस मौसम पैटर्न को अत्यधिक अनिश्चित बना दिया है, जो गंभीर क्षेत्रीय और स्थानीय वितरण विविधताओं को प्रस्तुत करता है। इस भेद्यता का मुकाबला करने के लिए, भारत ने बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन बुनियादी ढांचे, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के तहत बेहतर भूजल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा ब्रिड में तेजी से परिवर्तन के माध्यम से अपने आर्थिक लचीलेपन को संरचनात्मक रूप से बदल दिया है।

वर्तमान खराब मानसून पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- जून में भारी घासा: जून 2026 के लिए पूरे भारत में कुल वर्षा की कमी 40% की सीमा को पार कर गई है, एक ऐसा अंतर जिसे मौसम विज्ञानी जुलाई से पहले पाटने की संभावना नहीं मानते हैं।
- क्षेत्रीय कवरेज में पिछड़ना: मानसून की धाराओं ने देश के लगभग आधे भूभाग को ही कवर किया है, जबकि सामान्य ऐतिहासिक समयसीमा यह तय करती है कि वर्षा ब्रिड को जून के अंत तक लगभग पूरे देश को कवर करना चाहिए।
- व्यापक क्षेत्रीय कमियाँ: भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 75% वर्तमान में 20% या उससे अधिक की भारी वर्षा की कमी से पीड़ित है।

भारत में खराब मानसून के कारण:

- अल नीनो घटना का उद्भव: अल नीनो चरण - दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के असामान्य वार्मिंग की विशेषता - आधिकारिक तौर पर उभरा है, जिससे बहु-महीने की वर्षा गतिविधि दब गई है।
- वितंबित प्रभाव कारक (अंतराल प्रभाव): जबकि अल नीनो जून 2026 के पहले सप्ताह में उभरा, इससे पूर्ण, विघटनकारी वायुमंडलीय ब्लॉक को उपमहाद्वीप में फ़िल्टर करने में एक महीने से अधिक का समय लगता है, जिससे जुलाई और अगस्त के लिए चक्रवृद्धि दबाव पैदा होता है।
- एक प्रतिकूलमैडेन जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) चरण: जून के अधिकांश समय में, एमजेओ पवन-और-बादल प्रणाली की वर्षा-दबाने वाली वलय सीधे भारतीय क्षेत्र पर स्थित थी, जिससे बारिश वाले बादलों को बहुत दूर धकेल दिया गया था।
- कम दबाव प्रणालियों की अपर्याप्त संरचनात्मक ताकत: समुद्र के ऊपर बनने वाले क्षेत्रीय कम दबाव वाले वायुमंडलीय विन्यास में भूमि पर लगातार बारिश करने के लिए आवश्यक तापीय और संरचनात्मक शक्ति का अभाव था।
- कमजोर परिचालनमानसून धाराएं: प्रारंभिक मौसम की समुद्री हवा की धाराओं में मानसून ब्रिड को देश की केंद्रीय सीमाओं से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गति का अभाव था, जिससे आधा भूभाग सूख गया।

भारत पर खराब मानसून के प्रभाव:

- कृषि उत्पादकता के लिए खतरा: निरंतर शुष्क अवधि महत्वपूर्ण ग्रीष्मकालीन (खरीफ) फसलों की बुवाई को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिससे समग्र कृषि उत्पादन कम हो जाता है।
- ग्रामीण मांग और आय में कमी: क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है, कम फसल की पैदावार सीधे कृषि आय को कम करती है, जिससे ग्रामीण खुदरा खपत धीमी हो जाती है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर दबाव: कम फसल की पैदावार संरचनात्मक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है, जिससे सरकार को बफर स्टॉक पर भारी दबाव डालना पड़ता है या निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है।
- घटती भूजल और जल-जलाशय आधारित: एक कमजोर मानसून भूमिगत जलभृतों के प्राकृतिक पुनर्भरण में बाधा डालता है, स्थानीय कुओं को सुखाता है और पीने के पानी की उपलब्धता को कम करता है।

- जलविद्युत विद्युत उत्पादन में व्यवधान: प्रमुख नदी प्रणालियों में कम जल स्तर पनबिजली संयंत्रों की परिचालन क्षमता को कम करता है, जिससे राष्ट्रीय पावर ग्रिड पर दबाव बढ़ जाता है।

खराब मानसून से निपटने के लिए भारत की तैयारी:

- प्रचुर मात्रा में विरासत जलाशय भंडारण: पिछले लगातार दो वर्षों में असाधारण रूप से उच्च, बहु-वर्षीय वर्षा के लिए धन्यवाद, भारत के प्रमुख औद्योगिक और कृषि जलाशय स्वस्थ बफर भंडारण स्तरों पर काम कर रहे हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पनबिजली से पावर ग्रिड को अलग करना: पिछले दस वर्षों में सौर और पवन बिजली प्र
- तिष्ठानों के तेजी से विस्तार ने हाइड्रो-टर्बाइनों पर पावर ग्रिड की निर्भरता को कम कर दिया है, पीने और सिंचाई के लिए कीमती जलाशय जल को संरक्षित किया है।
- ग्रामीण योजनाओं के तहत लक्षित बुनियादी ढांचा: ग्रामीण परिसंपत्ति-निर्माण योजनाओं के तहत निष्पादित सार्वजनिक कार्यों का एक बड़ा हिस्सा चेक-डैम के निर्माण, वर्षा जल संचयन को लागू करने और जल संरक्षण को अनुकूलित करने पर केंद्रित है।
- भूजल की कमी में मापने योग्य उलटफेर: आधिकारिक वैज्ञानिक डेटा व्यवस्थित वाटरशेड प्रबंधन के कारण भारत के क्षेत्रीय भूजल स्तर में स्पष्ट बदलाव और सुधार को दर्शाता है।
- किसानों द्वारा सक्रिय बुवाई अनुकूलन: आईएमडी द्वारा जारी समय पर, डिजिटल मौसम पूर्वानुमानों ने किसानों को मानसून से पहले की शुरुआती बारिश का कुशलतापूर्वक लाभ उठाते हुए अपनी खरीफ फसल की समयसीमा को अनुकूलित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रेरित किया।

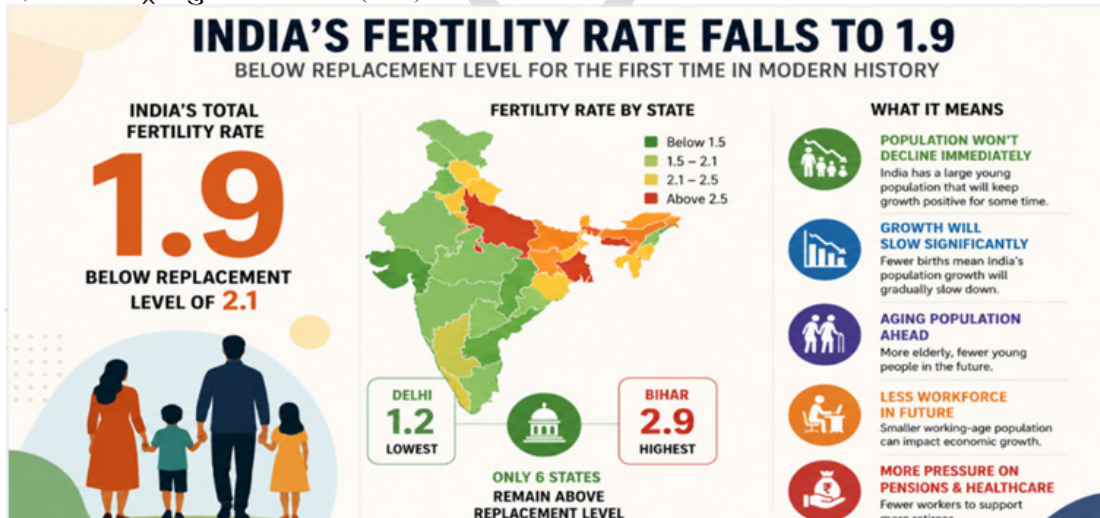
निष्कर्ष:

प्रमुख जलाशयों में बफर स्टॉक, एक तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड और व्यापक जल-संचयन नेटवर्क के साथ मिलकर, एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कुशन प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हुए, जलवायु परिवर्तन को अपनाने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था को अनियमित मौसम बदलाव से बचाने के लिए क्षेत्रीय जलवायु लचीलापन और स्मार्ट कृषि पूर्वानुमान में निरंतर निवेश की आवश्यकता होगी।

भारत की कम प्रजनन क्षमता वाली संरचना विकसित हो रही है

संदर्भ:

राष्ट्रीय नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने एक संरचनात्मक जनसांख्यिकीय संक्रमण में प्रवेश किया है, इसकी राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर (TFR) प्रति महिला 1.9 बच्चों तक गिर गई है।



भारत की कम प्रजनन क्षमता वाली संरचना विकसित हो रही है

भारत की विकसित कम प्रजनन क्षमता वाली वास्तुकला के बारे में:

यह क्या है?

- भारत की प्रजनन दर में गिरावट एक ऐसे देश के लिए एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है जिसने लंबे समय से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, यह जनसांख्यिकीय संक्रमण एक समान नहीं है, जिससे एक विभाजित अर्थव्यवस्था बन रही है जहां विभिन्न राज्य पूरी तरह से अलग-अलग गति से आगे बढ़ रहे हैं।
- जबकि कई दक्षिणी और पूर्वी राज्य तेजी से उम्र बढ़ने वाले समाजों में संक्रमण कर रहे हैं, गरीब उत्तरी क्षेत्र बड़े युवा समूहों का उत्पादन करना जारी रखते हैं जो अगले दो दशकों में कार्यबल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।
- भारत की प्रजनन क्षमता और उम्र बढ़ने के रुझान पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

डीप जियोग्राफिक TFR डिवाइड:

- शहरी-ग्रामीण भिन्नता: जबकि ग्रामीण प्रजनन क्षमता प्रतिस्थापन चिह्न के करीब बनी हुई है, शहरी प्रजनन क्षमता तेजी से गिरकर प्रति महिला 1.5 बच्चे हो गई है।

- अल्ट्रा-लो कोहोर्ट्स: दिल्ली 1.2 के अल्ट्रा-लो TFR तक पहुंच गया है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल 1.3 पर बैठे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (1.6) और जापान (1.3) जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है।
- उत्त्व प्रजनन पॉकेट: इसके विपरीत, उत्तरी राज्यों में उत्त्व प्रजनन दर बनी हुई है, जिसके बाद बिहार 2.9 है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.6), मध्य प्रदेश (2.4) और राजस्थान (2.3) हैं।

उभरते वरिष्ठ जनसांख्यिकीय अनुमान:

- वृद्ध आबादी की भीड़: भारत वर्तमान में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 150 मिलियन लोगों का घर है।
- 2050 की वृद्धि: वर्ष 2050 तक, इस बुजुर्ग समूह के दोगुने से अधिक होने का अनुमान है, जो 347 मिलियन व्यक्तियों या देश की कुल आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा होगा।
- गंभीर आर्थिक भेद्यता: नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि 70% बुजुर्ग पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं, जबकि 78% के पास कोई औपचारिक पेंशन कवरेज नहीं है।

प्रमुख संस्थागत और राजकोषीय चुनौतियाँ:

- बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण से पहले बड़े पैमाने पर बुढ़ापा: पश्चिमी यूरोप और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से औद्योगीकरण के बाद ही वृद्ध हुई, अपने कार्यबल को औपचारिक रूप दिया, अपने कर जाल का विस्तार किया, और मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल का निर्माण किया।
- इसके विपरीत, भारत लगभग 2,800 डॉलर की कम प्रति व्यक्ति आय के साथ एक नाजुक संस्थागत आधार पर बड़े पैमाने पर बुढ़ापा में प्रवेश कर रहा है।
- एक असाधारण रूप से संकीर्ण प्रत्यक्ष कर आधार: वरिष्ठ कल्याण कार्यक्रमों को निधि देने की राज्य की क्षमता भारी रूप से सीमित है क्योंकि शुद्ध प्रत्यक्ष करदाता कुल आबादी का 6% हिस्सा हैं।
- एक अत्यधिक नाजुक, अनौपचारिक श्रम बाजार: क्योंकि अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक या अर्ध-औपचारिक भूमिकाओं में अपना जीवन बिताते हैं, वृद्धावस्था आय सुरक्षा पूरी तरह से औपचारिक रोजगार अनुबंधों से बाहर रहती है। योगदान-आधारित कार्यक्रम अनौपचारिक श्रमिकों को उनकी अत्यधिक अस्थिर, अप्रत्याशित आय के कारण विफल करते हैं।
- कमजोर और पुराना सार्वजनिक नकद हस्तांतरण सुरक्षा जाल: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत वृद्धावस्था पेंशन 60 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए प्रति माह 200 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपये प्रदान करती है, जो वरिष्ठ नागरिकों को गरीबी से बचाने में विफल रहती है।
- घरेलू सुरक्षा जाल का संरचनात्मक कमजोरता: ऐतिहासिक रूप से, भारत का कल्याणकारी राज्य घर के अंदर छिपा हुआ है, जहाँ संयुक्त परिवार और अवैतनिक महिला श्रम बुजुर्गों की देखभाल की लागत को अवशोषित करते हैं। यह व्यवस्था शहरीकरण, प्रवासन और एकल परिवारों के दबाव में टूट रही है, जिससे पीछे छूट गए माता-पिता गंभीर अकेलेपन और स्वास्थ्य संकटों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल की मांग में एक बड़ा बदलाव: उम्र बढ़ने वाली आबादी उत्त्व रक्तचाप, मधुमेह, मनोभ्रंश, शारीरिक विकलांगता और उपशामक निर्भरता जैसी पुरानी बीमारियों के जटिल, दीर्घकालिक प्रबंधन की ओर अल्पकालिक उपचार से दूर चिकित्सा की मांग को काफी हद तक स्थानांतरित कर देगी।

आगे की राह:

- मुद्रास्फीति-अनुक्रमित न्यूनतम पेंशन फ्लोर को लागू करना: अनौपचारिक कार्यबल के लिए जोखिम-पूर्तिंग की आधारभूत परत के रूप में काम करने के लिए एक बुनियादी, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित, मुद्रास्फीति-अनुक्रमित पेंशन फ्लोर पेश करना।
- कल्याणकारी अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को अनिवार्य करना: एक राष्ट्रीय श्रम बाजार का निर्माण करें जहां सामाजिक सुरक्षा को स्थानीय अधिवास नियमों से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, जिससे अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को राज्य की सीमाओं के पार अपने स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी लाभों को ले जाने की अनुमति मिल सके।
- वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल के लिए मिशन-मोड कार्यों को तैनात करना: विशेष वृद्धावस्था देखभाल को सीधे नर्सिंग प्रथाओं, जिला स्वास्थ्य योजना और प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क में एम्बेड करने के लिए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना।
- युवा राज्यों में मानव पूंजी निवेश को बढ़ाना: बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे युवा राज्यों को उत्त्व गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और तकनीकी कौशल में आक्रामक रूप से निवेश करने के लिए निर्देशित करें ताकि उनके प्रवासी युवा कम वेतन वाली अनौपचारिकता में न फंसें।
- घरेलू देखभाल को बदलने के लिए औपचारिक सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करना: जैसे-जैसे पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं कमजोर होती जा रही हैं, राज्य को उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए औपचारिक सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिए जो परिवारों ने एक बार चुपचाप ले ली थीं।

निष्कर्ष:

व्यापक आर्थिक औपचारिकता या व्यापक कर आधार प्राप्त करने से पहले बड़े पैमाने पर उम्र बढ़ने में प्रवेश करना देश के वरिष्ठ नागरिकों को विशिष्ट रूप से कमजोर छोड़ देता है। अंततः, इस संक्रमण को बनाए रखना मजबूत, पोर्टेबल सार्वजनिक सुरक्षा जाल, मुद्रास्फीति-अनुक्रमित पेंशन और उन्नत वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क के निर्माण की ओर परिवार के समर्थन प्रणालियों को सिकोड़ने पर निर्भरता से दूर जाने पर निर्भर करेगा।

लिपुलेख दर्रा

संदर्भ:

भारत ने 2020 COVID-19 महामारी के दौरान शुरू हुए छह साल के निलंबन के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के माध्यम से चीन के साथ अपने सीमा व्यापार को आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया है।

लिपुलेख दर्रा

लिपुलेख दर्रे के बारे में:

यह क्या है?

- लिपुलेख हिमालय में एक अत्यधिक रणनीतिक, उत्तुंवाई वाला पर्वत दर्रा है जो एक महत्वपूर्ण सीमा पार व्यापार गलियारे और पारगमन प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह भारत, नेपाल और चीन (तिब्बत) को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण भौगोलिक त्रिकोण पर स्थित है।



स्थान:

- भारतीय: भारत के उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में व्यास घाटी के भीतर स्थित है।
- चीनी: भारत को तिब्बत, चीन में पुरोंग क्षेत्र (जिसे तकलाकोट के नाम से भी जाना जाता है) से सीधे जोड़ता है।
- ऊंचाई: समुद्र तल से 5,200 मीटर (लगभग 17,060 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है।

इतिहास और भू-राजनीतिक संघर्ष:

- 1816 सुगौली संधि: एंग्लो-नेपाल युद्ध के बाद, ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने काली नदी को नेपाल की निश्चित पश्चिमी सीमा के रूप में नामित किया।
- मूल असहमति: मुख्य विवाद इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि दोनों देश काली नदी के भौगोलिक स्रोत पर असहमत हैं। भारत का कहना है कि यह नदी कालापानी के झरनों से शुरू होती है, जिससे लिपुलेख सुरक्षित रूप से भारतीय सीमाओं के भीतर है। नेपाल का तर्क है कि नदी पश्चिम में लिपियाधुरा से निकलती है, जो पूरे भूखंड को नेपाली क्षेत्र के रूप में दावा करती है।
- 1991 की बहाली: 1962 के चीन-भारत युद्ध के बाद दशकों के बंद होने के बाद, दर्रे के माध्यम से द्विपक्षीय सीमा व्यापार मूल रूप से 1991 में एक औपचारिक द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के तहत फिर से शुरू हुआ।
- 2020 मानचित्र वृद्धि: 2020 में, भारत ने तीर्थयात्रियों के पारगमन को आसान बनाने के लिए धारचूला को लिपुलेख से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस बुनियादी ढांचा परियोजना का कड़ा विरोध किया और एक संशोधित संवैधानिक राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करके जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को एकतरफा रूप से अपने संप्रभु क्षेत्र में शामिल किया गया था - एक ऐसा कदम जिसे भारत ने खारिज कर दिया।

पास की मुख्य विशेषताएं:

- कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार: पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय, सबसे छोटे और ऐतिहासिक रूप से पसंदीदा ट्रेकिंग और ड्राइविंग मार्गों में से एक के रूप में कार्य करता है।
- सक्रियसीमा पार व्यापार केंद्र: भारतीय व्यापारियों और तिब्बती व्यापारिक डिपो के बीच एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष ओवरलैंड व्यापार लिंक के रूप में कार्य करता है। व्यापार में मुख्य रूप से उत्तुंवाई वाली वस्तुएं, ऊन और स्थानीय शिल्प शामिल हैं।
- लॉजिस्टिक असेंबली पॉइंट: इसमें नाभीढांग और गुंजी जैसे विशेष उत्तुंवाई वाले बेस कैम्प हैं, जो समर्पित सीमा शुल्क बुनियादी ढांचे, सीमा सुरक्षा चौकियों और गोदाम भंडारण सुविधाओं की मेजबानी करते हैं।
- खत्तर और पैक-पशु पारगमन: दर्रे के पास खड़ी इलाके के कारण, अंतिम 600 मीटर का दृष्टिकोण सीमा रेखा पर माल ले जाने के लिए घोड़ों और खत्तरों पर निर्भर करता है।

उत्तर पश्चिमी भारतीय धूल भरी आंधी

संदर्भ:

30 मई, 2026 को चूरू और राजस्थान के कई अन्य जिलों में भारी धूल भरी आंधी चली, जो अरावली पर्वतमाला के संरचनात्मक क्षरण को उजागर करती है।

उत्तर पश्चिमी भारतीय धूल भरी आंधी

उत्तर पश्चिम भारतीय धूल भरी आंधी के बारे में:

यह क्या है?



- धूल भरी आंधी (स्थानीय रूप से आंधी के रूप में जाना जाता है) एक मौसम संबंधी घटना है जो शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में आम है। यह तब होता है जब मजबूत, अशांत हवाएं सूखी मिट्टी से बड़ी मात्रा में ढीली रेत और धूल के कणों को वायुमंडल में उठाती हैं, जिससे धूल की एक व्यापक दीवार बनती है जो दृश्यता को काफी कम कर देती है और हवा की गुणवत्ता से समझौता करती है।

प्रभावित क्षेत्र:

- प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र उत्तर-पश्चिम भारत को कवर करता है, विशेष रूप से राजस्थान (वूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर), दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जैसे-जैसे सुरक्षात्मक अरावली अवरोध कम होता जा रहा है, धूल का प्रक्षेपवक्र घनी आबादी वाले भारत-गंगा के मैदानों में बहुत गहराई तक फैल रहा है।

यह कैसे बनता है?

- मानसून से पहले धूल भरी आंधी का गठन थर्मल और वायुमंडलीय स्थितियों के सटीक संयोजन से प्रेरित होता है:
- अत्यधिक तापीय ताप: मानसून से पहले के महीनों (अप्रैल से जून) के दौरान, तीव्र सौर विकिरण थार रेगिस्तान को पकाता है, जिससे अत्यधिक गर्मी और संवहनी अस्थिरता के स्थानीय क्षेत्र बनते हैं।
- कम दबाव उलटा: यह तीव्र ताप एक मजबूत सतह कम दबाव प्रणाली बनाता है। मध्य पूर्व और थार से धूल लेकर तेज दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं शून्य को भरने के लिए दौड़ती हैं।
- यांत्रिक भारोत्तोलन: जब हवा की गति सूखी, गैर-वनस्पति वाली मिट्टी पर 35-40 किमी प्रति घंटे की सीमा को पार करती है, तो कणों को यंत्रवत् उठा लिया जाता है। अरावली नदी के निरंतर वृक्ष आवरण और ऊंचाई के बिना, ये हवाएं तलछट को हजारों किलोमीटर पूर्व की ओर ले जाती हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- मौसमी: पूर्व-मानसून विंडो में सख्ती से केंद्रित होता है, मई और जून के दौरान तीव्रता में चरम पर होता है।
- बाधा के टीले: ऐतिहासिक रूप से, अरावली रेंज के पश्चिमी ढलानों ने भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य किया। ढलानों से टकराने वाली हवाएं अपना पेलोड गिरा देती हैं, जिससे रेगिस्तानी वनस्पतियों से बंधे अद्वितीय बाधा रेत के टीले बन जाते हैं।
- राजधानी क्षेत्रों में उच्च आवृत्ति: आईएमडी के दीर्घकालिक जलवायु संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले जून में दिल्ली में 2.5 धूल भरी आंधी के दिनों की औसत आवृत्ति होती है – जो भारत में सबसे अधिक है।
- मानवजनित अंतराल: आधुनिक तूफानों की एक प्रमुख विशेषता उनकी यात्रा में आसानी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के एक अध्ययन ने पुष्टि की है कि अवैध खनन के कारण 31 पूरी पहाड़ियों के गायब होने के कारण अरावली में 12 व्यापक परिचालन अंतराल हैं।

अल नीनो

संदर्भ:

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आधिकारिक तौर पर भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर अल नीनो की स्थिति की वापसी की पुष्टि की है।

अल नीनो

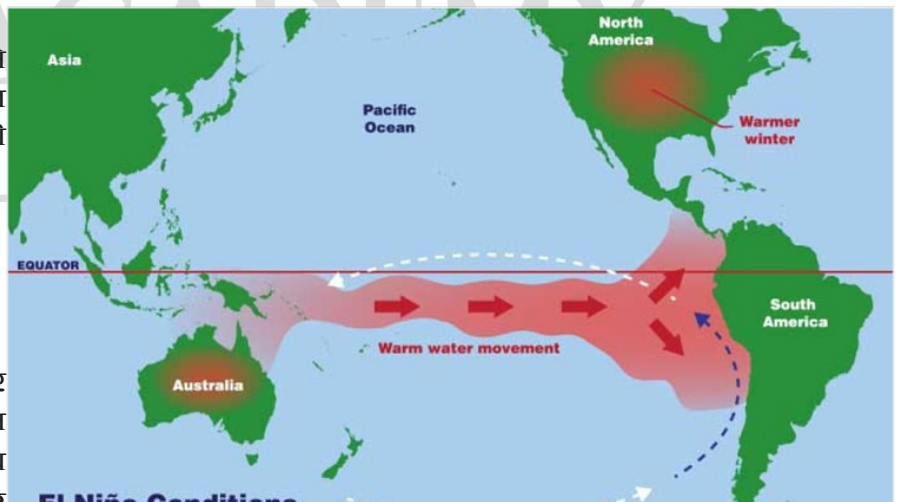
अल नीनो के बारे में:

यह क्या है?

- अल नीनो ("द बॉय चाइल्ड" के लिए स्पेनिश) अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) का गर्म चरण है, जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) में आवधिक परिवर्तनों से संचालित एक प्रमुख वैश्विक जलवायु घटना है, जो ऊपर के वातावरण में तीव्र उतार-चढ़ाव के साथ जोड़ा जाता है। यह ला नीना (शीतलन चरण) और वैकल्पिक तटस्थ चरणों के विपरीत है।

यह कैसे बनता है?

- सामान्य जलवायु परिस्थितियों में, भूमध्य रेखा के पार पूर्व से पश्चिम की ओर तेज व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जिससे गर्म सतह के पानी को एशिया और पश्चिमी प्रशांत की ओर धकेल दिया जाता है, जो दक्षिण अमेरिकी तट के साथ गहरे समुद्र से ठंडे पानी को अच्छी तरह से ऊपर ले जाने की अनुमति देता है।
- एक अल नीनो राज्य इस महासागरीय-वायुमंडलीय संतुलन के विघटन के माध्यम से विकसित होता है:
- व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना: पूरी तरह से समझ में नहीं आने के कारणों से, स्थिर पूर्वी व्यापारिक हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई कमजोर या पूरी तरह से उलट दिशा में बदल जाती हैं।



- पूर्व की ओर गर्मपानी का विस्थापन: तेज हवाओं के बिना इसे पश्चिम की ओर धकेलते हुए, इंडोनेशिया के चारों ओर निर्मित गर्म सतह के पानी का विशाल भंडार प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका की ओर पीछे की ओर झुकना शुरू कर देता है।
- थर्मोकलाइन का दमन: चूंकि यह गर्म पानी मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पूल करता है, यह थर्मोकलाइन (ठंडे गहरे पानी से गर्म सतह के पानी को अलग करने वाली पानी के नीचे की सीमा परत) को दबाता है, जिससे पेरू और इक्वाडोर के तटों के साथ पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी के सामान्य उत्थान को अवरुद्ध किया जाता है।
- वायुमंडलीय युग्मन: वायुमंडल इन गर्म समुद्र की सतह के तापमान पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। बढ़ती हवा और आंधी की गतिविधि का प्राथमिक क्षेत्र पश्चिमी प्रशांत से मध्य महासागर के विस्तार में पूर्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे ब्रह्मों की जेट धाराएं बदल जाती हैं और वैश्विक मौसम पैटर्न बदल जाता है।

अल नीनो की मुख्य विशेषताएं:

- चक्रीय लेकिन अनियमित ताल: अल नीनो की स्थिति गैर-आवधिक होती है, आमतौर पर हर दो से सात साल में अनियमित रूप से आवर्ती होती है। सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से, 2002, 2009, 2015 और 2023 में प्रमुख विन्यास उभरे हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव: क्योंकि यह ऊपरी वायुमंडल में भारी मात्रा में समुद्री गर्मी छोड़ता है, अल नीनो पूरे ग्रह पर एक अस्थायी वार्मिंग प्रभाव डालता है, जो अक्सर वैश्विक औसत तापमान को रिकॉर्ड तोड़ उच्च स्तर पर धकेल देता है।
- परिवर्तित वॉकर परिसंचरण: यह घटना सामान्य वॉकर परिसंचरण (पश्चिम में उठने वाली हवा का उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय लूप) को कमजोर या अलग कर देती है, स्थानीयकृत उच्च और निम्न दबाव वाली कोशिकाओं को उलट देती है।
- समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर गंभीर आर्थिक प्रभाव: ठंडे पानी के ऊपर उठने वाले पोषक तत्वों के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को भूखा रखता है, जिससे दक्षिण अमेरिकी समुद्र तटों के साथ मछली की आबादी (विशेष रूप से एंकोवेटास) में बड़े पैमाने पर गिरावट आती है और क्षेत्रीय मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचता है।

सुपर अल नीनो

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओए) ने भूमध्यरेखीय प्रशांत में एक नए अल नीनो के गठन की पुष्टि की, जिससे 63% की संभावना है कि यह उत्तरी सर्दियों तक एक बहुत मजबूत या सुपर अल नीनो में बदल जाएगा।

सुपर अल नीनो

सुपर अल नीनो के बारे में:

यह क्या है?

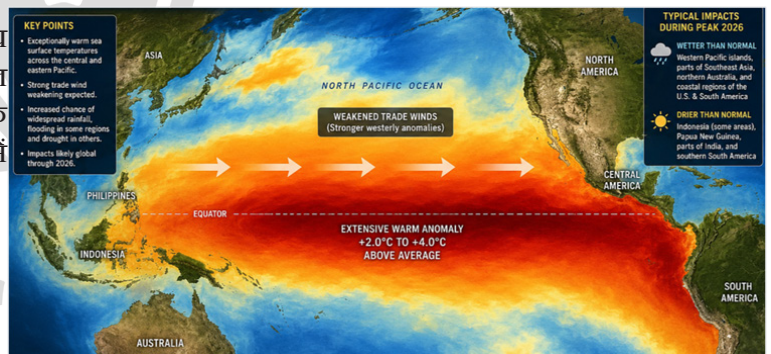
- एक अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान (एसएसटी) के आवधिक, विषम वार्मिंग का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) दीर्घकालिक औसत से तापमान विचलन के आधार पर एक मानक अल नीनो को वर्गीकृत करता है, एक बहुत मजबूत या सुपर अल नीनो को स्पष्ट रूप से प्रशांत के एक विशिष्ट संदर्भ पैच में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान प्रस्थान द्वारा परिभाषित किया जाता है।

यह कैसे बनता है?

- व्यापारिक हवाओं का सुस्ती: भूमध्यरेखीय व्यापारिक हवाएं जो सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर जोर से चलती हैं - गर्म सतह के पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं - रुकने या दिशा को उलटने लगती हैं।
- पश्चिम-से-पूर्वगर्म पानी का बहाव: कमजोर हवाओं के कारण, गर्म सतह के पानी के विशाल पूल जमा हो जाते हैं और दक्षिण अमेरिका के तट की ओर पूर्व की ओर बढ़ते हैं।
- फीडबैक लूप: जैसे-जैसे पूर्वी प्रशांत गर्म होता है, यह वायुमंडलीय दबाव क्षेत्रों को और बाधित करता है, जिससे व्यापारिक हवाएं और भी अधिक धीमी हो जाती हैं। यह लूप सिस्टम को एक स्व-सुदृढ़ीकरण चक्र में बंद कर देता है जो तापमान को महत्वपूर्ण 2 डिग्री सेल्सियस सीमा से आगे बढ़ाता है।
- जलवायु परिवर्तन गुणक: दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन एक इनक्यूबेटर के रूप में कार्य करता है, महासागरों में उपलब्ध आधारभूत गर्मी को बढ़ाता है और आधुनिक सुपर अल नीनो को ऐतिहासिक लोगों की तुलना में काफी अधिक तीव्र बनाता है।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं:

- एस-कर्व कैलेंडर जीवनचक्र: यह घटना एक सख्त मौसमी समयरेखा का अनुसरण करती है - वसंत के दौरान उभरती है, सर्दियों के महीनों के दौरान अपनी चरम तीव्रता तक पहुंचती है, और अगले वसंत ऋतु तक तेजी से ढह जाती है।
- विलंबित दमन संकेत: क्योंकि समुद्र का गर्म होना वर्ष के अंत में चरम पर होता है, वैश्विक मौसम प्रणालियों पर इसका दमन प्रभाव मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन मानसून चक्रों के मध्य और बाद के चरणों के दौरान महसूस किया जाता है, न कि उनकी शुरुआत में।
- पैमाने की दुर्लभता: सच्ची सुपर घटनाएं ऐतिहासिक रूप से दुर्लभ हैं। 1950 में मानक उपकरण ट्रैकिंग की शुरुआत के बाद से, केवल चार प्रमुख वर्षों ने इस चरम सीमा को पार किया है: 1972-73, 1982-83, 1997-98 और 2015-16।



- चक्रवाती पुनर्वितरण: यह घटना विश्व स्तर पर अधिक कुल चक्रवात उत्पन्न नहीं करती है; इसके बजाय, यह वहीं बदल जाती है जहां वे बनते हैं। तेज हवा का कतरनी अटलांटिक तूफान को दबा देता है, जबकि मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में सुपर टाइफून के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाता है।

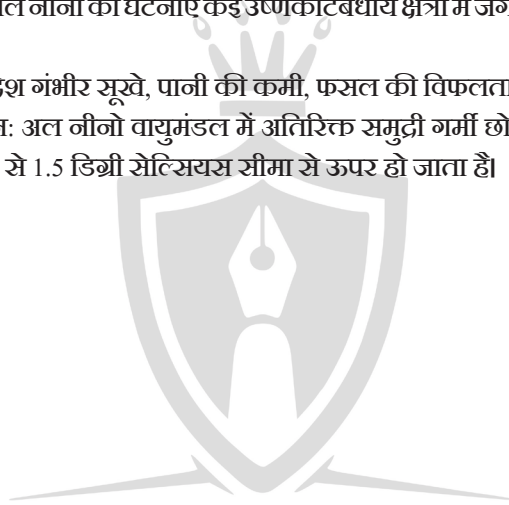
भारत और विश्व पर प्रभाव:

भारत पर प्रभाव:

- दक्षिण एशियाई मानसून का दमन: अल नीनो अक्सर भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है, जिससे सामान्य से कम वर्षा होती है और कई क्षेत्रों में सूखे का खतरा बढ़ जाता है।
- अत्यधिक अनियमित वर्षा वितरण: यह मानसून की शुरुआत में देरी कर सकता है और लंबे समय तक शुष्क दौर पैदा कर सकता है, जिससे फसल की वृद्धि और कृषि उत्पादकता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
- हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) चर: एक सकारात्मक IOD आंशिक रूप से अल नीनो के प्रभावों की भरपाई कर सकता है, लेकिन वर्तमान पूर्वानुमान मानसून के कमजोर होने से सीमित राहत का सुझाव देते हैं।

वैश्विक प्रभाव:

- गंभीर पारिस्थितिक विनाश: सुपर अल नीनो की घटनाएं कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगल की आग, प्रवाल विरंजन और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को ट्रिगर करती हैं।
- अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय सूखा: कई देश गंभीर सूखे, पानी की कमी, फसल की विफलता और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा देते हैं।
- वैश्विक तापमान सीमा का उल्लंघन: अल नीनो वायुमंडल में अतिरिक्त समुद्री गर्मी छोड़ता है, जिससे वैश्विक तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है और संभावित रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से ऊपर हो जाता है।



LK ACADEMY[®]
 YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

बायोचार

संदर्भ:

एक गंभीर कृषि विरोधाभास के बीच, जहां मूल्यवान बायोमास को खुले खेत की फसल अवशेषों के रूप में जलाया जाता है, बायोचार भारत की समाप्त हो चुकी मिट्टी को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्बन-नकारात्मक समाधान के रूप में उभरा है।

बायोचार

बायोचार के बारे में:

यह क्या है?

- बायोचार एक अत्यधिक छिद्रपूर्ण, कार्बन युक्त ठोस सामग्री है जो विभिन्न बायोमास स्रोतों से उत्पादित होती है - जिसमें लकड़ी के चिप्स, फसल अवशेष, खाद और बायोडिग्रेडेबल नगरपालिका अपशिष्ट शामिल हैं - जो पृथ्वी में मिश्रित होने पर असाधारण रूप से धीरे-धीरे टूट जाता है। एकल, समान उत्पाद के रूप में कार्य करने के बजाय, बायोचार रासायनिक और शारीरिक रूप से अद्वितीय काले कार्बन रूपों की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करता है।
- उद्देश्य: बायोचार बनाने और लागू करने का उद्देश्य दीर्घकालिक कार्बन पृथक्करण है - कार्बन को बंद करना जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अत्यधिक स्थिर, लगातार रूप में तय किया जाता है ताकि यह वायुमंडलीय पूल में वापस न आ सके।

यह कैसे बनता है?

- पायरोलिसिस प्रतिक्रिया: बायोचार पायरोलिसिस के माध्यम से बनता है, जिसमें नियंत्रित, कम ऑक्सीजन या ऑक्सीजन मुक्त स्थितियों में जैविक कृषि और शहरी कचरे को उच्च तापमान पर गर्म करना शामिल है।
- संपत्ति निर्धारण: अंतिम उत्पाद के आधारभूत गुण चुने गए फीडस्टॉक के प्रकार (जैसे, गन्ने की खोई, नारियल के डंठल, या खाद) और विनिर्माण के दौरान लागू किए गए विशिष्ट हीटिंग, शीतलन और भंडारण प्रोटोकॉल पर अत्यधिक निर्भर हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- उच्च संरचना: सूक्ष्म संरचनात्मक इमेजिंग से एक अत्यधिक छिद्रपूर्ण नेटवर्क का पता चलता है जो ऊपरी मिट्टी के अंदर एक भौतिक स्पंज के रूप में कार्य करता है।
- क्षय के प्रति असाधारण प्रतिरोध: कच्चे कार्बनिक पदार्थों के विपरीत, इसके कार्बन अणु कसकर बंधे होते हैं, जिससे यह माइक्रोबियल टूटने का विरोध कर सकता है और हजारों वर्षों तक मिट्टी के भीतर बरकरार रहता है।
- परिवर्तनीय रासायनिक गुणवत्ता: इसके सटीक पीएच स्तर, रख सामग्री, सतह क्षेत्र और पोषक तत्व मूल्य स्थिर नहीं हैं; वे अपने निर्माता की स्रोत बायोमास और प्रसंस्करण गर्मी की प्रसंग के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।
- उच्च जल और पोषक तत्व आत्मीयता: पूरी तरह से एकीकृत होने पर इसमें उच्च धनायन विनिमय क्षमता (सीईसी) होती है, जिससे यह ढीली मिट्टी के कणों को एकत्रित करने और ढीले खनिजों को कसकर बांधने में सक्षम होता है।
- उच्च कार्बन प्रतिधारण: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की तकनीक के रूप में कार्य करता है जो स्थायी अनुक्रमण के लिए कठोर स्थिरता मानकों को आसानी से पारित करता है।

प्रमुख अनुप्रयोग:

- बायोचार मिट्टी की नमी बनाए रखने और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करता है, मिट्टी के कार्बनिक कार्बन को बढ़ाता है और फसल उत्पादकता बढ़ाता है, विशेष रूप से खराब मिट्टी में।
- बायोचार स्थायी रूप से कार्बन संग्रहीत करता है और कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकता है, जिससे किसानों और सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा होते हैं।
- यह फसल अवशेषों, जैविक कचरे और सीवेज कीचड़ को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करता है, जिससे पराती जलाने, लैंडफिल अपशिष्ट और मीथेन उत्सर्जन कम होता है।
- बायोचार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों को बरकरार रखता है, पोषक तत्वों के नुकसान को कम करता है और उर्वरक-उपयोग दक्षता में सुधार करता है।



पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)

संदर्भ:

केंद्र सरकार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) के सीमांकन को चरणबद्ध तरीके से राज्य-वार तरीके से अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसकी शुरुआत गुजरात जैसे राज्यों से की गई है, जहां आम सहमति हासिल की गई है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के बारे में:

यह क्या है?

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक कानूनी रूप से संरक्षित भौगोलिक क्षेत्र है।
- इसमें एक अनुकूलित प्रबंधन व्यवस्था है जिसे अत्यधिक नाजुक, जैविक रूप से समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र को औद्योगिक क्षरण से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि पहले से मौजूद मानव बस्तियों को सतत विकास में संलग्न होने की अनुमति देता है।

योजना का इतिहास और विकास:

- माधव गाडगिल पैनल (2010-2011): सिफारिश की गई कि पूरे पश्चिमी घाट की सीमा (1,29,037 वर्ग किमी) को ESA के रूप में नामित किया जाए, जिससे विकासात्मक गतिविधियों पर एक समान, भारी क्रॉस-सेक्टरल प्रतिबंध लागू हो सकें।
- के. कस्तूरीरंगन वर्किंग ग्रुप (2012-2013): 60% सांस्कृतिक परिदृश्य (मानव-प्रभुत्व वाली बस्तियों और कृषि) और 40% प्राकृतिक परिदृश्य का मानचित्रण करते हुए, व्यापक दृष्टिकोण को स्वारिज कर दिया। इसने प्रस्तावित किया कि केवल 60,000 वर्ग किमी के प्राकृतिक परिदृश्य को औपचारिक रूप से ESA के रूप में अधिसूचित किया जाए।
- 2014 बेसलाइन ड्राफ्ट: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 56,825.7 वर्ग किमी को ESA के रूप में निर्धारित करते हुए अपनी पहली आधिकारिक मसौदा अधिसूचना जारी की, जिससे केरल के जमीनी आंकड़ों के बाद क्षेत्र में 3,000 वर्ग किमी से अधिक की कमी आई।
- संजय कुमार समिति (2022-2026): ग्राम-स्तरीय राजस्व मानचित्रों में विसंगतियों को दूर करने, राज्य की आपत्तियों की जांच करने और चरणबद्ध, राज्य-दर-राज्य निष्पादन रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए नियुक्त किया गया।

ESA योजना की मुख्य विशेषताएं:

- निषिद्धाल-श्रेणी की गतिविधियाँ: अत्यधिक विघटनकारी वाणिज्यिक संचालन, विशेष रूप से नए खनन और उत्खनन, थर्मल पावर प्लांट और भारी प्रदूषणकारी लाल-श्रेणी के उद्योगों पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लागू करती हैं।
- बुनियादी ढांचा और निर्माण कैप: 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के निर्मित क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक भवनों और टाउनशिप की सभी नई और विस्तार परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया।
- चरणबद्ध, राज्य-वार अधिसूचना खंड: नवीनतम मसौदा ढांचा केंद्र को पूर्ण छह-राज्यों की आम सहमति की प्रतीक्षा करने के बजाय अलग-अलग राज्यों के लिए ESA सीमाओं को क्रमिक रूप से अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने की अनुमति देता है।
- ग्राम-स्तरीय डेटा का समाधान: स्थानीय सीमाओं को पार करने और डेटा विसंगतियों को खत्म करने के लिए भौतिक राज्य राजस्व रजिस्ट्रियों के साथ जोड़ी गई उत्त्व-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी का लाभ उठाता है।
- वित्तीय मुआवजा ढांचा: प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए स्थानीय समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान के लिए एक संरचित कार्यक्रम के साथ-साथ केंद्र से अनुदान आर्थिक प्रोत्साहन प्रणाली का प्रस्ताव करता है।

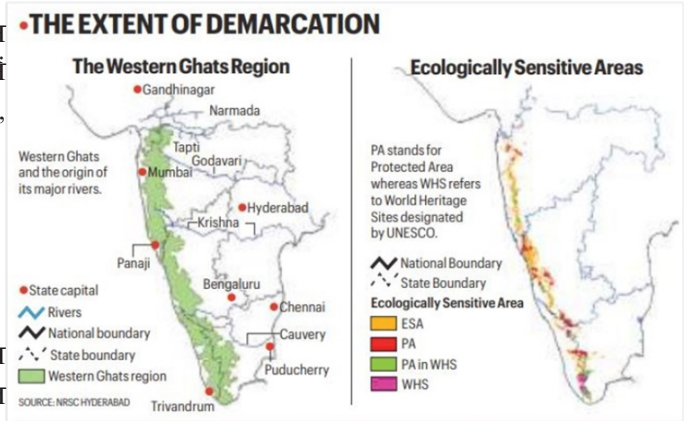
महत्व:

- पश्चिमी घाट दक्षिण-पश्चिम मानसून को नियंत्रित करता है और प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ESA संरक्षण वनों, जल स्रोतों और नदी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में मदद करता है।
- पश्चिमी घाट कई स्थानिक प्रजातियों की मेजबानी करता है जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ESA स्थिति वन्यजीव गलियारों, जंगलों और आवासों को विखंडन और पारिस्थितिक क्षरण से बचाती है।

नागालैंड कैस्केड मेंढक

संदर्भ:

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने नागालैंड में एक नई-से-विज्ञान कैस्केड-निवास मेंढक प्रजाति की खोज की है। अमोलोप्स कमल नाम का यह शोध पत्र इस विशिष्ट विकासवादी वंश की पुष्टि करने वाला शोध पत्र जेडएसआई के जर्नल में प्रकाशित हुआ था।



नागालैंड कैस्केड मेंढक

नागालैंड कैस्केड मेंढक के बारे में:

यह क्या है?

- अमोलोप्स कमल, जिसे आमतौर पर नागालैंड कैस्केड मेंढक के रूप में जाना जाता है, एक नई खोजी गई उभयचर प्रजाति है जो जीनस एमोलोप्स (परिवार रानिडे) से संबंधित है।
- ये सच्चे मेंढक हैं जो विशेष रूप से अशांत, तेजी से बहने वाली पहाड़ी धाराओं और झरनों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। प्रजाति का नाम कमल दिवंगत डॉ. कमल चौधरी के सम्मान में चुना गया था, जो एक प्रमुख प्राणी विज्ञानी और अध्ययन के प्रमुख लेखक के संरक्षक थे।

क्षेत्र और पर्यावास:

- नमूनों को नगालैंड के किफिरे जिले में सिंगरेप गांव के पास ऊबड़-खाबड़, अलग-थलग पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र से एकत्र किया गया था, जो म्यांमार की सीमा से लगे एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- यह क्षेत्र एक प्रमुख वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के भीतर बैठता है जो अद्वितीय माइक्रोक्लाइमेट और खंडित धारा आवासों की विशेषता है।

प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं:

- रूपात्मक नकल: अन्य कैस्केड मेंढकों की तरह, इसमें पानी की धाराओं के खिलाफ चालाक चढ़ानों को पकड़ने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर बड़ी डिजिटल डिस्क होती है। रूपात्मक रूप से, यह अविश्वसनीय रूप से संबंधित प्रजातियों के समान है, जो इसे एक गुप्त प्रजाति बनाता है - जो बाहर से दूसरों के समान दिखता है लेकिन आनुवंशिक रूप से अलग है।
- टैक्सोनोमिक ब्रुपिंग: इसे अत्यधिक विविध एमोलोप्स मामोरेट्स प्रजाति समूह के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो विशेष रूप से अमोलोप्स इंडोबर्मनेंसिस प्रजाति परिसर के भीतर बैठता है।
- आनुवंशिक विचलन: इसकी पहचान एकीकृत वर्गीकरण का उपयोग करके की गई थी, जो उन्नत आणविक फ़ाइलोजेनेटिक (डीएनए) मानचित्रण के साथ पारंपरिक शरीर माप को जोड़ती है। इससे पता चला कि मेंढक एक पूरी तरह से अलग, अद्वितीय विकासवादी वंश का गठन करता है।

महत्व:

- खोज से पता चलता है कि एमोलोप्स इंडोबर्मनेंसिस एक व्यापक प्रजाति नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित भौगोलिक वितरण के साथ अलग-अलग विकासवादी वंशों का एक समूह है।
- यह डीएनए-आधारित विश्लेषण के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि आनुवंशिक साक्ष्य छिपी हुई प्रजातियों को प्रकट कर सकते हैं जिन्हें अकेले शारीरिक उपस्थिति के माध्यम से मज़बूती से अलग नहीं किया जा सकता है।
- यह निष्कर्ष पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध लेकिन कम अध्ययन की गई जैव विविधता को रेखांकित करता है और नाजुक धारा और वन पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के मामले को मजबूत करता है।

फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026

संदर्भ:

आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) कार्यक्रम को स्वीडन के बास्ताड में प्रतिष्ठित 2026 फूड प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

फूड प्लैनेट पुरस्कार 2026

द फूड प्लैनेट प्राइज 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- फूड प्लैनेट पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार है जो पूरी तरह से वैश्विक खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए समर्पित है।
- स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित, यह जानबूझकर प्रारंभिक चरण, उत्तम क्षमता वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है, जो केवल पिछली विरासत उपलब्धियों का सम्मान करने के बजाय स्थायी खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को मौलिक रूप से नया आकार देने में सक्षम हैं।

संगठन और शासन:

- संस्थापक निकाय: कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन, स्वीडन।
- जूरी आर्किटेक्चर: अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और जमीनी स्तर के क्षेत्र के चिकित्सकों के बीच एक सरल 50-50 संस्थानगत विभाजन की सुविधा है, जो अकादमिक सिद्धांत और व्यावहारिक निष्पादन को समान लोकतांत्रिक महत्व देता है।

THE
CURT BERGFORS
FOOD
PLANET
PRIZE

2026 के विजेता:

- वैश्विक ग्रैंड पुरस्कार भारत के आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती (APCNF) कार्यक्रम द्वारा सुरक्षित किया गया था , जिसने छह महाद्वीपों में 1,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय नामांकनों को पीछे छोड़ दिया था।
- 2016 में रायथू साधिका संस्था (राज्य के कृषि विभाग के तहत) द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन अब 1.8 मिलियन किसान परिवारों और 340,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तक फैला हुआ है।

पुरस्कार वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं:

- मास्टर ग्रिड ब्लूप्रिंट: नामांकन को एक उत्तम उद्देश्य वाले 400-रपॉट मैट्रिक्स पर मैप किया जाता है जो भौगोलिक रेखाओं, वाणिज्यिक/ गैर-वाणिज्यिक संरचनात्मक प्रारूपों और स्वायत्त चक्र के भीतर प्रभाव के बिंदुओं में गहरा विविधीकरण सुनिश्चित करता है।
- कठोर वैज्ञानिक अंधा समीक्षा: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सख्त, गुमनाम पृष्ठभूमि की जांच से गुजरना पड़ता है जहां शीर्ष रैंकिंग वाले वैश्विक शिक्षाविद और उद्योग के अधिकारी परियोजना के साक्ष्य और जलवायु मैट्रिक्स का पूर्ण सत्यापन चलाते हैं।
- स्वतंत्र ऑन-ग्राउंड सत्यापन: फाउंडेशन खोजी पत्रकारों और वृत्तचित्र फोटोग्राफरों को परियोजना के वास्तविक दुनिया के सामुदायिक प्रभाव की पूरी तरह से अघोषित, वस्तुनिष्ठ क्षेत्र समीक्षा निष्पादित करने के लिए भेजता है।
- वित्तीय पैमाना: तेजी से प्रणालीगत स्केलिंग में तेजी लाने के लिए विजेता को \$1.5 मिलियन और प्रत्येक विशेष अंतरराष्ट्रीय फाइनलिस्ट को \$150,000 का भव्य पुरस्कार प्रदान करता है।

भारत के जलवायु भविष्य का वित्तपोषण**संदर्भ:**

कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर भारत के महत्वाकांक्षी परिवर्तन ने अपने बड़े पैमाने पर जलवायु-वित्तपोषण घाटे को पाटने के लिए आवश्यक घरेलू संरचनागत संरचना पर गहन ध्यान केंद्रित किया है।

भारत के जलवायु भविष्य का वित्तपोषण**भारत के जलवायु भविष्य के वित्तपोषण के बारे में:****यह क्या है?**

- भारत के जलवायु भविष्य का वित्तपोषण देश के जलवायु उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक, निजी और मिश्रित पूंजी की रणनीतिक लामबंदी, आवंटन और तैनाती को संदर्भित करता है।
- यह वित्तीय संरचना भारी उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने और स्थानीयकृत जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को निधि देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारत के जलवायु वित्त पोषण पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- ट्रिलियन-डॉलर लक्ष्य: भारत को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 2030 तक अनुमानित ₹162.5 ट्रिलियन (लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर) की आवश्यकता होगी।
- दीर्घकालिक शुद्ध-शून्य पूंजी मांग: 2070 के लक्षित वर्ष तक पूर्ण शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन डॉलर के संचयी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जो भारत के वर्तमान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग तीन गुना है।
- जीडीपी निवेश बेंचमार्क: मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रिपोर्ट का अनुमान है कि राष्ट्र को 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2.5% अतिरिक्त वार्षिक निवेश विशुद्ध रूप से हरित वित्तपोषण में डालना होगा।
- ऐतिहासिक हरित ऋण पदचिह्न: प्रारंभिक गति का प्रदर्शन करते हुए, भारत ने 2024 के अंत तक हरित, सामाजिक और स्थिरता से जुड़े ऋण में \$55.9 बिलियन सफलतापूर्वक जारी किए थे, जो 2021 से 186% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत के जलवायु भविष्य के वित्तपोषण की अनिवार्य आवश्यकता:

- हार्ड-टू-एबेट औद्योगिक क्षेत्रों को डीकार्बोनाइजिंग करना: भारी उद्योग समर्पित वित्तीय सहायता के बिना स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में संक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हरित विकल्प अभी तक अपने दम पर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।
- उदाहरण: स्टील, सीमेंट, बिजली और सड़क परिवहन को डीकार्बोनाइजिंग करने के लिए 2030 तक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में \$467 बिलियन या सालाना लगभग \$54 बिलियन की आवश्यकता होती है।
- अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहायता की क्षतिपूर्ति: विकसित राष्ट्र अपने वैश्विक जलवायु वित्त पोषण वादों को पूरा करने में लगातार विफल रहे हैं, जिससे भारत को आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- उदाहरण: बाकू न्यू क्लोविटव वॉटिफाइड गोल (एनसीयूजी) सभी विकासशील देशों के लिए 2035 तक केवल 300 बिलियन डॉलर का वादा करता है, एक पूल जिसे भारत सही मायने में अपर्याप्त मानता है।
- स्थानीय अनुकूलन के माध्यम से कमजोर ग्रामीण समुदायों की रक्षा करना: तत्काल पर्यावरणीय व्यवधानों और चरम मौसम का सामना करने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर वित्त पोषण की तत्काल आवश्यकता है।

- उदाहरण: लचीलापन बनाने के लिए लक्षित वित्त पोषण आवश्यक है, जैसे कि ओडिशा में तटीय गांवों को बढ़ते समुद्रों और विदर्भ में सूखा-रोधी कृषि भूमि से बचाना।
- बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय जोखिम प्रबंधन को लागू करना: वित्तीय संस्थानों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों से अपने ऋण पोर्टफोलियो को बचाने के लिए संरचनात्मक बफर का निर्माण करना चाहिए।
- उदाहरण: बैंकों को बिहार जैसे निचले राज्यों में ऋण पोर्टफोलियो के अचानक बाढ़ जोखिम का कड़ाई से मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट जोखिम ढांचे की आवश्यकता होती है।
- ग्रीनफील्ड वलीन टेक्नोलॉजीज की उच्च पूंजी लागत को कम करना: उच्च ब्याज दरें अक्सर निजी डेवलपर्स को राज्य समर्थित डी-रिस्किंग तंत्र के बिना नई, अप्रमाणित हरित परियोजनाओं में निवेश करने से हतोत्साहित करती हैं।
- उदाहरण: मिश्रित वित्त मॉडल को निधि देने के लिए रणनीतिक पूंजी महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि पारंपरिक कार्बन-गहन परियोजनाओं की तुलना में बैंकों के लिए हरित ऋण संरचनात्मक रूप से सस्ता हो जाए।

अब तक की गई पहल:

- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना: केंद्र सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में ₹477 बिलियन सफलतापूर्वक जारी किए हैं, जिससे स्पष्ट बाजार बेंचमार्क स्थापित हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।
- RBI ने जलवायु जोखिम ढांचे को अनिवार्य किया: RBI ने जलवायु परिवर्तन जोखिम निर्देशों के जलवायु वित्त और प्रबंधन को जारी किया, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को जलवायु कमजोरियों को सीधे अपने मुख्य ऋण संचालन में एकीकृत करने की आवश्यकता थी।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) समावेशन: पात्र हरित ऊर्जा और टिकाऊ बुनियादी ढांचा गतिविधियों को औपचारिक रूप से RBI के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण ढांचे में एकीकृत किया गया है, जिससे बैंकों को हरित परियोजनाओं की ओर ऋण निर्देशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
- ग्रीन सैंडबॉक्स विस्तार: सतत वित्त उपकरणों को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय बैंक के नियामक सैंडबॉक्स में शामिल किया गया है, जिससे वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित वातावरण में अभिनव हरित उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति मिलती है।

भारत के जलवायु भविष्य के वित्तपोषण में प्रमुख चुनौतियाँ:

- एक अधिनियमित कानूनी हरित वर्गीकरण की कुल अनुपस्थिति: एक मानकीकृत, कानूनी परिभाषा के बिना जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजना के रूप में योग्य है, वित्तीय प्रणाली भ्रामक विपणन के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।
- उदाहरण: औपचारिक वर्गीकरण की कमी हरे रंग के बांड को असत्यापित छोड़ देती है और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में ग्रीनवॉशिंग को प्रभावी ढंग से रोकना बेहद मुश्किल बना देती है।
- राज्य-स्तरीय उधार बुनियादी ढांचे में एकगंभीर संरचनात्मक कमी: जबकि जलवायु प्रभाव स्थानीय रूप से महसूस किए जाते हैं, क्षेत्रीय प्रशासन के पास वैश्विक ग्रीन बॉन्ड बाजारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष वित्तीय वैनलों की कमी है।
- उदाहरण: कमजोर राज्यों में अंतरराष्ट्रीय जलवायु पूंजी को जमीनी स्तर तक खींचने के लिए आवश्यक स्वतंत्र उधार क्षमता और संस्थागत सेटअप का अभाव है।
- मिश्रित वित्त साधनों का दीर्घकालिक कम उपयोग: सार्वजनिक और रियायती पूंजी को शायद ही कभी निजी निवेश के साथ जोड़ा जाता है, जिससे निजी ऋणदाताओं को उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं का पूरा बोझ उठाना पड़ता है।
- उदाहरण: राज्य समर्थित प्रथम-हानि गारंटी की कमी निजी उद्यम पूंजी को अपतटीय पवन या हरित हाइड्रोजन जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से हतोत्साहित करती है।
- ग्रीन-स्केल डीकार्बोनाइजेशन की उच्च लागत और अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल: पारंपरिक कोयला-निर्भर विनिर्माण कार्यों को हरित सेटअप में परिवर्तित करने के लिए बड़े पैमाने पर, दीर्घकालिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है जो धीमी वित्तीय रिटर्न प्रदान करते हैं।
- उदाहरण: कच्ची आर्थिक वास्तविकता निजी फर्मों को राज्य सब्सिडी के मिलान के बिना स्टील और सीमेंट में संक्रमण का नेतृत्व करने से रोकती है।
- वाणिज्यिक बैंकों में जलवायु तनाव-परीक्षण पद्धतियों की एक महत्वपूर्ण कमी: पारंपरिक परिसंपत्ति मूल्यांकन मॉडल दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं, जिससे वित्तीय नेटवर्क अचानक पर्यावरणीय झटकों के संपर्क में आ जाते हैं।

आगे की राह:

- एक व्यापक राष्ट्रीय जलवायु वित्त वर्गीकरण लागू करना: वित्त मंत्रालय को मानक परिभाषाएँ प्रदान करने, ग्रीनवॉशिंग को रोकने और विदेशी ईएसजी निवेश को अनलॉक करने के लिए एक स्पष्ट, कानूनी रूप से बाध्यकारी हरित वर्गीकरण को जल्दी से अंतिम रूप देना चाहिए।
- विभेदित बैंक पूंजी आवश्यकताओं को लागू करना: आरबीआई को जलवायु जोखिमों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को समायोजित करना चाहिए, जिससे कार्बन-भारी ऋण अधिक महंगा हो सके और वाणिज्यिक बैंकों के लिए हरित परियोजनाएं अधिक आर्थिक रूप से आकर्षक बन सकें।
- एक समर्पित राज्य जलवायु वित्त सुविधा की स्थापना: राज्य सरकारों और नगर पालिकाओं को स्थानीय अनुकूलन परियोजनाओं के लिए हरित ऋण बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए नाबार्ड और अंतरराष्ट्रीय पूंजी द्वारा समर्थित एक संयुक्त केंद्रीय कोष लॉन्च करना।

- एसएलआर ढांचे के भीतर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का विस्तार: सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने को तेजी से बढ़ाना और वाणिज्यिक बैंकों को घरेलू बाजार को गहरा करने के लिए अपने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) जनादेश में उन्हें गिनने की अनुमति देना।
- निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए संरचित प्रथम-हानि गारंटी को तैनात करना: मिश्रित वित्त मॉडल बनाने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करें, शुरुआती जोखिमों को अवशोषित करने और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पहले नुकसान की गारंटी प्रदान करें।

निष्कर्ष:

भारत की ट्रिलियन-डॉलर की जलवायु-वित्त चुनौती एक प्रमुख संरचनात्मक कार्य है, लेकिन यह पूरी तरह से हल करने की राष्ट्र की क्षमता के भीतर है। जबकि बाकू एनडीसी जैसे अंतराष्ट्रीय सहायता पूल अपर्याप्त हैं, भारत एक स्पष्ट कानूनी वर्गीकरण को अंतिम रूप देकर और आरबीआई के माध्यम से स्मार्ट नियामक प्रोत्साहन शुरू करके अपने घरेलू बाजारों को खोल सकता है।

भारत ने जलवायु वित्त पर बातचीत का आह्वान किया

संदर्भ:

जर्मनी के बॉन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्ता में, भारत ने अंतराष्ट्रीय जलवायु वित्त के सिकुड़ते पूल और बढ़ते अनुकूलन वित्त पोषण अंतर को संबोधित करने का आह्वान किया।

भारत ने जलवायु वित्त पर बातचीत का आह्वान किया

भारत के बारे में जलवायु वित्त पर बातचीत का आह्वान किया:

यह क्या है?

- जलवायु वित्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण को संदर्भित करता है - जो पूंजी के सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से लिया गया है - जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है।



वैश्विक जलवायु वित्त पर प्रमुख डेटा और सांख्यिकी

- अनुकूलन अंतर का चौड़ीकरण: संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि विकासशील देशों के लिए अनुकूलन वित्त अंतर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तीय प्रवाह की तुलना में 10 से 18 गुना अधिक है।
- वित्त पोषण की वास्तविकताओं में गिरावट: बढ़ते जलवायु प्रभावों के बावजूद, विकसित अर्थव्यवस्थाओं से वास्तविक वित्तीय हस्तांतरण को औसत दर्जे की गिरावट का सामना करना पड़ा है, जिससे उपलब्ध रियायती निधियों का पूल सिकुड़ गया है।
- विकासशील आवश्यकताओं का पैमाना: 2030 तक, विकासशील देशों को अपनी घरेलू जलवायु कार्य योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को लागू करने के लिए संघीय रूप से \$ 5 ट्रिलियन से \$ 6 ट्रिलियन के बीच की आवश्यकता होती है।
- अनुमानित आधारभूत लक्ष्य: 2025 के बाद के युग के लिए चर्चा किए गए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) लक्ष्य 2035 तक सालाना कम से कम \$300 बिलियन की आधारभूत प्रतिबद्धता की तलाश करते हैं, एक आंकड़ा विकासशील ब्लॉक अपर्याप्त के रूप में आलोचना करते हैं।

मजबूत जलवायु वित्त की तत्काल आवश्यकता:

- ऐतिहासिक जलवायु न्याय के सिद्धांत को बनाए रखना: विकसित देशों ने उच्च औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण किया है, जिससे विश्व स्तर पर हरित परिवर्तन को वित्तपोषित करने के लिए एक नैतिक और कानूनी कर्तव्य का निर्माण हुआ है।
- विकासशील देशों को अत्यधिक ऋण जाल से बचाना: मजबूत सार्वजनिक अनुदान गरीब देशों को चरम मौसम से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए उच्च ब्याज वाले वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए मजबूर होने से रोकते हैं।
- मापनीय ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाना: विकासशील अर्थव्यवस्थाएं पारंपरिक कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं कर सकती हैं और महत्वपूर्ण अग्रिम पूंजी निवेश के बिना स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क का विस्तार नहीं कर सकती हैं।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पर्यावरणीय झटकों से बचाना: अनुकूलन के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करना महत्वपूर्ण कृषि और विनिर्माण केंद्रों को गंभीर जलवायु व्यवधानों से बचाता है।

अब तक की गई पहल:

- पेरिस समझौता ढांचा: अनुच्छेद 9.1 को औपचारिक रूप दिया, जिससे विकसित देशों के लिए शमन और अनुकूलन के साथ विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया।
- बॉन SB64 नेगोशिएशन ट्रैक: 150 से अधिक देशों के वार्ताकार उच्च-स्तरीय प्रतिज्ञाओं को बाध्यकारी कानूनी ग्रंथों में बदलने के लिए सहायक निकायों के 64वें सत्र में एकत्र हुए।
- वैश्विक जलवायु कार्यवाई एजेंडा: ब्राजील की COP30 प्रेसीडेंसी द्वारा पांच साल की अवधि में अंतराष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को सीधे वास्तविक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित करने के लिए लॉन्च किया गया।

- द्विपक्षीय ब्लॉक संरक्षण: भारत ने G77 और चीन, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs), और BASIC ब्लॉक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन) सहित प्रमुख विकासशील गठबंधनों के साथ अपनी स्थिति को सक्रिय रूप से एकीकृत किया।

वैश्विक जलवायु वित्त के लिए प्रमुख चुनौतियाँ:

- एजेंडा प्रमुखता पर विकसित देशों से गंभीर प्रतिरोध: धनी अर्थव्यवस्थाएं अपने वित्तीय दायित्वों पर पूरी तरह से केंद्रित स्थायी, समर्पित बातचीत स्थान बनाने के प्रयासों को लगातार अवरुद्ध करती हैं।
- उदाहरण: भारत को स्पष्ट रूप से यह मांग करनी थी कि अनुच्छेद 9.1 कार्य कार्यक्रम को अमीर देशों द्वारा दरकिनार किए जाने से रोकने के लिए अपना स्वयं का समर्पित एजेंडा स्थान प्राप्त होता है।
- संरक्षणवादी एकतरफा हरित व्यापार बाधाओं को लागू करना: विकसित व्यापार ब्लॉक विकासशील देशों से आने वाले औद्योगिक निर्यात को दंडित करने के लिए घरेलू पर्यावरण नियमों का उपयोग कर रहे हैं।
- उदाहरण: यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) एकतरफा सीमा लेवी के रूप में कार्य करता है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार राजस्व को नुकसान पहुंचाता है।
- ग्लोबल साउथ पर समानांतर और असहमत जनादेश को लागू करने का प्रयास: धनी राष्ट्र अक्सर आवश्यक धन प्रदान किए बिना सख्त उत्सर्जन लक्ष्यों को जोड़कर संधियों को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं।
- भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का राजनीतिकरण: चल रहे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष अक्सर ध्यान और वित्तीय संसाधनों को दीर्घकालिक जलवायु अनुकूलन निधि से दूर कर देते हैं।
- उदाहरण: होर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहे पश्चिम एशियाई संकट और व्यवधानों ने पश्चिमी प्राथमिकताओं को जलवायु सहायता के बजाय तत्काल ऊर्जा सुरक्षा की ओर स्थानांतरित कर दिया है।
- अवास्तविक जीवाश्म ईंधन को आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र चैनलों के बाहर धकेलना: धनी देशों के छोटे समूह अक्सर बाहरी संधियाँ बनाते हैं जो उभरते देशों की विकासात्मक वास्तविकताओं की अनदेखी करती हैं।
- उदाहरण: कोलंबिया में सांता मार्टा सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन संधि के लिए धक्का देने वाले ने समावेशी UNFCCC ढांचे के बाहर पूरी तरह से बाध्यकारी चरणबद्ध नियम बनाने का प्रयास किया।

आगे की राह:

- अनुच्छेद 9.1 निष्पादन के लिए समर्पित एजेंडा स्थान सुरक्षित करना: विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत रहना चाहिए कि विकसित देशों के वित्तीय हस्तांतरण जनादेश को भविष्य के सभी यूएनएफसीसीसी सत्रों में प्राथमिक स्थान दिया जाए।
- बेलेम अनुकूलन संकेतकों को कानूनी रूप से मानकीकृत करना: स्थानीय अनुकूलन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए स्पष्ट, मापने योग्य आधार रेखा बनाने के लिए अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के तहत 59 संकेतकों को अंतिम रूप दें।
- एकतरफा कार्बन सीमा क्यों के खिलाफ औपचारिक चुनौतियां दर्ज करना: संरक्षणवादी हरित व्यापार शुल्कों को चुनौती देने के लिए कन्वेंशन के अनुच्छेद 3.5 का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्बन सीमा कर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को दंडित नहीं करते हैं।
- संस्थागत ग्रीन फंड के लिए पहुंच मानदंड को सरल बनाना: कमजोर देशों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) की प्रशासनिक आवश्यकताओं में बदलाव करना।
- 2025 के बाद के NCQG ढांचे के भीतर सख्त वितरण मेट्रिक्स लागू करना: सुनिश्चित करें कि 2025 के बाद का वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य पारदर्शी, अनुदान-समतुल्य सार्वजनिक पूंजी हस्तांतरण की ओर अस्पष्ट प्रतिज्ञाओं से दूर जाता है।

निष्कर्ष:

2026 बॉन जलवायु सम्मेलन उत्त्व-स्तरीय पर्यावरणीय वादों और वास्तविक वित्तीय वितरण के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। एकतरफा व्यापार बाधाओं और असमर्थित जनादेश के खिलाफ जी77 और बेसिक ब्लॉकों के साथ मजबूती से जुड़कर, भारत ने जलवायु समानता के मूल सिद्धांत को मजबूत किया है।

पेरिस समझौते के तहत पहला कार्बन क्रेडिट

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र कार्बन बाजार ने आधिकारिक तौर पर म्यांमार में एक साफ-खाना पकाने की परियोजना के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत अपना पहला कार्बन क्रेडिट जारी किया।

पहला कार्बन क्रेडिट

पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट के बारे में:

कार्बन क्रेडिट क्या है?

- कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य प्रमाणपत्र या परमिट है जो वायुमंडल से एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) या इसके समकक्ष ग्रीनहाउस गैस (CO₂) को सत्यापित कमी, परिहार या हटाने का प्रतिनिधित्व करता है।



- पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत, इन क्रेडिटों को वास्तविक, टिकाऊ जलवायु समाधानों की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय वित्त को फ़नल करने के लिए एक समर्पित संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा पर्यवेक्षित उत्त्व-अखंडता वाली संपत्ति के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

शामिल राष्ट्र और संस्थाएं:

- मेजबान राष्ट्र: म्यांमार, विशेष रूप से अपने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र (संघर्ष-भारी सगाइंग क्षेत्र सहित) में समुदायों को लक्षित कर रहा है।
- भागीदार राष्ट्र: कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया)।
- शासी प्राधिकरण: संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौते क्रेडिट तंत्र का अनुच्छेद 6.4 पर्यवेक्षी निकाय।

परियोजना कैसे काम करती है?

- जमीन पर तैनाती: साफ-खाना पकाने वाले स्टोव पारंपरिक लकड़ी से बने स्टोव की जगह लेते हैं, ईंधन की खपत को कम करते हैं और घरेलू ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं।
- उत्सर्जन और बायोमास ट्रैकिंग: जलाऊ लकड़ी के कम उपयोग से इनडोर वायु प्रदूषण और वनों की कटाई में कटौती होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्सर्जन में कमी कार्बन बचत के रूप में निर्धारित होती है।
- क्रेडिट सत्यापन और समायोजन: संयुक्त राष्ट्र अद्यतन वैज्ञानिक आधारेखाओं का उपयोग करके उत्सर्जन से बचने की पुष्टि करता है और पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कम क्रेडिट जारी करता है।
- क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर: ईटीएस अनुपालन के लिए क्रेडिट का एक हिस्सा दक्षिण कोरिया को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि शेष म्यांमार के एनडीसी लक्ष्यों का समर्थन करता है।

मुख्य विशेषताएं और सख्त डिज़ाइन सुरक्षा उपाय:

- लिगेसी सीडीएम से संक्रमण: यह परियोजना क्योटो प्रोटोकॉल के सीडीएम से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 तंत्र में संक्रमण करने वाले पहले लोगों में से एक है।
- रूढ़िवादी लेखांकन आधार रेखा: अद्यतन पद्धतियाँ सख्त उत्सर्जन गणनाओं का उपयोग करती हैं, जिससे पुराने सिस्टम की तुलना में जारी किए गए क्रेडिट की संख्या में काफी कमी आती है।
- निवारण और अपील के लिए प्रणाली: एक अनिवार्य 14-दिवसीय अपील विंडो सरकारों, समुदायों और हितधारकों को ऋण जारी करने के निर्णयों को चुनौती देने की अनुमति देती है।
- दोहरी जलवायु और सामाजिक सह-लाभ: यह परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला कल्याण और स्थानीय पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करते हुए उत्सर्जन को कम करती है।

शासन और विश्वसनीयता विवाद:

- आलोचक परियोजना की वैधता पर सवाल उठाते हैं क्योंकि म्यांमार का पर्यावरण मंत्रालय सैन्य जुटा नियंत्रण और प्रतिबंधों की चिंताओं के तहत काम करता है।
- संघर्ष और असुरक्षा ने ऑन-साइट सत्यापन को रोक दिया, जिससे दूरस्थ आकलन पर निर्भरता को मजबूर होना पड़ा जिसे आलोचक अविश्वसनीय मानते हैं।

एआई डेटा केंद्र और पर्यावरणीय घर्षण

संदर्भ:

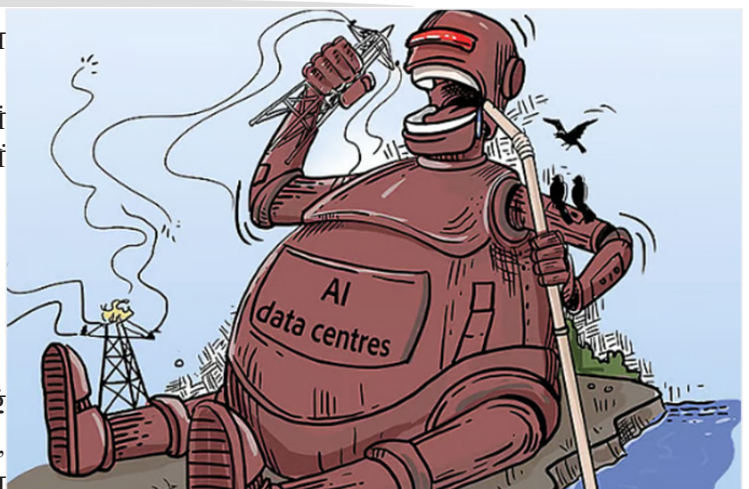
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा केंद्रों के पर्यावरणीय टोल के खिलाफ वैश्विक प्रतिरोध काफी तेज हो गया है। अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में समुदाय और कार्यकर्ता इन मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तेजी से विरोध कर रहे हैं।

एआई डेटा केंद्र और पर्यावरणीय घर्षण

एआई डेटा सेंटर और पर्यावरणीय घर्षण के बारे में:

वे क्या हैं?

- एआई डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर, हाइपर-स्केल सुविधाएं हैं जो जटिल मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने, तैनात करने और चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष सुपर कंप्यूटर के रूप में कार्य करती हैं।
- पारंपरिक डेटा केंद्रों के विपरीत, जो मुख्य रूप से डिजिटल रिकॉर्ड के लिए स्थिर भंडारण गोदामों के रूप में कार्य करते हैं, जनरेटिव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सेकंड अरबों संचालन को संसाधित करने के लिए निरंतर, उत्त्व-प्रदर्शन कम्यूटेशनल शक्ति की आवश्यकता होती है।



वैश्विक और भारतीय डेटा केंद्रों पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- ग्लोबल ब्लॉकेज मीट्रिक: अकेले 2025 में, संयुक्त राज्य भर में स्थानीय प्रतिरोध और सामुदायिक विरोध प्रदर्शनों ने \$152 बिलियन तक की डेटा सेंटर परियोजनाओं को सफलतापूर्वक विलंबित या अवरुद्ध कर दिया।
- \$100 बिलियन मेगाप्रोजेक्ट: अडानी समूह ने 2035 तक पूरे भारत में 5-गीगावाट (GW) AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए \$100 बिलियन की निवेश योजना की घोषणा की है।
- भारत का सबसे बड़ा हाइपरस्केल फुटप्रिंट: गूगल ने विशाखापत्तनम में 2 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने के लिए अडानी समूह के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है, जो देश की सबसे बड़ी एकल हाइपर-स्केल सुविधा बन जाएगी।
- बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन: विशाखापत्तनम में प्रौद्योगिकी उद्यम को पारिस्थितिक रूप से कमजोर तटीय क्षेत्र के भीतर सीधे स्थित 480 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

सरल पर्यावरण विनियमन की अनिवार्य आवश्यकता:

- स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिताओं की कमी को रोकना: हाइपर-स्केल सर्वर फार्म ऊर्जा ब्रिड और जल स्तर पर अत्यधिक दबाव डालते हैं, जो स्थानीय समुदायों की बुनियादी पेयजल और बिजली की जरूरतों को खतरे में डाल सकते हैं।
- उदाहरण: आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तकनीकी परियोजनाओं को 15 साल की बिजली और 10 साल की जल सब्सिडी प्रदान की है, जो पहले से ही अति-आवृत्ति नेटवर्क से संसाधनों को खींच रही है।
- नाजुक पारिस्थितिक तंत्र और तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना: नाजुक पारिस्थितिक क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक परिसरों के निर्माण से मिट्टी के क्षरण, प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण और स्थानीय जलभृतों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है।
- उदाहरण: हरे-भरे बगीचों, खेतों और तटीय पट्टियों पर बड़े पैमाने पर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वे पहले से ही गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
- भ्रामक आर्थिक आख्यानों को सुधारना: सरकारें अक्सर इन परियोजनाओं को समुदाय के लिए प्रमुख रोजगार इंजन के रूप में बढ़ावा देती हैं, लेकिन दीर्घकालिक घरेलू भर्ती क्षमता वास्तव में काफी कम है।
- रोजमर्रा के उपभोक्ताओं के लिए समान उपयोगिता मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना: बड़ी कॉर्पोरेट सब्सिडी देने से आम नागरिकों को तकनीकी कंपनियों के भारी उपयोग की भरपाई के लिए उच्च बिजली और पानी की दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- उदाहरण: आम उपभोक्ताओं को बढ़ते उपयोगिता बिलों और पानी में कटौती का सामना करना पड़ता है जबकि अत्यधिक लाभदायक तकनीकी दिग्गजों को अत्यधिक रियायती संसाधन प्राप्त होते हैं।
- उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं के लिए कानूनी छूट को रोकना: महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जांचों को माफ करने से बड़ी तकनीकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आवश्यक सुरक्षा और स्थिरता समीक्षाओं को बायपास करने की अनुमति मिलती है।
- उदाहरण: Google की संयुक्त सुविधा जैसे प्रमुख विकासों ने अपने अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को पूरी तरह से माफ कर दिया है।

वर्तमान वैश्विक पहल बनाम भारतीय नीति:

वैश्विक दृष्टिकोण:

- यूरोपीय संघ अनुपालन बदलाव: यूरोपीय संघ ने प्रमुख हाइपर-स्केल परियोजनाओं को रोकना शुरू कर दिया है, इसके बजाय छोटे क्षेत्रीय डेटा हब की ओर स्थानांतरित हो रहा है जो हरित ऊर्जा और गर्मी वसूली पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- द्विदलीय विधायी अधिस्थगन: अमेरिका में, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद मोरेटोरियम पारित कर रहे हैं, जिन्हें डेटा केंद्रों को मंजूरी देने से पहले सख्त संसाधन प्रभाव आकलन की आवश्यकता होती है।
- बुनियादी ढांचे पर राजनीतिक संरक्षण: वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसे अमेरिकी राज्यों में डेटा सेंटर स्थिरता एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है, जिससे सख्त पर्यावरणीय जांच को मजबूर किया गया है।

भारतीय दृष्टिकोण:

- लॉन्ग-टर्म टैक्स हॉलिडेज: केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय डेटा सेंटर निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न आयात रियायतों के साथ 20 साल की कर छूट की शुरुआत की है।
- आक्रामक भूमि आवंटन: राज्य प्रशासन तकनीकी कंपनियों और स्थानीय समूहों के लिए साइट प्रदान करने के लिए बड़े भूमि पार्सल को साफ कर रहे हैं, कभी-कभी बागों और खेतों के माध्यम से काट रहे हैं।
- उदार राज्य सब्सिडी: क्षेत्रीय सरकारें प्रमुख प्रोत्साहन दे रही हैं, जिसमें दीर्घकालिक पानी और बिजली सब्सिडी के साथ-साथ भूमि की कीमतों पर 25% की छूट शामिल है।

भारत में प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ:

- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर छूट: बड़े पैमाने पर सर्वर परियोजनाओं के लिए प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को माफ करना घरेलू पर्यावरण-शासन के लिए एक चिंताजनक मिसाल कायम करता है।
- गंभीर आधारभूत संसाधन की कमी: भारत पहले से ही अत्यधिक जल-संकट से ग्रस्त है और पुरानी बिजली की कमी का अनुभव कर रहा है, जिससे डेटा केंद्रों की उच्च संसाधन मांगों को बनाए रखना मुश्किल हो गया है।

- सीमित स्थानीय आर्थिक रिटर्न: क्योंकि हाइपर-स्केल डेटा सेंटर नई तकनीक विकसित करने के बजाय पूर्व-प्रशिक्षित एआई मॉडल चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार या प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाते हैं जो उनकी सब्सिडी को उचित ठहराते हैं।
- स्थिरता के लिए राजनीतिक वकालत की कमी: पश्चिमी देशों के विपरीत, भारत में किसी भी प्रमुख राजनीतिक नेता ने अनियंत्रित तकनीकी विस्तार की उच्च पर्यावरणीय लागत के बारे में चिंता नहीं जताई है।

आगे की राह:

- अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को बहाल करना: फास्ट-ट्रैकिंग तकनीकी बुनियादी ढांचे की प्रथा को समाप्त करें और एक निश्चित शक्ति सीमा से अधिक किसी भी डेटा सेंटर परियोजना के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव समीक्षा को अनिवार्य करें।
- सख्त जल-पुनर्चक्रण और उन्नत शीतलन जनादेश को लागू करना: डेटा केंद्रों को दुर्लभ स्थानीय सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति में दोहन करने के बजाय बंद-लूप तरल शीतलन प्रणाली या पुनर्नवीनीकरण औद्योगिक पानी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- उत्त्व-लाभ वाली तकनीकी फर्मों के लिए संसाधन सब्सिडी को वरणबद्ध करना: दीर्घकालिक जल और बिजली सब्सिडी को बाजार-दर उपयोगिता मूल्य निर्धारण के साथ बदलें, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी कंपनियां स्थानीय ग्रिड का समर्थन करने के लिए अपने उचित हिस्से का भुगतान करें।
- सतत क्षेत्रीय केंद्रों की ओर परियोजनाओं को निर्देशित करना: बड़े पैमाने पर, संसाधन-भारी तटीय हाइपर-स्केल परियोजनाओं से दूर छोटे क्षेत्रीय सुविधाओं की ओर स्थानांतरित करके वैश्विक स्थिरता मॉडल का पालन करें जो अपशिष्ट गर्मी का पुनः उपयोग करते हैं।
- स्वच्छ तकनीक विनियमों पर व्यापक राजनीतिक सहमति का निर्माण: भारतीय जलवायु कार्यकर्ताओं को ऊर्जा और भूमि उपयोग पर सख्त राज्य-स्तरीय संसाधन ऑडिट पर जोर देने के लिए राजनीतिक लाइन से परे स्थानीय नेताओं के साथ जुड़ना चाहिए।

निष्कर्ष:

एआई डेटा केंद्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए भारत का आक्रामक प्रयास भारी पर्यावरणीय लागतों को नजरअंदाज कर देता है जो दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाइपर-स्केल सर्वर फार्मों को व्यापक कर अवकाश और उपयोगिता सब्सिडी देने से देश के पहले से ही तनावपूर्ण जल स्तर और बिजली ग्रिड पर गंभीर बोझ पड़ता है।

पैराक्वाट शाकनाशी

संदर्भ:

तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर किसानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यधिक जहरीले स्वरूपितवार नाशक पैराक्वाट की बिक्री, वितरण, निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया।

पैराक्वाट शाकनाशी

पैराक्वाट हर्बिसाइड के बारे में:

यह क्या है?

- पैराक्वाट एक अत्यंत शक्तिशाली, तेज़-अभिनय और अत्यधिक जहरीले रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग गैर-चयनात्मक संपर्क शाकनाशी (स्वरूपितवार नाशक) के रूप में किया जाता है। क्योंकि यह गैर-चयनात्मक है, यह किसी भी हरे पौधे के ऊतक को नष्ट कर देता है जो प्रभाव पर सेल संरचनाओं को मारकर संपर्क में आता है, जिससे यह अपने घातक स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद तेजी से क्षेत्र समाशोधन के लिए कृषि क्षेत्रों द्वारा अत्यधिक मूल्यवान हो जाता है।

उत्पत्ति और ऐतिहासिक विकास

- प्रारंभिक खोज: पैराक्वाट को पहली बार 1880 के दशक में औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रासायनिक ऑक्सीकरण संकेतक और डाई के रूप में संश्लेषित किया गया था।
- कृषि खोज: इसके शक्तिशाली शाकनाशी गुणों को 1950 के दशक में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों द्वारा उजागर किया गया था।
- वाणिज्यिक लॉन्च: इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज (आईसीआई) ने 1960 के दशक में वाणिज्यिक ब्रांड नाम ग्रामोक्सेन के तहत विश्व स्तर पर रसायन का बड़े पैमाने पर विपणन शुरू किया।
- वैश्विक और भारतीय पदचिह्न: इस यौगिक का उपयोग भारत में लगभग 80 लाख एकड़ कृषि भूमि पर इसकी कम कीमत (₹280 प्रति लीटर) के कारण किया जाता है। यह गंभीर विषैले जोखिमों के कारण दुनिया भर के 74 देशों में प्रतिबंधित है।

प्रमुख तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं

- रंगहीन और बेस्वाद प्रोफ़ाइल: अपनी शुद्ध रासायनिक अवस्था में, यह एक रंगहीन, गंधहीन और वस्तुतः बेस्वाद तरल है, जो बिना लेबल वाले घरेलू कंटेनरों या जूस की बोतलों में स्थानांतरित होने पर इसे आक्रामक अंतर्ग्रहण के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है।
- तेजी से सेलुलर विनाश: प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों की कोशिकाओं के भीतर प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों



(सुपरऑक्साइड) को उत्पन्न करके, सेलुलर झिल्ली को बाधित करके और घंटों के भीतर लक्ष्य खरपतवारों को सुखाने से कार्य करता है।

- एक मारक की पूर्ण अनुपस्थिति: सांप के काटने या कार्बनिक फॉस्फेट कीटनाशक विषाक्तता के विपरीत, पैराक्वाट के लिए कोई चिकित्सा मारक नहीं है। एक बार जैविक प्रणाली के अंदर, सेलुलर क्षति तत्काल और अपरिवर्तनीय होती है।
- गंभीरप्रणालीगत अंग विफलता: एक छोटे से घूंट को भी निगलने से मुंह और गले को संक्षारक क्षति दिखाई देती है ("पैराक्वाट माउथ")। यह रक्तप्रवाह के माध्यम से तेजी से फैलता है, सीधे फेफड़ों में जमा होने से पहले गुर्दे और यकृत को नुकसान पहुंचाता है।
- त्वरित फेफड़े के फाइब्रोसिस: रासायनिक फेफड़ों के ऊतकों में बंद हो जाता है, जिससे अपरिवर्तनीय फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस (निशान) होता है। जहर वाले रोगी को मेडिकल वेंटिलेटर पर रखने से यह ऑक्सीडेटिव क्षति तेज हो जाती है, जिससे बहु-अंग विफलता हो जाती है।

भारत गरीबी के खिलाफ युद्ध जीतकर अपने जंगलों को बचा सकता है

संदर्भ:

नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक सफल अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ने गरीबी उन्मूलन और वन जैव विविधता के बीच सीधा संबंध स्थापित करके पारंपरिक किले संरक्षण मॉडल को चुनौती दी है।

भारत गरीबी के खिलाफ युद्ध जीतकर अपने जंगलों को बचा सकता है

गरीबी पर युद्ध जीतकर भारत अपने जंगलों को बचा सकता है:

यह क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय वानिकी संसाधन और संस्थान नेटवर्क के डेटा का उपयोग करते हुए, टीम ने 24 साल की समयरेखा (1993-2017) में 15 देशों में 322 समुदाय-प्रबंधित उष्णकटिबंधीय वनों का विश्लेषण किया।
- इस डेटासेट के आकार ने शोधकर्ताओं को यह मानचित्रण करने की अनुमति दी कि मानव आजीविका में परिवर्तन सीधे पेड़ की प्रजातियों की विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं - पारिस्थितिक स्थिरता और वन लचीलापन का एक प्राथमिक संकेतक।

पिछले दशक में प्रमुख रुझान और निष्कर्ष:

- गरीबी को दोष देने का भ्रम: शोधकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि गरीबी ही जैव विविधता के नुकसान का मूल कारण नहीं है। इसके बजाय, जब स्थानीय आबादी को वैकल्पिक आजीविका विकल्पों की प्रणालीगत कमी का सामना करना पड़ता है, तो बुनियादी अस्तित्व के लिए आस-पास के जंगलों पर उनकी संरचनात्मक निर्भरता स्वचालित रूप से तेज हो जाती है।
- अति-निकाले गए जंगलों की डूबती समृद्धि: गहराई से गरीब, घनी आबादी वाले समुदायों के पास स्थित वन जो ईंधन की लकड़ी पर बहुत अधिक निर्भर हैं, पेड़ प्रजातियों की विविधता में गंभीर गिरावट दिखाते हैं। यह कम प्रजातियों की समृद्धि इन पारिस्थितिक तंत्रों को कम स्थिर और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
- वैकल्पिक आय का स्थिर प्रभाव: इसके विपरीत, उष्णकटिबंधीय वन जहां स्थानीय समुदायों की वैकल्पिक आजीविका तक स्थिर पहुंच है - जैसे कि कृषि और गैर-वन व्यापार - बहुत अधिक वृक्ष प्रजातियों की विविधता प्रदर्शित करते हैं।
- किले के मॉडल का अलगाव: दशकों से, भारतीय वन शासन ने किले के मॉडल पर भरोसा किया है, जो मानव गतिविधि को कम करता है और संसाधन पहुंच को प्रतिबंधित करता है। हालांकि इसने विशिष्ट प्रतिष्ठित प्रजातियों की रक्षा करने में मदद की है, इसने कई अभयारण्यों को भारी मानव अतिक्रमण से घिरे अलग-थलग पारिस्थितिक द्वीपों में बदल दिया है।
- वन्यजीव गलियारों पर बोझ: क्योंकि मानव-प्रभुत्व वाले परिदृश्यों में वन छोटे होते हैं, वे 275 मिलियन भारतीय नागरिकों से एक अस्थिर निष्कर्षण बोझ वहन करते हैं जो दैनिक जरूरतों के लिए उन पर निर्भर हैं। यह गिरावट सीधे तौर पर संरक्षित क्षेत्रों के बीच प्रवास करने के लिए बड़े स्तनधारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन्यजीव गलियारों को खतरे में डालती है।

सकारात्मक संकेतक: समुदाय के नेतृत्व वाली संरक्षण सफलताएँ:

- हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम (अरुणाचल प्रदेश): नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित, इस पहल ने पूर्व निशी जनजाति के शिकारियों को सशुल्क घोंसला रक्षक और वन गश्ती दल में बदल दिया, जिससे महत्वपूर्ण एवियन आवासों की सफलतापूर्वक सुरक्षा हुई।
- मैंग्रोव सह-प्रबंधन समितियाँ (महाराष्ट्र): सिंधुदुर्ग जिले में ग्राम-आधारित समूह स्थायी जलकृषि, इकोटूरिज्म और स्थानीय मत्स्य पालन को सफलतापूर्वक चलाते हुए नाजुक मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की सक्रिय रूप से रक्षा करते हैं।
- हिम तेंदुआ संरक्षण पहल (लद्दाख): इस कार्यक्रम ने समुदाय द्वारा संचालित होमस्टे और समुदाय समर्थित पशुधन बीमा योजनाओं को शुरू करके मानव-वन्यजीव संघर्ष के नुकसान को सफलतापूर्वक कम किया है।
- लक्षित स्वच्छ ऊर्जा वितरण: भारत भर में राज्य वन विभागों ने वन ईंधन की लकड़ी पर स्थानीय निर्भरता को कम करने के लिए टाइगर रिजर्व के आसपास सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन, कुशल खाना पकाने के स्टोव और स्वच्छ हीटर व्यवस्थित रूप से वितरित किए हैं।



सह-प्रबंधित वानिकी में प्रमुख चुनौतियाँ:

- असंगत संस्थागत वित्तपोषण: नेक इरादे वाले राज्य कल्याण वितरण को अक्सर अनियमित वित्त पोषण चक्रों का सामना करना पड़ता है, जो दीर्घकालिक वैकल्पिक आजीविका समर्थन को रोकते हैं।
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी के परिवर्तनशील स्तर: वैकल्पिक आजीविका अपनाने के लिए अभिन्न पंक्ति के वन समुदायों की इच्छा क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है।
- वन्यजीव पर्यटन राजस्व का असममित वितरण: वन्यजीव पर्यटन भारत में एक बहु-मिलियन डॉलर के उद्योग के रूप में विकसित हुआ है, फिर भी इस राजस्व का केवल एक छोटा सा हिस्सा वास्तव में इन संरक्षित क्षेत्रों के साथ सीधे रहने वाले समुदायों तक पहुंचता है।
- पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का बहिष्करण: आधुनिक संरक्षण ढांचे अक्सर स्वदेशी समुदायों की मूल्यवान अंतर्दृष्टि को नजरअंदाज कर देते हैं जो पीढ़ियों से जंगलों के किनारे रहते हैं, वैज्ञानिक रणनीतियों के पूरक के अवसरों को खो देते हैं।

आगे की राह:

- वन्यजीव गलियारों के लिए सब्सिडी का विस्तार: राज्य ईंधन-प्रतिस्थापन कार्यक्रमों (जैसे सब्सिडी वाले एलपीजी और सौर हीटर) को अभयारण्य सीमाओं से पहले निजी भूमि और महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों के साथ स्थित सामुदायिक वनों तक विस्तारित करना।
- पर्यटन राजस्व को वन समुदायों को वापस निर्देशित करना: राष्ट्रीय उद्यानों के वित्तीय ढांचे में सुधार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इको-पर्यटन राजस्व का एक महत्वपूर्ण, कानूनी रूप से अनिवार्य हिस्सा सीधे ग्राम विकास निधि में प्रवाहित हो।
- माधव गाडगिल के समावेशी दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना: बहिष्करण प्रथाओं से एक समावेशी ढांचे में बदलाव जो स्थानीय समुदायों को औपचारिक कटाई अधिकार, आर्थिक प्रोत्साहन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में एक सार्थक भूमिका देता है।
- हाइपरलोकल समुदाय-संचालित उद्यमों को बढ़ाना: सफल क्षेत्रीय मॉडल का विस्तार करना- जैसे कि लद्दाख के सामुदायिक होमस्टे और सिंधुदुर्ग की जलीय कृषि समितियां- वन-किनारे वाले गांवों के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचे में।

निष्कर्ष:

नेचर सस्टेनेबिलिटी अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि गरीबी पर युद्ध और जैव विविधता संरक्षण के लिए लड़ाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कठोर, बहिष्करण वाले किले के मॉडल पर भरोसा करना अब मानव-प्रभुत्व वाले परिदृश्य में टिकाऊ नहीं है जहां 275 मिलियन लोग वन संसाधनों पर निर्भर हैं।

स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक

संदर्भ:

आईसीएआर-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईओआर) ने एक अभिनव, पेटेंट बायोपॉलिमर-आधारित स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक विकसित की है जो फसल की स्थापना और जलवायु तनाव के खिलाफ लचीलापन में सुधार करती है।

स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक

स्मार्ट सीड कोटिंग तकनीक के बारे में:

यह क्या है?

- स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी एक भारतीय-पेटेंट, बायोडिग्रेडेबल बीज वृद्धि मंच है। यह पारंपरिक एकल-उद्देश्य बीज उपचार को एक बहुक्रियाशील सुरक्षा कवच के साथ बदल देता है जो फसल के विकास के शुरुआती चरणों से बीज के प्रदर्शन में सुधार करता है।
- इस तकनीक को हैदराबाद स्थित ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR) द्वारा डिजाइन और वैज्ञानिक रूप से मान्य किया गया था।

उद्देश्य:

- प्रौद्योगिकी का उद्देश्य जलवायु-अनुकूल कृषि को मजबूत करना, वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों में उत्पादन जोखिम को कम करना और समग्र फसल उत्पादकता को बढ़ाना है।
- यह अनियमित मानसून, सूखा, तापमान में वृद्धि, मिट्टी के क्षरण और कीट के दबाव के खिलाफ उभरते अंकुरों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

यह कैसे काम करता है और प्रमुख विशेषताएं:

- स्तरित एनकैप्सुलेशन: कच्चे बीज को पर्यावरण के अनुकूल, बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर के साथ लेपित किया जाता है जो एक अनुकूलित खोल बनाते हैं।
- इनपुट एकीकरण: यह परत एक स्थानीय वाहक के रूप में कार्य करती है, लाभकारी सूक्ष्मजीवों, प्राथमिक पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों, फसल सुरक्षा एजेंटों और पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले यौगिकों को एक साथ पैक करती है।



- माइक्रोएन्वायरमेंट सक्रियण: एक बार बोने के बाद, कोटिंग मिट्टी की नमी के साथ प्रतिक्रिया करके बीज-मिट्टी के इंटरफेस पर एक सुरक्षात्मक सूक्ष्म वातावरण बनाती है।
- लक्षित रिलीज: एम्बेडेड जैविक और पोषक तत्व अंकुरण के दौरान सीधे जड़ क्षेत्र में निकलते हैं, जिससे जड़ों का विकास तेजी से होता है और अंकुर को पोषण तक तत्काल पहुंच मिलती है।

प्रमुख विशेषताएं:

- पेटेंट बायोपॉलिमर बेस: पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल, पॉलिमर-आधारित वाहक प्रणाली का उपयोग करता है जो मिट्टी के क्षरण या रासायनिक प्रदूषण के बिना स्वाभाविक रूप से टूट जाता है।
- ऑल-इन-वन इनपुट डिलीवरी: पारंपरिक, एकल-उद्देश्य बीज उपचार के विपरीत, यह प्लेटफॉर्म सुरक्षा, पोषण और जैविक समर्थन को एक ही एप्लिकेशन में एकीकृत करता है।
- अत्यधिक अनुकूलन योग्य डिजाइन: फॉर्मूलेशन को अनाज, बाजरा, दालें, तिलहन, फाइबर फसलें, चारा फसलों, सब्जियों, मसालों और अन्य बागवानी किस्मों की विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है।
- सिद्ध प्रदर्शन लाभ: मक्का, चना, कपास, सरसों और अरहर सहित विभिन्न फसलों में बहु-स्थान एआईसीआरपी-बीज परीक्षणों ने अनुपचारित नियंत्रणों पर 12% से 37% तक लगातार उत्पादकता लाभ दिखाया।
- संस्थागत परिनियोजन रणनीति: राज्य बीज विकास निगमों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और निजी बीज नेटवर्क के साथ साझेदारी करके बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक अपनाने के लिए बनाया गया है।



LK ACADEMY[®]
 YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

भारत की विकसित अंतरिक्ष वास्तुकला

संदर्भ:

पत्रसूचना कार्यालय (पीआईबी) ने पिछले बारह वर्षों में एक शीर्ष स्तरीय वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत के रणनीतिक परिवर्तन का विवरण देते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।

आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से प्रेरित, यह विकास निजी क्षेत्र के व्यावसायीकरण और अंतरिक्ष-आधारित नागरिक कल्याण के साथ उत्तम प्रभाव वाले अंतरग्रहीय अन्वेषण को संतुलित करता है।

भारत की विकसित अंतरिक्ष वास्तुकला

भारत की विकसित अंतरिक्ष वास्तुकला के बारे में:

यह क्या है?

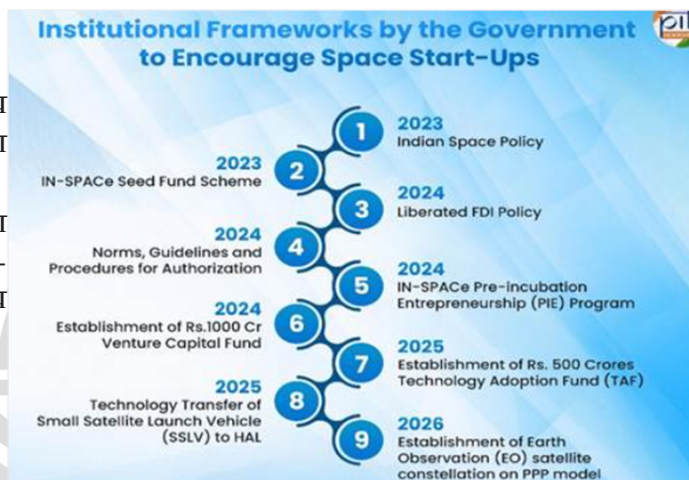
- भारत की आधुनिक अंतरिक्ष वास्तुकला एक बंद, विशुद्ध रूप से राज्य द्वारा संचालित वैज्ञानिक प्रयास से एक जीवंत, दोहरे उद्देश्य वाले पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित हो गई है जो राष्ट्रीय विकास को शक्ति प्रदान करता है।
- यह अद्यतन खाका घरेलू शासन, कृषि मानचित्रण, आपदा प्रबंधन और दूरसंचार को अनुकूलित करने के लिए अंतरिक्ष-आधारित भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है।

पैमाने और विस्तार की ओर इशारा करने वाले प्रमुख डेटा और आँकड़े:

- वाणिज्यिक राजस्व वेग: संस्थागत सुधारों द्वारा समर्थित, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का राजस्व लगभग दस गुना बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹321.77 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹3,246.09 करोड़ हो गया।
- घातीयस्टार्टअप विकास: घरेलू अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र 2014 में सिर्फ एक पंजीकृत उद्यम से बढ़कर फरवरी 2026 तक 400 से अधिक सक्रिय फर्मों तक पहुंच गया, जिससे कुल निजी निवेश में 500 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ।
- वैश्विक प्रक्षेपण विश्वसनीयता: अंतरराष्ट्रीय बाजार के अपार विश्वास का प्रदर्शन करते हुए, भारत ने 2014 और मार्च 2026 के बीच 399 विदेशी उपग्रहों को तैनात करने के लिए अपनी वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्षमता को बढ़ाया, जबकि 2014 से पहले केवल 35 प्रक्षेपण किए गए थे।
- उदारीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): अद्यतन नीति विनिर्माण घटकों के लिए 100% तक, उपग्रह संचालन के लिए 74% तक और निजी लॉन्च वाहनों और स्पेसपोर्ट के लिए 49% तक स्वचालित मार्ग FDI की अनुमति देती है।
- व्यापक डीप-स्पेस प्रसार: भारत की पहली समर्पित सौर वेधशाला, आदित्य-एला। ने वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में निरंतर सौर अवलोकन डेटा के 27 से अधिक टेरबाइट्स (टीबी) को सफलतापूर्वक संसाधित और जारी किया है।

वर्तमान अंतरिक्ष शासन और संस्थागत वास्तुकला:

- यूनिफाइड रेगुलेटरी गेटवे (IN-SPACe): एक स्वायत्त सिंगल-विंडो तंत्र के रूप में स्थापित, IN-SPACe निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों को सुविधा, अधिकृत और विनियमित करता है, जो पहले ही घरेलू उद्योगों को 71 ISRO प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मंजूरी दे चुका है।
- विधायी खाका (भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023): निश्चित कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसने स्पष्ट रूप से राज्य के एकाधिकार को तोड़ दिया, उपग्रह निर्माण, पेलोड लॉन्च और भू-स्थानिक डाउनस्ट्रीम सेवाओं में निजी भागीदारी को वैध बनाया।
- NSIL के माध्यम से व्यावसायीकरण: स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टैक के व्यावसायीकरण के लिए समर्पित राज्य के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट शाखा के रूप में कार्य करता है, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से लॉन्च वाहनों का निर्माण करता है, और उपग्रह सेवाओं को बेचता है।
- स्वायत्त नेविगेशन आत्मनिर्भरता (NavIC): भारत भारत को कवर करने के लिए पहली और दूसरी पीढ़ी (NVS) उपग्रहों के अनुकूलित समूह का उपयोग करके अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन नेटवर्क का संचालन करता है और इसकी सीमाओं से परे 1,500 किलोमीटर तक का संचालन करता है।
- मानकीकृत निजी प्रोटोकॉल (NGP 2024): मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रिया ढांचे की शुरुआत स्पष्ट पात्रता और अनुपालन पैरामीटर प्रदान करती है, जिससे निवेशकों का विश्वास और पूर्वानुमेयता बढ़ती है।



आगामी और भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रम:

- अपने अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए, भारत का प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पूरी तरह से स्वदेशी जीवन-समर्थन ब्रिड का उपयोग करके तीन दिनों तक तीन अंतरिक्ष यानियों को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजेगा।
- भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएसएस): लो अर्थ ऑर्बिट में भारत का नियोजित मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर 2028 तक अपने मूलभूत मॉड्यूल, बीएसएस-01 की तैनाती को मंजूरी दे दी है।
- चंद्रयान-4 नमूना वापसी मिशन: 2027 में लॉन्च के लिए प्रोग्राम किया गया, यह जटिल मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, भौतिक कोर नमूने निकालेगा और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चंद्रमा से एक स्वायत्त प्रक्षेपण निष्पादित करेगा।
- वीनस ऑर्बिटर मिशन: केंद्र सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित और मार्च 2028 में लॉन्च के लिए लक्ष्यित, यह अंतरिक्ष यान शुक्र के उच्च तापमान वाले वातावरण और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए उन्नत एरोब्रेकिंग और थर्मल शील्ड तैनात करेगा।
- चंद्रयान-5/LUPEX सहयोग: इसरो और जापान के जाक्सा के बीच 2027-28 के लिए एक संयुक्त डीप-स्पेस एक्सप्लोरेशन पहल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी की बर्फ जमा करने के लिए ड्रिल करने के लिए एक भारतीय लैंडर और एक जापानी रोवर को तैनात करने के लिए निर्धारित है।
- नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV): LEO में 30 टन तक तैनात करने में सक्षम एक हेवी-लिफ्ट रॉकेट का विकास, कम लागत वाली अंतरिक्ष पहुंच प्राप्त करने के लिए 14-टन क्षमता के साथ आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य संस्करण के साथ।
- तृष्णा थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट: वैश्विक फसल जल तनाव और शहरी ताप द्वीपों की निगरानी के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन थर्मल इन्फ्रारेड इमेजरी देने के लिए फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के साथ विकसित एक संयुक्त 2026 जलवायु-विज्ञान मिशन।

अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ:

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में मामूली पदचिह्न: बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद, भारत की पूर्ण अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य वर्तमान में 8 बिलियन डॉलर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का केवल 2% से 3% हिस्सा है।
- प्रयोगशालाओं को बड़े पैमाने पर एयरोस्पेस उत्पादन में बदलना: अत्यधिक जटिल, राज्य-डिज़ाइन किए गए घटकों को स्केल की गई वाणिज्यिक लाइनों में बदलने के लिए निजी क्षेत्र की गहरी विनिर्माण क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
- उच्च ऊंचाई वाले माइक्रोब्रैविटी लाइफ सपोर्ट जोखिमों का प्रबंधन: मानव अस्तित्व, कैप्सूल री-एंट्री और स्पेस डॉकिंग के लिए पूरी तरह से विश्वसनीय, शून्य-विफलता प्रणाली विकसित करना एक चल रही तकनीकी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है।
- ग्रहों की जांच के लिए गंभीर तापीय सीमाओं को कम करना: शुक्र के अत्यधिक वायुमंडलीय दबाव और अम्लीय गर्मी की स्थिति के अंदर रोबोटिक सुइट्स का संचालन जटिल सामग्री विज्ञान नवाचारों की मांग करता है।
- लगातार बहु-वर्षीय घरेलू फंडिंग को सुरक्षित करना: एक साथ गहरे अंतरिक्ष कार्यक्रमों, मानव प्रक्षेपण, और महंगे नए लॉन्चपैड बुनियादी ढांचे को बनाए रखना राज्य के बजट पर भारी राजकोषीय मांग रखता है।

आगे की राह:

- 2030 वैश्विक बाजार लक्ष्य को प्राप्त करना: 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 8% हिस्सेदारी के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी उत्पादन गहराई का विस्तार करना और टर्नअराउंड लॉन्च करना।
- दूसरे और तीसरे लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन: छोटे उपग्रहों के लिए कुलशेखरपट्टिनम में भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट को तेजी से पूरा करना और श्रीहरिकोटा में नए स्वीकृत ₹3,984.86 करोड़ के तीसरे लॉन्च पैड का निर्माण करना।
- वैश्विक वाणिज्यिक हंडसेट में एनएवीआईसी को एकीकृत करना: क्षेत्रीय पोजिशनिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार करते हुए, स्वदेशी एनएवीआईसी नेविगेशन चिपसेट को मुख्यधारा के वैश्विक स्मार्टफोन में एम्बेड करने के लिए ग्लोबल कॉम के साथ साझेदारी का लाभ उठाएं।
- पुनः प्रयोज्य शॉटलिंग प्रणोदन प्रणाली की तैनाती: पंखों वाले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन (आरएलवी-टीडी) की प्रायोगिक उड़ानों को बढ़ाएं और प्रति किलोग्राम कक्षीय पेलोड लागत को कम करने के लिए बूटस्ट्रैप इग्निशन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करें।
- वैश्विक पड़ोस को गहरा करना पहले साझा डेटा लिंक: क्षेत्रीय उपग्रह कार्यक्रमों का विस्तार करना - जैसे कि दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट -9) का उपयोग करना - भागीदार देशों को मुफ्त टेलीमेट्रिक्स, डिजिटल शिक्षा और प्रारंभिक आपदा अलर्ट प्रदान करने के लिए।

निष्कर्ष:

उदासीकृत एफडीआई नियमों और मजबूत स्टार्टअप ढांचे के साथ चंद्रयान-3 जैसे ऐतिहासिक गहरे अंतरिक्ष अन्वेषणों का समर्थन करके, देश ने वाणिज्यिक आर्थिक इंजनों के साथ विशिष्ट विज्ञान का सफलतापूर्वक मिलान किया है। आगे बढ़ते हुए, अगली पीढ़ी के पुनः प्रयोज्य रॉकेटों का निर्माण और राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना 2047 से पहले वैश्विक अंतरिक्ष शासन में भारत के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

प्रोजेक्ट निंबस

संदर्भ:

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के मुख्य भाषण के दौरान, 100 से अधिक छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडे लेकर और केफिया पहने हुए गूगल के प्रोजेक्ट निंबस अनुबंध का विरोध करते हुए वॉकआउट किया।

प्रोजेक्ट निंबस

प्रोजेक्ट निंबस के बारे में:

यह क्या है?

- प्रोजेक्ट निंबस एक विशाल, उच्च सुरक्षा वाला क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध है जो इजरायल सरकार और प्रमुख अमेरिकी प्रौद्योगिकी निगमों के बीच हस्ताक्षरित है। साझेदारी ने नैतिक चिंताओं पर तीव्र वैश्विक विरोध, कर्मचारी धरना, और छात्र के नेतृत्व वाले बहिष्कार को जन्म दिया है कि बिग टेक राज्य-प्रायोजित निगरानी और सैन्य अभियानों को सक्षम कर रहा है।
- द्वारा विकसित: Google (Google क्लाउड प्लेटफॉर्म) और Amazon (Amazon Web Services – AWS) द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित।

उद्देश्य:

- प्रोजेक्ट निंबस का उद्देश्य राज्य डेटा, प्रसंस्करण प्रणालियों और स्थानीय अनुप्रयोगों को वाणिज्यिक क्लाउड पारिस्थितिक तंत्र में स्थानांतरित करके इजरायल के सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को डिजिटलाइज़ और आधुनिक बनाना है।
- इसका उद्देश्य सरकारी संचालन के सभी स्तरों में उन्नत डेटा भंडारण, उच्च-गणना मशीन लर्निंग टूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेवाएं प्रदान करना है।

अनुबंध की मुख्य विशेषताएं:

- वित्तीय और अस्थायी पैमाना: व्यापक तकनीकी समझौते का मूल्य \$1 बिलियन से अधिक है। इसमें सात साल की प्रारंभिक परिचालन आधार रेखा है, जिसमें कानूनी खंड इजरायली सरकार को इसे 23 साल तक बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
- सॉफ्टवेयर-रेंस्ट्रिक्शन क्लॉज: लीक हुए कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों से पता चलता है कि इजरायल ने Google और Amazon को क्लाउड सेवाओं को बंद करने या सरकारी इकाइयों तक सीमित करने से रोकने के लिए एक सख्त खंड को अनिवार्य किया है - भले ही वे इकाइयों तकनीकी कंपनियों की मानक कॉर्पोरेट सेवा शर्तों का उल्लंघन करती हों।
- एआई और मशीन लर्निंग एकीकरण: अक्टूबर 2023 से, सेना इकाइयों ने उन्नत डेटा भंडारण और एआई क्षमताएं हासिल करने के लिए Google क्लाउड, AWS और Azure से अपनी तकनीकी सेवा मांगों को काफी बढ़ा दिया है।
- स्वतंत्रसंप्रभु संचालन: सेटअप इजरायल के भीतर स्थानीयकृत क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर नोड्स स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि डेटा प्रोसेसिंग, भंडारण और सर्वर प्रशासन प्रत्यक्ष विदेशी कॉर्पोरेट हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहे।

विवाद:

- रिपोर्टों से पता चलता है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म निगरानी डेटा भंडारण का समर्थन कर सकते हैं, जिससे यह चिंता बढ़ जाती है कि वाणिज्यिक डिजिटल बुनियादी ढांचा अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य अभियानों में सहायता कर सकता है।
- प्रोजेक्ट निंबस ने कर्मचारियों के विरोध, धरना, और कार्यस्थल की सक्रियता को ट्रिगर किया है, जो तकनीकी कंपनियों के रक्षा-संबंधी अनुबंधों पर बढ़ती नैतिक चिंताओं को दर्शाता है।

अमोनिया गैस

संदर्भ:

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक निजी समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात सुविधा में अमोनिया गैस के रिसाव से ओडिशा के दो प्रवासी श्रमिकों की दुखद मौत हो गई और 60 से अधिक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।



अमोनिया गैस

अमोनिया गैस के बारे में:

यह क्या है?

- अमोनिया (NH₃) नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना एक मूलभूत, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अकार्बनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन, तीखी गैस है जो पर्यावरण के भीतर स्वाभाविक रूप से ट्रेस मात्रा में मौजूद है - कार्बनिक नाइट्रोजनस पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न होती है - लेकिन इसके बहुमुखी रासायनिक गुणों के कारण विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक पैमाने पर निर्मित होती है।

अमोनिया का निर्माण:

- प्राकृतिक गठन: नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रोजन-फिक्सिंग मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों, पशु अपशिष्ट और मृत पौधों के अपघटन के माध्यम से अमोनिया का उत्पादन स्वाभाविक रूप से किया जाता है।
- औद्योगिक संश्लेषण (हैबर-बॉश प्रक्रिया): व्यावसायिक रूप से, अमोनिया का उत्पादन उच्च दबाव (150-250 वायुमंडल) और लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400-500 डिग्री सेल्सियस के तापमान के तहत हाइड्रोजन (H₂) के साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन (N₂) को प्रतिक्रिया करके किया जाता है।
- $$\text{N}_2 (\text{g}) + 3\text{H}_2 (\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3 (\text{g})$$

प्रमुख रासायनिक और भौतिक विशेषताएं:

- अत्यधिक तीखी गंध: अमोनिया में एक तेज, परेशान करने वाली गंध होती है जिसे बहुत कम सांद्रता में भी पता लगाया जा सकता है।
- असाधारण जल घुलनशीलता: यह आसानी से पानी में घुल जाता है और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड (NH₄OH) बनाता है, जो एक क्षारीय घोल है जो आंखों, त्वचा और श्वसन पथ में जलन पैदा कर सकता है।
- अनुकूल तापीय गुण: अमोनिया को दबाव में आसानी से तरलीकृत किया जा सकता है और इसमें उच्च गर्मी अवशोषण क्षमता होती है, जिससे यह एक कुशल रेफ्रिजेंट बन जाता है।
- संक्षारक प्रकृति: हालांकि आम तौर पर गैर-ज्वलनशील, केंद्रित अमोनिया सीमित स्थानों में खतरनाक हो सकता है और तांबे और पीतल जैसी धातुओं को खराब कर सकता है।

अमोनिया के प्रमुख अनुप्रयोग:

- औद्योगिक प्रशीतन: अमोनिया का व्यापक रूप से कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, बर्फ संयंत्रों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रेफ्रिजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके उत्कृष्ट गर्मी अवशोषण गुण होते हैं।
- उर्वरक उत्पादन: यह नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम फॉस्फेट के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में कार्य करता है।
- रासायनिक विनिर्माण: अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक एसिड, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, विस्फोटक और औद्योगिक रंगों के उत्पादन में किया जाता है।
- सफाई और जल उपचार: पतला अमोनिया समाधान औद्योगिक सफाई एजेंटों के रूप में और क्लोरीनीकरण और शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के लिए जल उपचार संयंत्रों में उपयोग किया जाता है।

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन

संदर्भ:

दक्षिणी लेबनान में हाल ही में युद्धविराम के बाद, हिजबुल्लाह मिलिशिया द्वारा कम लागत वाले फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन की रणनीतिक तैनाती ने असममित युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया है।

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन

फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन के बारे में:

यह क्या है?

- फाइबर-ऑप्टिक ड्रोन एक विशेष प्रकार का प्रथम-व्यक्ति दृश्य (एफपीवी) या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) है जो पारंपरिक वायरलेस रेडियो नियंत्रण को भौतिक, बंधे हुए फाइबर-ऑप्टिक लिंक से बदल देता है।
- खुली हवा के रेडियो संकेतों के बजाय भौतिक किरमों के माध्यम से प्रकाश दालों के माध्यम से डेटा संचारित करके, ये शिल्प व्यावहारिक रूप से अदृश्य ड्रोन के रूप में कार्य करते हैं जो पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स, स्पाफ़िंग और रडार डिटेक्शन के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

- भौतिक टेडरिंग: ड्रोन को कांच या प्लास्टिक के धागों से बने अल्ट्रा-पतली, उच्च शक्ति और बालों जैसी नेटवर्क केबल के माध्यम से भौतिक रूप से अपने ऑपरेटर से जोड़ा जाता है।



- स्पूल परिनियोजन: ऑप्टिकल केबल को एक विशेष स्पूल पर कसकर लपेटा जाता है, जो एक सुरक्षात्मक खोल में बंद होता है, और सीधे ड्रोन चेसिस पर लगाया जाता है। जैसे ही ड्रोन उड़ान भरता है और आगे बढ़ता है, लाइन हवा के बीच में उसके पीछे आसानी से खुल जाती है।
- प्रकाश के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन: ऑपरेटर के कमांड और ड्रोन से रीयल-टाइम वीडियो फीड को प्रकाश की उच्च गति दालों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रकाश शून्य परिचालन अंतराल के साथ केबल के माध्यम से आगे और पीछे यात्रा करता है, वास्तविक समय की निगरानी और उच्च-बैंडविड्थ प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
- वायरलेस ट्रेस का उन्मूलन: क्योंकि सभी संचार भौतिक तार के अंदर निहित हैं, ड्रोन कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) हस्ताक्षर नहीं करता है और नेविगेट करने के लिए जीपीएस जैसे कमजोर उपग्रह प्रणालियों पर निर्भर नहीं करता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- आरएफ जैमिंग के लिए पूर्ण प्रतिरक्षा: क्योंकि उनके पास एक खुले रेडियो रिसीवर की कमी है, ये ड्रोन पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आरएफ का पता लगाने और सिग्नल स्पूफिंग को पूरी तरह से बायपास करते हैं।
- उच्च-बैंडविड्थ, रीयल-टाइम वीडियो: फाइबर-ऑप्टिक कनेक्शन वायरलेस सिस्टम के लिए सामान्य ट्रांसमिशन देरी के बिना भारी मात्रा में डेटा और स्पष्ट वीडियो फीड के तात्कालिक प्रसारण की अनुमति देता है।
- परिचालन रेंज और गति: प्रारंभिक मॉडल लगभग 5 किमी की छोटी दूरी पर संचालित होते थे, लेकिन उन्नत पुनरावृत्तियों ने अत्यधिक वायुगतिकीय ड्रैग के बिना 20 से 30 किमी की दूरी तक अपनी परिचालन पहुंच बढ़ा दी है।
- शून्य आरएफ हस्ताक्षर: रेडियो उत्सर्जन की अनुपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयों को ड्रोन के पथ को ट्रैक करने या ऑपरेटर के स्थान को इंगित करने से रोकती है।
- उभयचर सभी मौसम में कमजोरियां: अपने हल्के संरचनात्मक फ्रेम के कारण, ये ड्रोन भारी बारिश और तेज हवाओं जैसे गंभीर मौसम के प्रति संवेदनशील रहते हैं। वे तुरंत सभी कार्यक्षमता भी खो सकते हैं यदि पतला टीडर पेड़ों या इमारतों जैसी भौतिक बाधाओं पर टूट जाता है।

केंद्र ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा पर प्रतिबंध लगाया

संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे भारत में 16 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो तुरंत प्रभावी है।

केंद्र ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा पर प्रतिबंध लगाया

केंद्र ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा पर प्रतिबंध लगाया:

फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) क्या हैं?

- फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) एक फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन है जिसमें दो या दो से अधिक सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व (एपीआई) होते हैं जो एक टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के भीतर एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। इसे उपचार को सरल बनाने और रोगी अनुपालन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एफडीसी कैसे बनते हैं?

- एफडीसी चिकित्सीय परिणामों में सुधार और गोली के बोझ को कम करने के लिए कई सक्रिय दवाओं को एक खुराक के रूप में जोड़कर निर्मित होते हैं।
- हालांकि, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी वाले तर्कहीन संयोजन प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकते हैं और रोगाणुरोधी प्रतिरोध में तेजी ला सकते हैं।

कानून और नियामक ढांचा:

- औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए केंद्र सरकार को असुरक्षित, चिकित्सीय मूल्य की कमी या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित, विनियमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

प्रतिबंध की मुख्य विशेषताएं:

- व्यापक चिकित्सीय कवरेज: प्रतिबंध में 16 तर्कहीन एफडीसी शामिल हैं, जिनमें कुछ त्वचा क्रीम, दर्द निवारक, एंटीस्परामोडिक्स और एंटीबायोटिक संयोजन शामिल हैं, जिनमें प्रतिकूल जोखिम-लाभ प्रोफाइल पाई गई थी।
- तत्कालराष्ट्रव्यापी प्रवर्तन: प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, जिससे निर्माताओं और वितरकों को बाजार से मौजूदा स्टॉक की निकासी सुनिश्चित करते हुए उत्पादन, बिक्री और वितरण को रोकने की आवश्यकता हुई।



- एक बड़े सुरक्षा अभियान का हिस्सा: यह कार्रवाई असुरक्षित दवाओं पर सरकार की व्यापक कार्रवाई का अनुसरण करती है, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षा चिंताओं से जुड़े कुछ ओटीसी औषधीय सिरप पर प्रतिबंध शामिल हैं।

महत्व:

- तर्कहीन दवा संयोजनों को हटाकर रोगी की सुरक्षा को मजबूत करता है जिसमें सिद्ध चिकित्सीय मूल्य की कमी होती है और हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
- तर्कहीन एंटीबायोटिक संयोजनों को प्रतिबंधित करके और आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को संरक्षित करके रोगानुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटने में मदद करता है।

प्रिलिम्स इन फोकस : सरकारी विधेयक और अधिनियम

संदर्भ:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दो प्रमुख ब्रांडों-श्रीमती बेवटर और स्टोरिया-प्रत्येक को उनकी फ्रंट पैकेजिंग पर भ्रामक 100% उत्पाद दावों को चलाने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में:

यह क्या है?

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 कल्याणकारी कानून का एक व्यापक, आधुनिक हिस्सा है जिसने विरासत 1986 अधिनियम का स्थान ले लिया है। यह भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, लागू और सुरक्षा के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करता है, जो ई-कॉमर्स, डिजिटल विज्ञापन और भ्रामक पैकेजिंग जैसी समकालीन खुदरा चुनौतियों को अपनाता है।
- नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।
- कार्यकारी शाखा: अधिनियम ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को एक शक्तिशाली नियामक प्रहरी के रूप में स्थापित किया।

उद्देश्य:

- औपचारिक रूप से बाजार के बोझ को कैविएट एम्प्टर (खरीदार को सावधान रहने दें) से कैविएट वेंडरिटर (विक्रेता को सावधान रहने दें) से स्थानांतरित करने के लिए।
- भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए जो उपभोक्ता वस्तुओं के मानक, शुद्ध संरचना या गुणवत्ता का गलत तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुलभ, बहु-स्तरीय उपभोक्ता विवाद आयोगों की स्थापना करके उपभोक्ता शिकायत निवारण को सरल बनाना।

अधिनियम की मुख्य कानूनी विशेषताएं

- भ्रामक विज्ञापनों की परिभाषा (धारा 2(28)): स्पष्ट रूप से किसी भी विज्ञापन या पैकेजिंग दावे को शामिल करता है जो किसी उत्पाद का गलत वर्णन करता है, झूठी गारंटी देता है, या जानबूझकर उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण सामग्री जानकारी छुपाता है।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं की परिभाषा (धारा 2(47)): उत्पादों के मानक, ब्रेड, शैली, शुद्ध संरचना या गुणवत्ता के बारे में किसी भी झूठे या भ्रामक प्रतिनिधित्व को अवैध व्यापार अभ्यास के रूप में वर्गीकृत करता है।
- स्वतः प्रेरणा हस्तक्षेप शक्ति: सीसीपीए को औपचारिक उपभोक्ता शिकायत की आवश्यकता के बिना झूठे विपणन अभियानों का स्वतंत्र रूप से स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देता है।
- सख्त दंड ढांचा: प्राधिकरण को भारी वित्तीय दंड (जैसे कि आपत्तिजनक खाद्य ब्रांडों के खिलाफ लगाया गया ₹1 लाख का जुर्माना) लगाने और भ्रामक उत्पाद लेबल को तत्काल बंद करने का आदेश देने की शक्ति देता है।
- ई-कॉमर्स और डार्क पैटर्न गवर्नेंस: ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सख्त दायित्व बढ़ाता है, छिपी हुई लागतों, हेरफेर करने वाले यूजर इंटरफेस (डार्क पैटर्न) और नकली समीक्षाओं के खिलाफ कानूनी सुरक्षा पेश करता है।

महत्व:

- सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि एफएसएसआई मानकों का अनुपालन भ्रामक विज्ञापनों को उचित नहीं ठहराता है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपणन दावे सच्चे हों और भ्रामक न हों।
- यह निर्णय स्थापित करता है कि फाइन-प्रिंट खुलासे भ्रामक फ्रंट-लेबल दावों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। यह पारदर्शी लेबलिंग को मजबूत करता है और उपभोक्ताओं को भ्रामक विपणन से बचाता है।



परमाणु ऊष्मा-आधारित Cu-Cl हाइड्रोजन सुविधा

संदर्भ:

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने आईजीसीएआर, कलपक्कम, तमिलनाडु में दुनिया की पहली परमाणु गर्मी आधारित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है।

- यह एक स्वदेशी कॉपर-क्लोरीन (Cu-Cl) थर्मोकेमिकल जल-विभाजन प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (FBTR) से गर्मी का उपयोग करता है।

परमाणु ऊष्मा-आधारित Cu-Cl हाइड्रोजन सुविधा

परमाणु ऊष्मा-आधारित Cu-Cl हाइड्रोजन सुविधा के बारे में:

यह क्या है?

- यह सुविधा एक अग्रणी, कार्बन-मुक्त प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है जो स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए परमाणु इंजीनियरिंग और रासायनिक लूपिंग को जोड़ती है। बिजली की भूख वाले पानी के इलेक्ट्रोलिसिस पर भरोसा करने के बजाय, यह सीधे परमाणु कोर से उत्पन्न तापमान वाले ज्वालामुखीय-पैमाने की प्रक्रिया गर्मी का उपयोग करता है ताकि रासायनिक रूप से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सके।

सहयोगात्मक विकास:

यह सुविधा स्वदेशी बहु-एजेंसी समन्वय की पूर्ण विजय का प्रतिनिधित्व करती है:

- कोर प्रौद्योगिकी: कॉपर-क्लोरीन (Cu-Cl) थर्मोकेमिकल रासायनिक चक्र की अवधारणा और विकास मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया था।
- रिएक्टर इंटरफेस और कमीशनिंग: कलपक्कम में बीएआरसी और आईजीसीएआर द्वारा संयुक्त रूप से संरचनात्मक डिजाइन, इंटरफेस निर्माण और साइट-स्तरीय कमीशनिंग को निष्पादित किया गया था।

उद्देश्य:

- फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए एक गैर-विद्युत, औद्योगिक अनुप्रयोग स्थापित करके भारत के हस्ताक्षर वाले तीन-चरण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना।
- भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक अत्यधिक निरंतर, मापनीय और जलवायु-तटस्थ मार्ग का प्रदर्शन करना।

Cu-Cl थर्मोकेमिकल चक्र कैसे काम करता है?

- हाइड्रोजन उत्पादन: कॉपर (Cu) 430-475°C पर शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl) गैस के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस (H₂) का उत्पादन होता है।
- हाइड्रोलिसिस: कॉपर क्लोराइड (CuCl₂) 400°C पर अत्यधिक गरम भाप के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (Cu₂OCl₂) बनाता है, जबकि HCl गैस को पुनर्जीवित करता है।
- ऑक्सीजन उत्पादन: कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को FBTR प्रक्रिया गर्मी का उपयोग करके लगभग 500 °C तक गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन गैस (O₂) जारी करता है और क्यूप्रस क्लोराइड (CuCl) का उत्पादन करता है।
- विद्युत रासायनिक चक्र: CuCl बंद चक्र को पूरा करते हुए, तांबे (Cu) और कॉपर क्लोराइड (CuCl₂) को पुनर्जीवित करने के लिए कम-वोल्टेज इलेक्ट्रोलिसिस से गुजरता है।

कलपक्कम सुविधा की मुख्य विशेषताएं:

- एफबीटीआर द्वारा संचालित: कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) से प्रोसेस हीट का उपयोग करता है, जो भारत का एकमात्र परिचालन सोडियम-कूल्ड फास्ट रिएक्टर है।
- कम तापमान की आवश्यकता: Cu-Cl चक्र के लिए केवल 530°C के अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि सल्फर-आयोडीन चक्र के लिए यह 850°C से अधिक होता है।
- कम बिजली की खपत: इलेक्ट्रोलिसिस चरण केवल 0.5-1.0 वोल्ट पर संचालित होता है, जो पारंपरिक जल इलेक्ट्रोलिसिस (1.23 वोल्ट या अधिक) से काफी कम है।
- चौबीसों घंटे संचालन: सौर या पवन-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के विपरीत, परमाणु-संचालित प्रणाली निरंतर, मौसम-स्वतंत्र हाइड्रोजन उत्पादन प्रदान करती है।

मुख्य अनुप्रयोग:

- भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइजिंग करना: स्वच्छ हाइड्रोजन स्टील, तेल शोधन और रासायनिक उद्योगों में जीवाश्म-ईंधन-आधारित ग्रे हाइड्रोजन की जगह ले सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है।



- हरित उर्वरक उत्पादन: हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए कार्बन मुक्त हाइड्रोजन प्रदान करता है, जिससे भारत का उर्वरक उत्पादन और खाद्य सुरक्षा मजबूत होता है।
- स्वच्छ परिवहन और ऊर्जा भंडारण: ईंधन-सेल वाहनों, शिपिंग, विमानन और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए हाइड्रोजन की आपूर्ति करता है।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली

संदर्भ:

कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को अपने नए लागू ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में बड़े पैमाने पर विसंगतियों पर तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग

ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली के बारे में:

यह क्या है?

- ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) हस्तलिखित परीक्षा पत्रों के लिए एक डिजिटल मूल्यांकन ढांचा है। भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं को लाल पेन के साथ मैन्युअल रूप से पैक, शिप और ब्रेड करने के बजाय, पुस्तिकाओं को केंद्रों पर एकत्र किया जाता है, स्कैन किया जाता है, गुमनाम किया जाता है, और एक सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है जहां मूल्यांकनकर्ता उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल रूप से ब्रेड करते हैं।

द्वारा विकसित और प्रबंधित:

- सीबीएसई द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल मूल्यांकन बुनियादी ढांचे और ऑनमार्क पोर्टल को कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया गया था।

इतिहास:

- सीबीएसई ने पहली बार 2013-14 में ओएसएम के शुरुआती संस्करण का परीक्षण किया, जो डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण विफल हो गया।
- जून 2025 में अपने स्वयं के शासी निकाय द्वारा परीक्षण के रूप में ओएसएम को छोटी मात्रा वाले विषयों तक सीमित करने की सलाह देने के बावजूद, सीबीएसई ने पायलट चरण को दरकिनार कर दिया और 2026 में सभी विषयों में पूर्ण पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अपनाने को लागू किया।

उद्देश्य:

- सीबीएसई ने अपनी मूल्यांकन पाइपलाइन को आधुनिक बनाने के लिए पूर्ण पैमाने पर ओएसएम की शुरुआत की। घोषित उद्देश्यों में शामिल हैं:
- मैन्युअल टोटलिंग और टेबुलेशन त्रुटियों का पूर्ण उन्मूलन।
- प्रसंस्करण विंडो को 12 दिनों से 9 दिनों तक संपीड़ित करने के लिए त्वरित मूल्यांकन चक्र।
- बढ़ी हुई पारदर्शिता और परिणाम के बाद सत्यापन अनुप्रयोगों में कमी।

यह कैसे काम करता है और प्रमुख विशेषताएं:

- गुमनामीकरण: परीक्षक पूर्वाग्रह को रोकने के लिए अपलोड करने से पहले छात्र रोल नंबर और बारकोड पहचानकर्ताओं को डिजिटल रूप से नकाबपोश किया जाता है।
- डिजिटल कैनवास ब्रेडिंग: मूल्यांकनकर्ता वीडियो निगरानी के तहत एक निगरानी पोर्टल में लॉग इन करते हैं, डिजिटल टूल का उपयोग करके टिक जोड़ते हैं, उत्तरों को काटते हैं, और स्क्रीन पर चरण-वार अंक निर्दिष्ट करते हैं।
- ऑटो-टेबुलेशन: सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से प्रश्न-वार स्कोर को अंतिम मिलान में एकत्रित करता है, जिससे मैन्युअल अंकगणितीय त्रुटियों को रोका जा सकता है।
- SLA-संचालित सुरक्षा (संविदात्मक): सिस्टम में एक सख्त सर्विस लेवल एग्रीमेंट (SLA) है, जो सॉफ्टवेयर डाउनटाइम या पेज-लोडिंग लैग को ₹1 लाख प्रति 15 मिनट की दर से दंडित करता है।

ब्लू माइक्रोमून

संदर्भ:

ब्लू माइक्रोमून के रूप में जानी जाने वाली एक असामान्य खगोलीय घटना रात के आकाश में दिखाई देने लगी।

नासा के अनुसार, यह विशिष्ट पूर्णिमा वर्ष की सबसे दूर, सबसे छोटी और सबसे धुंधली थी, जो एक दोहरी घटना को चिह्नित करती है जो वर्ष 2053 तक नहीं दोहराई जाएगी।



ब्लू माइक्रोमून:**ब्लू माइक्रोमून के बारे में:****यह क्या है?**

- ब्लू माइक्रोमून दो अलग-अलग चंद्र घटनाओं की एक साथ घटना है: एक ब्लू मून (एक कैलेंडर महीने के भीतर दूसरा पूर्णिमा) और एक माइक्रोमून (एक पूर्णिमा जो अपभू के साथ मेल खाती है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा में सबसे दूर का बिंदु)।

यह कैसे बनता है?**यह घटना कक्षीय यांत्रिकी और कैलेंडर संरेखण का परिणाम है:**

- माइक्रोमून यांत्रिकी: चंद्रमा 27.3 दिन के चक्र में एक अण्डाकार (लम्बी) पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी से सबसे दूर के बिंदु को अपभू (लगभग 403,945 किमी) कहा जाता है। जब चंद्रमा का पूरी तरह से प्रकाशित चरण (पूर्णिमा) चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के थोड़े समय के भीतर संरेखित होता है, तो यह पृथ्वी पर पर्यवेक्षकों के लिए शारीरिक रूप से छोटा और मंद दिखाई देता है।
- ब्लू मून कैलेंडर उलटा: अमावस्या से अमावस्या तक मानक चंद्र चक्र में 29.5 दिन लगते हैं। क्योंकि एक मानक कैलेंडर महीना 30 या 31 दिनों तक रहता है, महीने की 1 या 2 तारीख को दिखाई देने वाली पूर्णिमा कभी-कभी दूसरी पूर्णिमा को 30 या 31 तारीख को उसी महीने में निचोड़ने की अनुमति देती है।

ब्लू माइक्रोमून बनाम स्टैंडर्ड ब्लू मून:**इन दो खगोलीय पदनामों के बीच संरचनात्मक और ऑप्टिकल अंतर अलग-अलग हैं:**

विशेषता	मानक ब्लू मून	ब्लू माइक्रोमून
मूल परिभाषा	कड़ाई से एक कैलेंडर विसंगति (एक महीने में दो पूर्णिमा)।	एक कैलेंडर विसंगति जो चरम कक्षीय दूरी के साथ संयुक्त है।
कक्षीय स्थिति	अण्डाकार कक्षा के साथ कहीं भी हो सकता है।	Apogee पर या उसके पास सरस्ती से होना चाहिए (सबसे दूर बिंदु)।
दृश्य आकार	सामान्य संरचनात्मक आयामों पर प्रकट होता है।	सुपरमून से लगभग 14% छोटा दिखाई देता है।
चमक	सामान्य वायुमंडलीय चमक।	सुपरमून की तुलना में लगभग 30% धुंधला दिखाई देता है।
विरलता	हर 2 से 3 साल में लगातार पुनरावृत्ति होती है।	अत्यधिक असामान्य; अगला संरेखण 2053 में होगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- कम चमक: एपोजी पर इसकी अत्यधिक दूरी के कारण, यह पृथ्वी पर कम केंद्रित प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे यह कैलेंडर वर्ष की सबसे मंद पूर्णिमा बन जाती है।
- कोणीय व्यास शिफ्ट: डिस्क का पूर्ण कोणीय आकार काफी संकुचित होता है, जिससे यह औसत पूर्णिमा से लगभग 7% छोटा दिखाई देता है।
- गैर-ऑप्टिकल रंग नामकरण: नीला नाम देने के बावजूद, चंद्रमा का रंग नहीं बदलता है। यह अपने मानक मोती-भूरे रंग को तब तक बरकरार रखता है जब तक कि दुर्लभ स्थानीय वायुमंडलीय धूल या ज्वालामुखीय धुआं प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य को नीला रंग देने के लिए बिखेरता है।

कोयला गैसीकरण**संदर्भ:**

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने सतही कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक रोड शो के दौरान 37,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

कोयला गैसीकरण:**कोयला गैसीकरण के बारे में:****यह क्या है?**

- कोयला गैसीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले या लिग्नाइट को तोड़ती है और सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करती है, जिसे आमतौर पर सिनगैस के रूप में जाना जाता है।
- ठोस कोयले को सीधे जलाने के बजाय (जो भारी धुआं और राख पैदा करता है), गैसीकरण उच्च तापमान और दबाव के तहत अपने मौलिक बंधनों को विभाजित करता है, ईंधन को मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ), हाइड्रोजन (एच 2), और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ 2) से बना एक स्वच्छ, गैसीय मिश्रण में बदल देता है।



यह कैसे काम करता है (रासायनिक प्रक्रिया)?

- अभिकारक फ़ीड: कच्चे कोयले को चूर्णित किया जाता है और एक विशेष गैसीकरण रिएक्टर में डाला जाता है। इसे ऑक्सीजन (या हवा) की नियंत्रित धाराओं और तीव्र गर्मी (आमतौर पर 800°C से 1400°C तक) के तहत भाप के साथ मिलाया जाता है।
- आंशिक ऑक्सीकरण और गैसीकरण: क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, कोयले में आग या दहन नहीं होता है। इसके बजाय, कार्बनिक यौगिक थर्मल क्रैकिंग और आंशिक ऑक्सीकरण से गुजरते हैं, जिससे कच्चे सिनगैस का उत्पादन होता है।

भारतीय उच्च राख समाधान (द्रवीकृत बिस्तर):

- भारतीय कोयले में असाधारण रूप से उच्च राख सामग्री (अक्सर 40% से अधिक) और अलग-अलग कैलोरी मान होते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, भारत प्रेशराइज्ड फ्लुइडाइज्ड-बेड गैसिफिकेशन (PFBG) का उपयोग करता है।
- इस प्रणाली में, ऊपर की ओर बहने वाली गैस धाराएं भारी कोयले के कणों को भौतिक रूप से उठाती हैं और निलंबित करती हैं, जिससे उबलते तरल पदार्थ जैसी स्थिति बनती है।
- यह गर्मी को कार्बन को समान रूप से गैसीकृत करने की अनुमति देता है, जबकि भारी खनिज राख को स्लैग में पिघलाए बिना नीचे से साफ रूप से निकालता है।
- स्क्रबिंग और संश्लेषण: सल्फर और टार जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए कच्चे सिनगैस को साफ किया जाता है। परिष्कृत हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को तरल ईंधन, उर्वरक या स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग करके रासायनिक रूप से पुनर्संयोजित किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- विशिष्टस्वदेशी अनुकूलन: विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व वाली भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से तैयार किया गया है ताकि घरेलू भंडार के लिए अद्वितीय जटिल खनिज पदार्थ को संभाला जा सके।
- पूंजी-गहन बुनियादी ढांचा: इन सुविधाओं के लिए भारी अभ्रिम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है और इसमें लंबी अवधि होती है, जिसमें संरचनात्मक संयंत्र और मशीनरी कॉन्फिगरेशन कुल उत्पादन लागत का लगभग 30% होता है।
- उच्च स्थानीयकरण क्षमता: भारतीय औद्योगिक दिग्गजों ने लगभग 80% से 90% आवश्यक मशीनरी का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है, जिससे समग्र सेट-अप लागत लगभग 30-40% कम हो गई है।
- उच्चकार्बन-उपयोग मूल्य: भारत के विशाल घरेलू भूवैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करता है - जिसमें लगभग 401 बिलियन टन कोयला और 47 बिलियन टन लिग्नाइट शामिल है - पारंपरिक विमनी स्टैक कालिख के बिना।

महत्त्व:

- कोयला गैसीकरण घरेलू स्तर पर यूरिया, अमोनिया और मेथनॉल का उत्पादन करने में मदद करता है, आयात को कम करता है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत करता है।
- प्रत्यक्ष कोयला जलाने की तुलना में, गैसीकरण स्वच्छ है और कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों के साथ अधिक संगत है, जो डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों में सहायता करता है।

आरटीएक्स स्पार्क चिप

संदर्भ:

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने ताइपे में कंप्यूटेक्स 2026 प्रदर्शनी में आरटीएक्स स्पार्क सुपरचिप का अनावरण किया।

आरटीएक्स स्पार्क चिप

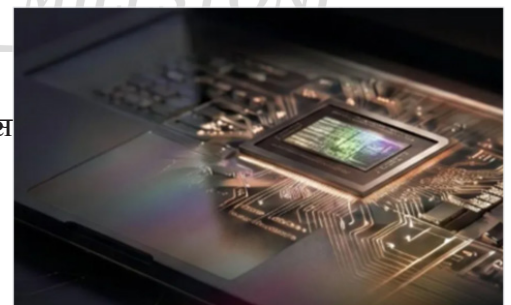
RTX स्पार्क चिप के बारे में:

यह क्या है?

- RTX स्पार्क एक सुपरचिप है - एक एकीकृत प्रोसेसर जिसे विशेष रूप से विंडोज एआई लैपटॉप और कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया है। पारंपरिक कंप्यूटरों के विपरीत जो अलग-अलग सीपीयू (इंटेल/एएमडी से) और जीपीयू (एनवीडिया से) का उपयोग करते हैं, स्पार्क दोनों को टीएसएमसी के 3-नैनोमीटर पर निर्मित एकल, उच्च-प्रदर्शन इकाई में जोड़ता है।
- द्वारा लॉन्च किया गया: चिप एनवीडिया के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उद्योग सहयोग का परिणाम है।

उद्देश्य:

- लक्ष्य पर्सनल एआई कंप्यूटरों की एक नई श्रेणी बनाना है जहां स्थानीय एआई एजेंट, मैन्युअल विलक और प्रकारों के बजाय, उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाते हैं।
- रणनीतिक रूप से, एनवीडिया का लक्ष्य डेवलपर्स को मोबाइल लैपटॉप स्तर से डेटा सेंटर तक अपने पारिस्थितिकी तंत्र में लॉक करके अपने CUDA सॉफ्टवेयर खाई का मुदीकरण करना है।



यह काम किस प्रकार करता है?

- स्पार्क NVLink-C2C (चिप-टू-चिप) तकनीक का उपयोग करता है - एक हाई-स्पीड इंटरकनेक्ट जो CPU और GPU को लगभग शून्य अंतराल के साथ एक-दूसरे से बात करने की अनुमति देता है।
- ब्लैकवेल आर्किटेक्चर GPU के साथ 20-कोर आर्म-आधारित CPU को फ्यूज करके, चिप एक एकीकृत मेमोरी बनाती है।
- यह प्रोसेसर को क्लाउड पर डेटा भेजने की आवश्यकता के बिना लैपटॉप पर स्थानीय रूप से बड़े पैमाने पर एआई मॉडल (120 बिलियन पैरामीटर तक) को संभालने की अनुमति देता है।

प्रमुख विशेषताएं

- प्रदर्शन: एआई प्रदर्शन का 1 पेटाफ्लॉप प्रदान करता है, जो इसे अब तक के सबसे शक्तिशाली उपभोक्ता चिप्स में से एक बनाता है।
- मेमोरी: 128GB तक की एकीकृत मेमोरी का समर्थन करता है, जो स्थानीय स्तर पर फ्रंटियर-स्तरीय AI मॉडल चलाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ग्राफिक्स: एलिट गेमिंग और पेशेवर रचनात्मक वर्कफ्लो के लिए 6,144 CUDA कोर के साथ एक ब्लैकवेल RTX GPU की सुविधा है।
- दक्षता: अपनी शक्ति के बावजूद, यह विंडोज-ऑन-आर्म लैपटॉप पर पूरे दिन की बैटरी लाइफ के लिए अनुकूलित है।
- सॉफ्टवेयर अनुकूलन: एडोब विशेष रूप से इस चिप के लिए फोटोशॉप और प्रीमियर को फिर से तैयार कर रहा है ताकि ग्राफिक्स प्रदर्शन को दोगुना किया जा सके।

अनुप्रयोगों:

- व्यक्तिगत एआई एजेंट: स्थानीय ऑलवेज-ऑन एजेंटों को सशक्त बनाना जो इंटरनेट निर्भरता के बिना विंडोज ऐप्स में जटिल कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं।
- जनरेटिव एआई विकास: डेवलपर्स को सीधे अपनी नोटबुक पर उच्च-पैरामीटर एआई मॉडल बनाने और परीक्षण करने की अनुमति देता है।
- व्यावसायिक रचनात्मक कार्य: एडोब क्रिएटिव क्लाउड में रीयल-टाइम 8K वीडियो संपादन और एआई-त्वरित रेंडरिंग।
- एलिट गेमिंग: पोर्टेबल गेमिंग लैपटॉप में डेटा-सेंटर स्तर ब्लैकवेल ग्राफिक्स आर्किटेक्चर लाना।

फोकस में प्रारंभिक परीक्षा: पर्यावरण

संदर्भ:

भारत में समुद्री शोधकर्ताओं ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह में कदमत द्वीप के पास अनुमानित 4,250 वर्ग मीटर में फैली द पावोना क्लावस कॉलोनी (पोर्टेनो पैच) नामक एक विशाल कोरल कॉलोनी का दस्तावेजीकरण किया है।

पावोना क्लावस कॉलोनी (आलू पैच)

पावोना क्लावस कॉलोनी (आलू पैच) के बारे में:

यह क्या है?

- आलू पैच एक असाधारण, निरंतर घास के मैदान जैसी कॉलोनी है जो पावोना क्लावस (आमतौर पर आलू कोरल के रूप में जाना जाता है) प्रजाति से संबंधित कठोर मूंगा है। यह अनोखा नाम इसके विशिष्ट स्तंभ, क्लब जैसी विकास संरचनाओं से आता है जो पानी के नीचे कसकर पैक किए गए आलू के खेत की तरह दिखते हैं।

स्थान:

- विशाल संरचना कदमत द्वीप के दक्षिण-पूर्वी तटीय जल में स्थित है, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है - भारत की एकमात्र प्रवाल द्वीप श्रृंखला।
- गठन 5.2 मीटर की गहराई पर उथले चट्टान के प्लैट पर शुरू होता है और लगभग 20 मीटर की गहराई तक एक खड़ी पानी के नीचे ढलान से नीचे गिरता है।

यह कैसे बना?

- विशाल कॉलोनी सदियों के निरंतर, निर्बाध कैल्शियम कार्बोनेट (CaCO_3) छोटे प्रवाल जंतु द्वारा जमाव का उत्पाद है।
- कैल्सीफिकेशन की शताब्दियाँ: प्रारंभिक विकास-दर मॉडलिंग के आधार पर, कॉलोनी 700 से 1,800 वर्ष पुरानी होने का अनुमान है। यह मध्ययुगीन युग के बाद से लगातार बढ़ रहा है, हालांकि स्वलेरोक्रोनोलॉजी (कोर विश्लेषण) जैसी औपचारिक तकनीकों को इसकी सटीक उम्र को इंगित करने की आवश्यकता होती है।
- हाइड्रोडायनामिक लचीलापन: एक खड़ी चट्टान ढलान पर इसके स्थान ने इसे मजबूत लहर कार्रवाई के लिए उजागर किया। सदियों से, कॉलोनी ने नाजुक शाखाओं के बजाय मोटे, भारी चूने वाले स्तंभों का निर्माण करके अनुकूलित किया, जिससे इसे समुद्री धाराओं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तीव्र यांत्रिक तनाव का सामना करने में मदद मिली।



प्रमुख विशेषताएँ:

- बड़े पैमाने पर आयाम: 4,250 वर्ग मीटर (लगभग 1.05 एकड़) के क्षेत्र को कवर करता है, जो इसे ग्रेट बैरियर रीफ (3,973 वर्ग मीटर) और सोलोमन द्वीप (1,000 वर्ग मीटर) पर प्रसिद्ध विशाल प्रवाल कॉलोनियों से बड़ा बनाता है।
- इसकी लंबाई 85 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 2.8 मीटर है।
- उत्तजीवित ऊतक अनुपात: दशकों के ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद, एक आधारभूत सर्वेक्षण से पता चला है कि कॉलोनी के 58.47% ऊतक पूरी तरह से जीवित और स्वस्थ हैं।
- संपन्न माइक्रो-इकोसिस्टम: कॉलोनी का विशाल सतह क्षेत्र विविध मछलियों के संयोजन की मेजबानी करता है, जो एटोल प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण नर्सरी और फीडिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करता है।

महत्व:

- प्रवाल प्रमुख विरंजन घटनाओं और समुद्री हीटवेव से बच गया है, जिससे यह जलवायु अनुकूलन और थर्मल सहिष्णुता का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान हो गया है।
- इसका प्राचीन कंकाल पिछले समुद्र के तापमान, समुद्र के स्तर में परिवर्तन और समुद्री स्थितियों को रिकॉर्ड करता है, जो दीर्घकालिक पैलियोक्लाइमेट रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है।
- यह खोज लक्ष्यद्वीप के पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालती है और भारत की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के मजबूत संरक्षण का समर्थन करती है।

टायलोसॉरस रेक्स**संदर्भ:**

जीवाश्म विज्ञानियों ने पहले से गलत पहचाने गए जीवाश्मों की फिर से जांच करने के बाद टायलोसॉरस रेक्स नामक बड़े पैमाने पर क्रेटेशियस-युग के समुद्री सरीसृप की एक नई, विशिष्ट प्रजाति की पहचान की है, जिसमें एक प्रसिद्ध 13.2 मीटर नमूना उपनाम बंकुर भी शामिल है।

**टायलोसॉरस रेक्स****टायलोसॉरस रेक्स के बारे में:****यह क्या है?**

- टायलोसॉरस रेक्स (जिसका अर्थ है टायलोसॉर का राजा) मोसासॉर की एक नई नामित प्रजाति है - विशाल, मांसाहारी समुद्री सरीसृपों का एक समूह जो लैट क्रेटेशियस युग के दौरान महासागरों पर हावी था। यह एक शीर्ष शिकारी था जो बड़े समुद्री जीवन का शिकार करने में सक्षम था, जिसने इसे टायरानोसॉरस रेक्स के पानी के नीचे के समकक्ष के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की।

उत्पत्ति और पर्यावास:

- भौगोलिक सीमा: यह समुद्री सरीसृप पश्चिमी आंतरिक समुद्री मार्ग को फैलाता था, जो एक विशाल अंतर्देशीय समुद्र था जिसने क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका को आधा काट दिया था। इसके अधिकांश जीवाश्मों की खुदाई उत्तर और मध्य टेक्सास के साथ-साथ कैनेसस में भी की गई है।
- कालक्रम: यह लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले रहता था। जबकि यह टायरानोसॉरस रेक्स के साथ एक समान नाम (रेक्स) और भौगोलिक महाद्वीप साझा करता है, दोनों समकालीन नहीं थे; टायलोसॉरस रेक्स ने भूमि पर रहने वाले टी. रेक्स के विकसित होने से लाखों साल पहले महासागरों पर शासन किया था, हालांकि यह भूमि डायनासोर के शुरुआती पूर्वजों के साथ सह-अस्तित्व में था।

विकासवादी इतिहास:

- मोसासॉर अद्वितीय हैं क्योंकि वे छोटे, भूमि-जीवित छिपकलियों से विकसित हुए हैं जो समुद्री वातावरण में चले गए हैं, डायनासोर की उम्र के अंतिम 30 मिलियन वर्षों के दौरान तेजी से पूरी तरह से जलीय शिकारियों में परिवर्तित हो गए हैं। उनके निकटतम जीवित आधुनिक रिश्तेदार मॉनिटर छिपकलियाँ हैं, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन।

प्रमुख विशेषताएँ:

- विशाल पैमाना: यह अब तक खोजे गए सबसे बड़े मोसासॉर में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख नमूना, जिसका उपनाम बंकुर (कैनेसस विश्वविद्यालय में रखा गया) है, लंबाई में आश्चर्यजनक रूप से 13.2 मीटर (लगभग 43.3 फीट) मापता है - सू की लंबाई को पार करते हुए, सबसे बड़ा ज्ञात भूमि-आधारित टायरानोसॉरस रेक्स (12.2 मीटर), और आज की सबसे बड़ी महान सफेद शार्क के आकार को दोगुना करता है।
- विशाल कपाल संरचना: इस प्राणी की खोपड़ी 1.7 मीटर (5 फीट 7 इंच) तक लंबी थी, जो एक औसत वयस्क मानव की ऊंचाई से मेल खाती थी।
- दाँतेदार हथियार: पहले से टायलोसॉरस प्रोरिगर के तहत समूहीकृत अन्य संबंधित प्रजातियों के विपरीत, टी. रेक्स के पास अपने दाँतों

के किनारों के साथ ठीक, ब्लेड जैसे दाँतेदार थे, जो विशेष रूप से अत्यधिक दक्षता के साथ घने मांसपेशियों और मांस के माध्यम से टुकड़ा करने के लिए अनुकूलित थे।

- भारी जबड़े और गर्दन की मांसलता: इसके कंकाल फ्रेम में मजबूत लगाव बिंदु एसटी भारी-भरकम गर्दन और जबड़े की मांसपेशियां, प्रदान करते हैं कुचलने वाला बल बढ़े, संघर्षरत जलीय शिकार को दबाने, वश में करने और अलग करने के लिए आवश्यक कुचलने वाला बल।
- जलीय अनुकूलन: इसमें एक अत्यधिक सुव्यवस्थित शरीर प्रोफाइल, एक लम्बा थूथन, चार बड़े आकार का, पैडल जैसी तैराकी पिलपर्स और एक लंबी, मांसल पूंछ थी जो अत्यधिक शिकारी त्वरण प्रदान करती थी।

महत्त्व:

- टायलोसॉरस रेक्स की खोज से पता चलता है कि आधुनिक तकनीकों के साथ पुराने जीवाश्मों की फिर से जांच करने से पहले से अपरिचित प्रजातियों का पता चल सकता है।
- एक शीर्ष समुद्री शिकारी के रूप में, टायलोसॉरस रेक्स प्रागैतिहासिक पश्चिमी आंतरिक समुद्री मार्ग के खाद्य जाल, शिकार की बहुतायत और पारिस्थितिकी के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर व्हीकल

संदर्भ:

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में मारुति सुजुकी द्वारा विकसित भारत के पहले फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया।

भारत का पहला फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर व्हीकल

भारत के पहले फ्लेक्स-फ्यूल यात्री वाहन के बारे में:

यह क्या है?

- फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) एक उन्नत परिवहन समाधान है जो आंतरिक दहन इंजन से लैस है जिसे ईंधन संयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर निर्बाध रूप से चलाने के लिए कॉन्फिगर किया गया है।
- पारंपरिक पेट्रोल इंजनों के विपरीत, जो केवल निम्न-स्तरीय अपडेट को सहन करते हैं, ये वाहन पेट्रोल और इथेनॉल के अलग-अलग मिश्रणों के लिए गतिशील रूप से अनुकूलित हो सकते हैं, E20 (20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल) से लेकर E100 (100% शुद्ध इथेनॉल) तक।

फ्लेक्स-ईंधन वाहन कैसे काम करता है?

- द्रव अंतर्ग्रहण: ड्राइवर मानक E20 से लेकर उच्च-सांद्रता E100 तक किसी भी अनुमोदित ईंधन मिश्रण को एकल, एकीकृत ईंधन टैंक में पंप करता है।
- वास्तविक समय ईंधन संवेदन: ईंधन लाइन में स्थापित एक विशेष ईंधन संरचना सेंसर लगातार गुजरने वाले तरल का विश्लेषण करता है, तुरंत सटीक अल्कोहल-टू-गैसोलीन अनुपात का पता लगाता है।
- गतिशील ईसीयू अनुकूलन: सेंसर इस संरचना डेटा को वाहन की इंजन नियंत्रण इकाई (ईसीयू) तक पहुंचाता है। क्योंकि इथेनॉल में कम ऊर्जा घनत्व होता है लेकिन मानक पेट्रोल की तुलना में उच्च ऑक्टेन रेटिंग होती है, ईसीयू स्वचालित रूप से इंजन की सेटिंग्स को अनुकूलित करता है।
- दहन अनुकूलन: ईसीयू तुरंत ईंधन इंजेक्टरों के समय और मात्रा को समायोजित करता है और स्पार्क प्लग इग्निशन को आगे बढ़ाता है या धीमा कर देता है। यह निरंतर ट्रैकिंग सुचारु रूप से सुनिश्चित करती है, उच्च दक्षता वाला दहन बिना किसी दस्तक या इंजन की शक्ति के नुकसान के, उपयोग किए गए इथेनॉल मिश्रण की परवाह किए बिना।

पारिस्थितिकी तंत्र और वाहन की मुख्य विशेषताएं:

- व्यापक मिश्रण संगतता: E20 से E100 तक किसी भी पेट्रोल-इथेनॉल मिश्रण पर मजबूती से काम करने के लिए इंजीनियर किया गया, जो स्थानीय उपलब्धता के आधार पर लचीले ईंधन विकल्प प्रदान करता है।
- मोनो-फ्यूल मानकीकरण: नीति आयोग और भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने आधिकारिक तौर पर प्रमाणित फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए मोनो-फ्यूल मानक विनिर्देश के रूप में E85 की पहचान की है।
- शून्य-उत्सर्जन वर्गीकरण: नीति आयोग आधिकारिक तौर पर इथेनॉल-आधारित एफएफवी को उनके न्यूनतम पर्यावरणीय पदचिह्न के कारण शून्य-उत्सर्जन वाहनों के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसमें उच्च-मिश्रण ई85 पर चलने वाले वाहन भी शामिल हैं।
- चरणबद्ध बुनियादी ढांचा रोलआउट: सरकार के रोडमैप में दिल्ली-एनसीआर और मुंबई-पुणे-नागपुर कॉरिडोर में 50-100 एफएफवी-तैयार रिटेल स्टेशनों को प्रारंभिक लॉन्च करने की योजना है। यह नेटवर्क दिसंबर 2026 तक लगभग 500 आउटलेट और 2027 के अंत तक प्रमुख शहरों में लगभग 5,000 आउटलेट तक विस्तारित होने के लिए तैयार है।
- व्यापक राजकोषीय और नीतिगत प्रोत्साहन: सहायक राज्य ढांचे द्वारा समर्थित, जिसमें मूल्य निर्धारण समर्थन, सड़क कर रियायतें, E85 परीक्षण ईंधन की उपलब्धता और अनुपालन वाहनों और पंपों के लिए विशेष टैग पहचानकर्ता शामिल हैं।
- विविध स्वदेशी फीडस्टॉक स्रोत: टूटे हुए अनाज, कृषि अपशिष्ट, बांस और समुद्री शैवाल सहित विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से पूरी तरह से भारत के भीतर उत्पादित इथेनॉल का उपयोग करता है।



मावेन मंगल मिशन

संदर्भ:

नासा ने आधिकारिक तौर पर MAVEN (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन) अंतरिक्ष यान के लिए डीकमीशनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जब एक विसंगति समीक्षा बोर्ड ने निर्धारित किया कि यह पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं है।

मावेन मंगल मिशन

मावेन मार्स मिशन के बारे में:

यह क्या है?

- MAVEN (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन) नासा की पहली रोबोटिक अंतरिक्ष जांच थी जो स्पष्ट रूप से मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल, आयनमंडल और इसके समग्र जलवायु विकास को देखने के लिए समर्पित थी।
- नवंबर 2013 में लॉन्च किए गए, अंतरिक्ष यान ने लाल ग्रह के चारों ओर कक्षा में 11 वर्षों से अधिक समय सफलतापूर्वक पूरा किया, जो अपने प्राथमिक एक साल की मिशन समयरेखा से परे एक पूरे दशक का विस्तार करता है।



उद्देश्य:

- मावेन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि कैसे मंगल ने अरबों वर्षों में अपने ऊपरी वायुमंडल और वाष्पशील यौगिकों को अंतरिक्ष में खो दिया।
- वर्तमान वायुमंडलीय कटाव दर को मापकर, मिशन ने वैज्ञानिकों को ग्रह की जलवायु परिवर्तन के इतिहास में गहरी अंतर्दृष्टि देने की मांग की, जो तरल पानी के साथ एक गर्म, संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया से आज के ठंडे, शुष्क रेगिस्तान में बदल गया है।

प्रमुख विशेषताएं:

- एक साथ पर्यावरण संवेदन: मंगल ग्रह पर एकमात्र अंतरिक्ष यान के रूप में संचालित किया जाता है जो एक साथ आने वाली सौर हवा और तत्काल मंगल ग्रह की वायुमंडलीय प्रतिक्रिया दोनों का डेटा माप लेने में सक्षम है।
- रीयल-टाइम स्पटरिंग मापन: गैर-प्रतिक्रियाशील आर्गन गैस को ट्रैक करके किसी भी ग्रह पर पहली बार वायुमंडलीय "स्पटरिंग" को मापा गया, वास्तविक समय में यह पता चलता है कि कैसे उच्च गति वाले आयन भौतिक रूप से गैस के अणुओं को गहरे अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं।
- वैश्विक प्रोटॉन अरोरा की खोज: मंगल ग्रह के कई प्रकार के प्रकाश शो की खोज की, यह साबित करते हुए कि प्रोटॉन-संचालित ऑरोरा पृथ्वी की तरह छोटे ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि मंगल की पूरी सतह पर हो सकते हैं।
- डस्ट स्टॉर्म वाटर-लॉस वेरिफिकेशन: 2018 के वैश्विक धूल तूफान को ट्रैक किया गया ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्षेत्रीय हीटिंग पानी के अणुओं को सामान्य से कहीं अधिक वायुमंडल में ले जाता है, जिससे ग्रह से बाहर निकलने वाले पानी की अचानक वृद्धि होती है।
- मल्टी-वेवलेंथ धूमकेतु इमेजिंग: धूमकेतु 31/ATLAS की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों को कैप्चर करने के लिए पराबैंगनी (यूवी) और बहु-तरंग दैर्घ्य फिल्टर का उपयोग करके एक विशेष अभियान तैयार किया गया, इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए इसके परमाणु हाइड्रोजन का मानचित्रण किया गया।
- रिकॉर्ड-ब्रेकिंग डेटा रिले नोड: नासा के मार्स रिले नेटवर्क के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल एंकर के रूप में कार्य किया, जो सतह रोवर्स से पृथ्वी तक संचार डेटा प्रसारित करता है और एक ही दिन में किसी अन्य ग्रह से रिले किए गए सबसे अधिक डेटा के लिए सौर मंडल का रिकॉर्ड रखता है।

मिशन का महत्व:

- सौर तूफान और विकिरण पर मावेन का डेटा वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए सुरक्षित अंतरिक्ष यान, परिरक्षण प्रणाली और आपातकालीन प्रोटोकॉल डिजाइन करने में मदद करता है।
- यह अध्ययन करके कि सौर हवाएं ग्रहों के वायुमंडल को कैसे छीन लेती हैं, मावेन हमारी समझ में सुधार करता है कि ग्रह समय के साथ रहने योग्य या निर्जन क्यों हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी से परे जीवन की खोज में सहायता मिलती है।

एक्सोप्लैनेट WASP-94A b

संदर्भ:

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक्सोप्लैनेट WASP-94A b पर मौसम के पैटर्न का मानचित्रण किया है।



एक्सोप्लैनेट WASP-94A b

एक्सोप्लैनेट WASP-94A b के बारे में:

यह क्या है?

- WASP-94A b एक गैसीय अतिरिक्त-सौर ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी वायुमंडलीय गतिशीलता और अलग-अलग सुबह-शाम मौसम प्रणालियों को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की अभूतपूर्व अवरक्त संवेदनशीलता का उपयोग करके मैप किया गया था।

प्रमुख विशेषताएँ:

- "हॉट ज्यूपिटर" वर्गीकरण: इसे "हॉट ज्यूपिटर" गैस विशाल के रूप में वर्गीकृत किया गया है; यह बृहस्पति के भौतिक आकार से लगभग दोगुना है, लेकिन इसमें इसके पूर्ण द्रव्यमान का केवल आधा हिस्सा है।
- एक्सट्रीम ऑर्बिट और टाइडल लॉकिंग: यह ग्रह अपने मूल मेजबान तारे के असाधारण रूप से करीब परिक्रमा करता है, केवल चार दिनों में एक पूर्ण क्रांति पूरी करता है। यह अत्यधिक निकटता ग्रह को ज्वार-भाटे से बंद कर देती है, इसके घूर्णन को उसकी क्रांति के साथ सिंक्रनाइज़ करती है।
- द्विध्रुवी तापमान चरम सीमा: क्योंकि यह ज्वार-भाटे से बंद है, एक तरफ बारहमासी रूप से तारे का सामना एक विल्विलाती रेगिस्तान के रूप में होता है जो चट्टान को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है, जबकि बारहमासी अंधेरा रात का हिस्सा पूर्ण शून्य के करीब गिरता है।
- विषम मौसम प्रणाली: ग्रह में एक स्पष्ट रूप से विभाजित वातावरण है। इसकी सुबह मैग्नीशियम सिलिकेट, आयर्न और मैग्नीशियम सल्फाइड से बने भारी बादलों से ढकी होती है, जबकि इसकी शुरुआती शामें पूरी तरह से साफ आसमान खेलती हैं।
- सुपरसोनिक वायुमंडलीय स्वीपिंग: ठंडी रात में लगातार बादल बनते हैं, क्रूर, बेहद तेज हवाओं से दुनिया भर में तेजी से बह जाते हैं, और दिन के तेज मौसम में प्रवेश करने पर तुरंत विघटित हो जाते हैं/वाष्पीकृत हो जाते हैं।
- स्लो-ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से देखा गया: खगोलविदों ने पारगमन विधि का उपयोग करके ग्रह के वायुमंडलीय हस्ताक्षर को उसके मेजबान तारे से अलग कर दिया। जैसे-जैसे ग्रह तारे के सामने धीरे-धीरे गुजरता है, अलग-अलग तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को विभाजित करके, उन्होंने सुबह और शाम के क्षितिज के बीच भिन्नता का मानचित्रण किया।

खोज का महत्व:

- बादल और स्पष्ट वायुमंडलीय क्षेत्रों को अलग करके, अध्ययन संरचना त्रुटियों को कम करता है और एक्सोप्लैनेट रासायनिक विश्लेषण की सटीकता में सुधार करता है।
- गर्म ज्यूपिटर की संरचना वैज्ञानिकों को प्राचीन प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के रसायन विज्ञान और ग्रह प्रणालियों के विकास के पुनर्निर्माण में मदद करती है।

E85 ईंधन

संदर्भ:

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में एक खुदरा आउटलेट पर ई85 ईंधन का शुभारंभ किया।

E85 ईंधन

E85 ईंधन के बारे में:

यह क्या है?

- E85 एक उत्त्व इथेनॉल, भारी अल्कोहल जैव ईंधन मिश्रण है जो 80% से 85% इथेनॉल और 14% से 19% पारंपरिक पेट्रोल से बना है। यह एक विशेष उत्त्व-ऑक्टेन वैकल्पिक ईंधन के रूप में कार्य करता है जिसे मानक पेट्रोलियम कारों के बजाय संशोधित आंतरिक दहन इंजनों के लिए स्पष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है।

संदर्भ और विकास:

- वैश्विक संदर्भ: तैनाती ब्राजील से संरचनात्मक टेम्पलेट्स का लाभ उठाती है, जहां 80% से अधिक हल्के वाहन पारिस्थितिकी तंत्र दशकों से लचीली, उत्त्व-मिश्रण इथेनॉल तकनीक पर मज़बूती से चलते हैं।
- भारतीय प्रक्षेपवक्र: भारत का इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2014 में 1.53% की आधार रेखा से बढ़कर 2026 में E20 (20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल) राष्ट्रव्यापी मानक प्राप्त कर चुका है, जो मूल समयरेखा से पांच साल पहले अपने मैक्रो लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है।

उद्देश्य:

- ई85 को शुरू करने का दोहरा उद्देश्य भारत के भारी कच्चे तेल के आयात बिल को कम करते हुए घरेलू कृषि-स्रोत इथेनॉल के आर्थिक लाभों को सीधे ड्राइवरों तक पहुंचाना है।
- यह शहरी डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए एक टिकाऊ, बुनियादी ढांचे के लिए तैयार विकल्प भी स्थापित करता है।



E85 पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषताएं:

- लॉन्ग खुदरा स्टेशनों पर एक अलग मूल्य निर्धारण और परिचालन ढांचा पेश करता है:
- फ्लेक्स-फ्यूएल व्हीकल (FFV) एक्सक्लूसिविटी: E85 का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल या बेसलाइन E20 कारों में इसकी संश्लेषक प्रकृति और विभिन्न दहन गुणों के कारण नहीं किया जा सकता है। यह केवल विशेष FFV के लिए है जो E20 से E100 तक के किसी भी मिश्रण को संभालने के लिए अपने इंजन मैपिंग को गतिशील रूप से समायोजित करते हैं।
- आक्रामक उपभोक्ता मूल्य निर्धारण: उपभोक्ता को अपना को प्रोत्साहित करने के लिए, E85 की कीमत पारंपरिक खुदरा पेट्रोल की तुलना में लगभग ₹20 प्रति लीटर कम है।
- चरणबद्ध वितरण रोडमैप: प्रारंभिक रोलआउट 48 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन खुदरा दुकानों पर शुरू होता है, जो दिसंबर 2026 तक 500 स्टेशनों तक बढ़ जाता है और दिसंबर 2027 तक 5,000 परिचालन पंपों को लक्षित करता है।
- खुदरा लेबलिंग साफ़ करें: आकस्मिक गलत ईंधन भरने को रोकने के लिए, E85 डिस्पेंसर में अत्यधिक दृश्यमान चेतावनी संकेत होंगे जिनमें लिखा होगा: केवल E85-अनुरूप करें।
- मैक्रो लक्ष्य 2030: यह उच्च-मिश्रण रोलआउट 2030-31 तक अपने कुल राष्ट्रव्यापी इथेनॉल सम्मिश्रण स्तर को लगभग 26% तक बढ़ाने की भारत की योजना का एक मुख्य घटक है।

नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी)

संदर्भ:

भारत अपने सामरिक रात्रि-युद्ध गियर का आधुनिकीकरण करके अपनी प्रतिस्पर्धी सीमाओं के साथ अपनी स्वदेशी युद्ध तत्परता को आक्रामक रूप से बढ़ा रहा है।

- नेट्रो एनडब्ल्यू 3000 नाइट साइट्स के लिए रक्षा मंत्रालय के 659.47 करोड़ रुपये के बड़े अनुबंध और आंध्र प्रदेश में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की समर्पित इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सुविधा की शुरुआत से हाइलाइट किया गया है।

नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी)

नाइट विजन डिवाइसेस (एनवीडी) के बारे में:

यह क्या है?

- नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी) एक परिष्कृत ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सैन्य बलों को लगभग पूर्ण अंधेरे, धुएं और छलावरण को अत्यधिक परिभाषित दृश्य इमेजरी में परिवर्तित करके एक परिचालन बढ़त प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- एनवीडी को हैंडहेल्ड इकाइयों, हथियार-युग्मवार जगहें, हेलमेट चश्मे, या बख्तरबंद स्तंभों और लड़ाकू विमानों के अंदर एकीकृत सेंसर के रूप में तैनात किया जाता है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- आधुनिक सैन्य एनवीडी दो प्राथमिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके काम करते हैं:
- छवि गहनता (प्रकाश प्रवर्धन): डिवाइस एक वस्तुनिष्ठ लेंस के माध्यम से परिवेश प्रकाश (सितारों, चंद्रमा, या अवरक्त प्रकाशकों से) की ट्रेस मात्रा को कैप्चर करता है।
- इन प्रकाश कणों (फोटॉन) को एक विशेष इमेज इंटेन्सिफायर ट्यूब (आईआईटी) के अंदर विद्युत ऊर्जा (इलेक्ट्रॉन) में परिवर्तित किया जाता है।
- ट्यूब फॉस्फोर स्क्रीन से टकराने से पहले इलेक्ट्रॉनों को तेजी से गुणा करती है, उन्हें वापस एक अत्यधिक विस्तृत, दृश्यमान हरे या सफेद छवि में परिवर्तित करती है।
- थर्मल इमेजिंग: प्रकाश को बढ़ाने के बजाय, थर्मल एनवीडी जीवित निकायों, वाहन के इंजन चलाने या डिस्चार्ज किए गए हथियारों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त गर्मी हस्ताक्षरों को पढ़ने के लिए माइक्रोबोलोमीटर सेंसर का उपयोग करते हैं।
- यह सैनिकों को कुल कालेपन, धूल भरी आंधी, घने जंगल की छतरी और सामरिक धुएं की स्क्रीन के माध्यम से लक्ष्य को ट्रैक करने की अनुमति देता है।

आधुनिक एनवीडी सिस्टम की मुख्य विशेषताएं:

- पीढ़ीगत प्रगति: प्रौद्योगिकी चार अलग-अलग विकास चक्रों के माध्यम से उन्नत हुई है। आधुनिक पीढ़ी-III/IV सेंसर न्यूनतम दानेदार हस्तक्षेप के साथ तेज लक्ष्य रिज़ॉल्यूशन देने के लिए स्वचालित गेटिंग और अत्यधिक उन्नत सिग्नल-टू-शोर अनुपात को एकीकृत करते हैं।
- फ्यूज्ड सेंसर टेक्नोलॉजी: अत्याधुनिक सेटअप थर्मल इमेजिंग और इमेज इंटेन्सिफिकेशन को एक एकवचन, ओवरलेड डिजिटल डिस्प्ले में जोड़ते हैं। यह ऑपरेटरों को एक समग्र दृष्टिकोण देता है जो पर्यावरण टोपोग्राफी और सक्रिय गर्मी हस्ताक्षर दोनों को एक साथ उजागर करता है।
- संवर्धित वास्तविकता (एआर) ओवरले: उन्नत सैन्य चश्मे वास्तविक समय के सामरिक मानचित्र, लक्ष्य डेटा और ब्लू-फोर्स ट्रैकिंग को सीधे सैनिक के देखने के क्षेत्र में फीड करते हैं, जिससे एनवीडी एक कनेक्टेड डेटा टर्मिनल में बदल जाता है।



भारत की तेजी से बढ़ती नाइट विजन क्षमताएं:

- सेना के हथियारों के लिए स्वदेशी नाइट साइट्स: रक्षा मंत्रालय ने एमकेयू लिमिटेड और मेडबिट टेक्नोलॉजीज को फ्रंटलाइन SIG 3000 असॉल्ट राइफलों के लिए 3 जेन-3 नाइट साइट्स की आपूर्ति करने के लिए अनुबंधित किया, जिससे रात से लड़ने की क्षमता बढ़ गई।
- बख्तरबंद और वायु प्लेटफार्मों में नाइट विजन विस्तार: स्वदेशी थर्मल स्थलों को बीएमपी-2एम पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों में एकीकृत किया जा रहा है, जबकि भारतीय वायुसेना ने एलसीएच प्रचंड और एलयूएच संचालन के लिए नेत्रो एनबी-3100 जेन-III एविएशन नाइट विजन गॉगल्स को शामिल किया है।
- बीईएल की निम्मलुरु में एडवांस्ड नाइट विजन फैक्ट्री: आंध्र प्रदेश में बीईएल द्वारा स्थापित 362 करोड़ रुपये की सुविधा नाइट विजन डिवाइस, मिसाइल इन्फ्रारेड सीकर्स और एंटी-ड्रोन सिस्टम का निर्माण करेगी, जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।

जापान का H3 रॉकेट

संदर्भ:

जापान के प्रमुख H3 रॉकेट ने दिसंबर में अपने पिछले मिशन के समय से पहले दूसरे चरण के इंजन समाप्ति के कारण विफलता में समाप्त होने के महीनों बाद तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान भरी।

जापान का H3 रॉकेट

जापान के H3 रॉकेट के बारे में:

यह क्या है?

- H3 रॉकेट जापान की अगली पीढ़ी, तरल-प्रणोदक फ्लैगशिप लॉन्च वाहन है जिसे विरासत H-IIA प्रणाली को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे स्वायत्त अंतरिक्ष पहुंच को सुरक्षित करने और वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए एक उत्त्व-लचीलेपन, उत्त्व-विश्वसनीयता और लागत प्रभावी भारी-लिफ्ट वाहन के रूप में काम करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- द्वारा विकसित: जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (MHI)।

प्रमुख विशेषताएं:

- उत्त्व लागत-प्रदर्शन: वाणिज्यिक ऑफ-द-शेल्फ ऑटोमोटिव घटकों और 3डी-प्रिंटेड हार्डवेयर का उपयोग करके अपने पूर्ववर्ती, एच-आईआई की तुलना में लॉन्च लागत में लगभग 50% की कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
- लिविड-प्रोपेलेंट कोर: नए विकसित LE-9 फर्स्ट-स्टेज इंजन की सुविधा है, जो लिफ्ट-ऑफ के दौरान सुरक्षा और थ्रस्ट दक्षता को अधिकतम करने के लिए एक उन्नत विस्तारक ब्लीड साइकिल का उपयोग करता है।
- वाणिज्यिक और चंद्र पेलोड क्षमता: एक मॉड्यूलर संरचना के साथ बनाया गया है जो बड़े वाणिज्यिक दूरसंचार उपग्रहों, सैन्य भू-स्थानिक संपत्तियों को तैनात करने और अंततः चंद्र सतह के ठिकानों पर भारी कार्गो पेलोड पहुंचाने में सक्षम है।
- लचीला कॉन्फिगरेशन: ठोस रॉकेट बूस्टर (0, 2, या 4) और पेलोड फेयरिंग आकार की संख्या के संबंध में कई संरचनात्मक विकल्प प्रदान करता है, जिससे यह अलग-अलग मिशन प्रोफाइल और कक्षा आवश्यकताओं के लिए सफाई से अनुकूलित हो सकता है।

अन्य अंतरिक्ष संगठनों के प्रसिद्ध प्रमुख रॉकेट:

अंतरिक्ष एजेंसी/कंपनी	राष्ट्र/क्षेत्र	प्रसिद्ध फ्लैगशिप लॉन्च वाहन
स्पेसएक्स	संयुक्त राज्य अमेरिका (निजी)	फाल्कन 9 (H3 का प्राथमिक वैश्विक प्रतियोगी), फाल्कन हेवी, स्टारशिप
इसरो (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन)	भारत	एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3), पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)
नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन)	संयुक्त राज्य अमेरिका	एसएलएस (स्पेस लॉन्च सिस्टम)
ईएसए (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी)	यूरोप	एरियन 6, वेगा-सी
सीएनएसए (चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन)	चीन	लॉन्ग मार्च 5 (चांगज़ेंग 5)
रोस्कोस्मोस	रूस	सोयुज -2, अंगारा ए 5

ड्रॉप शिपिंग

संदर्भ:

एआई-संचालित स्टोरफ्रंट निर्माण और सोशल मीडिया वीडियो रुझानों के उदय ने ड्रॉप शिपिंग के वैश्विक पदचिह्न का तेजी से विस्तार किया है।

ड्रॉप शिपिंग

ड्रॉप शिपिंग के बारे में:

यह क्या है?

- ड्रॉप शिपिंग एक ई-कॉमर्स खुदरा पूर्ति व्यवसाय अभ्यास है जहां एक ऑनलाइन व्यक्ति, निर्माता या विपणन एजेंट स्टॉक में किसी भी भौतिक इन्वेंट्री को रखे बिना उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचता है। इसके बजाय, ड्रॉप शिपर खुद को एक उद्यमी बिचौलिए के रूप में सीधे वाणिज्यिक लेनदेन में सम्मिलित करता है, भौतिक भंडारण, पैकेजिंग और रसद प्रबंधन को तीसरे पक्ष के निर्माता, थोक व्यापारी या पूर्ति केंद्र में ऑफलोड करता है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- स्टोरफ्रंट सेटअप और प्रचार निर्माण: एक ड्रॉप शिपर Shopify जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक उपयोगकर्ता के अनुकूल, आकर्षक डिजिटल स्टोरफ्रंट स्थापित करता है, Instagram Professional खाते, या विशेष वेब डोमेन - यथार्थवादी उत्पाद इमेजरी और विवरण बनाने के लिए अवसर जनरेटिव AI का उपयोग करता है।
- ग्राहक ऑर्डर प्लेसमेंट: एक खरीदार एक विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट पर रुकता है और एक ट्रेंडिंग आइटम खरीदता है, पूरी सूचीबद्ध खुदरा कीमत का भुगतान सीधे बिचौलिए को करता है।
- ऑर्डर फॉरवर्डिंग: ड्रॉप शिपर ग्राहक के ऑर्डर और शिपिंग विवरण लेता है और उन्हें किसी तीसरे पक्ष के घरेलू या अंतरराष्ट्रीय थोक व्यापारी या निर्माता को अत्रेपित करता है।
- प्रत्यक्ष पूर्ति: ड्रॉप शिपर ग्राहक के धन का उपयोग करके आपूर्तिकर्ता को वस्तु की थोक लागत का भुगतान करता है। आपूर्तिकर्ता तब उत्पाद को पैकेज करता है और सीधे अंतिम उपभोक्ता को भेजता है, बिचौलिए को पूरी तरह से दरकिनार करता है।
- लाभ प्रतिधारण: ड्रॉप शिपर उपभोक्ता से वसूले गए खुदरा मूल्य और आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई थोक लागत के बीच शुद्ध वित्तीय मार्जिन को पॉकेट में रखता है, किसी भी डिजिटल विज्ञापन व्यय को घटाकर।

ड्रॉप शिपिंग की मुख्य विशेषताएं:

- शून्य भौतिक इन्वेंटरी ओवरहेड: विक्रेता पहले से उत्पादों को खरीदते या संग्रहीत नहीं करते हैं, जिससे गोदाम की लागत समाप्त हो जाती है और स्टार्टअप पूंजी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है।
- भौगोलिक और नियामक परिरक्षण: विक्रेता वैश्विक बाजारों तक पहुंच सकते हैं जबकि आपूर्तिकर्ता लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और थोक खरीद जटिलताओं को संभालते हैं।
- एआई-नेटिव ऑटोमेशन: एआई उपकरण प्रवृत्ति विश्लेषण, ग्राहक सहायता, इन्वेंट्री निगरानी और विपणन संचालन को स्वचालित करते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होता है।
- आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता का नुकसान: ग्राहक अक्सर वास्तविक निर्माता की पहचान नहीं कर पाते हैं, जिससे उत्पाद की उत्पत्ति और प्रामाणिकता को सत्यापित करना मुश्किल हो जाता है।
- खंडित ग्राहक सहायता: कुछ विक्रेता सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं, लेकिन अविश्वसनीय स्टोर गायब हो सकते हैं, जिससे ग्राहकों को धनवापसी विकल्प नहीं मिल सकते हैं।

वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग:

- सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कॉमर्स: इन्फ्लुएंसर इन्वेंट्री या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाए रखे बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशिष्ट उत्पाद बेचते हैं।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एकत्रीकरण: ऑनलाइन मार्केटप्लेस भंडारण सुविधाओं में भारी निवेश किए बिना विविध उत्पादों की पेशकश करने के लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल का उपयोग करते हैं।
- रुझान और मौसमी पूंजीकरण: विपणक जल्दी से वायरल उत्पादों के आसपास स्टोर लॉन्च करते हैं, उपभोक्ता मांग में गिरावट से पहले मुनाफा कमाते हैं।
- ज्ञान और पाठ्यक्रम ट्रेडिंग इकोसिस्टम: उद्यमी ड्रॉप-शिपिंग व्यवसायों से संबंधित पाठ्यक्रम, आपूर्तिकर्ता सूची और सॉफ्टवेयर बेचकर विशेषज्ञता का मुद्रीकरण करते हैं।



मेमोरी चिप्स

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेमोरी चिप सेगमेंट में एक गंभीर वैश्विक मांग-आपूर्ति असंतुलन सी ऑनसुमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि कर रहा है और भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा है।

मेमोरी चिप्स

मेमोरी चिप्स के बारे में:

यह क्या है?

- मेमोरी चिप लाखों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बना एक एकीकृत सर्किट है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए डेटा स्टोरेज रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। कम्प्यूटेशनल तर्क को निष्पादित करने वाले प्राथमिक माइक्रोप्रोसेसरों के विपरीत, मेमोरी चिप्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुचारु रूप से काम करने के लिए उच्च गति पर डेटा, कोड और डिजिटल निर्देशों को पकड़ने, बनाए रखने और स्ट्रीम करने के लिए विशिष्ट हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

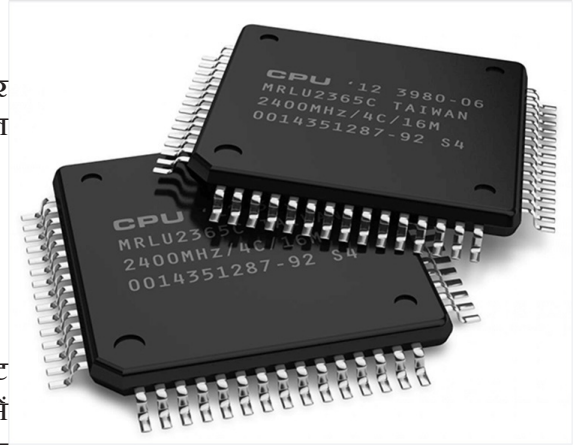
- डेटा चार्जिंग और ट्रैपिंग: एक मानक मेमोरी कॉन्फिगरेशन (जैसे DRAM) में, प्रत्येक व्यक्तिगत मेमोरी सेल में एक अल्ट्रा-माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। संधारित्र एक विद्युत आवेश रखता है (एक बाइनरी 1 का प्रतिनिधित्व करता है) या बाइनरी 0 का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने चार्ज को लीक करता है।
- ताज़ा चक्र: क्योंकि ये सूक्ष्म कैपेसिटर स्वाभाविक रूप से समय के साथ बिजली का रिसाव करते हैं, चिप डेटा हानि को रोकने के लिए प्रति सेकंड लाखों बार चार्ज को ताज़ा करने के लिए निरंतर बाहरी शक्ति पर निर्भर करती है।
- फ्लैश फ्लोटिंग गेट्स: गैर-वाष्पशील मेमोरी (जैसे पेन ड्राइव में पाए जाने वाले नंद फ्लैश) में, इलेक्ट्रॉनों को एक विद्युत बाधा के माध्यम से एक अलग फ्लोटिंग गेट में धकेल दिया जाता है। डिवाइस के पूरी तरह से बंद होने पर भी इलेक्ट्रॉन वहां फंसे रहते हैं, जिससे स्थायी डेटा प्रतिधारण सुनिश्चित होता है।
- एआई डेटा पाइपलाइन: उन्नत कॉन्फिगरेशन, जैसे कि उच्च बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम), माइक्रोस्कोपिक थ्रू-सिलिकॉन वायरस (टीएसवी) का उपयोग करके कई मेमोरी एक दूसरे के ऊपर लंबवत रूप से मर जाती हैं। यह घना लेआउट पारंपरिक मदरबोर्ड बस बाधाओं को दूरकरना करता है, जिससे जटिल डेटा सेंटर प्रश्नों को संभालने के लिए एआई प्रोसेसर में डेटा प्रवाह होता है।

वर्तमान बाजार वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं:

- संरचनात्मक आपूर्ति पुनर्निर्माण: प्रमुख चिपमेकर उपभोक्ता मेमोरी चिप्स से उत्पादन को उच्च-लाभ वाले एआई चिप्स में स्थानांतरित कर रहे हैं। इससे स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेमोरी उपलब्धता कम हो जाती है।
- LPDDR4 घाटा: LPDDR4 मेमोरी में उत्पादन में कटौती से वैश्विक आपूर्ति में 40% से अधिक की कमी आने की उम्मीद है। इससे बजट और मिड-रेंज मोबाइल उपकरणों की लागत और कमी बढ़ सकती है।
- लगातार मेमोरी मुद्रास्फीति: कम आपूर्ति ने दुनिया भर में मेमोरी-स्टोरेज की कीमतों को लगातार बढ़ा दिया है। पेन ड्राइव, एसएसडी और हार्ड डिस्क जैसे उत्पादों की कीमतों में बार-बार वृद्धि देखी गई है।
- बहु-वर्षीय आपूर्ति लॉक-इन: मेमोरी चिप्स की मांग अगले 3-5 वर्षों तक आपूर्ति से अधिक होने की उम्मीद है। खरीदार अग्रिम वित्त पोषण और दीर्घकालिक अनुबंधों के माध्यम से भविष्य की आपूर्ति को सुरक्षित कर रहे हैं।
- मितव्ययी बुनियादी ढांचा नवाचार: डेटा सेंटर संसाधनों के उपयोग को कम करने के लिए कुशल कूलिंग तकनीकों को अपना रहे हैं। बंद-लूप शीतलन प्रणाली पानी की खपत को लगभग 70% तक कम कर सकती है।

मुख्य अनुप्रयोग:

- जनरेटिव एआई और क्लाउड डेटा सेंटर: एचबीएम चिप्स एआई मॉडल और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अल्ट्रा-फास्ट डेटा प्रोसेसिंग प्रदान करते हैं। वे बड़े पैमाने पर मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई वर्कलोड का समर्थन करते हैं।
- व्यक्तिगत और मोबाइल कंप्यूटिंग: एलपीडीडीआर मेमोरी स्मार्टफोन और लैपटॉप में त्वरित प्रसंस्करण और मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाती है। यह न्यूनतम बिजली की खपत करते हुए उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है।
- स्मार्टउपभोक्ता उपकरण: DRAM चिप्स स्मार्ट घरेलू उपकरणों में डिजिटल कार्यों को शक्ति प्रदान करते हैं। वे स्वचालन, स्पर्श इंटरफेस और कनेक्टेड-डिवाइस सुविधाओं का समर्थन करते हैं।
- मास स्टोरेज डिवाइस: नंद फ्लैश मेमोरी एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहीत करती है। यह विश्वसनीय, उच्च क्षमता और ऊर्जा-कुशल भंडारण प्रदान करता है।



उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (एचईएमसीपी)

संदर्भ:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आधिकारिक तौर पर नागपुर में 300 करोड़ रुपये की उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (एचईएमसीपी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (एचईएमसीपी)

हाई-एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट (HEMCP) के बारे में:

यह क्या है?

- हाई-एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट (एचईएमसीपी) एक अत्याधुनिक परमाणु चिकित्सा सुविधा है जो एक उच्च-ऊर्जा कण त्वरक के आसपास केंद्रित है। इस परियोजना को स्थानीय स्तर पर विशेष, अल्पकालिक चिकित्सा रेडियोआइसोटोप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्नत ऑन्कोलॉजिकल इमेजिंग, लक्षित कैंसर उपचारों और आणविक अनुसंधान के लिए अपरिहार्य हैं।

यह काम किस प्रकार करता है?

- कण त्वरण: साइक्लोट्रॉन एक निर्वात कक्ष के अंदर तेजी से विस्तारित सर्पिल पथ के साथ चार्ज किए गए उप-परमाणु कणों (जैसे प्रोटॉन या ड्यूटेरॉन) को तेज करने के लिए मजबूत चुंबकीय और वैकल्पिक रेडियो-आवृत्ति विद्युत क्षेत्रों के संयोजन का उपयोग करता है।
- लक्ष्य बमबारी: एक बार जब ये कण अत्यधिक उच्च गतिज ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें एक स्थिर लक्ष्य सामग्री (जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या तरल धातुओं के विशिष्ट आइसोटोप) पर बमबारी करने के लिए एक केंद्रित बीम के रूप में सर्पिल ट्रैक से बाहर निर्देशित किया जाता है।
- परमाणु परिवर्तन: उच्च-ऊर्जा टकराव लक्ष्य सामग्री के परमाणु नाभिक को बदल देता है, स्थिर परमाणुओं को अल्पकालिक, अस्थिर रेडियोधर्मी आइसोटोप (जैसे फ्लोरीन-18, कार्बन-11, या आयोडीन-123) में बदल देता है।
- रेडियोफार्मास्यूटिकल संश्लेषण: इन नव निर्मित कच्चे रेडियोआइसोटोप को तुरंत स्वचालित सीसा-परिरक्षित गर्म कोशिकाओं में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंदर, वे रासायनिक रूप से जैविक अणुओं (जैसे ग्लूकोज) के साथ जुड़े होते हैं ताकि मेडिकल-ग्रेड रेडियोफार्मास्यूटिकल्स को संश्लेषित किया जा सके जो रोगी नैदानिक स्कैनिंग के लिए सुरक्षित रूप से निगलना या नसों में प्राप्त कर सकते हैं।

नागपुर एचईएमसीपी की मुख्य विशेषताएं:

- रणनीतिक बहु-राज्यीय जलग्रहण क्षेत्र: केंद्र में स्थित, यह सुविधा 500 किलोमीटर के सेवा दायरे में पांच राज्यों में रोगियों को उन्नत कैंसर-देखभाल सहायता प्रदान करेगी।
- संस्थागत नेटवर्क एकीकरण: यह एम्स नागपुर, एनसीआई और जीएमसी को महत्वपूर्ण रेडियोफार्मास्यूटिकल्स की आपूर्ति करेगा, जिससे क्षेत्रीय कैंसर-उपचार क्षमता मजबूत होगी।
- 50:50 वित्तीय वास्तुकला: ₹300 करोड़ की परियोजना को चिकित्सा शिक्षा और उद्योग विभागों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है, जिसमें 30 हेक्टेयर पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
- विशिष्टकॉर्पोरेट गवर्नेंस: महाकयूर के तहत एक समर्पित एसपीवी संचालन का प्रबंधन करेगा, पेशेवर निरीक्षण और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

प्रमुख चिकित्सा अनुप्रयोग:

- उन्नतपीईटी-सीटी डायग्नोस्टिक इमेजिंग: पीईटी-सीटी स्कैन के लिए फ्लोरीन-18 जैसे रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करता है, जिससे कैंसर कोशिकाओं का शीघ्र और सटीक पता लगाया जा सकता है।
- लक्षित परमाणु चिकित्सा चिकित्सा: रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जो संपार्श्विक क्षति को कम करते हुए सीधे ट्यूमर पर केंद्रित विकिरण प्रदान करता है।
- ऑन्कोलॉजिकल रिसर्च एंडड्रग डिस्कवरी: विलनिकल परीक्षाओं और नए इमेजिंग ट्रेसर और कैंसर उपचारों के विकास का समर्थन करने वाले एक शोध केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- सटीक व्यक्तिगत सुराक अंशांकन: स्थानीय उत्पादन यह सुनिश्चित करता है कि अल्पकालिक आइसोटोप अस्पतालों तक जल्दी पहुंचें, जिससे सटीक रोगी-विशिष्ट नैदानिक सुराक सक्षम हो सके।



बीजीपी अपहरण

संदर्भ:

टेलीग्राम पर भारत सरकार के अस्थायी ब्लॉक के बाद, प्लेटफॉर्म के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव ने दावा किया कि बीजीपी अपहरण के माध्यम से ऐप की वैश्विक पहुंच से समझौता किया जा रहा था।

बीजीपी अपहरण

BGP अपहरण के बारे में:

यह क्या है?

- बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल (बीजीपी) अपहरण एक उन्नत साइबर-सामरिक घटना है जिसमें इंटरनेट ट्रैफिक दुर्भावनापूर्ण या गलती से गलत दिशा में निर्देशित होता है। ऐसा तब होता है जब कोई नेटवर्क ऑपरेटर गलत तरीके से आईपी एड्रेस स्पेस का विज्ञापन करता है जो उसके पास नहीं है, जिससे इंटरनेट की वैश्विक रूटिंग निर्देशिका भ्रमित हो जाती है।



यह काम किस प्रकार करता है?

- इंटरनेट का डाकघर: वैश्विक इंटरनेट को हजारों विशाल, स्वतंत्र नेटवर्क ब्लॉकों में विभाजित किया गया है जिन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों, आईएसपी और क्लाउड प्रदाताओं द्वारा संचालित स्वायत्त प्रणाली (एएस) कहा जाता है। प्रत्येक एएस बीजीपी का उपयोग यह घोषणा करने के लिए करता है कि वह किस आईपी पते तक पहुंच सकता है।
- ट्रस्ट वेरिफिकेशन: इंटरनेट का मुख्य बुनियादी ढांचा अंतर्निहित विश्वास पर निर्भर करता है; नेटवर्क आम तौर पर इन बीजीपी रूटिंग पथों को सर्वोत्तम मानचित्र मानकों के सटीक प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार करते हैं।
- झूठा विज्ञापन: एक अपहरण के दौरान, एक दुष्ट या गलत कॉन्फिगर किया गया स्वायत्त प्रणाली एक धोखाधड़ी रूटिंग घोषणा प्रसारित करती है जिसमें दावा किया जाता है कि उसके पास लक्ष्य सेवा के आईपी पते के लिए सबसे छोटा, सबसे कुशल मार्ग है।
- ट्रैफिक डायवर्जन: अपस्ट्रीम ट्रांजिट नेटवर्क इस झूठी मानचित्र प्रविष्टि को स्वीकार करते हैं, वैश्विक रूटिंग तालिका को अपडेट करते हैं। नतीजतन, वैध सेवा के लिए आने वाले ट्रैफिक को दूर खींच लिया जाता है और इसके बजाय दुष्ट नेटवर्क में भेज दिया जाता है।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं:

- रूट आक्रामक प्राथमिकता: BGP स्वाभाविक रूप से सबसे विशिष्ट IP उपसर्गों या सबसे छोटे नेटवर्क पथों को प्राथमिकता देता है। हमलावर अत्यधिक विशिष्ट झूठी घोषणाएं करके इस व्यवहार का फायदा उठाते हैं जो बाहरी नेटवर्क को वैध विकल्पों पर अपने दुष्ट मार्ग को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करते हैं।
- ट्रैफिक ब्लैकहोलिंग: एक बार जब ट्रैफिक को दुष्ट नेटवर्क में सफलतापूर्वक खींच लिया जाता है, तो ऑपरेटर पैकेट को पूरी तरह से छोड़ सकता है। यह डेटा को एक परिचालन शून्य में छोड़ देता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए तत्काल सेवा से इनकार (DoS) होता है।
- मैन-इन-द-मिडिल (एमआईटीएम) क्षमता: डायवर्ट किए गए ट्रैफिक को नष्ट करने के बजाय, एक दुर्भावनापूर्ण ऑपरेटर डेटा को वास्तविक गंतव्य पर अग्रेषित करने से पहले गुप्त रूप से निरीक्षण, लॉग या हेरफेर कर सकता है, मूक निगरानी निष्पादित कर सकता है।
- कैस्केडिंग ग्लोबल प्रोपेगेशन: क्योंकि ऑटोनॉमस सिस्टम लगातार एक-दूसरे के साथ रूटिंग टेबल साझा करते हैं, एक क्षेत्र में की गई एक भी झूठी प्रविष्टि मिनटों के भीतर वैश्विक वाहक नेटवर्क में तरंग पैदा कर सकती है, जिससे दुनिया भर के उपयोगकर्ता बाधित हो सकते हैं।

निहितार्थ:

- बीजीपी अपहरण इंटरनेट ट्रैफिक को सीमाओं के पार पुनर्निर्देशित कर सकता है, जिससे अनपेक्षित व्यवधान पैदा हो सकता है और साइबर संघर्षों के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- यहां तक कि छोटी-मोटी रूटिंग त्रुटियां भी प्रमुख वेबसाइटों और एप्लिकेशन को डिस्कनेक्ट कर सकती हैं, जिससे व्यापक डिजिटल सेवा विफलता हो सकती है।
- रीरूट किया गया ट्रैफिक अनएन्क्रिप्टेड डेटा को इंटरसेप्शन के लिए उजागर कर सकता है, जिससे जासूसी, क्रेडेंशियल चोरी और गोपनीयता उल्लंघनों का खतरा बढ़ सकता है।

डाउनलोडिंग प्रक्रिया

संदर्भ:

पश्चिम एशिया संकट को समाप्त करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक सहयोग ज्ञापन के तहत, अमेरिका और ईरान सख्त अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की देखरेख में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करने के लिए सहमत हुए हैं।

डाउनलोडिंग प्रक्रिया

डाउनलोडिंग प्रक्रिया के बारे में:

यह क्या है?

- डाउनलोडिंग एक अत्यधिक विनियमित परमाणु इंजीनियरिंग प्रक्रिया है जो यूरेनियम संवर्धन के ठीक विपरीत के रूप में कार्य करती है। इसमें अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम (एचईयू) लेना शामिल है - जिसमें परमाणु बम को बनाए रखने में सक्षम विखंडनीय आइसोटोप यूरेनियम-235 (235 यू) की उच्च सांद्रता होती है - और इसकी रासायनिक शुद्धता को एक सुरक्षित, कम समृद्ध यूरेनियम (एलईयू) अवस्था में कम करने के लिए इसे प्राकृतिक या समाप्त यूरेनियम के साथ मिलाना शामिल है।
- उद्देश्य: डाउनलोडिंग का प्राथमिक उद्देश्य हथियार बनाने के लिए उपलब्ध 235U की भौतिक मात्रा को व्यवस्थित रूप से कम करके परमाणु प्रसार के तत्काल खतरे को खत्म करना है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- आटोक्लेव के माध्यम से गैसीकरण: आटोक्लेव में UF_6 फीडस्टॉक को 80-110 °C तक गर्म किया जाता है, जिससे कुशल सम्मिश्रण और प्रसंस्करण के लिए ठोस को गैस में परिवर्तित किया जाता है।
- ब्लेंडस्टॉक परिवय: समृद्ध सामग्री में यूरेनियम-235 की सांद्रता को कम करने के लिए एक कम समृद्ध यूरेनियम गैस को तनुकरण एजेंट के रूप में जोड़ा जाता है।
- ब्लेंडिंग टी में अज्ञात मिश्रण: दोनों गैस धाराएँ एक सम्मिश्रण टी में प्रवेश करती हैं जहाँ बाफ़ल अज्ञाति पैदा करते हैं, जिससे पूर्ण और समान मिश्रण सुनिश्चित होता है।
- मास फ्लो कंट्रोल और मॉनिटरिंग: स्वचालित सेंसर गैस अनुपात को नियंत्रित करते हैं जबकि संवर्धन मॉनिटर U-235 स्तरों को ट्रैक करते हैं और सीमा पार होने पर शटडाउन को ट्रिगर करते हैं।
- ठोसीकरण और पुनः रूपांतरण: मिश्रित UF_6 को जम जाता है और फिर यूरेनियम डाइऑक्साइड (UO_2) में परिवर्तित किया जाता है, जो प्रत्यक्ष संवर्धन के लिए अनुपयुक्त एक स्थिर रूप है।
- आईईए लैब सत्यापन और सीलिंग: आईईए विशेषज्ञ प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से संवर्धन स्तर की पुष्टि करते हैं और सामग्री को छेड़छाड़-रोधी सील से सुरक्षित करते हैं।

सिस्टम की मुख्य विशेषताएं: YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- सख्त कम-संवर्धन सीमाएं: यह प्रक्रिया हथियार-ग्रेड यूरेनियम को 5% U-235 से कम कर देती है, जिससे यह केवल नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त हो जाता है।
- रिवर्सल बैरियर प्रवर्तन: UF_6 को UO_2 में परिवर्तित करना एक तकनीकी बाधा पैदा करता है, जिसके लिए पुनः संवर्धन के लिए एक दृश्यमान और जटिल पुनः रूपांतरण सुविधा की आवश्यकता होती है।
- गहन सुरक्षा प्रोटोकॉल: निरंतर निगरानी, स्वचालित ट्रैकिंग सिस्टम और 24/7 निगरानी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और अनधिकृत डायवर्जन को रोकती है।



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

संदर्भ:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने ओडिशा के बलांगीर से ऑस्ट्रेलिया को सूखे पूरे अंडे के पाउडर के भारत के पहले वाणिज्यिक निर्यात शिपमेंट की सफलतापूर्वक सुविधा प्रदान की है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के बारे में:

यह क्या है?

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित एक शीर्ष वैधानिक निर्यात-संवर्धन निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चैनलों के निर्माण, गुणवत्ता मानक स्थापित करने और भारत के कृषि, बागवानी और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के वैश्विक बाजार विस्तार को चलाते के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- एपीडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी।



उद्देश्य:

- एपीडा का उद्देश्य निर्यातानुमुखी डाउनस्ट्रीम कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देकर भारत की कृषि निर्यात क्षमता को अधिकतम करना है।
- इसका उद्देश्य भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, कम मूल्य वाले कच्चे निर्यात को उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत वस्तुओं से प्रतिस्थापित करना, सख्त अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और घरेलू किसानों और कृषि-उद्यमियों के लिए वित्तीय रिटर्न का अनुकूलन करना है।

महत्वपूर्ण कार्य:

- निर्यातकों का वैधानिक पंजीकरण: भारत से अनुसूचित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात करने वाले व्यक्तियों या कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए अनिवार्य रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानक स्थापित करना: अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमों, पैकेजिंग आवश्यकताओं और स्वच्छता उपायों का सख्त अनुपालन लागू करता है - जिससे घरेलू इकाइयों को FSSC 22000, हलाल और कोषेर जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र सुरक्षित करने में मदद मिलती है।
- वित्तीय अवसंरचना सहायता: प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं को उन्नत करने और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए पंजीकृत निर्यातकों को लक्षित वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार करता है।
- बाजार विकास और वैश्विक प्रचार: अंतरराष्ट्रीय बाजार-सुफिया सर्वेक्षण आयोजित करता है, वैश्विक व्यापार मेलों का समन्वय करता है, स्वरीदार-विक्रेता बैठकों का प्रबंधन करता है, और यूरोपीय संघ जैसे प्रीमियम क्षेत्रों में नए निर्यात रास्ते खोलने के लिए वर्चुअल प्लेनिंग समारोहों का नेतृत्व करता है।
- अनुसूचित उत्पाद विकास: फलों, सब्जियों, मांस उत्पादों, पोल्ट्री, डेयरी, कन्फेक्शनरी, बिस्कुट और बेकरी आइटम सहित निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात जीवनचक्र की निगरानी और वृद्धि करता है।
- निर्यात आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण: ग्रामीण और विकासशील क्षेत्रों में मजबूत, निर्यात-आधारित कृषि-प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य विभागों, जिला प्रशासनों और निजी उद्योगों के साथ सीधे समन्वय करता है।

महत्त्व:

- अंडे को स्प्रे-ड्राइड पाउडर में परिवर्तित करने से शेल्फ लाइफ बढ़ती है, परिवहन लागत कम होती है, और भारतीय पोल्ट्री निर्यातकों को प्रसंस्कृत उत्पादों से उच्च मूल्य अर्जित करने में सक्षम बनाता है।
- ऑस्ट्रेलिया को निर्यात से पता चलता है कि भारतीय पोल्ट्री उत्पाद सख्त यूरोपीय संघ के सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे अन्य विनियमित वैश्विक बाजारों तक पहुंच खुल जाती है।

भारत 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज रीसाइक्लिंग राष्ट्र बना

संदर्भ:

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में दुनिया के अग्रणी जहाज रीसाइक्लिंग राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसने शीर्ष रैंकिंग 35.4% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया।

भारत 2025 में दुनिया का शीर्ष जहाज रीसाइक्लिंग राष्ट्र बना

2025 में भारत दुनिया का शीर्ष जहाज रीसाइक्लिंग राष्ट्र बन गया:

यह क्या है?

- यह नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलों द्वारा संचालित एक प्रमुख समुद्री मील का पत्थर है, जिसने भारत को जिम्मेदार, टिकाऊ और उत्त्व मात्रा में जहाज तोड़ने और रीसाइक्लिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदल दिया है।

भारत द्वारा की गई पहल:

- एक स्थायी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने कई लक्षित कार्यक्रम लागू किए:
- हांगकांग कन्वेंशन सेरेखण: जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि पुनर्वर्तन (HKC) के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ घरेलू यादों को सेरेखित करने के लिए जहाजों का पुनर्वर्तन अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया गया।
- वित्तीय बुनियादी ढांचा सहायता: जहाज रीसाइक्लिंग सुविधाओं को उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रमाणित करने के लिए वित्तीय सहायता में ₹53.5 करोड़ वितरित किए गए।
- शिप-ब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना: एक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया जहां जहाज मालिकों को पुनर्नवीनीकरण जहाज के स्ट्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट नोट प्राप्त होता है, जिसे भारतीय शिपयार्ड में एक नए जहाज के निर्माण की लागत के 5% तक ऑफसेट करने के लिए लागू किया जा सकता है।
- वैश्विक पहुंच की खोज: भारतीय जहाज रीसाइक्लिंग यार्ड को यूरोपीय संघ जहाज पुनर्वर्तन विनियम (ईयूएसआरआर) अनुमोदित सुविधा सूची में एकीकृत करने के लिए यूरोपीय अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना।

भारत के 2025 प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं:

- विशाल मात्रा में वृद्धि: भारत ने 2025 में 99 मिलियन सकल टन (जीटी) शिपिंग मात्रा का पुनर्वर्तन किया, जो 2024 में दर्ज 1.86 मिलियन जीटी से 60% की तेज वृद्धि को दर्शाता है।
- प्रमुख बाजार हिस्सेदारी: देश की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में 4% हो गई, जो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन करती है।
- व्यापक हरित अनुपालन: वित्तीय सहायता ने 115 घरेलू सुविधाओं को स्वस्थ, पर्यावरण-अनुकूल एवकेसी अनुपालन प्राप्त करने में सफलतापूर्वक मदद की।
- अलंग में क्षमता विस्तार: अलंग शिप रीसाइक्लिंग यार्ड का विस्तार करने के लिए गुजरात सरकार के माध्यम से एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसका लक्ष्य 9 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन (LDT) की क्षमता को लगभग दोगुना करना है।
- सहयोगात्मक उद्योग शासन: पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, गुजरात समुद्री बोर्ड, नकद खरीदारों, वर्गीकरण समितियों और शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जोड़ने वाली संरचित समन्वय पाइपलाइनों की स्थापना की गई।

चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

संदर्भ:

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग III के तहत सीमांकित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।

चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है:

यह क्या है?

- चलने का अधिकार एक नया मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार है जो कानूनी रूप से नागरिकों को मोटर चालित सड़कों के साथ-साथ अच्छी तरह से बनाए रखा, सीमांकित फुटपाथों और पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के सुरक्षित और निर्बाध उपयोग की गारंटी देता है।



- यह निर्णय स्थापित करता है कि यदि कोई सार्वजनिक सड़क मौजूद है तो राज्य का चलने योग्य स्थानों का निर्माण और सुरक्षा करने का एक अनुरूप, गैर-परक्राम्य कर्तव्य है।

संवैधानिक नींव:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई लेखों को एक साथ पढ़कर संविधान के भाग III में चलने के अधिकार को एकीकृत किया:
- अनुच्छेद 19(1)(d): प्राथमिक आधार के रूप में कार्य करता है, जो भारत के पूरे क्षेत्र में आवाजाही की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), और 19(1)(c): अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संघ की सहायक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपस में जुड़े हुए हैं, जिनमें से सभी को निष्पादित करने के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 21: जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मानजनक सार्वजनिक अस्तित्व के मौलिक अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में पैदल यात्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू किया गया।

निर्णय की मुख्य विशेषताएं:

- मोटर परिवहन पर प्राथमिक प्राथमिकता: अदालत ने माना कि सीमांकित फुटपाथ का उपयोग करने का नागरिक का अधिकार प्राथमिक है और मोटर चालित वाहनों पर कानूनी प्राथमिकता रखता है।
- विशिष्ट कर्तव्य धारकों की पहचान: निर्णय स्पष्ट रूप से पैदल मार्ग के निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक निकायों को परिभाषित करता है, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों का स्पष्ट रूप से नामकरण किया गया है।
- नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचार: सुरक्षित फुटपाथों का कोई भी उत्लंघन या बाधा नागरिकों को क्षतिपूर्ति और वित्तीय मुआवजे के लिए कर्तव्यवाहकों के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपचार लागू करने का अधिकार देती है। यह मार्ग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मानक दावों से पूरी तरह से स्वतंत्र है।
- एक नए वैधानिक ढांचे का आह्वान: स्टैंडअलोन पैदल यात्री कानून की कुल अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पैदल यात्री बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने के लिए एक समर्पित कानूनी ढांचे की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया।
- एक समर्पित नियामक का निर्माण: यह निर्णय एक पूर्णकालिक, स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की सिफारिश करता है जिसे विशेष रूप से पैदल यात्री सुरक्षा मानकों की योजना बनाने, लागू करने और लागू करने का काम सौंपा गया है।

ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

संदर्भ:

भारत ने 2026 के लिए BRICS अध्यक्ष के रूप में बेंगलुरु में BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों (HOSA) की बैठक की मेजबानी की। भारत ने सदस्य देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग, नवाचार और सतत विकास को मजबूत करने के लिए "ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था" की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है।

ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बारे में:

यह क्या है?

- ब्रिक्स अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नवाचार, उपग्रह अनुप्रयोगों और वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों में ब्रिक्स देशों के बीच गहरे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्तावित सहयोगी ढांचा है।

उद्देश्य:

- ब्रिक्स देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण और संयुक्त नवाचार के माध्यम से एक लचीली और समावेशी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
- जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन (RSSC) को मजबूत करना: आपदा प्रबंधन, कृषि, मौसम निगरानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच उपग्रह डेटा साझाकरण को बढ़ावा देता है।
- प्रस्तावित ब्रिक्स अंतरिक्ष परिषद: अंतरिक्ष सहयोग में दीर्घकालिक समन्वय और नीति निरंतरता के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है।
- अंतरिक्ष स्थिरता पर ध्यान: सदस्य देशों ने मलबे मुक्त मिशनों, जिम्मेदार अंतरिक्ष संचालन और बाहरी अंतरिक्ष के सतत उपयोग पर जोर दिया।



- न्यूरुपेस और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: यह पहल ब्रिक्स देशों में स्टार्टअप, निजी उद्योगों, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

महत्व:

- ब्रिक्स देशों के पास महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षमताएं, औद्योगिक ताकत और बाजार का आकार है, जो उन्हें वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने में सक्षम बनाता है।
- संयुक्त अंतरिक्ष अनुप्रयोग आपदा प्रबंधन, जलवायु निगरानी, नेविगेशन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन कर सकते हैं।

सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी)

संदर्भ:

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए जुलाई 2026 में सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।

सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी)

सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) के बारे में:

यह क्या है?

- सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी) एक मैक्रो-इकोनॉमिक अल्पकालिक संकेतक है जिसे सेवा क्षेत्र द्वारा उत्पादित आउटपुट की वास्तविक मात्रा में समय के साथ मासिक परिवर्तनों को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के प्रत्यक्ष समकक्ष के रूप में कार्य करता है।
- नोडल मंत्रालय: सूचकांक भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा संकलित, प्रबंधित और प्रसारित किया जाता है।

उद्देश्य और उद्देश्य

- उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक रुझानों को पकड़ने के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक आंदोलन पर आईआईपी के पूरक हैं।
- साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों, आर्थिक पूर्वानुमान और व्यापार चक्र विश्लेषण का समर्थन करने के लिए सेवा उद्योग के प्रदर्शन पर समय पर जानकारी के साथ योजनाकारों और नीति निर्माताओं को प्रदान करना।
- एक ऐसे क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करना जो एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जो 2013-14 से भारत के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 50% से अधिक का योगदान देता है।

इसकी गणना कैसे की जाती है:

- डेटा स्रोतों का संरचना: आउटपुट डेटा को तीन प्रमुख परिचालन पाइपलाइनों में जमा किया जाता है:
- जीएसटी डेटाबेस: वास्तविक समय सेवा कारोबार को दर्शाने के लिए बाहरी आपूर्ति पर जीएसटीआर -1 फाइलिंग से एकत्रित सेवा लेखा कोड (एसएसी) डेटा का उपयोग करता है।
- प्रशासनिक रिकॉर्ड: बैंकिंग और बीमा के लिए प्रदर्शन लॉग के साथ-साथ हवाई और रेलवे परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए सीधे द्वितीयक मात्रा मेट्रिक्स खींचता है।
- एसआईएसएसई सर्वेक्षण: गैर-सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा उप-क्षेत्रों के लिए निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण से अनुमान लगाया जाता है।
- अपस्फीति प्रक्रिया: वास्तविक मात्रा मेट्रिक्स प्राप्त करने के लिए नामित सूचकांकों का उपयोग करके मूल्य-आधारित (नाममात्र) टर्नओवर डेटा को अपस्फीति की जाती है। थोक व्यापार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का उपयोग करता है; बैंकिंग और बीमा सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का उपयोग करते हैं; जबकि अन्य उप-क्षेत्र स्वीकार्य प्रॉक्सी के रूप में विशिष्ट सीपीआई डिवीजनों या सीपीआई (गैर-खाद्य) पर भरोसा करते हैं।
- वजन असाइनमेंट: व्यक्तिगत क्षेत्र के भार को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से खींचे गए सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में उनके सापेक्ष आर्थिक योगदान के आधार पर सख्ती से सौंपा जाता है।
- गणितीय सूत्र: अंतिम गणना संरचनात्मक रूप से एक निश्चित वजन वाले लास्पेयर्स वॉल्यूम इंडेक्स फॉर्मूला का उपयोग करके संकलित की जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- आधार वर्ष चयन: श्रृंखला 2024-25 को अपने आधार वर्ष के रूप में उपयोग करती है, जो सीपीआई की नई श्रृंखला के साथ संरचनात्मक नवीनता और संरेखण के मानदंडों को पूरा करती है।
- मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र कवरेज: सूचकांक औपचारिक कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र को दर्शाता है क्योंकि इसके आधारभूत पैरामीटर जीएसटी नेट के तहत आधिकारिक तौर पर पंजीकृत इकाइयों के आसपास बनाए गए हैं।

- रणनीतिक बहिष्करण: यह स्पष्ट रूप से मुख्य सरकार, गैर-बाजार, और भारी असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रों को बाहर करता है, जिसमें लोक प्रशासन और रक्षा, व्यक्तिगत सेवाएं, जुआ, आवास के बिना सामाजिक कार्य और केंद्रीय बैंक मौद्रिक गतिविधियां शामिल हैं।
- प्रारंभिक चरणबद्ध रोलआउट: स्वास्थ्य और शिक्षा (सरकार को छोड़कर) जैसे उप-क्षेत्रों को बाद में ढांचे में एकीकृत किया जाएगा, एक बार पूर्ण ASISSE सर्वेक्षण रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हो जाएगी।
- मासिक रिलीज चक्र: लगभग 60 दिनों के संरचनात्मक अंतराल के साथ मासिक आधार पर प्रसारित, विशेष रूप से हर महीने के 29वें दिन रिलीज के लिए निर्धारित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

संदर्भ:

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपना अब तक का सबसे अधिक समुद्री खाद्य निर्यात दर्ज किया , जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक बाजार स्थितियों के बावजूद ₹73,890 करोड़ (8.46 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के 19.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया:

यह क्या है?

- भारत ने समुद्री उत्पाद निर्यात में अब तक का उच्चतम स्तर हासिल किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,890.46 करोड़ (8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 19,72,018 मीट्रिक टन तक पहुंच गया।

मुख्य निष्कर्ष:

- रिकॉर्ड निर्यात प्रदर्शन: समुद्री खाद्य निर्यात 19.72 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जिसका मूल्य ₹73,890 करोड़ (8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जो मात्रा और मूल्य दोनों में अब तक का सबसे अधिक है।

जमे हुए झींगा स्टार निर्यात बने रहे:

- 49,037.93 करोड़ रुपये (5.62 बिलियन अमरीकी डालर) मूल्य के 7,92,647 मीट्रिक टन जमे हुए झींगा का निर्यात किया।
- निर्यात मात्रा का 40.19% और निर्यात आय का 66.52% हिस्सा है।
- रुपये के संदर्भ में 13.16 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।



जमे हुए झींगा स्टार निर्यात बने रहे



जमे हुए झींगा स्टार निर्यात बने रहे

- प्रमुख निर्यात बंदरगाह: विशाखापत्तनम (विजाग), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) और कोच्चि पोर्ट।
- झींगा प्रभुत्व जारी है: वन्नामेई और ब्लैक टाइगर झींगा ने मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत के वैश्विक झींगा नेतृत्व को मजबूती मिली।

महत्व:

- रिकॉर्ड समुद्री खाद्य निर्यात से भारत की नीली अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, रोजगार, विदेशी मुद्रा और तटीय आर्थिक वृद्धि हुई है।
- तटीय राज्यों में मछली पकड़ने, जलीय कृषि, प्रसंस्करण, रसद और समुद्री निर्यात में लगे लाखों लोगों की सहायता करता है।
- 8.46 बिलियन अमरीकी डालर की निर्यात आय भारत के व्यापार संतुलन और निर्यात विविधीकरण को मजबूत करती है।

अनुसूचित इंडियन एयरलाइंस के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के एकमुश्त बजटीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है।

अनुसूचित इंडियन एयरलाइंस के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि

अनुसूचित भारतीय एयरलाइंस के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के बारे में:

यह क्या है?

- अनुसूचित इंडियन एयरलाइंस के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित एक अस्थायी, एकल-खिड़की सूक्ष्म-आर्थिक बफर तंत्र है।
- इसे पश्चिम एशिया संकट के बढ़ने के बाद अभूतपूर्व वैश्विक ईंधन बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए एक प्रत्यक्ष नीति प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित किया गया था, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय एटीएफ की कीमतें मार्च 2026 में ₹60.50 प्रति लीटर से 2.5 गुना बढ़कर मई 2026 में ₹142 प्रति लीटर हो गई।

उद्देश्य:

- इस कोष का उद्देश्य ईंधन खरीद के लिए मूल्य स्थिरता और संरचनात्मक पूर्वानुमान प्रदान करना है, जिससे घरेलू वाहकों और ओएमसी दोनों को गंभीर वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके।
- अचानक ईंधन में वृद्धि को बेअसर करके, यह भारत के हवाई संपर्क नेटवर्क को बनाए रखने, यात्री टिकट किराए को स्थिर करने और व्यापक नागरिक उड्डयन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने का प्रयास करता है।

फंड की मुख्य विशेषताएं:

- ओएमसी को ब्याज मुक्तअग्रिम: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों के माध्यम से ₹10,000 करोड़ तक का आवंटन करता है। यह कॉर्पस सीधे OMC के नुकसान की भरपाई करता है जब अंतराष्ट्रीय आयात समता मूल्य (IPP) फंड के निर्दिष्ट बेंचमार्क से अधिक हो जाता है।
- पुनर्प्राप्ति और टू-अप तंत्र: एक परिक्रामी, गैर-घाटे वाले मॉडल के रूप में कार्य करता है। जब वैश्विक एटीएफ दरें सीमा से नीचे गिर जाती हैं, तो ओएमसीज से अंतर कुशन वसूल किया जाता है और अग्रिम का निपटान होने तक भारत की संवित निधि में वापस कर दिया जाता है।
- सार्वभौमिक उड़ान संचालन कवरेज: पिछले तदर्थ राहत पैकेजों के विपरीत, यह स्थिरीकरण विंडो सभी इच्छुक अनुसूचित भारतीय वाहकों के लिए उनके घरेलू और अंतराष्ट्रीय उड़ान मांगों दोनों के लिए उपलब्ध है।
- फिक्स्ड-प्राइस फ्यूल अरेंजमेंट: ओपन-मार्केट ट्रेडिंग अस्थिरता के लिए एयरलाइन के दैनिक जोखिम को खत्म करने के लिए फिक्स्ड-प्राइस फ्यूल एग्जीमेंट स्थापित करता है, जो कॉर्पोरेट पूर्वानुमान के लिए स्पष्ट लागत पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- विशेष OMC सोर्सिंग लॉक-इन: भाग लेने वाली एयरलाइंस, OMC, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित एक औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। स्थिर मूल्य निर्धारण के बदले में, एयरलाइनें तीन साल तक के लिए भाग लेने वाली ओएमसीज से विशेष रूप से एटीएफ खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- कठोर त्रि-मंत्रालयी निरीक्षण: दावों को सत्यापित करने और सख्त स्वतंत्र ऑडिट को अनिवार्य करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और व्यय विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक समर्पित निगरानी समिति की स्थापना करती है।
- परिभाषित ऑपरेशन जीवनकाल: फंड 36 महीने तक सक्रिय रहने के लिए तैयार है। हालांकि, इसमें वार्षिक समीक्षा या पूर्ण नकद वसूली पर जल्दी बंद करने का प्रावधान है, एक विस्तार विकल्प के साथ यदि कॉर्पस तीन साल के भीतर पूरी तरह से नहीं हुआ है।



ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: भारत के व्यापार ढांचे को मजबूत करना

संदर्भ:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत के व्यापार परिदृश्य को बदलने वाले व्यापक नियामक सुधारों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक पृष्ठभूमि जारी की।

- डिजिटल गवर्नेंस, विश्वास-आधारित प्रशासन और अनुपालन बोझ में कमी से प्रेरित इन पहलों ने निवेशकों के विश्वास को काफी बढ़ाया है और भारत की वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है।

व्यापार करने में आसानी

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में: भारत के व्यापार ढांचे को मजबूत करना

यह क्या है?

- भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेमवर्क एक रणनीतिक, राज्य-निर्देशित परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक अनुपालन-भारी नौकरशाही प्रणाली से डिजिटल, सुविधा-संचालित नियामक इकोसिस्टम में बदल गया है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और कई केंद्रीय मंत्रालयों के तत्वावधान में प्रबंधित, यह कागज रहित प्रविष्टि, स्वचालित अनुमोदन, खुले डिजिटल वाणिज्य और विश्वास-आधारित शासन ढांचे के माध्यम से व्यावसायिक जीवन चक्र को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित है।

प्रमुख प्रदर्शन रैंकिंग और मेट्रिक्स:

- विश्व बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट: भारत की रैंक ने 79 स्थानों की भारी छलांग का अनुभव किया, जो 2014 में 142 वें स्थान से बढ़कर 2019 में 63 वें स्थान पर पहुंच गया।
- IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग: निरंतर संरचनात्मक और शासन दक्षता को दर्शाते हुए, भारत की रैंकिंग 2021 में 43वें स्थान से बढ़कर 2025 में 41वें स्थान पर पहुंच गई।
- गोवटेक मैट्योरिटी इंडेक्स: विश्व बैंक ने उन्नत डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र के परिवर्तन का सम्मान करते हुए भारत को 2020, 2022 और 2025 में अपनी शीर्ष स्तरीय ग्रुप ए श्रेणी में रखा।
- संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण: भारत ने दूरसंचार बुनियादी ढांचे और मानव पूंजी में मजबूत मेट्रिक्स के साथ-साथ ऑनलाइन सेवा सूचकांक में बहुत उच्च स्कोर हासिल किया।

भारत के व्यापार ढांचे की वर्तमान स्थिति:

व्यवसाय में प्रवेश और औपचारिकता:

- स्टार्टअप इंडिया: मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 502 (2016) से बढ़कर 2.23 लाख (2026) हो गए, जिससे 23.3 लाख नौकरियां पैदा हुईं; लगभग 48% के पास कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार हैं।
- SPICe+ फॉर्म: एकीकृत 10 निगमन प्रक्रियाओं को एक ही ऑनलाइन फॉर्म में, कई मंत्रालयों और राज्यों में सेवाओं को एकीकृत करना।
- एमसीए21 वी3 और उद्यम: एमसीए21 ने 3.84 करोड़ फाइलिंग (2021-25) की प्रोसेसिंग की, जिसमें 3.33 करोड़ एसटीपी के माध्यम से स्वीकृत किए गए। मासिक उद्यम पंजीकरण 10,000 (2020) से बढ़कर 8.58 लाख (2026) हो गया।

संपत्ति पंजीकरण और परमिट:

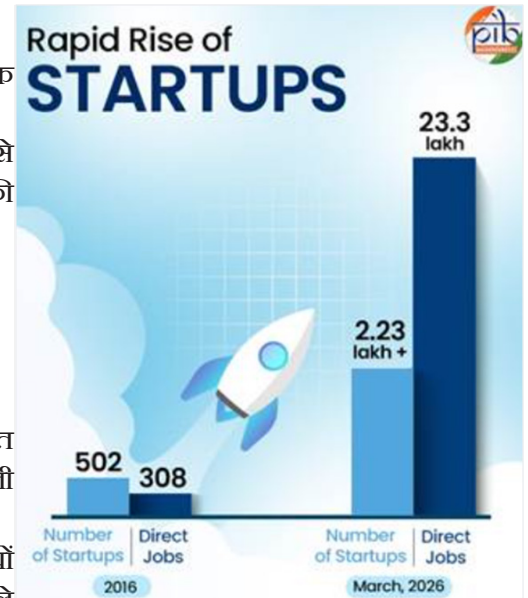
- डीआईएलआरएमपी: भूकर मानचित्रों के 97.37% का डिजिटलीकरण किया गया और 36 करोड़ से अधिक भूमि पार्सल को यूएलपीआईएन (भूमि के लिए आधार) सौंपा गया।
- एनएसडब्ल्यूएस और परिवेश 2.0: एनएसडब्ल्यूएस 32 केंद्रीय विभागों और 34 राज्यों से अनुमोदनों को एकीकृत करता है, 8.29 लाख+ मंजूरी देता है। परिवेश ने निकासी का समय घटाकर 64 दिन कर दिया।

बाजार कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स:

- जीईएम: अकेले वित्त वर्ष 26 में 5 लाख करोड़ रुपये के साथ 18.4 लाख करोड़ रुपये की संचयी खरीद हासिल की; एमएसई ने 68% ऑर्डर दिए।
- पीएम गतिशक्ति: 3,199 जीआईएस परतों के माध्यम से 58 मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना को एकीकृत करता है; 16.1 लाख करोड़ रुपये की 352 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन: भारत लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 54वें (2014) से 38वें (2023) तक सुधर गया है। एलडीबी 2.0 ने 100% एविजम कंटेनरों (~95 मिलियन) को ट्रैक किया।

ऋण पहुंच, कराधान और डिजिटल बुनियादी ढांचा:

- ऋण सहायता: CGTMSE ने 2015 से गारंटी के रूप में ₹9.34 लाख करोड़ प्रदान किए, जबकि PMMY ने 57 करोड़ ऋणों के माध्यम से ₹40.07 लाख करोड़ वितरित किए।



- UPI विस्तार: ट्रांज़ैक्शन 2 करोड़ (FY17) से बढ़कर 24,162 करोड़ (FY26) हो गया, जिससे ₹314 लाख करोड़ प्रोसेस हुआ, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन गई।
- जीएसटी और ई-वे बिल: जीएसटी करदाताओं की संख्या 60 लाख से बढ़कर 1.64 करोड़ हो गई; इस प्रणाली ने भुगतान में ₹107.64 लाख करोड़ की प्रक्रिया की। वित्त वर्ष 2026 में 188.27 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए।

सुधारों की सफलता:

- सुविधा-संचालित ऑडिट के माध्यम से इंस्पेक्टर राज का उन्मूलन: पारंपरिक, भ्रष्ट भौतिक निरीक्षणों को व्यवस्थित रूप से पारदर्शी डिजिटल प्रोटोकॉल द्वारा बदल दिया गया है।
- उदाहरण: 2025 श्रम संहिताओं ने वेब-आधारित, यादृच्छिक निरीक्षण असाइनमेंट पेश किए और कॉर्पोरेट अनुपालन को सक्रिय रूप से मार्गदर्शन करने के लिए फ़िल्ड निरीक्षकों को निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ताओं में बदल दिया।
- दोहराव वाले औद्योगिक अनुपालन ओवरहेड में कमी: हरित उद्योगों को दीर्घकालिक परिचालन निरंतरता देने के लिए कॉर्पोरेट अनुपालन नवीनीकरण को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- उदाहरण: समान सहमति दिशानिर्देशों में संशोधन ने औद्योगिक सहमति को रद्द होने तक संचालित करने के लिए औद्योगिक सहमति (सीटीओ) को वैध बना दिया, जिससे समय-समय पर नवीनीकरण का नौकरशाही बोझ दूर हो गया।
- समावेशिता और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना: ऋण की औपचारिकता ने ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुख्यधारा की राजकोषीय अर्थव्यवस्था में ला दिया है।
- उदाहरण: मुद्रा योजना योजना के तहत, महिला उद्यमी कुल परिचालन ऋण खातों में 59.81% हिस्सेदारी का दावा करती हैं।
- ई-कॉमर्स और सार्वजनिक खरीद बाजारों का लोकतंत्रीकरण: खुले नेटवर्क ने पहले बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा-विरोधी एकाधिकार को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है।
- उदाहरण: ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने 616+ शहरों में 7.64 लाख से अधिक विक्रेताओं को सफलतापूर्वक शामिल किया है, जिससे छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए खेल का मैदान समतल हो गया है।

व्यापार ढांचे से जुड़ी चुनौतियाँ:

- राज्यों और जिलों में असमान कार्यान्वयन गति: जबकि केंद्रीय डिजिटल पोर्टल निर्बाध रूप से काम करते हैं, अंतिम-मील निष्पादन विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों में खंडित रहता है।
- उदाहरण: राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) केवल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित है, जिससे आधे से अधिक देश विरासत भूमि-उत्पत्ति रिकॉर्ड मॉडल पर रह गया है।
- कॉर्पोरेट संकट को हल करने में प्रारंभिक टर्नअराउंड घर्षण: एक एकीकृत दिवाला ढांचे के बावजूद, स्थानीय न्यायाधिकरण की बाधाएं अभी भी परिसंपत्ति परिसमापन में देरी कर सकती हैं।
- उदाहरण: निर्णायक अधिकारी नियमित रूप से अपनी अनिवार्य समयसीमा के भीतर दिवालियापन याचिकाओं को संसाधित करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेनदारों के लिए पूंजी वसूली खिड़कियों को खींचते हैं।
- स्थानीय भू-राजस्व रिकॉर्ड में डेटा विसंगतियाँ: ग्रामीण डेटा बहीखातों के भीतर मौजूद ऐतिहासिक त्रुटियों के कारण भूमि पंजीकरण पारदर्शिता अक्सर बाधित होती है।
- उदाहरण: मैनुअल विरासत राजस्व कागजात और आधुनिक उत्त-रिज़ॉल्यूशन हवाई भूकर मानचित्रों के बीच विसंगतियाँ डिजिटल बंधक सत्यापन के दौरान घर्षण पैदा करती हैं।
- उन्नत तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के लिए भाषा बाधाएं: छोटे कारीगरों और ग्रामीण एमएसएमई को परिष्कृत ऑनलाइन बोली डैशबोर्ड को नेविगेट करते समय सीखने की अवस्था का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण: जीईएम ई-लॉनिंग पाठ्यक्रमों के 12 आधिकारिक भाषाओं में विस्तार के बावजूद, हजारों ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को अभी भी स्वचालित बोली वर्कफ़्लो का प्रबंधन करने के लिए बाहरी बिचौलियों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- दिवाला निर्णय के लिए सख्त समय सीमा लागू करना: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए यह अनिवार्य करें कि स्थानीय पीठ 14 दिनों की सख्त अवधि के भीतर याचिकाओं को स्वीकार या अस्वीकार करें।
- जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (D-BRAP) का विस्तार: सभी ग्रामीण कलेक्ट्रेट और नगर निगमों में D-BRAP की तैनाती में तेजी लाना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिंगल-विंडो सिस्टम जमीनी स्तर पर अनुमानित रूप से कार्य करे।
- MSME लिविबिलिटी के लिए TReDS सेटलमेंट आर्किटेक्चर को अनिवार्य करना: सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) को अनिवार्य बनाने के लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट प्रस्ताव को लागू करना, विलंबित चालानों की तेजी से निकासी सुनिश्चित करना।
- शेष छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना: मामूली, गैर-धोखाधड़ी वाली अनुपालन त्रुटियों को आपराधिक जेल की शर्तों से साधारण मौद्रिक जुर्माने में बदलने के लिए शेष क्षेत्रीय कानूनों को रकैन करके जन विश्वास अधिनियम 2026 पर निर्माण करें।
- निर्यात संवर्धन मिशन के माध्यम से वैश्विक व्यापार नेटवर्क को गहरा करना: छोटे निर्यातकों को विदेशी भंडारण और व्यापार

वित्त तक स्वचालित पहुंच प्रदान करने के लिए नई अनुमोदित निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा उप-योजनाओं के पदचिह्न को अधिकतम करना।

निष्कर्ष:

एक सुव्यवस्थित, सुविधा-संचालित कारोबारी माहौल की ओर भारत का परिवर्तन मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ नीति डिजाइन के संयोजन की शक्ति पर प्रकाश डालता है। प्रवेश प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से आधुनिक बनाकर, ओएनडीसी जैसे खुले वाणिज्य प्रोटोकॉल का विस्तार करके और पुरानी नियामक बाधाओं को विश्वास-आधारित प्रशासन के साथ बदलकर, राष्ट्र ने स्थायी उद्यमिता के लिए एक लचीली नींव रखी है।

ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स

संदर्भ:

भारत वर्तमान में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स के भीतर अपने सरकारी बॉन्ड को शामिल करने के लिए प्रमुख पूंजी बाजार सुधारों को क्रियान्वित कर रहा है।

ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स

ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स के बारे में:

यह क्या है?

- ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिक्स्ड-इनकम बेंचमार्क है जो वैश्विक स्तर पर निवेश-ग्रेड, फिक्स्ड-रेट बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। जिस तरह निपटी 50 या सेंसेक्स बेंचमार्क सूचीबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाओं के इतिवटी प्रदर्शन की निगरानी करते हैं, उसी तरह यह सूचकांक बहु-ट्रिलियन डॉलर के संप्रभु और कॉर्पोरेट ऋण बाजारों के लिए निश्चित वैश्विक ट्रैकिंग लेजर के रूप में कार्य करता है।
- विकसित: सूचकांक का निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य:

- इंडेक्स का उद्देश्य संस्थागत फंड मैनेजरों को अत्यधिक पारदर्शी, बहु-मुद्रा और व्यापक मैक्रो-मेजरमेंट टूल प्रदान करना है।
- यह एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और इंडेक्स फंड के लिए एक निष्क्रिय निवेश ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ सक्रिय वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए एक कठोर प्रदर्शन स्कोरकार्ड के रूप में कार्य करता है।
- सूचकांक की मुख्य विशेषताएं और भारत की समावेशन स्थिति:
- श्रेणीबद्ध पैमाना और पहुंच: सूचकांक दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड बेंचमार्क में से एक है, जो कई मुद्राओं में संप्रभु और सुपरनेशनल ऋण को कवर करता है।
- इसे सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरर और ग्लोबल एसेट मैनेजर्स द्वारा व्यापक रूप से ट्रैक किया जाता है।
- लक्ष्य परिसंपत्ति आधार (एफएआर बॉन्ड): भारत का समावेशन एफएआर-नामित सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर आधारित है। पूरी तरह से सुलभ मार्ग (2020) के तहत, एफपीआई, एनआरआई और ओसीआई बिना निवेश सीमा के इन बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं।
- अनुमानित वजन और पूंजी प्रवाह: विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत को 7-1.0% सूचकांक भार प्राप्त हो सकता है। इससे भारत सरकार के बॉन्ड में 20-25 अरब डॉलर का निष्क्रिय विदेशी निवेश आकर्षित हो सकता है।
- ब्लूमबर्ग के स्थगन के कारण: वैश्विक निवेशकों ने लंबी पंजीकरण प्रक्रियाओं, सीमित पोस्ट-ट्रेड ऑटोमेशन, निपटान में देरी और जटिल कर-संबंधी प्रक्रियाओं जैसी परिचालन चुनौतियों का हवाला दिया।
- सूचकांक पदानुक्रम संदर्भ: भारत पहले ही जेपी मॉर्गन ईएम इंडेक्स (2024), ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी इंडेक्स (2025) और एफटीएसई रसेल ईएम इंडेक्स (2025) में प्रवेश कर चुका है।

10 वर्षों में भारत के रोजगार की एक शारीरिक रचना

संदर्भ:

पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में विसंगतियों के खिलाफ बढ़ते युवा विरोध के बीच, सार्वजनिक और नीतिगत ध्यान समग्र आर्थिक विकास के आंकड़ों से वास्तविक रोजगार सृजन पर केंद्रित हो गया है।



Employment Rate (in%) : By Age Group : All India									
Year	15-19 years	20-24 years	25-29 years	30-34 years	35-39 years	40-44 years	45-49 years	50-54 years	55-59 years
2016-17	9.81	33.28	50.09	53.30	55.15	55.14	57.71	55.87	49.75
2017-18	6.07	30.87	51.11	52.62	55.42	54.14	58.82	55.46	52.35
2018-19	4.33	27.73	51.98	51.80	54.74	52.76	58.82	54.26	52.34
2019-20	3.80	27.01	52.80	50.64	53.78	51.38	58.80	53.96	52.31
2020-21	1.96	21.13	50.40	47.62	50.51	47.80	57.16	51.71	50.54
2021-22	1.84	20.13	53.14	48.19	52.51	47.50	58.63	53.16	53.12
2022-23	1.68	18.89	53.76	49.02	51.59	45.56	57.97	52.44	53.74
2023-24	2.62	20.54	52.65	50.82	51.60	45.86	58.46	52.39	52.66
2024-25	3.28	20.92	51.33	51.18	52.11	47.03	57.60	53.51	51.40
2025-26	3.22	21.36	51.20	51.36	52.86	47.73	57.62	53.93	51.90

10 वर्षों में भारत के रोजगार की एक शारीरिक रचना

10 वर्षों में भारत के रोजगार की एक शारीरिक रचना के बारे में:

यह क्या है?

- पिछले दस वर्षों में भारत के रोजगार की शारीरिक रचना घरेलू श्रम बाजार में एक संरचनात्मक बेमेल को उजागर करती है, जहां मजबूत आर्थिक विकास पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रहता है।

रोजगार पर मुख्य डेटा और सांख्यिकी (2016-2026):

- कुल गिरावट: राष्ट्रीय रोजगार दर 2016-17 में 42.7% से गिरकर मार्च 2026 के अंत तक 38.7% हो गई।
- जनसंख्या वृद्धि आउटपेसिंग ओपनिंग: जबकि नियोजित भारतीयों की कुल संख्या दशक में 406 मिलियन से बढ़कर 438 मिलियन हो गई, यह 32 मिलियन विस्तार अंतर्निहित कामकाजी उम्र की आबादी की वृद्धि से पूरी तरह से आगे निकल गया।
- लिंग घाटा: पुरुषों के लिए ईआर 70.5% से 64.8% तक सिकुड़ गया, जबकि महिलाओं के लिए दर 11.8% की पहले से ही कम आधार रेखा से गिरकर केवल 9.4% हो गई।
- शैक्षिक मुद्रास्फीति का नतीजा: शैक्षिक उपलब्धियों में बेरोजगारी एक धर्मनिरपेक्ष समस्या बनी हुई है; यहां तक कि स्नातक समूह ने भी अपने ईआर को 51% से 49% तक फिसलते हुए देखा।
- जनसांख्यिकी में धर्मनिरपेक्ष गिरावट: ईआर लगभग सभी प्रमुख धार्मिक और जाति रेखाओं में गिर गया, जिसमें हिंदू ईआर 43% से गिरकर 39% हो गया, और मुस्लिम और सिख 37% तक गिर गए।

पिछले दशक में भारतीय रोजगार में प्रमुख रुझान:

- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का विचलन: भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार बेरोजगार विकास का अनुभव किया है, जहां उत्तव कॉर्पोरेट उत्पादन संख्या के परिणामस्वरूप व्यापक-आधारित, उत्तव-गुणवत्ता वाले औपचारिक रोजगार नहीं होते हैं।
- युवा समूहों का व्यापक संपीड़न: युवा समूहों के लिए नौकरी के अवसर लगातार कड़े हुए हैं, जिससे व्यापक युवा असंतोष, राजनीतिक आंदोलन और सीमित सरकारी भूमिकाओं के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हाथापाई हुई है।
- बेरोजगारी दर का कृत्रिम अपरस्फीति: सक्रिय श्रम बल से हतोत्साहित, दीर्घकालिक बेरोजगार व्यक्तियों का बाहर निकलना नियमित रूप से देश के एलएफपीआर को सिकोड़ता है, यूईआर को विकृत करता है और वास्तविक बाजार संकट को छुपाता है।
- सामाजिक पदानुक्रमों में व्यापक संरचनात्मक मंदी: रोजगार दर में गिरावट ने समाज के सभी स्तरों को प्रभावित किया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी एक जाति या धार्मिक वर्ग व्यापक आर्थिक मंदी को कम करने में कामयाब नहीं हुआ है।
- अपारदर्शी आधिकारिक पद्धतियों पर बढ़ती निर्भरता: आधिकारिक सर्वेक्षणों में आवधिक समायोजन (जैसे कि MoSPI ने अपने वार्षिक PLFS चक्रों को स्थानांतरित कर दिया है) ने विश्लेषकों को निरंतर दीर्घकालिक ट्रैकिंग को सुरक्षित करने के लिए CMIE जैसे निजी डेटासेट पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया है।

श्रम बाजार में सकारात्मक संकेतक:

- लचीले गैर-कृषि पॉकेट: डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, फिनटेक और उन्नत लॉजिस्टिक्स हब सहित विशिष्ट उत्तव-मूल्य वाले उप-क्षेत्र विशेष तकनीकी भूमिकाओं को जोड़ना जारी रखते हैं।
- चयनात्मक समूह प्रगति: 25-29 और 55-59 आयु वर्ग दस साल की अवधि में अपने संबंधित रोजगार दरों में मामूली, स्थानीयकृत वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रहे।
- लक्षित क्षेत्रीय अपवाद: कुछ स्थानीयकृत जनसांख्यिकी, जैसे कि ईसाई समुदाय समूह, ने अपने समग्र रोजगार मेट्रिक्स में मामूली सुधार दर्ज करके व्यापक प्रवृत्ति को कम कर दिया।

- महामारी के बाद धीरे-धीरे सुधार: 2020 और 2021 के महामारी लॉकडाउन के दौरान अनुभव किए गए ऐतिहासिक संकुचन से पूर्ण रोजगार पूल उबर गया, जो 438 मिलियन सक्रिय नौकरियों तक वापस आ गया।

नौकरी सृजन से जुड़ी प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ:

- आवश्यक बनाम पर्याप्त जीडीपी विरोधाभास: जबकि तेजी से जीडीपी वृद्धि विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है, भारत का वर्तमान कॉर्पोरेट-भारी मॉडल साबित करता है कि यह पीढ़ी-स्तरीय रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है।
- बढ़ती वैश्विक आर्थिक स्थिरता और संरक्षणवाद: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ बाधाओं और सख्त आव्रजन नीतियों जैसे संरक्षणवादी उपायों के माध्यम से तेजी से अंदर की ओर बढ़ रही हैं, जिससे निर्यात के नेतृत्व वाली रोजगार रणनीतियों को निष्पादित करना मुश्किल हो गया है।
- जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज़, विघटनकारी प्रगति: अगली पीढ़ी के स्वचालन उपकरण मानक तकनीकी संचालन, कॉल सेंटर और सेवा-क्षेत्र की लाइनों के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं, जिन्होंने पारंपरिक रूप से शिक्षित शहरी युवाओं को अवशोषित किया है।
- नीति डिजाइन निरपेक्ष पूंजी एकाग्रता को अधिक तरफदेह करते हैं: प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने ध्यान दिया है कि मौजूदा राज्य नीतियों को मुख्य रूप से श्रम-गहन विनिर्माण समूहों को प्रोत्साहित करने के बजाय कच्चे सकल घरेलू उत्पाद मूल्य को अधिकतम करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- उच्च शिक्षित स्नातकों का सामना करने वाली गंभीर कमजोरियाँ: बाजार कुशल सफेदपोश भूमिकाओं की भारी कमी से ग्रस्त है, जिससे उच्च योग्य इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालय के स्नातक पुरानी बेरोजगारी के चक्र में फंस गए हैं।

आगे की राह:

- नौकरी मेट्रिक्स की ओर राष्ट्रीय व्यापक आर्थिक प्राथमिकताओं को पुनर्विन्यास करना: आर्थिक नियोजन के केंद्रीय फोकस को अकेले कच्चे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रतिशत से रोजगार सृजन के लिए स्पष्ट, कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने की ओर स्थानांतरित करें।
- उदारीकृत सीमा पार व्यापार गठबंधनों के साथ फिर से जुड़ना: घरेलू श्रम-गहन विनिर्माण केंद्रों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने में मदद करने के लिए बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर भारत के सतर्क रुख का पुनर्मूल्यांकन करना।
- कॉर्पोरेट कर रियायतों पर श्रम-प्रोत्साहन जनादेश लागू करना : उन कंपनियों को सीधे पुरस्कृत करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और कर छूट को फिर से डिजाइन करना जो अपने स्थानीय मानव पेट्रोल और तकनीकी शिक्षुता में औसत दर्जे की वृद्धि प्रदर्शित करते हैं।
- स्वचालन और एआई जोखिमों का मुकाबला करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ओवरहालिंग: स्वनात्मक समस्या-समाधान और एआई-लचीले वर्कफ़्लो पर जोर देने के लिए तकनीकी शिक्षा और विश्वविद्यालय के ढांचे को बदलना, स्नातक बेरोजगारी को कम करना।

निष्कर्ष:

भारत के दीर्घकालिक रोजगार डेटा एक महत्वपूर्ण चुनौती पर प्रकाश डालते हैं: तेजी से व्यापक आर्थिक विकास दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहा है। आयु समूहों, शिक्षा के स्तर और सामाजिक समूहों में रोजगार दर में व्यापक गिरावट से पता चलता है कि बेरोजगारी विकास एक संरचनात्मक समस्या बन गई है।

केंद्रीय बैंक का अधिशेष हस्तांतरण ढांचा

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ के एक स्मारकीय, रिकॉर्ड-तोड़ अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है।

- आर्थिक पूंजी ढांचे (2019) के अनुरूप होने के बावजूद, अभूतपूर्व भुगतान ने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, राजकोषीयकरण और राजकोषीय संघवाद के लिए इसके निहितार्थ पर बहस छेड़ दी है।

केंद्रीय बैंक का अधिशेष हस्तांतरण ढांचा

केंद्रीय बैंक के अधिशेष हस्तांतरण ढांचे के बारे में:

यह क्या है?

- केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य लाभ को अधिकतम करना नहीं है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, खुले बाजार के संचालन और मुद्रा स्थिरकरण जैसी गतिविधियां आय उत्पन्न करती हैं। आरबीआई के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (2019) के तहत, अनिवार्य जोखिम बफर से ऊपर अधिशेष आय को गैर-कर राजस्व के रूप में सरकार को हस्तांतरित किया जाता है, जिससे कर बढ़ाए बिना या उधार लिए बिना राजकोषीय स्थान बनता है।



RBI के वित्तीय प्रदर्शन पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- विस्फोटक बैलेंस शीट विस्तार: RBI की कुल बैलेंस शीट एक ही वर्ष में 20.6% तक बढ़ गई, जो मार्च 2026 तक ₹91.97 लाख करोड़ के पूर्ण मूल्यांकन तक पहुंच गई।
- सकल आय वेग: आक्रामक वैश्विक रिजर्व प्रबंधन को दर्शाते हुए, केंद्रीय बैंक की सकल आय उसी वार्षिक वित्तीय चक्र के दौरान 26% से अधिक बढ़ गई।
- टिपिंग पॉइंट शिफ्ट: जबकि बेसलाइन सरप्लस भुगतान पारंपरिक रूप से ₹30,000 करोड़ से ₹65,000 करोड़ ब्रैकेट के आसपास होता है, वहीं ₹2.87 लाख करोड़ का FY26 भुगतान राज्य राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
- रणनीतिक मुद्रा हस्तक्षेप: गंभीर बाहरी विनिमय दर के झटकों के खिलाफ घरेलू मुद्रा की रक्षा करने के लिए, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आरबीआई ने सामरिक आरक्षित पुनर्संतुलन को निष्पादित किया, लगभग 12 बिलियन डॉलर मूल्य का रणनीतिक सोना बेचा और लगभग 7.5 बिलियन डॉलर की तरल विदेशी मुद्रा संपत्ति खरीदी।

केंद्रीय बैंक के वित्तीयकरण का गहराई से विश्लेषण करने की अनिवार्यता है:

- अंतर्निहित संस्थागत दूरी का संरक्षण: एक केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता कार्यकारी सरकार के अस्थायी खर्च के दबावों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर निर्भर करती है। इन भुगतानों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मानक मौद्रिक हस्तक्षेप राज्य के राजस्व को अधिकतम करने की इच्छा के बजाय बाजार स्थिरता लक्ष्यों से प्रेरित हैं।
- केंद्रीय बैंक की आय के संरचनात्मक चालकों का आकलन: उन्नत पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जिन्होंने मात्रात्मक सहजता और बड़े पैमाने पर घरेलू बॉण्ड खरीद के माध्यम से अपनी बैलेंस शीट को उलझाया था, भारत का केंद्रीय बैंक लिक इसकी विदेशी परिसंपत्ति आय, विदेशी मुद्रा लेनदेन और सुरक्षा होल्डिंग्स पर ब्याज के बढ़ते मूल्य से उपजा है।
- राजकोषीय संघर्ष में ब्लाइंड स्पॉट को उजागर करना: क्योंकि पूरे ₹2.87 लाख करोड़ के हस्तांतरण को कानूनी रूप से गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के खातों में प्रवाहित होता है। यह वित्त आयोग के फॉर्मूले द्वारा शासित विभाज्य कर पूल से पूरी तरह बाहर बैठता है, जो राज्य सरकारों को शून्य स्वचालित वित्तीय हस्तांतरण प्रदान करता है।
- व्यापक आर्थिक शक्ति समीकरणों को संतुलित करना: जबकि केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर राजकोषीय स्थान प्राप्त होता है, राज्य संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत सख्त उधार सीमा से बंधे रहते हैं, जिससे उनके भारी स्थानीय कल्याण और विकास व्यय दायित्वों के बावजूद क्षेत्रीय संसाधन असंतुलन बढ़ जाता है।

प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ और सामान्य आलोचनाएँ:

- असममित राजकोषीय केंद्रीकरण की ओर प्रगति: आलोचकों का तर्क है कि बड़े पैमाने पर, गैर-साझा करने योग्य लाभांश हस्तांतरण, गैर-विभाज्य उपकरणों और अधिभारों पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता के साथ जोड़ा गया, वित्तीय परिदृश्य को केंद्र की ओर भारी रूप से स्थानांतरित कर देता है।
- दीर्घकालिक केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के लिए जोखिम: जैसे-जैसे राज्य खर्च का दबाव तेज होता है, विशाल लाभांश भुगतान पर नियमित निर्भरता संस्थागत दूरी बनाए रखना कठिन बना सकती है। यह केंद्रीय बैंक को परिसंपत्ति आवंटन और विनिमय दर नीतियों के बारे में सूक्ष्म कार्यकारी दबावों के लिए उजागर कर सकता है।
- सक्रिय रणनीतिक पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन की जटिलताएं: रुपये की रक्षा के लिए सोने जैसी ठोस, दीर्घकालिक रणनीतिक आरक्षित परिसंपत्तियों को तरल विदेशी मुद्रा के कागजात में परिवर्तित करने से राष्ट्रीय बैलेंस शीट की जोखिम प्रोफाइल बदल जाती है। यह मौद्रिक स्थिरता निर्णयों को विदेशी सुरक्षा पैदावार के प्रदर्शन के साथ निकटता से जोड़कर वित्तीयकरण करता है।
- अंतर-राज्य जवाबदेही और पारदर्शिता में एक पूर्ण कमी: क्योंकि यह बहु-अरब डॉलर का सार्वजनिक क्षेत्र का संसाधन हस्तांतरण संघीय हस्तांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ देता है, यह किसी भी औपचारिक अंतर-राज्य परामर्श, क्षेत्रीय जवाबदेही या संघीय संतुलन समीक्षा के बिना होता है।

आगे की राह:

- पूंजी ढांचे के तहत विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करना: सुनिश्चित करें कि आरबीआई अपने आर्थिक पूंजी ढांचे के भीतर रूढ़िवादी जोखिम बफर बनाए रखता है, संप्रभु को लाभांश भेजने से पहले अपनी ₹92 लाख करोड़ की बैलेंस शीट की दीर्घकालिक सुरक्षा की रक्षा करता है।
- गैर-कर राजस्व हस्तांतरण की स्वेच्छा से समीक्षा करना: एक ऐसा तंत्र शुरू करना जहां केंद्र सरकार स्वेच्छा से बड़े पैमाने पर गैर-कर राजस्व लाभ की समीक्षा करती है ताकि अनुच्छेद 293 के तहत तंग उधार सीमा का सामना कर रहे राज्यों की सहायता की जा सके।
- रिजर्व पोर्टफोलियो निर्णयों पर पारदर्शी रिपोर्टिंग को लागू करना : बड़े पैमाने पर सोने के परिसमापन और विदेशी कागजों की खरीद पर व्यापक, समय पर प्रकटीकरण को अनिवार्य करना ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आरक्षित प्रबंधन राज्य के राजस्व को बढ़ावा देने के बजाय वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित है।
- राजकोषीय-मौद्रिक अन्योन्याश्रयता पर नियमित समीक्षाओं को संस्थागत बनाना: केंद्रीय बैंक की आय और राज्य के बजट के बीच कड़ी कड़ी की निगरानी के लिए स्वतंत्र शैक्षणिक और विधायी समीक्षा स्थापित करना, दीर्घकालिक संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

आरबीआई का रिकॉर्ड तोड़ ₹2.87 लाख करोड़ का अधिशेष हस्तांतरण राज्य राजकोषीय क्षमता के स्रोत के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करता है, जो मौद्रिक स्थिरता के संरक्षक के रूप में अपने पारंपरिक जनादेश से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह अप्रत्याशित लाभ संघीय उधार के दबाव को कम करने में मदद करता है, लेकिन राज्य-स्तरीय राजकोषीय हस्तांतरण से इसका बहिष्कार भारत के संघीय ढांचे के भीतर संरचनात्मक असंतुलन को तेज करता है।

एकीकृत वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीतियां

संदर्भ:

भारत ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावी रूप से मुक्त होकर एक ऐतिहासिक आंतरिक सुरक्षा मील का पत्थर हासिल किया।

एकीकृत वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीतियां

एकीकृत वामपंथी उग्रवाद विरोधी रणनीतियों के बारे में:

यह क्या है?

- रेड कॉरिडोर का एक सक्रिय संघर्ष क्षेत्र से एक स्थिर विकास क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लक्षित कल्याणकारी पहलों के साथ निर्णायक उग्रवाद विरोधी अभियानों के संयोजन वाले एक व्यापक ढांचे द्वारा संचालित था।
- पुराने, खंडित दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाते हुए, जो केवल तात्कालिक लक्षणों को प्रबंधित करते थे, गृह मंत्रालय ने तीन विकासवादी और सुरक्षा स्तंभों द्वारा लंगर डाले गए एक केंद्रीकृत रणनीति को तैनात किया: विश्वास (ट्रस्ट), निर्माण (विकास), और जन कल्याण (लोक कल्याण)।



वामपंथी उग्रवाद पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- सिकुड़ता रेड कॉरिडोर: पूरे भारत में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 2014 में 126 जिलों से घटकर 2026 तक केवल 2 जिले रह गई।
- शून्यअत्यधिक प्रभावित क्षेत्र: "सबसे अधिक प्रभावित जिलों" की कुल संख्या 35 के शिखर से गिरकर पूर्ण शून्य हो गई।
- निर्णायक रूप से कम होती हिंसा: नक्सल संबंधी हिंसक घटनाएं 2014 में 870 से घटकर 2025 में 234 हो गईं, जबकि इसी अवधि में वार्षिक मृत्यु दर 310 से घटकर 100 हो गई।
- आत्मसमर्पण की एक विशाल लहर: आकर्षक पुनर्वास शर्तों से प्रेरित होकर, 2024 और मार्च 2026 के बीच 3,927 सक्रिय कैडरों ने आत्मसमर्पण किया, अकेले 2025 में 2,337 नक्सलियों ने अपने हथियार डाल दिए।
- अवैध वित्तीय नेटवर्क का गला घोटना: विशेष वित्तीय जांच के कारण राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 12 करोड़ रुपये और राज्य इकाइयों द्वारा 40 करोड़ रुपये जब्त किए गए।

मुख्य तीन-स्तंभ रणनीति:

विश्वास (राज्य में विश्वास बहाल करना)

- सुरक्षा रिक्रता को भरना: सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में 597 किलेबंद पुलिस स्टेशन बनाए (2014 से पहले सिर्फ 66 से) और निरंतर क्षेत्र वर्चस्व बनाए रखने के लिए 408 नए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) शिविर स्थापित किए।
- सामरिक गतिशीलता बुनियादी ढांचा: तेजी से सैनिकों की तैनाती, खुफिया निगरानी और आपातकालीन हताहत चिकित्सा निकासी की सुविधा के लिए 68 विशेष नाइट-लैंडिंग हेलीपैड तैनात किए गए।
- एलीट स्पेशल फोर्सेज इंटरऑपरेबिलिटी: छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) और आंध्र प्रदेश के ब्रेहाउंड जैसे राज्य बलों के साथ CoBRA जैसी विशिष्ट केंद्रीय इकाइयों को एकीकृत करना, एक उच्च समन्वित कमांड संरचना बनाना।
- प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा: चरमपंथियों के ठिकानों की निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी), उच्च ऊंचाई वाली उपग्रह इमेजरी, मोबाइल डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित कॉल-लॉग ट्रैकिंग तैनात की गई।
- लक्षित विशेष अभियान: लंबे समय से आयोजित विद्रोही गढ़ों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे सफल खुफिया नेतृत्व वाले अभियानों को अंजाम दिया।

निर्माण (नए भविष्य का निर्माण)

- सड़क बुनियादी ढांचे का विस्तार: कुल स्वीकृत परियोजनाओं में से 17,319 किलोमीटर दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में 12,249 किलोमीटर से अधिक बारहमासी सड़कों का निर्माण किया गया।
- डिजिटल डिवाइड को खत्म करना: 9,600 से अधिक मोबाइल टावर स्थापित किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पहले से कट-ऑफ किए गए 96% गांवों में विश्वसनीय सेलुलर कनेक्टिविटी हो।

- वित्तीय समावेशन को गहरा करना: 1,804 नई बैंक शाखाएँ खोलीं, 1,321 एटीएम स्थापित किए, 74,720 बैंकिंग कॉरिस्पोंडेंट तैनात किए और आदिवासी समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए 6,025 डाकघर स्थापित किए।
- व्यावसायिक कौशल केंद्र: 90,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), और 49 कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) का निर्माण किया गया।

जन कल्याण (पीपुल्स वेलफेयर एंड डिविनिटी)

- आत्मसमर्पण के बाद उदार प्रोत्साहन: आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को ₹5 लाख तक का तत्काल पुनर्वास अनुदान, 36 महीनों के लिए ₹10,000 का मासिक वजीफा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सहायता मिलती है।
- पारिवारिक प्रक्षेपवक्र को सुरक्षित करना: हिंसा के बहु-पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने के लिए आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के बच्चों के लिए बारहवीं कक्षा तक पूर्ण, मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई।
- कमजोर जनजातीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना: कमजोर आदिवासी गांवों में बुनियादी ढांचे, आवास और स्वच्छ पेयजल के अंतर को व्यवस्थित रूप से पाटने के लिए पीएम-जनमन पहल और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उपयोग किया।

केस स्टडी: बस्तर का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन (छत्तीसगढ़)

- दशकों तक, बस्तर क्षेत्र अपने अलग-थलग इलाके और सीमित राज्य उपस्थिति के कारण नक्सलवाद से काफी प्रभावित रहा। 2017 में बस्तरिया बटालियन के निर्माण के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसने बीजापुर, सुकमा और दंतवाड़ा के 1,143 स्थानीय आदिवासी युवाओं की भर्ती की, जिससे स्थानीय समुदायों और सुरक्षा बलों के बीच विश्वास की कमी को दूर किया गया।
- सुरक्षा में सुधार के बाद, श्रमिकों ने जिले भर में 3,240 किलोमीटर से अधिक सड़कें बिछाई और 889 मोबाइल टावर स्थापित किए। मई 2026 में, राज्य ने शहीद वीरगुंडा धुर सेवा डेरा पहल शुरू की, जिसमें 70 पूर्व सीएपीएफ शिविरों को व्यवस्थित रूप से नागरिक सेवा केंद्रों में परिवर्तित किया गया, जिससे स्थानीय समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल, कृषि उपकरण और डिजिटल शासन तक सुव्यवस्थित पहुंच प्रदान की गई।

पुनः प्राप्त क्षेत्रों में शेष प्रमुख चुनौतियाँ:

- परिसंपत्ति रखरखाव के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण सुरक्षित करना: ऊबड़-खाबड़ इलाकों में नई सड़कों और मोबाइल टावरों के विशाल नेटवर्क को बनाए रखने के लिए लगातार, बहु-वर्षीय राज्य वित्त पोषण की आवश्यकता होती है।
- कौशल कार्यक्रमों में उत्तम भागीदारी सुनिश्चित करना: अभ्रम पंक्ति के वन समुदाय आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण में रुचि के विभिन्न स्तर दिखा सकते हैं, जिसके लिए लक्षित आउटरीच की आवश्यकता होती है।
- सीमा पार से विद्रोहियों के पुनरुत्थान को रोकना: सुरक्षा बलों को बिखरे हुए कैडरों को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए शेष दो प्रभावित जिलों की सीमाओं पर उत्तम सतर्कता बनाए रखनी चाहिए।
- जनजातीय शोषण नेटवर्क को खत्म करना: दीर्घकालिक शांति के लिए राज्य एजेंसियों को सामुदायिक भूमि अधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा करने और वाणिज्यिक संस्थाओं को आदिवासी संसाधनों का दोहन करने से रोकने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- फिजिटलकैंप सर्विस सेंटर का विस्तार: पुराने सुरक्षा शिविरों को स्थानीय नागरिक उपयोगिता नोड्स में बदलने के लिए सभी पूर्व प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ के शिविर-रूपांतरण मॉडल को बढ़ाना।
- ईएमआरएस शैक्षिक तैनाती में तेजी लाना: जनजातीय क्षेत्रों में उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए शेष स्वीकृत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को तेजी से पूरा करना और कर्मचारियों को नियुक्त करना।
- हाइपरलोकल कारीगरों को ई-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ना: ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आदिवासी हस्तशिल्प और उत्पादों को सीधे डिजिटल मार्केटप्लेस पर सूचीबद्ध करके सफल जमीनी स्तर के मॉडल को प्रतिबिंबित करना।
- जिला-स्तरीय खेल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को संस्थागत बनाना: आदिवासी युवाओं के बीच सामाजिक एकीकरण और नेतृत्व के अवसरों का निर्माण करने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे क्षेत्रीय जुड़ाव प्लेटफॉर्मों को बढ़ाना।

निष्कर्ष:

वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में भारत की सफलता इसकी आधुनिक आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अलग-थलग, प्रतिक्रियाशील कार्यों को एक एकीकृत रणनीति के साथ प्रतिस्थापित करके, जो सड़क, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के साथ सुरक्षा को संतुलित करता है, राज्य ने शासन में जनता के विश्वास को सफलतापूर्वक बहाल किया है। जैसा कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां इन लाभों को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं, भारत के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए इस विकासात्मक फोकस को बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

सिकल सेल रोग

संदर्भ:

भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में भाग लिया, जो एक प्रमुख स्वास्थ्य मील का पत्थर है।

सिकल सेल रोग

सिकल सेल रोग के बारे में:

यह क्या है?

- सिकल सेल रोग (एससीडी) विरासत में मिले पुराने रक्त विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन की संरचना को बदल देता है - लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर महत्वपूर्ण प्रोटीन जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। लचीले और गोल रहने के बजाय, प्रभावित लाल रक्त कोशिकाएं कठोर, अर्धचंद्राकार या दरांती के आकार में बदल जाती हैं।

कारण:

- आनुवंशिक उत्परिवर्तन: एससीडी एक वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है जो एचबीबी जीन में संरचनात्मक उत्परिवर्तन के कारण होती है, जो बीटा-ग्लोबिन (हीमोग्लोबिन का एक घटक) बनाने के लिए निर्देश प्रदान करती है।
- वंशानुक्रम पैटर्न: यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न का अनुसरण करता है। एक व्यक्ति केवल तभी बीमारी विकसित करता है जब उन्हें दो असामान्य हीमोग्लोबिन जीन (प्रत्येक माता-पिता से एक) विरासत में मिलते हैं।
- वाहक राज्य: जिन व्यक्तियों को केवल एक उत्परिवर्तित जीन प्रति विरासत में मिलती है, उन्हें वाहक कहा जाता है (या सिकल सेल विशेषता होती है)। वाहक आम तौर पर लक्षणों के बिना स्वस्थ जीवन जीते हैं लेकिन उत्परिवर्तित जीन को अपने जैविक बच्चों को पारित कर सकते हैं।

यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है?

- वासो-रोड़ा संकट: सिकल कोशिकाएं छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करती हैं, जिससे गंभीर दर्द एपिसोड और ऊतक क्षति होती है।
- क्रोनिक एनीमिया: सिकल कोशिकाओं के तेजी से नष्ट होने से लगातार थकान, सांस फूलना और कमजोरी होती है।
- प्लीहा क्षति और संक्रमण का जोखिम: प्लीहा की बार-बार चोट प्रतिरक्षा को कम करती है, जिससे गंभीर संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है।
- प्रगतिशील अंग क्षति: लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है।

प्रमुख महामारी विज्ञान विशेषताएं:

- जनजातीय समुदायों में उच्च बोझ: यह बीमारी कई आदिवासी और हाशिए पर रहने वाली आबादी के बीच केंद्रित है।
- बड़ी वाहक जनसंख्या: स्पर्शोन्मुख वाहक रोगियों से कहीं अधिक संख्या में हैं, जिससे आनुवंशिक जांच आवश्यक हो जाती है।
- बचपन की शुरुआत: लक्षण आमतौर पर लगभग 5-6 महीने में दिखाई देते हैं क्योंकि भ्रूण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।

उपचार और प्रबंधन:

- दर्द प्रबंधन: एनाल्जेसिक, विरोधी भड़काऊ दवाएं और जलयोजन सिकल सेल संकट को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
- हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी: भ्रूण के हीमोग्लोबिन उत्पादन को बढ़ाता है, बीमारी और दर्द के एपिसोड को कम करता है।
- एंटीबायोटिक्स और टीकाकरण: गंभीर संक्रमण को रोकें, खासकर शिशुओं और छोटे बच्चों में।
- रक्त आधान: स्ट्रोक और गंभीर एनीमिया जैसी जटिलताओं को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना की आधारशिला रखेंगे।

कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना

कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के बारे में:

यह क्या है?

- यह परियोजना भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की औद्योगिक सुविधा है जिसे कच्चे घरेलू कोयले को अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित, यह सुविधा भूतल कोयला और लिग्नाइट



गैसीकरण के लिए एक मॉडल संयंत्र के रूप में कार्य करती है, जो ठोस कोयले को उच्च मूल्य वाले डाउनस्ट्रीम रासायनिक फीडस्टॉक में बदल देती है।

- स्थान: इस परियोजना का निर्माण ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में स्थित लखनपुर में किया जा रहा है।
- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य भारत के प्रचुर कोयला भंडार का उपयोग घरेलू स्तर पर अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने, आयात निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए करना है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- गैसीकरण प्रतिघात: उच्च राख वाले घरेलू कोयले को बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक उन्नत गैसीफायर में खिलाया जाता है, जहां यह भाप और ऑक्सीजन के साथ नियंत्रित उच्च तापमान और दबाव में प्रतिक्रिया करता है।
- सिनगैस पीढ़ी: कोयले को सीधे जलाने के बजाय, यह प्रक्रिया इसे रासायनिक रूप से संश्लेषण गैस, या सिनगैस में तोड़ देती है - एक गैस मिश्रण जो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) और हाइड्रोजन (एच 2) से बना होता है।
- शुद्धिकरण और शिप्ट: कच्चे सिनगैस को अशुद्धियों (जैसे सल्फर) से साफ किया जाता है और अमोनिया (NH₃) को संश्लेषित करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन-से-नाइट्रोजन अनुपात को अनुकूलित करने के लिए रासायनिक बदलाव प्रतिक्रियाओं के माध्यम से चलाया जाता है।
- अमोनियम नाइट्रेट संश्लेषण: उत्पन्न अमोनिया को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक एसिड (HNO₃) बनाया जाता है। शेष अमोनिया को तब तरल या प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट (NH₄NO₃) प्राप्त करने के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया की जाती है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

- रणनीतिक कॉर्पोरेट संयुक्त उद्यम: यह सुविधा भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल) द्वारा निष्पादित की जा रही है, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- वाणिज्यिक उत्पादन उत्पादन: संयंत्र को प्रति दिन अनुमानित 2,000 टन रासायनिक-ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- 100% स्वदेशी प्रौद्योगिकी: यह संयंत्र बीएचईएल द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस विकसित विशेष कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करता है, जो भारत की विशिष्ट उच्च-राख वाले कोयले की किस्मों को संसाधित करने के लिए तैयार किया गया है।
- केंद्रीय राजकोषीय प्रोत्साहन: इस परियोजना को राष्ट्रीय सतह गैसीकरण के लिए 46,000 करोड़ रुपये की व्यापक प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्रीय कोयला मंत्रालय से 1,350 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का समर्थन प्राप्त है।
- कानूनी भूमि सक्षमीकरण: लेआउट संशोधित कोयला-असर भूमि उपयोग नीतियों का उपयोग करता है, जो सक्रिय खनन क्षेत्रों को सीधे डाउनस्ट्रीम रासायनिक परियोजनाओं को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की अनुमति देता है।

हरित यूरिया उत्पादन को वास्तविकता बनाने का रोडमैप

संदर्भ:

उर्वरक विभाग (डीओएफ) ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रीन यूरिया विनिर्माण रोडमैप स्थापित करने के लिए नोएडा में पीडीआईएल मुख्यालय में एक उच्च-स्तरीय प्री-एक्सप्रेशन ऑफ इंटेरेस्ट (ईओआई) बैठक आयोजित की।

हरित यूरिया उत्पादन को वास्तविकता बनाने का रोडमैप

हरित यूरिया उत्पादन को वास्तविकता बनाने के रोडमैप के बारे में:

यह क्या है?

- ग्रीन यूरिया एक पर्यावरण के अनुकूल उर्वरक है जो जीवाश्म ईंधन के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। यह हाइड्रोजन के लिए पानी को विभाजित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, इसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के साथ जोड़ता है, और टिकाऊ यूरिया के निर्माण के लिए उद्योगों से प्राप्त CO₂ का उपयोग करता है।

भारत के ग्रीन यूरिया कार्यक्रम पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: MNRE ने भारत के हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत ₹19,744 करोड़ आवंटित किए हैं।
- ग्रीन अमोनिया खरीद: मोड 2A के तहत, SECI ई-रिवर्स नीलामी के माध्यम से सालाना 7.24 लाख मीट्रिक टन (MT) ग्रीन अमोनिया की खरीद करेगा।
- उच्चयूरिया आयात: भारत हर साल लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन (10 मिलियन टन) पारंपरिक यूरिया का आयात करता है, जिसे ग्रीन यूरिया कार्यक्रम कम करना चाहता है।
- CO₂ की आवश्यकता: विश्व स्तर पर 12.7 लाख मीट्रिक टन हरित यूरिया संयंत्र को फीडस्टॉक के रूप में सालाना लगभग 10 लाख मीट्रिक टन कैप्चर किए गए CO₂ की आवश्यकता होती है।



हरित यूरिया रोडमैप की अनिवार्य आवश्यकता:

- 2070 नेट जीरो मैसेट को पूरा करना: पारंपरिक उर्वरक संचालन अत्यधिक कार्बन-गहन हैं; 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की जलवायु प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना आवश्यक है।
- उम्र बढ़ने, अक्षम कारखाने के बेड़े को बदलना: भारत के घरेलू रासायनिक संयंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 30 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसका अर्थ है कि उन्हें व्यापक प्रौद्योगिकी अपडेट या टिकाऊ ग्रीनफील्ड इकाइयों के साथ कुल प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।
- कार्बन कैप्चर (सीसीयूएस) के लिए विश्वसनीय बाजारों को सुरक्षित करना: एकीकृत उर्वरक हब विकसित करने से थर्मल पावर, स्टील और सीमेंट कारखानों को उनके कैप्चर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तत्काल, बड़े पैमाने पर उपभोक्ता मिलता है, जो कार्बन-कमी कार्यक्रमों का व्यावसायीकरण करता है।
- कृषि को अस्थिर आयात के झटकों से बचाना: स्थानीय हरित संचालन के साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रतिस्थापित करना भारतीय किसानों को अप्रत्याशित विदेशी प्राकृतिक गैस स्पाइक्स और समुद्री परिवहन व्यवधानों से बचाता है।

अब तक की गई प्रमुख पहलें:

- पुडिमडका 150-TPD पायलट प्लांट: आंध्र प्रदेश में पुडिमडका ग्रीन हाइड्रोजन हब में NETRA (NTPC का R&D विंग) द्वारा विकसित, यह 150 टन-प्रति-दिन की सुविधा कार्बन उपयोग के साथ जल इलेक्ट्रोलिसिस को जोड़कर प्रौद्योगिकी बेंचमार्क के रूप में कार्य करती है।
- ऑफटेकर-साइड डिफरेंशियल सब्सिडी को लागू करना: लागत अंतराल को हल करने के लिए, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) उत्पादकों से ग्रीन अमोनिया खरीदेगा और इसे मानक, बाजार से जुड़ी ग्रे अमोनिया कीमतों पर कारखानों को आपूर्ति करेगा, जिसमें DoF मूल्य अंतर को कवर करेगा।
- दीर्घकालिक 10-वर्षीय अनुबंध निश्चितता प्रदान करना: डेवलपर विश्वास बनाने के लिए, राज्य बाध्यकारी ग्रीन अमोनिया खरीद समझौतों (GAPA) के माध्यम से वाणिज्यिक आपूर्ति की तारीख से 10 साल की अवधि के लिए नकद प्रोत्साहन की गारंटी देता है।
- सृजन और सृजन दीप डिजिटल रजिस्ट्री का शुभारंभ: मंत्रालय ने स्थानीय तकनीकी प्रदाताओं, इलेक्ट्रोलाइजर निर्माताओं और नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेताओं को एक लचीले इकोसिस्टम में सुचारू रूप से मैप करने के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस शुरू किया है।

हरित यूरिया एकीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- एक उत्तम प्रारंभिक चरण मूल्य प्रीमियम: क्योंकि नवीकरणीय बिजली और इलेक्ट्रोलाइजर महंगे रहते हैं, ग्रीन अमोनिया वर्तमान में पारंपरिक प्राकृतिक गैस-आधारित ग्रे अमोनिया की तुलना में निर्माण के लिए काफी अधिक महंगा है।
- कैप्चर किए गए कार्बन के लिए निरंतर रसद सुरक्षित करना: बिखरे हुए बिजली या सीमेंट संयंत्रों से 10 लाख मीट्रिक टन CO₂ को एक ही उर्वरक हब तक एकत्र करने, शुद्ध करने और परिवहन करने के लिए एक जटिल, अत्यधिक विशिष्ट संपीड़न पाइपलाइन नेटवर्क की आवश्यकता होती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिक आपूर्ति: परिवर्तनीय पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक निरंतर, 24/7 रासायनिक संश्लेषण संयंत्र के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर, महंगी ग्रिड-स्केल बैटरी भंडारण या हरित हाइड्रोजन जलाशयों की आवश्यकता होती है।
- उत्तम बुनियादी ढांचे में संशोधन लागत: शुद्ध हरित हाइड्रोजन इनपुट को सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए मौजूदा तीन दशक पुरानी उर्वरक इकाइयों को फिर से तैयार करने के लिए उत्तम पूंजी व्यय और जटिल इंजीनियरिंग परिवर्तनों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- एसईसीआई रिवर्स नीलामी में तेजी लाना: 7.24 लाख मीट्रिक टन ग्रीन फीडस्टॉक को लॉक करने और निजी निवेशकों को स्पष्ट बाजार प्रवेश बिंदु देने के लिए एनजीएवएम मोड 2ए के तहत ई-रिवर्स नीलामी को तेजी से निष्पादित करना।
- एकीकृतकार्बन कैप्चर हब का विस्तार: CO₂ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए थर्मल पावर और स्टील क्लस्टर के पास समर्पित औद्योगिक कार्बन कैप्चर सिस्टम स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय करना।
- ग्रीन क्रेडिट और सागरमाला फंडिंग का अनुकूलन: ग्रीनफील्ड स्वच्छ उर्वरक परियोजनाओं के लिए कम लागत, दीर्घकालिक ऋण देने के लिए सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी विशेष गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का लाभ उठाएं।
- स्वच्छ ऊर्जा शुद्धता के लिए क्षेत्रीय ग्रिडों का उन्नयन: निरंतर नवीकरणीय बिजली को सीधे स्थानीयकृत जल इलेक्ट्रोलाइजर हब में खिलाने के लिए विशेष उत्तम-वोल्टेज हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण करना।

निष्कर्ष:

एक व्यावहारिक अंतर सब्सिडी तंत्र के साथ स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण में ₹19,744 करोड़ का मिलान करके, राज्य ने स्थानीय कारखानों को शुरुआती चरण के मूल्य झटके से सफलतापूर्वक बचाया है। आगे बढ़ते हुए, उन्नत कार्बन कैप्चर नेटवर्क को बढ़ाना और उत्तम क्षमता वाले ग्रीन हाइड्रोजन हब का निर्माण विदेशी आयात को बदलने और 2070 से पहले भारत के कृषि भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

सुमन रोडमैप 2030

संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद (CCHFW) के 16 वें सम्मेलन के दौरान 'सुमन रोडमैप 2030' लॉन्च किया।

सुमन रोडमैप 2030

सुमन रोडमैप 2030 के बारे में:

यह क्या है?

- सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन) रोडमैप 2030 एक बहुआयामी, डेटा-संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीति है। सभी के लिए एक ही मॉडल से हटकर, यह एक विशेष परिचालन मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है, जिसे स्थानीयकृत, तकनीक-सक्षम सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार।

उद्देश्य:

- 2030 तक भारत के एमएमआर को आक्रामक रूप से प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से नीचे धकेलना, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ पूरी तरह से संरेखित है।
- नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) दोनों में भारी कमी प्राप्त करना।
- भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सार्वभौमिक, न्यायसंगत और शीर्ष स्तरीय स्वास्थ्य सेवा संतृप्ति सुनिश्चित करना।

रोडमैप की मुख्य विशेषताएं:

- देखभाल की एकीकृत निरंतरता: गर्भावस्था से पहले से प्रसवोत्तर चरणों तक निरंतर मातृ देखभाल प्रदान करता है, जिसमें फोलिक एसिड पूरकता, प्रसवपूर्व जांच, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल शामिल है।
- चार-चरण उत्तम जोखिम वाली गर्भावस्था ट्रैकिंग: प्रारंभिक प्रसवपूर्व देखभाल, तीसरी तिमाही, प्रसव और प्रसवोत्तर वसूली के दौरान उत्तम जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान और निगरानी करता है।
- लक्षित उत्तम-बोझ हस्तक्षेप: 13 राज्यों के 130 जिलों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वंचित क्षेत्रों में जन्म प्रतीक्षा गृहों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग और प्रसूति एचडीयू/आईसीयू के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करता है।

जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी):

- सुमन पंचायतें: स्थानीय ग्राम परिषदों को स्वास्थ्य लक्ष्यों को ट्रैक करने, जवाबदेही लागू करने और अपने क्षेत्रों के भीतर 100% संस्थागत प्रसव और बाल टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक शासन का स्वामित्व दिया जाता है।
- द्वि-साप्ताहिक आशास्त्रीकरण: अभिन्न पंक्ति की आशा कार्यकर्ता गर्भावस्था के महत्वपूर्ण 8वें और 9वें महीनों के दौरान सप्ताह में दो बार घरेलू स्वास्थ्य जांच करती हैं ताकि चेतावनी के संकेतों को जल्दी पहचाना जा सके, पोषण परामर्श दिया जा सके और जन्म की तैयारी में सहायता की जा सके।
- माताओं का पिकनिक प्लेटफॉर्म: एक रचनात्मक सामुदायिक जुड़ाव पहल जो स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने, अनुभव साझा करने और स्थानीय माताओं के बीच सकारात्मक नवजात देखभाल प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

उन्नत नैदानिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी

- एआई-सक्षम लेबर रूम: प्रसव के दौरान मातृ महत्वपूर्ण अंगों और भ्रूण के संकट को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए श्रम इकाइयों के अंदर स्मार्ट डिजिटल निगरानी तैनात करता है।
- जननी पोर्टल: एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसे देश भर में उत्तम जोखिम वाले मामलों, नैदानिक हस्तक्षेपों और क्षेत्रीय स्वास्थ्य डेटा की वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए इंजीनियर किया गया है।
- एंटी-शॉक गारमेंट डिप्लॉयमेंट: आपातकालीन पारगमन के दौरान गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रबंधन करने के लिए गैर-वायवीय एंटी-शॉक गारमेंट्स (NASG) के व्यापक उपयोग को अनिवार्य करता है।
- केंद्रीकृत देखभाल पहुंच: स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए नामित उत्कृष्टता केंद्रों के साथ-साथ त्वरित शिकायत निवारण के लिए चौबीसों घंटे, केंद्रीकृत सुमन कॉल सेंटर की स्थापना करता है।
- जलवायु-उत्तरदायी ढांचे: जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसम विसंगतियों से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए अनुकूली स्थानीय प्रोटोकॉल पेश करता है।

महत्व:

- उत्तम बोझ वाले जिलों को प्राथमिकता देना है, यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन, बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य कार्यकर्ता सबसे बड़ी मातृ स्वास्थ्य आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों तक पहुंचें।
- समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एसएसबीएसके) के साथ मातृ सेवाओं को एकीकृत करता है, जो 36 महीने तक मां और बच्चे दोनों के लिए निरंतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है।



द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' के उच्च राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है।

द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड

द गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड के बारे में:

यह क्या है?

- 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' एक विशिष्ट राष्ट्रपति गौरव है और सेशेल्स गणराज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु लचीलापन, हरित विकास और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्थायी प्रबंधन में अनुकरणीय अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह सम्मान विक्टोरिया, माहे में एक विशेष राज्य समारोह में प्रधान मंत्री मोदी को सेशेल्स गणराज्य के 6 वें राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी द्वारा प्रदान किया गया था।

इतिहास:

- एक ऐतिहासिक पहला: यह इतिहास में पहली बार है कि इस प्रतिष्ठित राष्ट्रपति सम्मान का निर्माण किया गया है और किसी भी वैश्विक नेता को प्रदान किया गया है, जो इस अवसर से जुड़े अद्वितीय राजनयिक महत्व को उजागर करता है।
- संचित वैश्विक सम्मान: यह पुरस्कार किसी विदेशी राष्ट्र से पीएम मोदी के 34 वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को चिह्नित करता है।

चयन के पीछे मुख्य विशेषताएं और स्तंभ:

- नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना: यह सम्मान महासागर और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) दृष्टिकोण के तहत भारत के रणनीतिक प्रयास को मान्यता देता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्वच्छ महासागर व्यापार, समुद्री सुरक्षा और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।
- छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) का चैंपियनिंग: सेशेल्स जैसे SIDS के एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को स्वीकार करता है, उनकी विकासात्मक आकांक्षाओं का समर्थन करता है और जलवायु चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए क्षमता निर्माण करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): विकासशील और उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा पर तेजी से कब्जा करने के लिए ISA की सह-स्थापना का सम्मान करता है।
- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली): सचेत और शून्य-अपशिष्ट जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देकर जलवायु कार्रवाई को एक व्यक्तिगत प्रयास में बदलने के लिए वैश्विक आंदोलन को मान्यता देता है।
- बड़े पैमाने पर वनीकरण और जैव विविधता अभियान: 'एक पेड़ मां के नाम' (मां के लिए पौधा) और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के निर्माण जैसी बड़े पैमाने पर पर्यावरण परियोजनाओं की सराहना करता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

संदर्भ:

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) ने देश भर में 90 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA) बनाकर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में:

यह क्या है?

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) परियोजना है।
- यह एक एकल, एकीकृत डिजिटल राजमार्ग के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों, डॉक्टरों, अस्पतालों, फार्मसियों और बीमाकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों को जोड़ता है।
- लॉन्च किया गया: मिशन को आधिकारिक तौर पर सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।



उद्देश्य:

- एबीडीएम का उद्देश्य भारत के लिए एक एकीकृत, पारदर्शी और अंतर-संचालित डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थाओं के बीच सूचना के अंतर को पाटना, स्वास्थ्य डेटा के लिए सच्चाई का एक एकल स्रोत स्थापित करना और नागरिकों को उनके आजीवन अनुदैर्ध्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड का पूर्ण स्वामित्व सौंपना है।

मुख्य विशेषताएं और बिल्डिंग ब्लॉक्स:

- एबीडीएम आर्किटेक्चर छह मूलभूत, खुले-मानक घटकों द्वारा संचालित है जो पूरे देश में घर्षण रहित डेटा विनिमय को चलाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं:
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए): नागरिकों को सौंपा गया एक अद्वितीय, 14-अंकीय डिजिटल स्वास्थ्य पहचानकर्ता। यह विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल ऐप्स और सुविधाओं में डिजिटल चिकित्सा इतिहास को सुरक्षित रूप से संकलित करने, लिंक करने और साझा करने के लिए मास्टर कुंजी के रूप में कार्य करता है।
- हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (एचपीआर): डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा की आधुनिक और पारंपरिक प्रणालियों में अभ्यास करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य पेशेवरों का एक केंद्रीकृत, सत्यापित राष्ट्रीय भंडार।
- स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर): देश भर में अस्पतालों, क्लीनिकों, डायग्नोस्टिक केंद्रों और फार्मसियों सहित सभी सार्वजनिक और निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों की एक व्यापक मास्टर रजिस्ट्री।
- स्वास्थ्य सूचना विनिमय और सहमति प्रबंधक (एचआईई-सीएम): एक सुरक्षित डेटा-रूटिंग आर्किटेक्चर जो यह सुनिश्चित करता है कि मेडिकल फाइलें केवल स्पष्ट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रतिसंश्लेषीय सहमति-आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग करके डॉक्टरों और रोगियों के बीच स्थानांतरित की जाती हैं।
- यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (HI): एक ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल जो रोगियों को टेलीकंसल्टेशन को निर्बाध रूप से शेड्यूल करने, डायग्नोस्टिक स्टॉट बुक करने, या किसी भी अनुपालन एप्लिकेशन या पोर्टल पर चिकित्सा सेवाओं को देखने की अनुमति देता है।
- नेशनल हेल्थ वलेम एक्सचेंज (NHCE): अस्पतालों और बीमा प्रदाताओं के बीच स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान को मानकीकृत, तेज और स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

प्रोजेक्ट उदयक**संदर्भ:**

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने असम के डूमडूमा में प्रोजेक्ट उदयक का 37वां स्थापना दिवस मनाया।

प्रोजेक्ट उदयक**प्रोजेक्ट उदयक के बारे में:****यह क्या है?**

- प्रोजेक्ट उदयक सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की एक विशेष क्षेत्रीय शाखा है, जिसे पूर्वोत्तर भारत के सबसे दूरस्थ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में एक विशाल सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव का काम सौंपा गया है। यह वर्तमान में 1,457 किमी से अधिक रणनीतिक सड़कों का प्रबंधन करता है।
- शुरू किया गया: यह परियोजना 1989 में स्थापित की गई थी (2026 में इसके संचालन के 37वें वर्ष को चिह्नित करते हुए)।
- संगठन: यह सीमा सड़क संगठन (BRO) के तहत काम करता है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

**मुख्य विशेषताएं और जिम्मेदारी के क्षेत्र:**

- भौगोलिक कवरेज: यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्रों और असम के कुछ हिस्सों के लिए जिम्मेदार है। इसके संचालन के प्राथमिक जिलों में शामिल हैं:
- अंजाव, लोहित और दिबांग घाटी।
- लोंगिंग, तिरप और चांगलांग।
- रणनीतिक सीमा प्रबंधन: यह दो संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ सड़क बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है:
- चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)।
- भारत-म्यांमार सीमा।
- सीमा पर बाड़ लगाना: सड़क निर्माण के अलावा, यह परियोजना वर्तमान में विद्रोही गतिविधियों और अवैध सीमा पार गतिविधियों को रोकने के लिए भारत-म्यांमार सीमा के साथ प्रमुख सीमा बाड़ लगाने के बुनियादी ढांचे को निष्पादित कर रही है।
- पुल और हेलीपैड बुनियादी ढांचा: अकेले 2025 में, परियोजना ने 12 रणनीतिक पुलों, एक प्रमुख सड़क और एक हेलीपैड को पूरा किया और उनका उद्घाटन किया, जिससे भारतीय सेना की तेजी से तैनाती क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई।

- नागरिक-सैन्य एकीकरण: यह परियोजना नियमित रूप से दूरदराज की सीमावर्ती बस्तियों में स्थानीय आदिवासी आबादी के लिए चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान और सड़क सुरक्षा जागरूकता सहित सामुदायिक आउटरीच आयोजित करती है।

महत्त्व:

- एलएसी और भारत-म्यांमार सीमा पर सैनिकों, उपकरणों और आपूर्ति की तेज आवाजाही को सक्षम करके सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- दूरदराज के सीमावर्ती गांवों को बाजारों, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं से जोड़ता है, आजीविका और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

मिशन सेनेहजोरी

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री ने असम के अनूठे मुगा सिल्क को एक वैश्विक लक्जरी ब्रांड में बदलने के लिए मिशन सेनेहजोरी का शुभारंभ किया।

मिशन सेनेहजोरी

मिशन सेनेहजोरी के बारे में:

यह क्या है?

- मिशन सेनेहजोरी एक व्यापक, क्लस्टर-आधारित कपड़ा पहल है जिसे विशेष रूप से असम में पाए जाने वाले मुगा रेशम क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी लक्जरी इकोसिस्टम में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह एक आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर परियोजना है जिसका संचालन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र मंत्रालय और असम सरकार के साथ मिलकर एक समिति का गठन किया गया है।
- लॉन्च किया गया: मिशन को आधिकारिक तौर पर 2 जून, 2026 को लॉन्च किया गया था।

उद्देश्य:

- इसका प्राथमिक उद्देश्य मुगा पालकों और बुनकरों की वार्षिक आय (वर्तमान में केवल ₹18,000-21,000 का अनुमानित) को खेत के गेट से विदेशी तटों तक रेशम के पूर्ण प्रीमियम मूल्य पर कब्जा करके निर्णायक रूप से बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य असम की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए मुगा सिल्क को एक ट्रेस करने योग्य, उच्च अंत वैश्विक वस्तु के रूप में स्थापित करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- क्लस्टर-आधारित विकास: जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, सुआलकुची और माजुली सहित प्रमुख उत्पादन केंद्रों में प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पारिस्थितिकी और बुनियादी ढांचा: इसका उद्देश्य 5,000 हेक्टेयर सोम और सोलू मेजबान संयंत्रों को पुनर्जीवित करना और एक विशेष मुगा स्पन मिल के साथ पांच आधुनिक रीलिंग इकाइयाँ स्थापित करना है।
- संस्थागत सहायता: स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए 30 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और 1,180 से अधिक किसान हित समूह बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- डिजिटल ट्रेसिबिलिटी और ब्रांडिंग: 8,000 से अधिक घरों के लिए क्यूआर-कोड, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी लागू करता है और यह सुनिश्चित करता है कि 80% व्यापारिक मुगा रेशम भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के तहत प्रमाणित है।
- निर्यात लक्ष्य: 2028 तक मुगा रेशम निर्यात को सालाना 2,000 किलोग्राम से अधिक तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- सिल्क पर्यटन: इसमें मुगा सिल्क ट्रेल, एक समर्पित सिल्क टूरिज्म पार्क और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक मुगा उत्सव का आयोजन शामिल है।

महत्त्व:

- बिचौलियों को कम करके और एक सामान्य ब्रांड बनाकर, मिशन बुनकरों और पालकों को प्रीमियम रेशम उत्पादों से बेहतर आय अर्जित करने में मदद करता है।
- यह मिशन जीआई-टैग वाले मुगा सिल्क का विपणन करता है, जो दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक रूप से सुनहरा रेशम है, जो लक्जरी कपड़ा बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है।



नवाचार मंत्र पहल

संदर्भ:

नवाचार मंत्र आईआईटी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय नवोन्मेषकों को जोड़कर टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण भारत से जमीनी स्तर के नवाचारों की पहचान, समर्थन और पैमाने पर किया जाता है।

नवाचार मंत्र पहल

नवाचार मंत्र पहल के बारे में:

यह क्या है?

- नवाचार मंत्र एक राष्ट्रव्यापी इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम है जो विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमियों, ग्रामीण नवोन्मेषकों और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए तैयार किया गया है।
- यह स्थानीयकृत, समुदाय-प्रभाव समस्या समाधान को लक्षित करता है, जिससे छोटे उद्यमों को क्षेत्रीय प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट से स्केलेबल राष्ट्रीय उद्यमों में संक्रमण में मदद मिलती है।
- शामिल मंत्रालय: यह कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है।
- कार्यान्वयन: राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईआईएसबीयूडी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- लक्ष्य जनसांख्यिकी: 18 से 55 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए तैयार किया गया है जो आकांक्षी जिलों, वंचित भौगोलिक क्षेत्रों और छोटे शहरों में रहते हैं।
- लचीले पंजीकरण मानदंड: कठोर तकनीकी त्वरक के विपरीत, व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए पूरी तरह से पंजीकृत कॉर्पोरेट इकाई या तैयार बाजार उत्पाद की आवश्यकता नहीं होती है; सत्यापन चरण या प्रारंभिक प्रोटोटाइप चरणों में विचार पूरी तरह से पात्र होते हैं।
- प्राथमिकता वाले परिचालन क्षेत्र: छह उच्च प्रभाव वाले सामाजिक आर्थिक कार्यक्षेत्रों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है:
- एग्रीटेक और खाद्य प्रौद्योगिकी
- हेल्थटेक और वेलनेस
- एडटेक और वोकेशनल स्किलिंग
- जलवायु कार्बन और पर्यावरणीय स्थिरता
- ग्रामीण वाणिज्य और खुदरा लॉजिस्टिक्स

एमएसएमई सक्षमता और पारंपरिक कारीगर तकनीक

- 1-वर्षीय संरचित ऊष्मायन: चयनित नवप्रवर्तकों को विषयगत वेबिनार, नियामक अनुपालन मार्गदर्शन, बौद्धिक संपदा (आईपी) संरचना और अनुरूप व्यवसाय धन उगाहने वाले रोडमैप के साथ एक साल के लंबे जुड़ाव चक्र से गुजरना पड़ता है।
- हाई-डेसिबल नेशनल विजिबिलिटी: जमीनी स्तर के रचनाकारों पर संस्थागत ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष मंत्रिस्तरीय पॉडकास्ट, डिजिटल शोकेस और राष्ट्रीय कहानी कहने की घटनाओं सहित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए समर्पित चैनल पेश करता है।
- समयरेखा की बाधा: डिजिटल पोर्टल आवेदन 5 जुलाई, 2026 तक लाइव रहेंगे, इसके बाद बहु-स्तरीय विशेषज्ञ स्क्रीनिंग होगी।

महत्व:

- ग्रामीण और छोटे शहर के उद्यमियों को टियर-1 शहरों से परे वित्त पोषण, परामर्श और नवाचार सहायता प्रदान करता है।
- एआई, बायोटेक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घरेलू प्रौद्योगिकियों और पेटेंट के विकास को प्रोत्साहित करता है।

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित होकर 2022-23 किया गया

संदर्भ:

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधार वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक संशोधन की घोषणा की, साथ ही WPI को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की।

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित होकर 2022-23 किया गया

2011-12 से 2022-23 तक संशोधित थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के बारे में:

यह क्या है?

- यह भारत के मैक्रो-प्राइसिंग आंकड़ों का एक व्यापक संरचनात्मक और कार्टोग्राफिक आधुनिकीकरण है। संशोधन माल की टोकरी



को अपग्रेड करता है, आर्थिक आधार रेखा को हाल के वित्तीय वर्ष (2022-23) में अपडेट करता है, और एक चरणबद्ध दोहरे सूचकांक रिलीज विंडो का परिचय देता है जहां नया उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) अंततः व्यवसाय-स्तरीय मुद्रास्फीति पर नज़र रखने के लिए देश का प्राथमिक मीट्रिक बन जाएगा।

- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य भारत के मूल्य निर्धारण डेटा ढांचे को आधुनिक बनाना, पुराने आधार वर्षों के कारण होने वाले संरचनात्मक तिरछे को ठीक करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की सिफारिशों के साथ डेटा पाइपलाइनों को संरेखित करना है।

संशोधित श्रृंखला की मुख्य विशेषताएं:

नया संरचनात्मक लेआउट मूल्य निर्धारण पाइपलाइन में कई महत्वपूर्ण डेटा सुधार पेश करता है:

- विस्तारित कमोडिटी कवरेज: डब्ल्यूपीआई बारकेट में ट्रैक की गई वस्तुओं की कुल संख्या को 697 से बढ़ाकर 957 आइटम कर दिया गया है, जो आधुनिक औद्योगिक गतिविधि के व्यापक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।
- हरित ऊर्जा समावेशन: पहली बार, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों-विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा-को परमाणु ऊर्जा को शामिल करने के साथ-साथ 'बिजली' ट्रैकिंग समूह के तहत एकीकृत किया गया है।
- एकीकृत ईंधन संरचना: कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और 'प्राथमिक वस्तुओं' से 'ईंधन और बिजली' में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह सभी प्राथमिक ऊर्जा आदानों (कोयला, बिजली, पेट्रोलियम) को एक ही सांख्यिकीय छत के नीचे एकीकृत करता है।
- उत्पादन-केंद्रित भारांक: आइटम वजन प्राप्त करने की पद्धति पुराने शुद्ध व्यापार मूल्य (जीवीओ + आयात - निर्यात) की जगह आउटपुट के सकल मूल्य (जीवीओ) पर बदल गई है। जीवीओ घरेलू उत्पादक के दृष्टिकोण से वस्तुओं के वास्तविक आर्थिक महत्व को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
- अल्पकालिक सूत्रीकरण: प्राथमिक सूचकांकों की गणना अब 2011-12 श्रृंखला में उपयोग की जाने वाली कठोर, दीर्घकालिक सूत्रीकरण विधि के बजाय अल्पकालिक, श्रृंखला-आधारित विधि का उपयोग करके की जाएगी।
- उन्नत डेटा आरोपण: लापता मूल्य डेटा बिंदुओं को 'लक्षित माध्य प्रतिगणना' पद्धति का उपयोग करके नियंत्रित किया जाएगा, जो विरासत, त्रुटि-प्रवण 'कैरी-फॉरवर्ड' दृष्टिकोण को पूरी तरह से समाप्त कर देगा।

बहु-स्तरीय PPI रोलआउट: संशोधित WPI के साथ, सरकार जारी करेगी:

- आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (OPPI) और एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए)।
- सेवा पीपीआई सात महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों को कवर करता है: बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, रेलवे, एयर पैसेंजर और दूरसंचार।
- मूल बनाम क्रेता मूल्य निर्धारण मूल्यांकन: WPI, आउटपुट PPI, और सर्विस PPI को मूल कीमतों (शुद्ध कर और व्यापार/परिवहन मार्जिन को छोड़कर) का उपयोग करके संकलित किया जाएगा, जबकि इनपुट PPI क्रेता की कीमत का उपयोग यह प्रतिबिंबित करने के लिए करेगा कि कारखाने वास्तव में खुले बाजार में क्या भुगतान करते हैं।

पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री आज पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।



WORLDYOGASANA

पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026

पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एक प्रमुख, अपनी तरह का पहला वैश्विक टूर्नामेंट है जिसे योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास को एक संरचित, उत्तम प्रदर्शन वाले प्रतिस्पर्धी खेल में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशुद्ध रूप से ध्यान दिनचर्या से दूर जाते हुए, यह चैंपियनशिप एथलीटों का मूल्यांकन शारीरिक परिशुद्धता, लचीलेपन, संतुलन और सहनशक्ति के आधार पर करती है।
- मेजबान और स्थान: उद्घाटन 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में ईकेए एरिना में किया जा रहा है।
- इसमें शामिल संगठन: वैश्विक बैठक का आयोजन योगासन भारत द्वारा विश्व योगासन निकाय और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के संयुक्त सहयोग से किया जाता है।

उद्देश्य:

- प्राथमिक मिशन प्रतिस्पर्धी योग के लिए नियमों, स्कोरिंग मेट्रिक्स और शासी कोड को मानकीकृत करना है ताकि ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे भविष्य के बहु-खेल वैश्विक तमाशों में योगासन को शामिल करने के लिए एक स्पष्ट, संरचित मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

चैंपियनशिप की मुख्य विशेषताएं:

- वैश्विक स्तर और पदचिह्न: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, उज्बेकिस्तान, घाना, मलेशिया, नीदरलैंड और नेपाल के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दलों सहित 70 से अधिक देशों के 500 से अधिक विशिष्ट एथलीटों को एक साथ लाता है।
- विविध प्रतिस्पर्धी अनुशासनात्मक कार्यक्रम: एथलीट विशेष डिवीजनों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पारंपरिक योगासन: अत्यधिक सटीकता और स्थिरता के साथ संरचनात्मक मुद्राओं को धारण करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- कलात्मक योगासन (एकल, जोड़े, समूह): कोरियोग्राफ किए गए, तरल आंदोलनों को लय में सेट करना।
- लयबद्ध जोड़े: दो एथलीटों द्वारा पूर्ण सामंजस्य में निष्पादित अत्यधिक सिंक्रनाइज़ संक्रमण।
- शारीरिक विशिष्टता: प्रतियोगिताओं को विशिष्ट आसन समूहों में पार्स किया जाता है, जिसमें आगे की ओर झुकना, बैकबेंड, शरीर का घुमा, हाथ का संतुलन, पैर का संतुलन और लापरवाह मुद्राएं शामिल हैं।
- छह संस्थागत आयु वर्ग: मेजबान देश भारत 122 सदस्यीय दल को मैदान में उतार रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों से मेल खाता है जो प्रतियोगियों को छह डिवीजनों में विभाजित करता है:
- सब-जूनियर (10-14 वर्ष)
- जूनियर (14-18 वर्ष)
- वरिष्ठ (18-28 वर्ष)
- वरिष्ठ ए (28-35 वर्ष)
- वरिष्ठ बी (35-45 वर्ष), और
- वरिष्ठ सी (45-55 वर्ष)।
- इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम स्टाई: वैश्विक योग इतिहास में पहली बार, इस आयोजन में इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम पेश किया गया है। यह लचीलापन, संतुलन और मुद्रा नियंत्रण स्कोर करने के लिए मानकीकृत, पारदर्शी मेट्रिक्स का उपयोग करके व्यक्तिपरक निर्णय पूर्वाग्रहों को समाप्त करता है।

MUC1-लक्षित सिलिका नैनोकैरियर (MPPM)

संदर्भ:

पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई) के वैज्ञानिकों ने एक अभिनव जीन-साइलेंसिंग नैनोमेडिसिन विकसित की है जो स्तन कैंसर में प्रभावी ट्यूमर निषेध को चलाती है।

MUC1-लक्षित सिलिका नैनोकैरियर (MPPM)

MUC1-लक्षित सिलिका नैनोकैरियर (MPPM) के बारे में:

यह क्या है?

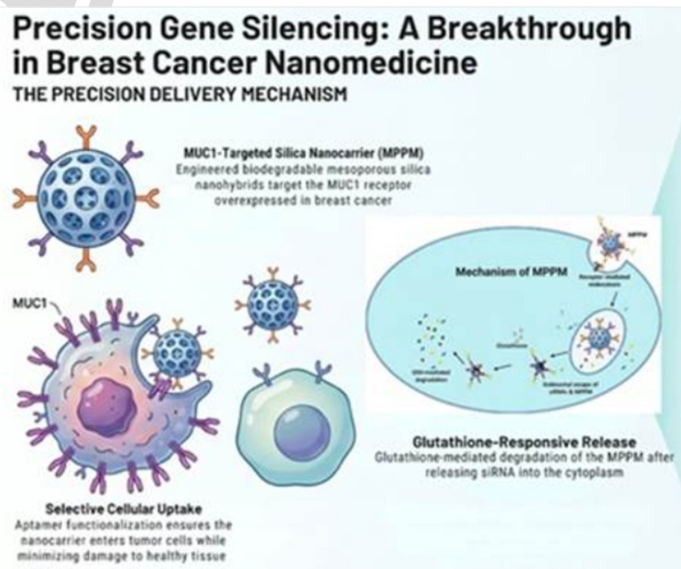
- नैनोमेडिसिन को MUC1-लक्षित सिलिका नैनोकैरियर नाम दिया गया है, जिसे संरचनात्मक रूप से MPPM के रूप में भी नामित किया गया है। यह एक इंजीनियर, बायोडिग्रेडेबल मेसोपोरस सिलिका नैनोहाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जिसे लक्षित जीन थेरेपी के लिए एक वाहन के रूप में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली आनुवंशिक सामग्री को शरीर में सुरक्षित रूप से समाहित करने और परिवहन करने के लिए अनुकूलन योग्य सतह रसायन विज्ञान का उपयोग करती है।
- इस प्लेटफॉर्म को पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई) में नैनोबायोसाइंस ग्रुप के भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था।

उद्देश्य:

- एमपीपीएम का उद्देश्य प्रणालीगत विषाक्तता को कम करते हुए घातक स्तन कैंसर कोशिकाओं के भीतर सटीक, स्थानीयकृत जीन साइलेंसिंग प्राप्त करना है।
- विशिष्ट उत्तरजीविता मार्गों को बंद करके जो ट्यूमर को पारंपरिक उपचारों का विरोध करने की अनुमति देते हैं, मंच पारंपरिक कीमोथेरेपी के लिए एक सुरक्षित और अधिक प्रभावी विकल्प प्रदान करना चाहता है।

प्रमुख विशेषताएं:

- बायोडिग्रेडेबल सिलिका कोर: बायोडिग्रेडेबल मेसोपोरस सिलिका नैनोकणों पर निर्मित, जो असाधारण रूप से उच्च पेलोड लोडिंग क्षमता और अत्यधिक ट्यून करने योग्य सतह संरचनाएं प्रदान करते हैं।
- Aptamer-निर्देशित प्रेसिजन लक्ष्यीकरण: एक प्रोटीमाइन बायोपॉलिमर और एक MUC1-विशिष्ट aptamer के साथ कार्यात्मक। यह डिज़ाइन एक लॉक-एंड-की तंत्र की तरह कार्य करता है जो स्तन कैंसर कोशिकाओं पर MUC1 रिसेप्टर्स को लक्षित करता है, सेलुलर तेज को काफी बढ़ाता है और ऑफ-टारगेट साइड इफेक्ट्स को कम करता है।



- डुअल-एक्शन siRNA पेलोड: दो महत्वपूर्ण एंटी-एपोप्टोटिक जीन: MCL-1 और सर्वाइविन के उद्देश्य से एक साथ छोटे हस्तक्षेप करने वाले RNA (siRNA) अणुओं को ले जाकर एक डबल आनुवंशिक पंच प्रदान करता है।
- ग्लूटाथियोन-उत्तरदायी रिंजीज: इसमें एक उत्तेजना-उत्तरदायी वास्तुकला होती है जो चिकित्सीय पेलोड की नियंत्रित रिहाई को तभी ट्रिगर करती है जब यह ट्यूमर के विशिष्ट रासायनिक वातावरण का सामना करती है, जिससे सटीक इंट्रासेल्युलर गतिविधि सुनिश्चित होती है।
- वीवो सुरक्षा प्रोफाइल में सिद्ध: पशु मॉडल (एससीआईडी चूहों) ने पुष्टि की कि नैनोकैरियर स्वाभाविक रूप से ट्यूमर साइट पर जमा होता है और न्यूनतम प्रणालीगत विषाक्तता प्रदर्शित करता है, जो अत्यधिक अनुकूल उतक परिणाम दिखाता है।

एमपीपीएम के अनुप्रयोग:

- एमसीएफ -7 स्तन कैंसर मॉडल में, नैनोमेडिसिन ने प्रभावी रूप से लक्ष्य जीन को चुप करा दिया, एपोप्टोसिस (क्रमादेशित कोशिका मृत्यु) को प्रेरित किया और ट्यूमर के विकास को काफी कम कर दिया।
- एमसीएल -1 और सर्वाइविन को लक्षित करके, प्रमुख जीन जो ट्यूमर को चिकित्सा से बचने में मदद करते हैं, यह पारंपरिक कैंसर उपचार के प्रतिरोध को दूर कर सकता है।
- इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन विभिन्न siRNA अणुओं को लोड करने की अनुमति देता है, जिससे कई प्रकार के कैंसर के लिए अनुकूलित जीन-साइलेंसिंग थेरेपी सक्षम हो जाती है।

ई-जागृति प्लेटफॉर्म

संदर्भ:

उपभोक्ता मामले विभाग के एआई-संचालित ई-जागृति प्लेटफॉर्म को ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रतिष्ठित रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ई-जागृति प्लेटफॉर्म

ई-जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में:

यह क्या है?

- ई-जागृति एक उन्नत, एआई-सक्षम, कागज रहित कोर पोर्टल है जिसे पूरे भारत में उपभोक्ता न्याय वितरण को आधुनिकीकरण, केंद्रीकृत और तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उपभोक्ता अदालत के विवादों को पूरी तरह से आभासी वातावरण में परिवर्तित करके भौतिक उपस्थिति या मैनुअल कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा देता है।
- शामिल मंत्रालय: यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा डिज़ाइन और कार्यान्वित की गई एक प्रमुख डिजिटल पहल है।
- में लॉन्च किया गया: प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी, 2025 को लाइव हो गया।

उद्देश्य:

- ई-जागृति का उद्देश्य उपभोक्ता कमीशन को पंगु बनाने वाले भारी मामलों के बैकलॉग को समाप्त करना और निर्बाध, लागत प्रभावी और त्वरित शिकायत निवारण प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है, जिससे किसी भी भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को दुनिया में कहीं से भी व्यवसायों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाया जा सके।

प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

- डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र चार पुराने सॉफ्टवेयर मॉडल को एकल, स्वचालित, क्लाउड-आधारित डेटा स्ट्रीम में समेकित करता है:
- विरासत प्रणाली एकीकरण: पोर्टल प्रभावी रूप से चार विशाल, स्वतंत्र ऐतिहासिक सॉफ्टवेयर इंजनों को एक लेआउट में विलय करता है: ओसीएमएस, ई-दाखिल, एनसीडीआरसी सीएमएस और कॉन्फोनेट।
- एआई और मशीन लर्निंग इंजन: इसमें एक स्वचालित एआई चैटबॉट, फाइलिंग के लिए वॉयस-टू-टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन कार्यक्षमताएं और डेटा एनालिटिक्स टूल सहित अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल शामिल हैं जो अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए भूमिका-आधारित ट्रेकिंग डैशबोर्ड तैयार करते हैं।
- एनआरआई के लिए ग्लोबल एक्सेस मैट्रिक्स: इसमें विशेष बहु-देशीय ऑनबोर्डिंग प्रोफाइल शामिल हैं। अपनी संक्षिप्त परिचालन विंडो में, इसने 3,312 अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को पंजीकृत किया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा के उपयोगकर्ताओं को भारत में कदम रखे बिना उपभोक्ता विवादों को सफलतापूर्वक दर्ज करने और हल करने की अनुमति मिली।
- यूनिफाइड पेमेंट गेटवे: पूरी तरह से कैशलेस, ऑनलाइन फाइलिंग सेटअप की सुविधा है जो सीधे भारत कोष, पेगॉव और एसबीआई ईपे जैसी सुरक्षित राज्य वित्तीय पाइपलाइनों से जुड़ी हुई है।

- वर्चुअलकोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: न्यायिक बातचीत के लिए डिफॉल्ट मानक के रूप में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्रोटोकॉल स्थापित करता है। यह प्रणाली राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) और 35 राज्य आयोगों की सभी पीठों में वास्तविक समय के डिजिटल दस्तावेज़ एक्सचेंज, स्वचालित ओटीपी ऑनबोर्डिंग सत्यापन और हाइब्रिड वीडियो सेटअप चलाती है।
- व्यापक अधिसूचना मुद्रा: एक स्वचालित अलर्ट प्रणाली का उपयोग करता है जो लगभग 20 लाख एसएमएस अलर्ट और 37 लाख से अधिक रीयल-टाइम ईमेल प्रगति अपडेट वादियों को मामले के घटनाक्रम पर अपडेट रखने के लिए भेजता है।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र

संदर्भ:

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने औपचारिक रूप से वैश्विक दवा कंपनियों को भारत के बढ़ते स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, यह देखते हुए कि देश का फार्मा उद्योग अगले पांच वर्षों में अपने वर्तमान 60 बिलियन डॉलर मूल्य को दोगुना कर सकता है।

भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र के बारे में:

यह क्या है?

- भारत का फार्मास्युटिकल क्षेत्र, जिसे विश्व स्तर पर "विश्व की फार्मेसी" के रूप में मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे दोनों के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में खड़ा है।
- यह क्षेत्र किफायती जेनेरिक दवाओं, टीकों, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और जटिल बायोसिमिलर के निर्माण में माहिर है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी:

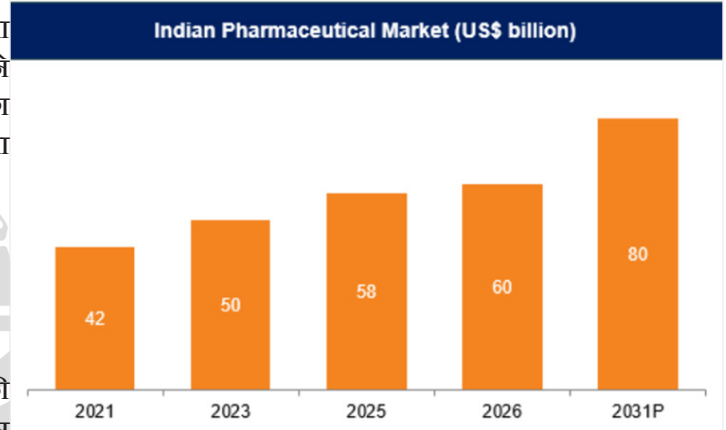
- मार्केट वैल्यूएशन प्रोजेक्शन: भारतीय फार्मास्युटिकल मार्केट वर्तमान में 2026 में \$60 बिलियन का मूल्य है और आने वाले वर्षों में आक्रामक रूप से स्केल करने का अनुमान है।
- वैश्विक वैक्सीन प्रभुत्व: भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक वैक्सीन आवश्यकताओं का लगभग 65% से 70% प्रदान करता है।
- बड़े पैमाने पर विनिर्माण पदचिह्न: भारत दुनिया की 25 सबसे बड़ी जेनेरिक दवा फर्मों में से 10 की मेजबानी करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर यूएस एफडीए-अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों की सबसे अधिक संख्या रखता है।
- वृहद-आर्थिक प्रदर्शन: 7.7% की समग्र घरेलू आर्थिक विकास दर के समर्थन से, भारत का फार्मास्युटिकल निर्यात ऐतिहासिक रूप से 2013-14 में 15.07 बिलियन डॉलर से बढ़कर हाल के वित्तीय चक्रों में 27.85 बिलियन डॉलर हो गया है।

फार्मास्युटिकल वितरण और सेगमेंट ब्रेकडाउन:

- पारंपरिक छोटे अणु प्रभुत्व: पारंपरिक छोटे-अणु पारंपरिक दवाएं उद्योग की आधार रेखा बनाना जारी रखती हैं, जो पूर्ण बाजार में 76% राजस्व हिस्सेदारी का नेतृत्व करती हैं।
- बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में घातीय वृद्धि: बड़े-अणु चिकित्सा विज्ञान और जटिल बायोसिमिलर सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पर विशेष ध्यान देने के साथ अनुमानित 15.8% सीएजीआर पर विस्तार कर रहे हैं।
- चिकित्सीय क्षेत्र का टूटना: एंटी-इंफेक्टिव पारंपरिक रूप से पोर्टफोलियो शेयर का नेतृत्व करते हैं, जबकि क्रोनिक थेरेपी श्रेणियां-जैसे कार्डियोवैस्कुलर (14.6% बाजार हिस्सेदारी) और एंटी-डायबिटिक सेगमेंट-तेजी से विस्तार कर रही हैं।
- प्रमुख खुदराफार्मेसी चैनल: ईट-और-मोर्टार खुदरा फार्मेशियां सभी घरेलू दवा बिक्री का लगभग 64.57% संभालती हैं, हालांकि डिजिटल ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म सालाना 9% से अधिक की दर से बढ़ रहे हैं।
- असममित क्षेत्रीय उत्पादन केंद्र: भौगोलिक रूप से, पश्चिम भारत (गुजरात और महाराष्ट्र में विनिर्माण केंद्रों सहित) समग्र बाजार उत्पादन का 32.24% हिस्सा रखता है, इसके बाद दक्षिण भारत में तेजी से बढ़ते वलस्टर हैं।

फार्मा क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- आयातित कच्चे माल (एपीआई) पर भारी निर्भरता: भारत बाहरी आपूर्ति श्रृंखला के झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, जो सालाना लगभग 4.35 बिलियन डॉलर मूल्य की बल्क ड्रग्स और बल्क इंटरमीडिएट्स का आयात करता है, जिसमें एक ही देश उन आयातों का 73.7% हिस्सा है।
- उन्नत अनुसंधान एवं विकास खोज पर कम सापेक्ष खर्च: भारतीय कंपनियां ऐतिहासिक रूप से अपने कॉर्पोरेट राजस्व का केवल 7% से 8% कोर अनुसंधान एवं विकास में निवेश करती हैं, जो वैश्विक नवप्रवर्तकों द्वारा निवेश किए गए 15% से 25% से काफी कम है।
- बढ़ती अनुपालन और उपचार निरीक्षण लागत: सख्त अंतरराष्ट्रीय नियामक बदलावों को पूरा करने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, साइट की सफाई और अनुपालन उन्नयन की लागत \$6 मिलियन से \$18 मिलियन प्रति सुविधा होती है।



- तीव्रअंतर्राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धी दबाव: लाभ मार्जिन को देश में राज्य-अनिवार्य मूल्य नियंत्रण और विदेशों में उभरते विनिर्माण देशों से आक्रामक बाजार प्रतिस्पर्धा से निरंतर दबाव का सामना करना पड़ता है।
- जटिल सीमा पार नियामक बाधाएं: निर्यातकों को लगातार परस्पर विरोधी अनुमोदन समयसीमा और यूएसएफडीए, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) और उभरते बाजारों द्वारा लागू अलग-अलग मानकों के अनुकूल होना चाहिए।

आगे की राह:

- उन्नत विशेषता जीवविज्ञान में बदलाव में तेजी लाना: कम-मार्जिन वाले सरल जेनेरिक को जटिल बायोसिमिलर, सेल और जीन थेरेपी, और सटीक अनाथ दवाओं में स्थानांतरित करने के लिए सार्वजनिक-निजी वित्त पोषण का समन्वय करें।
- बल्क ड्रग प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का विस्तार: घरेलू रासायनिक संश्लेषण और किण्वन परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष आक्रामक सार्वजनिक पूंजी संवितरण, आयातित प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) पर निर्भरता को कम करना।
- दीर्घकालिक नवाचार वित्त पोषण धाराओं को अधिकतम करना: स्थानीय शोधकर्ताओं को दवा की खोज के लिए उत्तम जोखिम वाली पूंजी प्रदान करने के लिए हाल ही में शुरू की गई बायोफार्मा शक्ति पहल और सरकार के बहु-क्षेत्रीय \$ 10 बिलियन के अनुसंधान एवं विकास सहायता कोष का लाभ उठाएं।
- व्यापक वैश्विक गुणवत्ता सामंजस्य को लागू करना: घरेलू MSME कारखानों को अंतरराष्ट्रीय गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के साथ संरेखित करने और वैश्विक व्यापार पहुंच को आसान बनाने के लिए संशोधित अनुसूची M विनिर्माण दिशानिर्देशों के रोलआउट में तेजी लाना।
- उन्नत एआई और डिजिटल गुणवत्ता प्रणालियों को तैनात करना: पूर्वानुमानित लक्ष्य खोज में तेजी लाने, डिजिटल गुणवत्ता ऑडिट को स्वचालित करने और परिचालन ओवरहेड को कम करने के लिए फ़ैक्ट्री लाइनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम को एकीकृत करना।

निष्कर्ष:

भारत के फार्मास्युटिकल क्षेत्र ने लागत-कुशल उत्पादन मॉडल के साथ वैश्विक विनिर्माण मानकों का मिलान करके "विश्व की फार्मसी" के रूप में अपनी विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। जबकि कच्चे माल पर निर्भरता और कम कोर खोज बजट संरचनात्मक बाधाएं बनी हुई हैं, लक्षित पीएलआई योजनाओं और समर्पित नवाचार वित्त पोषण का विस्तार आगे बढ़ने का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है।

एलपीएमएस - विनिमे सिस्टम

संदर्भ:

केंद्रीय गृह मंत्री ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'विनिमेय' नामक उन्नत भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस) प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया।

एलपीएमएस - विनिमे सिस्टम

LPMS – विनिमे सिस्टम के बारे में:

यह क्या है?

- 'विनिमेय' एक केंद्रीकृत, रीयल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे भारत के अंतरराष्ट्रीय भूमि बंदरगाहों पर संचालन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह कार्गो ट्रैकिंग, यात्री लॉग और वाहन प्रसंस्करण को एकीकृत करके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से ही संचालित आधुनिक, स्वचालित नेटवर्क के बराबर भूमि सीमा सुरक्षा और व्यापारिक बुनियादी ढांचे को लाता है।
- डेवलपर और रणनीति: पोर्टल को गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक मार्गदर्शन में भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (LPAI) द्वारा विकसित किया गया है।

उद्देश्य:

- विनिमेय प्रणाली का उद्देश्य गंभीर रसद बाधाओं और कागज-भारी वर्कफ्लो को खत्म करना है जो ओवरलैंड व्यापार में देरी करते हैं।
- राष्ट्रीय नियामक और सुरक्षा डेटाबेस को एक ही इंटरफेस पर निर्बाध रूप से जोड़कर, इसका उद्देश्य भौतिक सीमाओं को सुरक्षित करना, अनधिकृत क्रॉसिंग को रोकना, परिचालन ओवरहेड लागत को कम करना और विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप क्षेत्रीय सीमा पार वाणिज्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

'विनिमेय' की मुख्य परिचालन विशेषताएं:

- प्रसंस्करण घर्षण में आमूल-चूल कमी: यह प्रणाली सभी भौतिक कागजी कार्रवाई का लगभग 90% सफलतापूर्वक समाप्त कर देती है। यह स्वचालित प्रक्रियाओं का परिचय देता है जो सीमा पर ट्रक प्रतीक्षा समय को 40% से 60% तक कम करता है और कुल गेट प्रसंस्करण समय को 22% से 35% तक कम करता है।



- इंटर-एजेंसी रीयल-टाइम डेटा मोट: विनिमे पहले से अलग-थलग किए गए सरकारी डेटाबेस को जोड़ता है, जिससे एक ही डैशबोर्ड पर वास्तविक समय की जानकारी साझा करने में सक्षम होता है;
- ICEGATE और CBIC (सीमा शुल्क फाइलिंग और वित्तीय अनुपालन ट्रैकिंग)
- बीएसएफ (फ्रंटलाइन फिजिकल बॉर्डर गार्डिंग एंड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन)

यूआईडीएआई (बायोमेट्रिक और पहचान जांच)

- डीजीएफटी और यूलिप (व्यापार लाइसेंस और लॉजिस्टिक्स शृंखला दृश्यता)
- राष्ट्रीय मोटर वाहन प्रणाली (वाणिज्यिक वाहन ट्रैकिंग)
- एएनपीआर-संचालित गेट स्वचालन: प्रवेश और निकास द्वारों पर उन्नत स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम का उपयोग करता है। यह आने वाले वाहनों को पहले से बुक किए गए स्लॉट के साथ स्वचालित रूप से मेल खाता है, मैनुअल लॉगबुक प्रविष्टियों को दूर करता है और मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है।
- मैक्रो नेटवर्क एकीकरण: पोर्टल वर्तमान में भारत के 15 सक्रिय भूमि बंदरगाहों में संचालन का समन्वय करता है, जिसमें अगले तीन वर्षों में चालू होने वाले 11 अतिरिक्त भूमि बंदरगाहों को निर्बाध रूप से ऑनबोर्ड करने की अंतर्निहित संरचनात्मक क्षमता है।

तिलहन किसान मित्र

संदर्भ:

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तिलहन की खेती के लिए भारत की पहली व्हाट्सएप-आधारित एआई सलाहकार सेवा 'तिलहन किसान मित्र' के राष्ट्रव्यापी प्रभाव पर प्रकाश डाला, क्योंकि किसान महत्वपूर्ण खरीफ बुवाई मौसम में प्रवेश कर रहे हैं।

तिलहन किसान मित्र

तिलहन किसान मित्र के बारे में:

यह क्या है?

- तिलहन किसान मित्र एक 24x7, बहुभाषी, एआई-संचालित डिजिटल सलाहकार चैटबॉट है जिसे सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- यह एक तत्काल, नि: शुल्क वैज्ञानिक परामर्श गेटवे के रूप में कार्य करता है जो पारंपरिक किसानों को बाहरी मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने या जटिल इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना दशकों के सामूहिक कृषि अनुसंधान से जोड़ता है।
- द्वारा विकसित: डिजिटल प्लेटफॉर्म को ICAR-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOR), हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया था।



कैसे एक्सेस करें और यह कैसे काम करता है?

- प्लेटफॉर्म उच्च तकनीक कृषि विस्तार को तीन बुनियादी उपयोगकर्ता वर्गों में सरल बनाता है:
- चरण 1: किसान अपने स्मार्टफोन पर आधिकारिक समर्पित संपर्क नंबर +91 4024598180 'तिलहन किसान मित्र' के रूप में सहेजता है।
- चरण 2: उपयोगकर्ता व्हाट्सएप खोलता है और अपनी मूल क्षेत्रीय भाषा में क्रॉप-संबंधित क्वेरी टाइप करता है, बोलता है या भेजता है।
- चरण 3: अंतर्निहित एआई इंजन तुरंत स्थानीयकृत पाठ को पार्स करता है, इसे एक सत्यापित वैज्ञानिक भंडार से मिलाता है, और स्पष्ट, शोध-मान्य सलाह देता है।

प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

- व्यापक तिलहन कवरेज: मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन और नाइजर सहित सभी प्रमुख घरेलू तिलहन समूहों में सटीक, स्थान-विशिष्ट सलाह प्रदान करता है।
- पूर्ण बहुभाषी एकीकरण: इसमें एक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण वास्तुकला है जो सभी आधिकारिक भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं (हिंदी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु और मलयालम सहित) में तुरंत समझती है और प्रतिक्रिया देती है।
- एंड-टू-एंड फसल चक्र मार्गदर्शन: कृषि कार्यों के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करता है:
- उच्च उपज वाले क्षेत्रीय बीज किस्म का चयन और आधिकारिक बीज उपलब्धता।
- कृषि संबंधी मिट्टी की तैयारी और बुवाई की प्रथाएं।
- वास्तविक समय कीट, खरपतवार और रोग नियंत्रण निदान।
- सटीक सिंचाई शेड्यूलिंग और अनुरूप उर्वरक अनुप्रयोग।
- कटाई के बाद प्रसंस्करण, सुखाने और भंडारण तकनीकें।
- मल्टी-इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव ब्रेन: डेटाबेस अलग-थलग नहीं है; यह कई प्रमुख अनुसंधान निकायों के संयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान को एकीकृत करता है:

- भाकृअनुप-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर (एनएसआरआई)
- भाकृअनुप-भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान, जूनागढ़ (आईआईजीआर)
- भाकृअनुप-भारतीय रेपसीड एवं सरसों अनुसंधान संस्थान, भरतपुर (आईआईआरएमआर)
- तिल और नाइजर के लिए परियोजना समन्वय इकाई

वर्या एआई मॉडल

संदर्भ:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले स्वदेशी, डिस्टिल्ड वीडियो स्टोरी-जनरेटिंग AI मॉडल "Varya" का अनावरण किया है।

वर्या एआई मॉडल

वर्या एआई मॉडल के बारे में:

यह क्या है?

- वर्या एक अभूतपूर्व, स्वदेशी फाउंडेशन एआई वीडियो मॉडल है जिसे उन्नत मशीन लर्निंग डिस्टिलेशन का उपयोग करके इंजीनियर किया गया है।
- यह एक जनरेटिव टेक्स्ट-टू-वीडियो और इमेज-टू-वीडियो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जिसे सरल लिखित विचारों, संकेतों या अपलोड की गई छवियों को उत्तम-गुणवत्ता, चलती डिजिटल कहानियों में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- द्वारा विकसित: मूलभूत मॉडल अवतार द्वारा बनाया गया था, जो एक एआई-देशी परिवर्तन कंपनी है।
- उद्देश्य: वर्या का लक्ष्य गणना लागत, भाषा और हार्डवेयर आवश्यकताओं की भारी बाधाओं को दूर करके पूरे भारत में उत्तम-स्तरीय जनरेटिव एआई तकनीक का लोकतंत्रीकरण करना है।



प्रमुख विशेषताएँ:

- आसुत वीडियो निर्माण की शक्ति: वर्या एक बड़े एआई मॉडल को हटके संस्करण में संपीड़ित करता है, जिससे 4 के बजाय केवल 50 चरणों में उत्तम गुणवत्ता वाले वीडियो तैयार होते हैं, जिससे गति और दक्षता में काफी सुधार होता है।
- भारीलागत-दक्षता: वीडियो के लगभग ₹0.48 प्रति सेकंड पर, वर्या नाटकीय रूप से सामग्री-निर्माण लागत को कम कर देता है, जिससे उन्नत एआई वीडियो पीढ़ी व्यापक उपयोग के लिए सस्ती हो जाती है।
- विस्तृत सांस्कृतिक संदर्भ जागरूकता: मॉडल को भारतीय संदर्भों पर प्रशिक्षित किया गया है, जो क्षेत्रीय त्योहारों, पोशाक, भोजन की आदतों, भाषाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के सटीक प्रतिनिधित्व को सक्षम करता है।
- "वीडियो → कहानी → विचार" वर्कफ्लो: उपयोगकर्ता टेक्स्ट या छवियों से वीडियो उत्पन्न कर सकते हैं और फिर उन्हें निर्बाध लंबी-फॉर्म कथाएँ बनाने के लिए अतिरिक्त संकेतों के साथ विस्तारित कर सकते हैं।

महत्त्व:

- कम परिचालन लागत उन्नत एआई उपकरणों को शहरी और ग्रामीण भारत में शिक्षकों, छात्रों, उद्यमियों और रचनाकारों के लिए सुलभ बनाती है।
- एमएसएमई किफायती, क्षेत्र-विशिष्ट विज्ञापन और प्रचार सामग्री बना सकते हैं, विपणन लागत को कम कर सकते हैं और बाजार पहुंच में सुधार कर सकते हैं।

सशक्त युवा, मजबूत राष्ट्र: विकसित भारत @ 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण

संदर्भ:

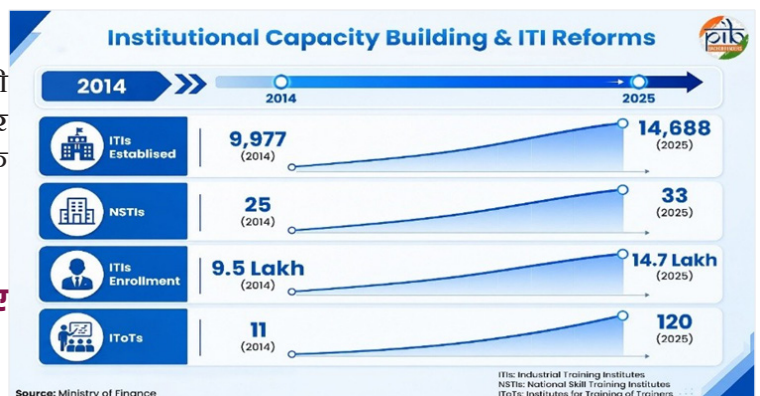
रोजगार की गुणवत्ता और युवाओं की आकांक्षाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच, हाल के श्रम बाजार के आकलन ने निरंतर आर्थिक विकास के बावजूद भारत की रोजगार दर में एक दशक की गिरावट को उजागर किया है।

विकसित भारत के लिए भारत का विजन @ 2047

सशक्त युवा, मजबूत राष्ट्र के बारे में: विकसित भारत @ 2047 के लिए भारत का विजन:

यह क्या है?

- अपनी लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु के साथ, भारत युवाओं को निष्क्रिय प्रशासनिक लाभार्थियों के रूप में मानने



से उन्हें राष्ट्रीय विकास के सक्रिय, युवाओं के नेतृत्व वाले सह-निर्माता के रूप में शामिल करने के लिए एक संरचनात्मक बदलाव कर रहा है।

- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के मूलभूत दिशानिर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, नई प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति 2025 फ्रेमवर्क अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक कार्यबल के निर्माण के लिए भविष्य के लिए तैयार कौशल, डिजिटल भागीदारी, नागरिक जुड़ाव और टिकाऊ उद्यम को प्राथमिकता देती है।

भारत की युवा पहलों पर प्रमुख डेटा और आंकड़े:

शैक्षिक पुनर्गठन और पहुंच:

- बुनियादी ढांचे का पैमाना: भारत दुनिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क में से एक चलाता है, जो 24.69 करोड़ छात्रों की सेवा करने वाले 14.71 लाख स्कूलों में फैला हुआ है। उच्च शिक्षा स्तर पर, जून 2025 तक कुल परिचालन संस्थान 51,000 से बढ़कर 70,000 से अधिक हो गए।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी): एनईपी 2020 द्वारा संचालित, एबीसी प्लेटफॉर्म ने 2,469 संस्थानों को शामिल किया है और 32 करोड़ से अधिक छात्र आईडी जारी किए हैं, जो निर्बाध क्रॉस-इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पोर्टेबिलिटी को सक्षम करते हैं।
- डिजिटल रजिस्ट्रियां (एपीएआर आईडी): ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ने निरंतर शैक्षणिक और कौशल क्रेडिट जमा करने के लिए 15.48 करोड़ सत्यापित छात्र पहचानकर्ता खाते तैयार किए हैं।
- मेडिकल सीटों का विस्तार: 2025-26 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 818 हो गई, जिससे कुल परिचालन एमबीबीएस और पीजी क्षमता क्रमशः 1,28,976 और 85,822 सीटों तक पहुंच गई।
- अटल इनोवेशन नेटवर्क: 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स की महत्वपूर्ण तैनाती ने 1.1 करोड़ स्कूली छात्रों को 16 लाख तकनीकी प्रोटोटाइप बनाने के लिए सशक्त बनाया है।

कौशल, इंटरनशिप और औपचारिकता:

- पीएम-सेतु आधुनिकीकरण: अक्टूबर 2025 में ₹60,000 करोड़ के अनुमानित पूंजी लेआउट के साथ शुरू की गई, यह योजना केंद्रीकृत हब-एंड-स्पोक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल के माध्यम से 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण करती है।
- प्लैगशिप शॉर्ट-टर्म रिक्रानिंग (पीएमकेवीवाई): अपने मांग-संचालित चरणों में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 40 विशेष क्षेत्रों में 27 लाख से अधिक उम्मीदवारों सहित लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है।
- राष्ट्रीय शिक्षता कार्यक्रम: अपने दूसरे चरण (एनएपीएस 2.0) में संचालित, पोर्टल ने 2016 से 54.41 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल किया है, जो 25% प्रत्यक्ष राज्य वजीफा योगदान द्वारा समर्थित है।
- प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (PMIS): अकादमिक-उद्योग अंतर को कम करने के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू की गई, यह योजना 25+ क्षेत्रों में 63,000 से अधिक संरचित इंटरनशिप रिक्रानियों की पेशकश करती है, जो ₹9,000 के मासिक वजीफे द्वारा समर्थित है।
- औपचारिक कार्यबल विस्तार: आधिकारिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल 2020 और जून 2025 के बीच 18-28 आयु वर्ग के 3.45 करोड़ से अधिक युवा औपचारिक संगठित कार्यबल में शामिल हुए।

स्टार्टअप, समावेशिता और डिजिटल प्लेटफॉर्म:

- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम: डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 2014 से पहले 350 की न्यूनतम बेसलाइन से बढ़कर जून 2026 तक 2.3 लाख से अधिक उद्यम हो गए, जिससे कुल 23 लाख नौकरियां पैदा हुईं।
- यूनिकॉर्न का उछाल: 1 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य वाले निजी तौर पर आयोजित तकनीकी स्टार्टअप 2014 में 4 से बढ़कर 2026 की शुरुआत में 120 से अधिक फर्मों तक पहुंच गए, जिसका संयुक्त बाजार मूल्यांकन 350 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया।
- जमीनी स्तर पर स्तरीय विस्तार: सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से लगभग 50 प्रतिशत अब क्षेत्रीय आर्थिक विकास को संतुलित करते हुए टियर- II और टियर- III शहरों से निकलते हैं।
- स्टैंड-अप इंडिया रिकॉर्ड: महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संस्थापकों के बीच समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया, कुल ऋण अनुमोदन 2018 में ₹14,431.14 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 तक ₹61,020.41 करोड़ हो गया।
- द डिजिटल अम्ब्रेला (MY भारत): 31 अक्टूबर, 2023 को स्थापित, मेरा युवा भारत नेटवर्क डिजिटल जुड़ाव और अनुभवात्मक सीखने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें जून 2026 तक 2.19 करोड़ से अधिक पंजीकृत युवा शामिल होंगे।
- खेल और निवारक स्वास्थ्य देखभाल:
- खेलो इंडिया पहचान: 1,067 विशेष जिला केंद्रों में स्थापित, कीर्ति कार्यक्रम ने ग्रामीण स्तर पर 1.8 लाख डेटा-संचालित प्रतिभा मूल्यांकन निष्पादित किए हैं, जिसमें 6.28 लाख रुपये के वार्षिक अनुदान के साथ 23,080 विशिष्ट युवा एथलीटों का समर्थन किया गया है।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके): एक समुदाय-केंद्रित मॉडल में संक्रमण, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एफएचसी) में नैदानिक परामर्श का उपयोग 2014-15 में 39 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1.7 करोड़ हो गया।
- टेली-मानस मानसिक स्वास्थ्य सेवा: विशेष 24/7 टेली-परामर्श हेलपलाइन ने बिना किसी कलंक के युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपनी शुरुआत के बाद से 39.52 लाख से अधिक कॉल का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है।

पिछले 12 वर्षों में युवा विकास में प्रमुख रुझान:

- खंडित देखभाल से संरचित बहु-विषयक प्रणालियों की ओर बढ़ना: एनईपी 2020 का कार्यान्वयन कई प्रवेश और निकास मार्ग पेश करता है, कठोर शैक्षणिक सीमाओं को समाप्त करता है और 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) का लक्ष्य रखता है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण से मांग-संचालित उत्तम तकनीक कौशल में परिवर्तन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन विमानन सहित उत्तम विकास वाले क्षेत्रों में नौकरी पर प्रशिक्षण को एकीकृत करने के लिए प्रमुख कौशल मिशनों को अद्यतन किया गया है।
- क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ संरेखित हाइपरलोकल रिकलिंग: 776 जिलों में जिला कौशल समितियों (डीएससी) को बढ़ाने से जिला कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से स्थानीय कार्यबल प्रशिक्षण को सीधे क्षेत्रीय व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है।
- वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी का विस्तार: अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ दोहरी डिग्री के लिए मार्ग बनाना और विदेशी परिसर (जैसे आईआईटी ज़ांज़ीबार, आईआईटी अबू धाबी और दुबई में आईआईएम अहमदाबाद) खोलने से भारत के वैश्विक शैक्षणिक पदचिह्न को काफी बढ़ावा मिला है।

युवा कल्याण और रोजगार में प्रमुख चुनौतियाँ:

- अकादमिक स्नातकों के लिए सॉफ्ट स्किल गैप को बंद करना: जबकि प्रधान मंत्री इंटरशिप योजना व्यावहारिक कॉर्पोरेट अनुभव प्रदान करती है, कई तकनीकी और मानविकी स्नातकों में अभी भी नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक व्यावहारिक वर्कप्लो कौशल की कमी है।
- गिन और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक बदलावों का प्रबंधन: डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए युवा गिन श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा जाल और मजदूरी प्रतिभूतियों के लिए चल रहे अपडेट की आवश्यकता होती है।
- प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए स्थानीय लालफीताशाही पर काबू पाना: स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल जैसे केंद्रीकृत फंडिंग प्लेटफॉर्म के बावजूद, प्रारंभिक चरण के व्यवसायों को नगरपालिका स्तर पर विलंबित परिचालन अनुमोदन का सामना करना पड़ सकता है।
- पूर्व सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए करियर परिवर्तन में सुधार: युवा पूर्व सैनिकों को सिविल सेवा भूमिकाओं में एकीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय रेलवे और राज्य पुलिस बलों के बीच स्थिर, दीर्घकालिक समन्वय की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- SOAR पहल के माध्यम से AI-संचालित कक्षाओं में तेजी लाना: छात्रों को कोर मशीन-लर्निंग कौशल से लैस करने के लिए ग्रामीण स्कूलों में AI रेडीनेस (SOAR) मॉड्यूल के लिए रिकलिंग का विस्तार करें।
- प्रारंभिक चरण के इनक्यूबेशन फंड की पूंजी पहुंच का विस्तार: स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) की क्षमता को बढ़ावा देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टियर-III शहरों में प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट पूंजी तक पहुंच प्राप्त हो।
- विकसित भारत रोजगार योजना के प्रोत्साहनों को लागू करना: पहली बार नौकरी चाहने वालों के लिए औपचारिक-क्षेत्र की भूमिकाएं बनाने के लिए व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1 लाख करोड़ के परिकल्पित कार्यक्रम को लागू करना।
- डिजिटल स्वास्थ्य ब्रिड में सामाजिक सुरक्षा का मानकीकरण: राज्य की सीमाओं के पार जाने वाले युवा श्रमिकों के लिए पोर्टेबल, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उपयोग करें।

निष्कर्ष:

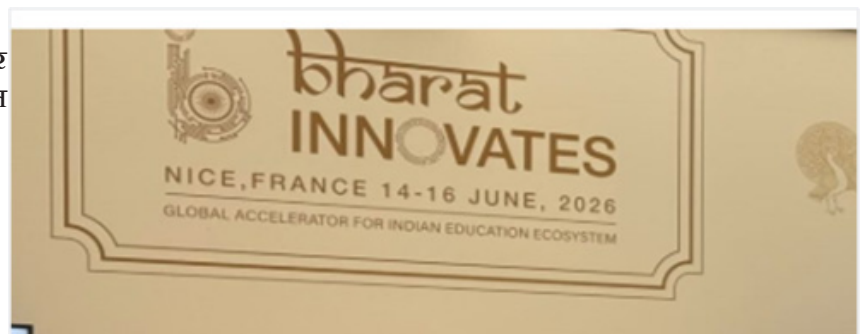
निष्क्रिय युवा विकास से सक्रिय, युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यम पर केंद्रित मॉडल में भारत का संरचनात्मक बदलाव इसकी सामाजिक-आर्थिक नीति में एक बड़ा कदम है। लचीली शैक्षणिक ऋण रजिस्ट्रियों को मांग-संचालित कौशल नेटवर्क और पूर्ण-जीवनचक्र स्टार्टअप फंडिंग के साथ जोड़कर, राष्ट्र ने अपने जनसांख्यिकीय लाभों के लिए एक लचीली नींव बनाई है।

भारत-फ्रांस एटीएल ब्रिज**संदर्भ:**

भारत-फ्रांस एटीएल ब्रिज को आधिकारिक तौर पर नीस, फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था।

भारत-फ्रांस एटीएल ब्रिज**भारत-फ्रांस ATL ब्रिज के बारे में:****यह क्या है?**

- भारत-फ्रांस एटीएल ब्रिज एक उत्तम स्तरीय द्विपक्षीय शिक्षा और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम कॉरिडोर है। यह एक सीमा पार मंच के रूप में कार्य करता है जो संरचनात्मक रूप से भारत और फ्रांस के बीच स्कूल स्तर के नवप्रवर्तकों, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी ढांचे को जोड़ता है।



- हितधारक: अटल इनोवेशन मिशन (AIM), NITI आयोग (भारत सरकार) और ला फोंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स (फ्रांस) के बीच एक संयुक्त साझेदारी के माध्यम से स्थापित।

उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य स्कूली आयु वर्ग के युवाओं के बीच प्रारंभिक चरण की इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक सोच और डिजाइन सोच का लोकतंत्रीकरण करना है।
- भारत की जमीनी स्तर पर टिकरिंग पद्धति का निर्यात करके, यह एक सिंक्रनाइज़ अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का प्रयास करता है जहां दोनों देशों के छात्र वास्तविक दुनिया की वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों पर सहयोग कर सकते हैं।

पहल की मुख्य विशेषताएं:

- जमीनी स्तर पर टिकरिंग फ्रेमवर्क का निर्यात: यह पहल फ्रांस की पहली स्कूल इनोवेशन लैब की स्थापना करती है, जो व्यावहारिक शिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत के एटीएल मॉडल की नकल करती है।
- सीमा पार उद्यमशीलता पाइपलाइन: छात्र आदान-प्रदान और मेंटरशिप कार्यक्रम युवा नवप्रवर्तकों को वैश्विक विशेषज्ञों से जोड़ते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और सहयोगात्मक समस्या-समाधान करते हैं।
- उन्नत तकनीकी फोकस: प्रयोगशालाएं रोबोटिक्स, एआई, 3डी प्रिंटिंग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन थिंकिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती हैं।
- दार्शनिक आधार: वसुधैव कुटुम्बकम् से प्रेरित होकर, साझेदारी वैश्विक सामूहिक विकास के लिए शैक्षिक नवाचारों और प्रौद्योगिकी को साझा करने को बढ़ावा देती है।

भारत इनोवेट्स 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- भारत इनोवेट्स 2026 एक उत्त्व-स्तरीय राष्ट्रीय डीप-टेक एक्सेलरेशन प्रोग्राम का पहला संस्करण है, जिसे भारत से उभरने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारतीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक कॉर्पोरेट नेटवर्क, निवेशकों और विदेशी पूर्व छात्रों के साथ जोड़ने वाले एक निरंतर, अंतराष्ट्रीय सहयोग ढांचे के रूप में कार्य करता है।

शासन:

- इस पहल की मेजबानी और संचालन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- 2026 वर्ष को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाता है।

मेज़बान: नाइस, फ्रांस

- उद्देश्य: भारत इनोवेट्स 2026 का प्राथमिक उद्देश्य भारत के घरेलू नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक बाजारों के बीच एक उत्त्व प्रभाव वाले संरचनात्मक पुल का निर्माण करना है।

2026 संस्करण की मुख्य विशेषताएं:

- वैश्विक स्थान और पैमाना: यह आयोजन 120 प्रमुख भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप को फ्रांस में लाता है, जो वैश्विक खरीदारों, निवेशकों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सीधा संपर्क सक्षम बनाता है।
- शैक्षणिक और वैज्ञानिक कोर: आईआईटी और आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थान भाग लेते हैं, भारत की अनुसंधान शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- 13 अग्रणी प्रौद्योगिकी क्षेत्र: नवाचार सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, रक्षा, बायोटेक, जलवायु तकनीक और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
- निवेशक-इनोवेटर वर्कशेप: समर्पित मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ते हैं, फंडिंग के अवसरों, साझेदारी और वाणिज्यिक विस्तार में तेजी लाते हैं।
- सॉफ्ट-लैंडिंग और संयुक्त प्रोटोटाइप मार्ग: ढांचा सह-ऊष्मायन, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और तेजी से उत्पाद सत्यापन का समर्थन करता है, जिससे स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजारों में अधिक कुशलता से प्रवेश करने में मदद मिलती है।

औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K

संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें छोटे गांवों में कफ सिरप बेचने के लिए पहले दी गई लाइसेंसिंग छूट को स्पष्ट रूप से वापस ले लिया गया है।

औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K

औषधि नियम, 1945 की अनुसूची K के बारे में:



यह क्या है?

- अनुसूची K भारत के दवा नियामक ढांचे के भीतर एक अत्यधिक विशिष्ट वैधानिक अनुबंध है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय IV के कुछ प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों से छूट प्राप्त दवाओं के विशिष्ट वर्गों को सूचीबद्ध करता है।
- यह विशिष्ट परिस्थितियों में सख्त खुदरा बिक्री लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल में ढील देकर कम सेवा वाले क्षेत्रों में बुनियादी ओवर-द-काउंटर या आवश्यक दवाओं की आसान उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नियामक राहत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- शासी कानून: अनुसूची K सीधे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के वैधानिक प्राधिकरण के तहत संचालित होती है, और इसे औषधि नियम, 1945 के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

उद्देश्य:

- अनुसूची K का उद्देश्य सुरक्षा मानकों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य पहुंच को संतुलित करना है।
- यह एक बुनियादी ढांचा बनाता है जो ग्रामीण, दूरदराज या आर्थिक रूप से अलग-थलग क्षेत्रों में आम घरेलू दवाओं के वितरण की अनुमति देता है, जबकि सरकार को गतिशील रूप से छूट को दूर करने की अनुमति देता है जब एक विशिष्ट दवा वर्ग एक उभरता हुआ सार्वजनिक सुरक्षा या गुणवत्ता नियंत्रण जोखिम प्रस्तुत करता है।

अनुसूची K और इसके हालिया संशोधन की मुख्य विशेषताएं:

- लक्षित लाइसेंसिंग छूट: दवा वर्गों की एक निश्चित, मदवार सूची प्रदान करता है जिन्हें औपचारिक खुदरा बिक्री लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है, बशर्ते वे विशिष्ट भंडारण, पैकेजिंग और सोर्सिंग शर्तों को पूरा करते हों।
- ऐतिहासिक ग्राम छूट आधाररेखा: अनुसूची के क्रम संख्या 13, प्रविष्टि 7 के तहत, 1,000 से कम व्यक्तियों की आबादी वाले छोटे गांवों को कानूनी रूप से स्थानीय दुकानदारों के बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट लाइसेंस रखने की आवश्यकता के बिना चुनिंदा वस्तुओं को स्टॉक करने और बेचने की अनुमति दी गई थी।
- सिरप हटाने का निर्देश: नवीनतम संशोधन निर्दिष्ट प्रविष्टि से सिरप शब्द को व्यवस्थित रूप से हटा देता है। यह छोटा सा पाठ्य चूक पूरे कानूनी समर्थन को हटा देता है जिसने कफ सिरप फॉर्मूलेशन को खुदरा निरीक्षण ढांचे से बेचने की अनुमति दी।
- अनिवार्य फार्मसी ऑनबोर्डिंग: इस चूक के बाद, तरल खांसी फॉर्मूलेशन बेचने का प्रयास करने वाले किसी भी ग्रामीण आउटलेट, वितरक, या जनरल स्टोर को प्रमाणित पेशेवरों द्वारा संचालित पूरी तरह से अनुपालन, लाइसेंस प्राप्त खुदरा फार्मसी में संक्रमण करना चाहिए।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए सख्त अनुपालन अधिदेश: यह ढांचा सभी निर्माताओं, थोक वितरकों और ग्रामीण खुदरा विक्रेताओं को अपने आपूर्ति नेटवर्क को तुरंत अपडेट करने के लिए बाध्य करता है, जिससे सिरप की बोटलों की किसी भी अलिखित या बिना लाइसेंस वाली ओवर-द-काउंटर ड्रॉप-शिपिंग को रोक दिया जा सके।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी)**संदर्भ:**

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आधिकारिक तौर पर डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी, साथ ही तीन प्रमुख डोमेन विशेषज्ञों को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) के अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी)**राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के बारे में:****यह क्या है?**

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) एक सशक्त, स्वायत्त सलाहकार निकाय है जिसे पूरे भारत में सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। यह एक केंद्रीकृत नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसे डेटा संग्रह और वितरण के लिए राष्ट्रव्यापी बेंचमार्क स्थापित करते हुए आधिकारिक डेटा संग्रह को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्थापना और उत्पत्ति:

- रंगराजन फाउंडेशन: सरकार ने जनवरी 2000 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ आयोग का गठन किया, जो संपूर्ण भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करेगा।
- औपचारिक अधिसूचना: इन सिफारिशों के अनुरूप, भारत सरकार ने 1 जून, 2005 को एक कार्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आधिकारिक तौर पर एनएससी का निर्माण हुआ। आयोग औपचारिक रूप से प्रभावी हुआ और 12 जुलाई, 2006 को अपना जनादेश शुरू किया।



NATIONAL STATISTICAL COMMISSION

शासन संरचना:

- कार्यकारी नेतृत्व: आयोग में चार अंशकालिक सदस्यों के साथ एक अंशकालिक अध्यक्ष होता है, जिन्हें सांख्यिकीय क्षेत्रों, परिचालन अनुसंधान और कंप्यूटर विज्ञान में उनकी विशेषज्ञता और तकनीकी अनुभव के लिए चुना जाता है।
- पदेन संस्थागत प्रतिनिधित्व: नीति आयोग के सीईओ राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के साथ सांख्यिकीय योजना को संरेखित करने के लिए एक स्थायी, पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
- सचिवालय: भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) - जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रमुख है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के भीतर भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य करता है - एनएससी के औपचारिक सचिव के रूप में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

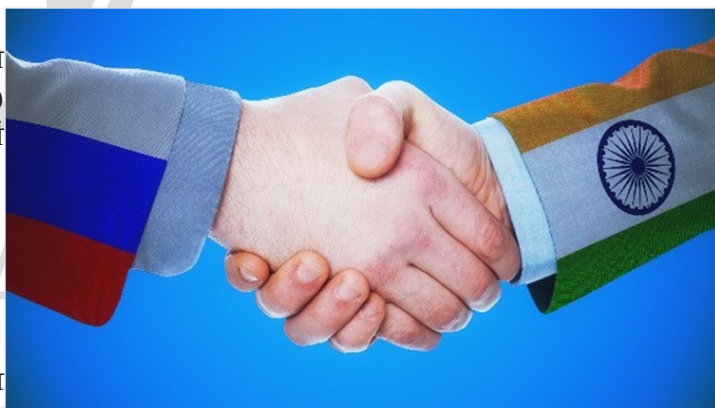
- राष्ट्रीय नीतियां तैयार करना: व्यापक राष्ट्रीय नीतियों को विकसित करने, रणनीतिक प्राथमिकताएं निर्धारित करने और आधिकारिक आंकड़ों की सभी शाखाओं में अवधारणाओं, परिभाषाओं और वर्गीकरण पद्धतियों को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार।
- गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना: मुख्य सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के लिए सख्त राष्ट्रीय गुणवत्ता बेंचमार्क स्थापित और निगरानी करता है - जैसे कि मुद्रास्फीति मेट्रिक्स, औद्योगिक उत्पादन डेटा और राष्ट्रीय आय खाते।
- अंतर-एजेंसी सांख्यिकीय समन्वय: राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के साथ ऊर्ध्वाधर सहयोग का प्रबंधन करते हुए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बीच क्षैतिज समन्वय का नेतृत्व करता है।
- स्वतंत्र सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना: राष्ट्रीय डेटा उत्पादों की गुणवत्ता और संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित करने के लिए डेटा संकलन पद्धतियों पर व्यापक सांख्यिकीय ऑडिट निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है।
- सतत प्रणालीगत समीक्षा: स्थापित पद्धतियों के खिलाफ व्यापक सांख्यिकीय प्रणाली के कामकाज की निगरानी और समीक्षा करता है, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश करता है।

प्रोलिम्स इन फोकस : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**संदर्भ:**

भारत-रूस द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (LSA), जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOA/RELOS) के रूप में जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में संचालित किया गया था।

रसद समझौते का पारस्परिक आदान-प्रदान (RELOS)**रसद समझौते के पारस्परिक आदान-प्रदान (RELOS) के बारे में:****यह क्या है?**

- RELOS एक मूलभूत, गैर-आक्रामक सैन्य सहयोग समझौता है जिसे प्रशासनिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पारस्परिक रूप से सहमत नौसैनिक और हवाई तैनाती के दौरान ईंधन भरने, आपूर्ति और रखरखाव के लिए एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों, हवाई क्षेत्रों और बंदरगाहों के पारस्परिक उपयोग के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करता है।

**समयरेखा और द्विपक्षीय फाउंडेशन:**

- हस्ताक्षर: समझौते पर औपचारिक रूप से दोनों देशों द्वारा 18 फरवरी, 2025 को मास्को में हस्ताक्षर किए गए थे।
- परिचालन: यह समझौता आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में लागू हुआ।
- भाग लेने वाले सदस्य: भारत गणराज्य और रूसी संघ के बीच विशेष रूप से द्विपक्षीय।
- उद्देश्य: RELOS का उद्देश्य संयुक्त अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच प्रशासनिक नौकरशाही को सरल और कम करना है। एक मानकीकृत लेखा प्रणाली के साथ धीमी, मामला-दर-मामला मंजूरी को बदलकर, समझौते का उद्देश्य टर्नअराउंड समय में तेजी लाना, रसद बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के युद्धपोतों और सैन्य विमानों की परिचालन पहुंच का विस्तार करना है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- विनियमित परिचालन अवसर: रसद ढांचे को केवल विशिष्ट, पारस्परिक रूप से नियोजित घटनाओं के दौरान सक्रिय किया जा सकता है: संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन, या अनुसूचित बंदरगाह यात्राएं।
- 3,000-कार्मिक कैप की व्याख्या: पाठ में 3,000 सैन्य कर्मियों की ऊपरी सीमा शामिल है। यह आंकड़ा अस्थायी संयुक्त अभ्यास के दौरान बड़ी टुकड़ियों, कई जहाजों या साथ वाले विमानों को समायोजित करने के लिए एक प्रशासनिक सीमा है - यह स्थायी सैनिकों के लिए जनादेश नहीं है।
- व्यापकरसद कवरेज: यह व्यवस्था मानक सैन्य सेवाओं तक पारस्परिक पहुंच की अनुमति देती है, जिनमें शामिल हैं:

- भोजन, ताजा पानी, और पारगमन कर्मियों के लिए बिलेटिंग (आवास)।
- पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक (पीओएल), और परिवहन सेवाएं।
- चिकित्सा सहायता, भंडारण सुविधाएं और बंदरगाह मरम्मत कार्य।
- स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति, रखरखाव अंशांकन और घटक पहुंच।
- सख्त गैर-आधार खंड: समझौता स्पष्ट रूप से सैनिकों, संपत्तियों की स्थायी या दीर्घकालिक तैनाती या किसी भी देश के क्षेत्र में विदेशी सैन्य ठिकानों की स्थापना के लिए किसी भी प्रावधान पर रोक लगाता है।
- अवधि: समझौते में पांच साल की प्रारंभिक वैधता अवधि है, जिससे दोनों पक्षों को भू-राजनीतिक जरूरतों के विकसित होने पर शर्तों की समीक्षा और संशोधन करने की अनुमति मिलती है।

कादियान-ब्यास रेलवे लाइन परियोजना

संदर्भ:

भारत सरकार ने लगभग एक सदी की देरी के बाद पंजाब के माझा क्षेत्र में लंबे समय से लंबित कादियान-ब्यास नई रेलवे लाइन परियोजना को आधिकारिक तौर पर पुनर्जीवित कर दिया है।

कादियान-ब्यास रेलवे लाइन परियोजना

कादियान-ब्यास रेलवे लाइन परियोजना के बारे में:

यह क्या है?

- कादियान-ब्यास नई रेलवे लाइन परियोजना एक अत्यधिक रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना पुनरुद्धार है। यह भारत सरकार के सामाजिक रूप से वांछनीय रेल कनेक्टिविटी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य उत्तरी ट्रेन संचालन के लिए एक वैकल्पिक आपातकालीन लाइन के रूप में कार्य करते हुए ऐतिहासिक रूप से डिस्कनेक्ट किए गए शहरों को राष्ट्रीय ब्रॉड-गेज नेटवर्क पर लाना है।

स्थान:

- राज्य और बेल्ट: यह परियोजना पूरी तरह से पंजाब, भारत के माझा क्षेत्र के भीतर स्थित है।
- कनेक्टिंग नोड्स: कॉरिडोर कादियान (गुरदासपुर जिले में स्थित) को ब्यास (अमृतसर जिले में स्थित) से जोड़ता है।
- मार्ग पुनर्संरक्षण: ट्रेन ट्रैक सीधे प्रमुख ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों, विशेष रूप से कादियान, धापाई, घुमन, बुटाला, सथियाला और ब्यास के अनुक्रम से होकर गुजरेंगे।

इतिहास और प्रशासनिक विकास:

- ब्रिटिश औपनिवेशिक युग उत्पत्ति: रेल लिंक की उत्पत्ति 1928-29 के वित्तीय वर्ष के अंत में हुई थी, जब इसे औपचारिक रूप से ब्रिटिश द्वारा संचालित उत्तर-पश्चिमी रेलवे द्वारा स्वीकृत किया गया था।
- अंतर-युद्ध बंद करना: जबकि 1930 के दशक की शुरुआत तक भौतिक निर्माण काफी हद तक आगे बढ़ा, भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं और बजट पुनर्गठन में बदलाव ने औपनिवेशिक प्रशासन को लाइन को छोड़ने के लिए प्रेरित किया।
- आधुनिक पुनर्समावेशन: इसके सामाजिक आर्थिक मूल्य को पहचानते हुए, परियोजना को निष्क्रियता से बाहर निकाला गया और अनुपूरक रेल बजट 2010-11 में एकीकृत किया गया।
- अंतिम पुनरुद्धार: दशकों के भूमि अधिग्रहण विवादों और प्रक्रियात्मक बाधाओं को पार करने के बाद, जून 2026 में उत्तर रेलवे द्वारा प्रबंधित एक अद्यतन निर्माण रोडमैप के साथ परियोजना को आधिकारिक तौर पर तेज किया गया था।

प्रमुख तकनीकी और बुनियादी ढांचा विशेषताएं:

- कॉरिडोर स्केल और प्रकार: लाइन में 39.68 किलोमीटर का ब्रॉड-गेज लेआउट है जिसे आधुनिक वजन-असर और उच्च गति सुरक्षा मापदंडों के लिए बनाया गया है।
- वित्तीय पूंजी परिव्यय: लगभग ₹1,400 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ वित्तपोषित किया गया।
- नए क्रॉसिंग स्टेशन: दोहरी दिशा वाले यातायात के प्रबंधन के लिए घुमन और बुटाला में निर्मित दो उन्नत क्रॉसिंग स्टेशनों का विकास शामिल है।
- पुल और अंडरपास: सिविल इंजीनियरिंग योजना में स्थानीय जल वैनलों और सड़कों पर सुचारु रूप से क्रॉसिंग सुनिश्चित करने के लिए 11 प्रमुख पुल, 121 छोटे पुल और 54 रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) शामिल हैं।
- स्वदेशी सुरक्षा तैनाती: पटरियों और ट्रेनों को उन्नत डिजिटल सिग्नलिंग और दूरसंचार नेटवर्क के साथ-साथ भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच से पूरी तरह से सुसज्जित किया जाएगा।



8

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रिटर्न रेगुलेशन

संदर्भ:

यूरोपीय संसद ने रिटर्न रेगुलेशन पारित किया है, जो एक नया प्रवासन विरोधी कानून है जो यूरोपीय संघ (ईयू) देशों को गैर-यूरोपीय संघ के देशों में अपतटीय निर्वासन केंद्र स्थापित करने या वापसी केंद्र स्थापित करने की अनुमति देता है।

रिटर्न विनियमन

रिटर्न विनियमन के बारे में:

यह क्या है?

- रिटर्न रेगुलेशन एक प्रमुख, कानूनी रूप से बाध्यकारी यूरोपीय संघ ढांचा है जो अनियमित प्रवासियों को तेजी से हटाने और अपतटीय हिरासत को मानकीकृत करता है, जिनके पास यूरोपीय संघ में प्रवेश करने या रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- अधिनियमित: यूरोपीय आयोग द्वारा और यूरोपीय संघ के सांसदों द्वारा अंतिम रूप दिया गया।
- उद्देश्य: कानून का उद्देश्य वापसी प्रक्रिया में तेजी लाना, उन व्यक्तियों के लिए निर्वासन की दक्षता में वृद्धि करना है जिनके पास रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की विश्वसनीयता को मजबूत करना है।

कानून की मुख्य विशेषताएं:

- तृतीय-पक्ष 'रिटर्न हब' की स्थापना: अलग-अलग यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को अपतटीय निर्वासन केंद्र स्थापित करने के लिए गैर-यूरोपीय संघ के देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते बनाने की अनुमति देता है। इन तीसरे पक्ष के देशों को मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और गैर-रिफ्यूलमेंट के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए।
- लक्ष्य जनसांख्यिकी और छूट: हब शरण चाहने वालों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया है, लेकिन जिनकी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती है या जिनके गृह देश उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अकेले नाबालिगों को सख्ती से छूट दी गई है; हालांकि, इस श्रेणी में आने वाले बच्चों वाले परिवारों को कानूनी रूप से निर्वासित किया जा सकता है।
- विस्तारित निरोध विवरणियां: वापसी की प्रतीक्षा कर रहे अनियमित प्रवासियों के लिए अधिकतम कानूनी हिरासत अवधि छह महीने से बढ़ाकर दो साल कर दी गई है। इसके अलावा, सुरक्षा जोखिम समझे जाने वाले व्यक्तियों को असीमित हिरासत का सामना करना पड़ सकता है।
- विस्तारित घरेलू खोज शक्तियां: अधिकारियों को निर्वासन आदेशों से बचने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए अनिर्दिष्ट आप्रवासियों के आवासों या संबंधित परिसरों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- सख्त दंडात्मक प्रतिबंध: अनियमित प्रवासियों के खिलाफ सख्त प्रवेश प्रतिबंध, वित्तीय जुर्माना और आपराधिक प्रतिबंध लागू करता है जो वापसी प्रक्रियाओं में सहयोग करने में विफल रहते हैं।
- 2024 प्रवासन संधि के साथ एकीकरण: प्रवासन और शरण पर यूरोपीय संघ समझौते के साथ काम करता है, जो सभी सदस्य राज्यों में सीमा स्क्रिनिंग और एक एकीकृत प्रवासन डेटाबेस को अनिवार्य करता है।

भारत पर निहितार्थ:

- शरण से इनकार किए गए या वैध दस्तावेजों की कमी वाले भारतीय प्रवासियों को तेजी से निर्वासन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब पहचान सत्यापन में देरी हो रही हो।
- निर्वासित व्यक्तियों को बहु-वर्षीय प्रवेश प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे यूरोपीय संघ में कानूनी यात्रा, शिक्षा या रोजगार के भविष्य के अवसर सीमित हो सकते हैं।
- यूरोपीय संघ भारत के साथ मजबूत पुनः प्रवेश व्यवस्था की मांग कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यूरोप छोड़ने का आदेश दिया गया भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी हो।

ऑपरेशन अमिस्ताद

संदर्भ:

हाल ही में वेनेजुएला में आए विनाशकारी बैक-टू-बैक भूकंपों के जवाब में, भारत ने आधिकारिक तौर पर एक आपातकालीन मानवीय मिशन के रूप में 'ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया है।





ऑपरेशन अमिस्ताद

ऑपरेशन अमिस्ताद के बारे में:

यह क्या है?

- ऑपरेशन अमिस्ताद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक फास्ट-ट्रैक, उच्च क्षमता वाला मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मिशन है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से निपटने वाले एक विदेशी राष्ट्र की सहायता के लिए भेजी गई आपातकालीन राहत परिसंपत्तियों की एक प्रमुख रणनीतिक और राजनयिक तैनाती का प्रतिनिधित्व करता है।

शामिल राष्ट्र:

- दाता राष्ट्र: भारत गणराज्य (विदेश मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र बलों के माध्यम से भेजा गया)।
- प्राप्तकर्ता राष्ट्र: वेनेजुएला गणराज्य।
- उद्देश्य: मिशन स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और मानवीय राहत का समर्थन करता है।

मिशन की मुख्य विशेषताएं:

- स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट फ्रेमवर्क: दो भारी-भरकम भारतीय वायु सेना (आईएएफ) सी-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक परिवहन विमान द्वारा संचालित तेजी से अंतरमहाद्वीपीय वितरण सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया।
- विशिष्ट कार्य बल: इसमें 41 सदस्यीय विशेषज्ञ बचाव दल शामिल हैं जिसमें अनुभवी खोज और बचाव कर्मी, आपदा प्रतिक्रिया विशेषज्ञ और उच्च प्रशिक्षित सैन्य चिकित्सा पेशेवर शामिल हैं।
- भारीमानवीय कार्गो: आपातकालीन आश्रयों, कंबल और आवश्यक उत्तरजीविता गियर युक्त समर्पित एचएडीआर पैलेट के साथ 30 टन राहत आपूर्ति ले जाता है।
- लक्षित चिकित्सा आपूर्ति: गंभीर क्रश चोटों, फ्रैक्चर और थर्मल आघात को संभालने के लिए तैयार की गई 6 टन लक्षित दवाएं और विशेष चिकित्सा उपकरण भेजता है।
- आर्मी फ़िल्ड अस्पताल तैनाती: जटिल आपातकालीन सर्जरी को संभालने और स्थानीय ट्राइएज ब्रिड स्थापित करने के लिए सुसज्जित एक आत्मनिर्भर भारतीय सेना फ़िल्ड अस्पताल इकाई तैनात की गई है।
- भीष्म क्यूब टेक्नोलॉजी: इसमें दो भीष्म (सहयोग हिता और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) क्यूब्स शामिल हैं। ये अत्याधुनिक, मॉड्यूलर और पूरी तरह से पोर्टेबल फ़िल्ड अस्पताल हैं, जिन्हें मौजूदा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना आपदा क्षेत्रों में उन्नत ट्रॉमा देखभाल प्रदान करने के लिए मिनटों में स्थापित किया जा सकता है।

महत्व:

- ऑपरेशन अमिस्ताद अंतरराष्ट्रीय आपदाओं के दौरान समय पर मानवीय सहायता प्रदान करने वाले वैश्विक प्रथम उत्तरदाता के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- भीष्म पोर्टेबल अस्पतालों की तैनाती तेजी से आपदा राहत और आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत की उन्नत, आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीक को प्रदर्शित करती है।

हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का एक महासागर

संदर्भ:

सेशेल्स की अपनी आधिकारिक तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान, भारत के प्रधान मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) को अवसर के महासागर में बदलने के लिए एक परिवर्तनकारी द्विपक्षीय रोडमैप का सह-शुभारंभ किया।

हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का एक महासागर

हिंद महासागर क्षेत्र में अवसर के महासागर के बारे में:

यह क्या है?

- अवसर का महासागर हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में समावेशी समुद्री विकास के लिए एक रणनीतिक ढांचा है। यह समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी और जलवायु लचीलापन को एकीकृत करते हुए आपसी सम्मान के आधार पर साझेदारी को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से सेशेल्स, मॉरीशस, मालदीव और श्रीलंका जैसे एसआईडीएस के बीच।



हिंद महासागर क्षेत्र पर मुख्य डेटा और सांख्यिकी:

- सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ़ ऋण: भारत ने आधिकारिक तौर पर सेशेल्स में प्राथमिकता वाली बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए ₹1,250 करोड़ की एक विशाल, रुपया-मूल्यवर्ग की ऋण सहायता प्रदान की।
- महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियां सौंपना: द्विपक्षीय रक्षा पेलोड में सेशेल्स रक्षा बल को एक उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 उपयोगिता वाहन और 5 लेजर रेडियल क्लास सामरिक नौकाएं उपहार में दी गईं।
- प्रत्यक्षमानवीय सब्सिडी: द्वीप को पश्चिम एशिया संकट से जुड़े आपूर्ति श्रृंखला के झटके से बचाने के लिए, भारत ने 8,500 मीट्रिक टन संरचनात्मक सीमेंट और 500 मीट्रिक टन मुख्य चावल का निर्यात किया।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं का विस्तार: चिकित्सा पैकेज में स्थानीय तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष भारतीय पैरामेडिक्स की एक टीम के साथ 6 आधुनिक एम्बुलेंस का पहला बैच वितरित करना शामिल था।

अवसरों के सागर के रूप में हिंद महासागर:

- क्षेत्रीय समुद्री साझेदारी का लोकतंत्रीकरण: रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि अंतराष्ट्रीय सहयोग सरासर आर्थिक या सैन्य आकार के बजाय संप्रभु समानता और संस्थागत विश्वास द्वारा तय किया जाता है।
- भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसररचना (DPI) का निर्यात: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) नेटवर्क शुरू करने के लिए ऐतिहासिक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) समझौते पर हस्ताक्षर करके, यह दृष्टिकोण सीमा पार खुदरा व्यापार को अत्यधिक सुलभ बनाता है।
- गतिशील बहु-क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण: संयुक्त SESEL (एन्हांसड लिंकेज के माध्यम से स्थिरता, आर्थिक विकास और सुरक्षा) ब्लूप्रिंट स्वास्थ्य सेवा, वाणिज्यिक अंतरिक्ष अवलोकन और टिकाऊ कृषि में नए, भविष्य के लिए तैयार व्यावसायिक मार्ग खोलता है।
- जमीनी स्तर परहरित ऊर्जा केंद्रों की प्रतिकृति: यह ढांचा विकेन्द्रीकृत व्यावसायिक केंद्रों की स्थापना करके क्षेत्रीय क्षमता का निर्माण करता है, जैसे कि हाल ही में शुरू किया गया सेशेल्स व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा केंद्र।
- नीली अर्थव्यवस्था की पहुंच का विस्तार: यह मंच संयुक्त समुद्री विज्ञान अन्वेषण को सक्षम बनाता है, जिससे सदस्य देशों को स्थानीय पारिस्थितिक आधार रेखाओं का सम्मान करते हुए पानी के नीचे के संसाधनों का सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति मिलती है।

IOR से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- असममित अंतरराष्ट्रीय अपराध का उदय: सुरक्षा एजेंसियां समुद्री डकैती, स्थानीय आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी से बढ़ते क्षेत्रीय खतरों से लगातार जूझ रही हैं।
- अनियमित और अवैध मछली पकड़ने की प्रथाएं (IUU): विदेशी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर नियमित रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) का उल्लंघन करते हैं, नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करते हैं और स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका को खतरे में डालते हैं।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर संवेदनशीलता: छोटे द्वीप राष्ट्र समुद्र के बढ़ते स्तर और चरम मौसम विसंगतियों का सामना करते हैं, जिससे संरचनात्मक अनुकूलन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पैदा होती है।
- भू-राजनीतिक चोकपॉइंट निर्भरता: पूरा क्षेत्र समुद्री व्यापार द्वारों पर व्यवधानों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है, जहां एकल स्थानीय गर्म युद्ध रसद लागत और बीमा प्रीमियम को बढ़ाते हैं।

- रणनीतिक बुनियादी ढांचे की प्रतियोगिता: गहरे पानी में दोहरे उपयोग वाली नौसैनिक संपत्तियों के निर्माण की कोशिश कर रही गैर-क्षेत्रीय शक्तियों का प्रवेश एक उत्त्व-दांव वाली प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जो प्राथमिक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की पारंपरिक भूमिका को खतरे में डालता है।

आगे की राह:

- UPI और डिजिटल कैश डिप्लॉयमेंट में तेजी लाना: पर्यटकों और व्यवसायों के लिए निर्बाध, कम लागत वाले डिजिटल रिटेल लेनदेन की अनुमति देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ़ सेशेल्स को भारतीय भुगतान रेल के साथ तेजी से एकीकृत करना।
- उन्नत एआई और साइबर सुरक्षा केंद्रों को संस्थागत बनाना: साइबर युद्ध के खिलाफ स्थानीय डिजिटल नेटवर्क की सुरक्षा के लिए विशेष, भारतीय समर्थित रक्षात्मक कमांड हब स्थापित करने के लिए सेशेल्स के औपचारिक अनुरोध को पूरा करना।
- गश्त के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) की तैनाती: खोज-और-बचाव प्रतिक्रिया बढ़ाने और विशाल आर्थिक क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए SIDS तट रक्षकों को विशेष भारतीय एयरोस्पेस संपत्ति प्रदान करना।
- सीडीआरआई के माध्यम से जलवायु अनुकूल ढांचे को बढ़ाना: जलवायु-रोधी तटीय प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों को डिजाइन करने के लिए आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए सेशेल्स का लाभ उठाना।
- सख्त समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) को लागू करना: अवैध मछली पकड़ने के बेड़े के खिलाफ कमजोर वोक्पॉइंट्स की रक्षा के लिए निरंतर संयुक्त नौसैनिक गश्त और उपग्रह डेटा साझाकरण का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

यूपीआई एकीकरण और अंतरिक्ष तकनीक समझौते जैसे अत्याधुनिक अपग्रेड के साथ वित्तीय सहायता में ₹1,250 करोड़ का मिलान करके, भारत ने ग्लोबल साउथ की जरूरतों के साथ अपने महासागर सिद्धांत को सफलतापूर्वक संरेखित किया है। आगे बढ़ते हुए, विशेष एआई साइबर केंद्रों को क्रियान्वित करना और गश्ती परिसंपत्तियों को बढ़ाना इन महत्वपूर्ण व्यापार गलियारों की रक्षा और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध समुद्री क्षितिज को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।

भूल जाने का अधिकार

संदर्भ:

एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में 'भूल जाने के अधिकार' को मान्यता दी।

भूल जाने का अधिकार

भूल जाने के अधिकार के बारे में:

यह क्या है?

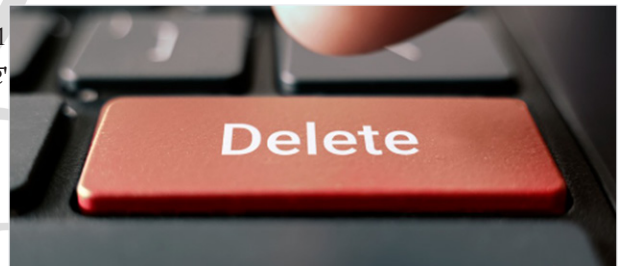
- भूल जाने का अधिकार किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि पिछले आपराधिक रिकॉर्ड या निजी विवाद, को विशिष्ट परिस्थितियों में इंटरनेट खोजों और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों से हटा दे।
- यह सूचनात्मक आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित है, जो लोगों को पिछली घटनाओं से आगे बढ़ने की अनुमति देता है जो अब प्रासंगिक नहीं हैं या जहां जानकारी जानने में सार्वजनिक हित व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा के अधिकार से अधिक है।

इतिहास और विकास:

- यूरोपीय जड़ें: इस अवधारणा को 2014 के यूरोपीय न्यायालय के फैसले (Google Spain बनाम AEPD) के बाद वैश्विक प्रमुखता मिली, जिसने स्थापित किया कि खोज इंजनों को व्यक्तिगत डेटा के लिंक को हटाना होगा जो अपर्याप्त, अप्रासंगिक या अत्यधिक हैं। इसे अब यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) में संविधानबद्ध किया गया है।
- भारतीय संदर्भ: संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2017 के केएस पुट्टास्वामी फैसले ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, जिससे आर्टीबीएफ का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- विधायी स्थिति: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023 में व्यक्तिगत डेटा के सुधार, पूर्णता और मिटाने के प्रावधान शामिल हैं, जो भारत में इस अधिकार के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला:

- न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने जनता के जानने के अधिकार के साथ निजी गरिमा को संतुलित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया:
- डी-इंडेक्सिंग जनादेश: प्लेटफॉर्म को विशिष्ट मामलों के लिए नाम-आधारित खोज कार्यक्षमता को अक्षम करना होगा। इसका मतलब है कि निर्णय ऑनलाइन रहता है, लेकिन व्यक्ति का नाम खोजकर इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।
- राहत का दायरा: सुरक्षा मुख्य रूप से इन तक बढ़ाई गई है:
- आपराधिक आरोपों से बरी किए गए व्यक्ति।
- वैवाहिक या निजी नागरिक विवादों में शामिल पक्ष।



- ऐसे व्यक्ति जिनके नाम मामले में पक्षकार नहीं होने के बावजूद रिकॉर्ड में संयोग से दिखाई देते हैं।
- मारिकिंग प्रोटोकॉल: अदालत ने आदेश दिया कि व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं (नाम, पते) को नकाबपोश/संशोधित किया जाए, जबकि न्यायिक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कानूनी तर्क और निर्णय के निष्कर्ष सार्वजनिक रहते हैं।
- मध्यस्थ जिम्मेदारी: अदालत ने स्पष्ट किया कि खोज इंजन स्वचालित एल्गोरिदम के माध्यम से काम करते हैं और किसी व्यक्ति के सूचनात्मक गोपनीयता के मौलिक अधिकार को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। आईटी नियम 2021 के तहत, वे ऐसे निष्कासन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

महत्व:

- यह डिजिटल कलंक को रोकता है, जहां व्यक्तियों को अदालतों द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी पिछले कानूनी मुद्दों के कारण आजीवन पेशेवर या सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है।
- सतारुद्ध स्वीकार करता है कि एक डिजिटल युग में जहां रिकॉर्ड लगभग अमिट हैं, पिछले डेटा को किसी व्यक्ति के भविष्य को परेशान करने से रोकने के लिए कानून विकसित होना चाहिए।
- पूर्ण विलोपन के बजाय मारिकिंग की वकालत करके, अदालत यह सुनिश्चित करती है कि कानून अनुसंधान और मिसाल के लिए सुलभ बना रहे, लेकिन व्यक्तिगत उत्पीड़न के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS)

संदर्भ:

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) के तहत सेवारत 53 महिलाओं सहित कम से कम 565 भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक सम्मान से सम्मानित किया गया।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) के बारे में:

यह क्या है?

- UNMISS संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैनात एक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय शांति अभियान है। यह सैन्य कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और नागरिक विशेषज्ञों का उपयोग करता है - जिन्हें सामूहिक रूप से ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है - अपनी स्वतंत्रता के बाद दक्षिण सूडान में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
- मिशन को आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई, 2011 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1996 के तहत स्थापित किया गया था, जो दक्षिण सूडान गणराज्य के ऐतिहासिक जन्म के साथ मेल खाता था।
- उद्देश्य: UNMISS का उद्देश्य दीर्घकालिक शांति समेकन सुनिश्चित करना, व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मजबूत राजनीतिक, न्यायिक और सुरक्षा ढांचे के निर्माण में राष्ट्रीय सरकार की सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- नागरिक सुरक्षा जनादेश: मुख्य परिचालन प्रोटोकॉल ब्लू हेलमेट को सक्रिय रूप से हिंसा को रोकने और आक्रामक सामरिक गश्त और प्रारंभिक चेतावनी निगरानी प्रणालियों के माध्यम से स्थानीय आबादी की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- बड़े पैमाने पर: यह दुनिया के सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से एक है। भारत विश्व स्तर पर इस ढांचे में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता है (नेपाल के ठीक पीछे रैंकिंग), अस्थिर क्षेत्रीय क्षेत्रों में 4,200 से अधिक वर्दीधारी कर्मियों की निरंतर तैनाती बनाए रखता है।
- जमीनी स्तर पर नागरिक-सैन्य कार्रवाई: शुद्ध सुरक्षा अभियानों से परे, मिशन महत्वपूर्ण सामुदायिक पहल चलाता है। 2026 के भारतीय दल को विशेष रूप से विशेष पशु चिकित्सा शिविरों के प्रबंधन, मानवीय आपूर्ति मार्गों के निर्माण और महिलाओं की आत्मरक्षा और लिंग-विरोधी हिंसा कार्यक्रमों के संचालन के लिए उद्घृत किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मंडल ऑफ ऑनर के बारे में:

यह क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र पदक एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य अलंकरण है जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा वर्दीधारी कर्मियों (सेना और पुलिस) को प्रदान किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य वैश्विक शांति मिशन के तहत परिचालन सेवा की एक निर्दिष्ट अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

- पात्रता सीमा: पदक के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक शांतिरक्षक को निरंतर सेवा की एक अनिवार्य आधारभूत अवधि को पूरा करना होगा - आमतौर पर 90 दिन - एक सक्रिय संयुक्त राष्ट्र फ़िल्ड मिशन से जुड़ा होता है।
- विशिष्ट आइकनोग्राफी: पदक में एक कांस्य पदक होता है जो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मानचित्र प्रतीक को दर्शाता है, जिसके शीर्ष पर



संक्षिप्त नाम संयुक्त राष्ट्र है। इसे एक कपड़े के रिबन से निलंबित कर दिया जाता है जिसकी रंग योजना विशिष्ट मिशन के अनुसार भिन्न होती है (उदाहरण के लिए, दक्षिण सूडान के भौगोलिक रंगों से मेल खाती है)।

भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी

संदर्भ:

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने औपचारिक रूप से नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO) लॉन्च की।

भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी

भारत-यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के बारे में:

यह क्या है?

- क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (GSCO) एक विशेष, प्रौद्योगिकी-समर्थित द्विपक्षीय खुफिया मंच है।
- अक्टूबर 2025 में भारत-ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय भागीदारी के दौरान कल्पना की गई और मार्च 2026 में एक अनुसंधान सहयोग समझौते के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया, यह भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) और व्यापक भारत-यूके प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के व्यापक लक्ष्यों के तहत संचालित होता है।
- सदस्य राष्ट्र: भारत और यूनाइटेड किंगडम।



उद्देश्य:

- वेधशाला का अंतिम उद्देश्य आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं, उन्नत विनिर्माण ढांचे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक रणनीतिक संसाधनों तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करना है।
- वास्तविक समय में खनिजों पर नज़र रखकर, प्लेटफॉर्म दोनों लोकतंत्रों को बाजार एकाधिकार, भू-राजनीतिक आपूर्ति झटके और महत्वपूर्ण संसाधन की कमी से बचाने के लिए एक स्वचालित तंत्र के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- वास्तविक समय आपूर्ति श्रृंखला निगरानी: वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं की लगातार निगरानी करने के लिए डेटा-संचालित ट्रैकिंग आर्किटेक्चर को नियोजित करता है, जिससे विश्लेषकों को निष्कर्षण स्थलों से अंतिम औद्योगिक समापन बिंदुओं तक कच्चे माल का पता लगाने की अनुमति मिलती है।
- स्वचालित व्यवधान और जोखिम का पता लगाना: उभरते आपूर्ति-श्रृंखला जोखिमों, अचानक लॉजिस्टिक चोक पॉइंट्स, अप्रत्याशित निर्यात नियंत्रण और बाजार की बाधाओं की तुरंत पहचान करने के लिए पूर्वानुमानित मॉडलिंग का उपयोग करता है।
- उन्नतबाजार खुफिया जनरेशन: वाणिज्यिक हितधारकों की सहायता के लिए मूल्य निर्धारण पैटर्न, वैश्विक भंडार संतुलन और औद्योगिक खपत प्रक्षेपवक्र पर उत्तम-निष्ठा आर्थिक खुफिया प्रोफाइल बनाता है।
- साक्ष्य-आधारित नीति एंकरिंग: कच्चे विश्लेषणात्मक डेटा को सीधे सार्वजनिक नीति के बुनियादी ढांचे से जोड़ता है, व्यापार समझौतों और रणनीतिक भंडारण पर सूचित, सक्रिय निर्णय लेने में सरकारों का समर्थन करता है।
- क्रॉस-बॉर्डर रिसर्च इंटरऑपरेबिलिटी: भारत और यूके के संस्थानों के बीच साझा अनुसंधान पाइपलाइनों, खनिज डेटा-पूटिंग और एल्गोरिथम सत्यापन को सक्षम करके विश्व स्तरीय शैक्षणिक विशेषज्ञता को जोड़ता है।
- समावेशी हितधारक इकोसिस्टम: खान मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ब्रिटिश उच्चायोग, उद्योग जगत के नेताओं और अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के एक विस्तृत नेटवर्क को चल रहे सहयोगात्मक संवाद में एकीकृत करता है।

मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड

UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में:

यह क्या है?

- यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान है जो महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1325 (UNSCR 1325) के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और लागू करने में एक व्यक्तिगत सैन्य शांति रक्षक के समर्पण और अग्रिम प्रयासों को मान्यता देता है।
- में स्थापित: वार्षिक पुरस्कार 2016 में संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन विभाग (डीपीओ) के भीतर सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा बनाया गया था।



उद्देश्य:

- पुरस्कार का उद्देश्य सैन्य कर्मियों को प्रोत्साहित करना और सम्मानित करना है जो क्षेत्र-स्तरीय शांति गतिविधियों में तैनात गतिशीलता और दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक एकीकृत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय महिलाओं और लड़कियों की अद्वितीय सुरक्षा, सुरक्षा और मानवीय जरूरतों को पूरा किया जाए।

पुरस्कार की मुख्य विशेषताएं:

- कठोर चयन पूल: पुरस्कार विजेताओं को दुनिया भर में सभी सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से फोर्स कमांडरों और मिशन के प्रमुखों द्वारा सीधे नामित उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पूल में से चुना जाता है।
- समावेशिता पर ध्यान दें: मूल्यांकन व्यावहारिक क्षेत्र नवाचारों पर भारी जोर देता है, जैसे कि मिश्रित-लिंग गश्त शुरू करना, स्थानीय लिंग-जवाबदेही प्रशिक्षण आयोजित करना और स्थानीय महिला समूहों के साथ विश्वसनीय नेटवर्क का निर्माण करना।
- वकालत के लिए मंच: पुरस्कार जीतना प्राप्तकर्ता को अपने क्षेत्र के तरीकों को साझा करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के सभी सैन्य घटकों में मुख्यधारा के लिंग-संवेदनशील रणनीतिक योजना में मदद मिलती है।

अब तक के भारतीय विजेता

सालों	पुरस्कार विजेता	मिशन
2019	मेजर सुमन गवानी	दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS)
2023	मेजर राधिका सेन	डीआर कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन (MONUSCO)
2025/26	मेजर अभिलाषा बराक	लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL)

मेजर अभिलाषा बराक के बारे में:**वह कौन है और उसका कार्य?**

- मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जो वर्तमान में मध्य पूर्व में इयूटी के अंतरराष्ट्रीय दौरे पर तैनात हैं।
- वह लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के भीतर काम करती हैं, जो एक अत्यधिक अस्थिर परिचालन क्षेत्र है जिसे लेबनान और इज़राइल के बीच ब्लू लाइन के साथ स्थिरता बनाए रखने का काम सौंपा गया है।

उनका कार्य और योगदान:

- सगाई टीम कमांडर: वह सामरिक सगाई टीमों के लिए परिचालन कमांडर के रूप में कार्य करती हैं, महत्वपूर्ण नागरिक सुरक्षा डेटा इकट्ठा करने के लिए जमीनी स्तर पर सामुदायिक बातचीत का नेतृत्व करती हैं।
- लिंग केंद्र बिंदु: एक लिंग केंद्र बिंदु के रूप में अपनी क्षमता में, मेजर बराक संयुक्त राष्ट्र सैन्य कमान और स्थानीय लेबनानी महिला संगठनों के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। उनका काम लिंग-आधारित कमजोरियों को दूर करने, मानवीय संसाधन वितरण में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामुदायिक सुरक्षा ढांचे महिलाओं और बच्चों के लिए समावेशी और उत्तरदायी हैं।

भारत-नेपाल सीमा मुद्दा**संदर्भ:**

नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री, बालेंद्र शाह बालेन ने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा सीमा विवादों को हल करने के लिए एक तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का आह्वान करके राजनयिक प्रवचन को मौलिक रूप से बदल दिया है।

भारत-नेपाल सीमा मुद्दा**भारत-नेपाल सीमा मुद्दे के बारे में:****यह क्या है?**

- सीमा विवाद मुख्य रूप से 372 वर्ग किलोमीटर के रणनीतिक ट्राई-जंक्शन क्षेत्र पर केंद्रित है, जिसमें नेपाल के उत्तर-पश्चिमी सिरे और उत्तराखंड की उत्तरी सीमा पर स्थित कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा शामिल हैं।
- यह क्षेत्र अत्यधिक रणनीतिक और सैन्य महत्व रखता है क्योंकि यह लिपुलेख दर्रे को देखता है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है और तिब्बत के लिए धार्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक प्राथमिक गलियारा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: विवाद की जड़:

- सुगौली की संधि (1816): एंग्लो-नेपाली युद्ध के बाद नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित, इस संधि ने काली नदी को नेपाल की निश्चित पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया।



- स्रोत मानचित्रण संघर्ष: संधि में वैज्ञानिक रूप से सर्वेक्षण किए गए समन्वय मानचित्र शामिल नहीं थे या काली नदी के सटीक भौगोलिक स्रोत को परिभाषित नहीं किया गया था।

प्रतिस्पर्धी व्याख्याएँ:

- नेपाल की स्थिति: काठमांडू का तर्क है कि नदी तिंपियाधुरा में सबसे पश्चिमी धारा से निकलती है, जिसका अर्थ है कि कालापानी और लिपुलेख इसके क्षेत्र में आते हैं। इसे मजबूत करने के लिए, नेपाल ने पहले अपने करेंसी नोटों पर इस विस्तारित मानचित्र को मुद्रित किया था।
- भारत की स्थिति: नई दिल्ली का कहना है कि नदी कालापानी के पास एक रिज लाइन से शुरू होती है, जो 1847 के बाद ब्रिटिश भारत द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों से मेल खाती है। भारत ने महत्वपूर्ण सुरक्षा हितों के कारण 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से इस यथास्थिति क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रबंधन किया है और उसके पास है।
- हाल ही में भड़कने के बाद तनाव बढ़ गया जब नेपाल ने औपचारिक रूप से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत-चीन व्यापार को फिर से शुरू करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत के सड़क लिंक के निर्माण पर आपत्ति जताई। भारत ने काठमांडू की आपत्तियों को स्वारिज करते हुए कहा कि यह क्षेत्र का अनुचित कृत्रिम विस्तार है।

काठमांडू में बदलता राजनीतिक स्वर:

- जेन-जेड और युवा-नेतृत्व वाले शासन का उदय: आरएसपी और बालेंद्र शाह जैसे नेताओं का उदय नौकरियों, विकास और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों पर केंद्रित पारदर्शी, प्रदर्शन-उन्मुख शासन की बढ़ती युवा मांग को दर्शाता है।
- विशेष संबंध प्रोटोकॉल को दरकिनारा करना: नेपाल का नया नेतृत्व पारंपरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषाधिकारों पर भरोसा करने के बजाय भारत को एक समान संप्रभु भागीदार के रूप में मानते हुए नियम-आधारित राजनयिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है।
- अतिक्रमण पर एक व्यावहारिक रुख: प्रधान मंत्री शाह ने सीमा मुद्दों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर जोर दिया है, यह सुझाव देते हुए कि विवादों को राष्ट्रवादी बयानबाजी के बजाय तथ्यों, संवाद और आपसी विश्वास के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।
- सक्रिय तृतीय-पक्ष प्लूताल: नेपाल ने अधिक स्पष्टता के लिए चीन और ब्रिटेन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जांच करने का प्रस्ताव दिया है, हालांकि चीन द्विपक्षीय भारत-नेपाल समाधान प्रक्रिया का समर्थन करना जारी रखता है।

भारत-नेपाल संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ:

- विरोधाभासी ऐतिहासिक अभिलेखागार: विशुद्ध रूप से ब्रिटिश युग के मानचित्रों पर भरोसा करना अक्सर भ्रम पैदा करता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश भारत प्रशासन ने समय के साथ विभिन्न तकनीकों के साथ अपने कार्टोग्राफिक सर्वेक्षणों को अपडेट किया।
- यथास्थिति में गहरी सुरक्षा दांव: ट्राई-जंक्शन क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में भारत के गंभीर रणनीतिक सुरक्षा हित हैं, जिससे चीन सीमा पर अपनी रक्षात्मक रखाओं को बदलने की संभावना बहुत कम है।
- राष्ट्रवाद का घरेलू राजनीतिक शोषण: नेपाल में पारंपरिक राजनीतिक दल स्थानीय राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए घरेलू संकट के दौरान अक्सर भारत विरोधी सीमा भावना का फायदा उठाते हैं।
- अंतहीन विशेषज्ञ-स्तरीय देरी का जोखिम: अंतहीन विशेषज्ञ-स्तरीय समितियों में फंसे जटिल सीमा मुद्दों को छोड़ने से मामूली विवादों को स्थायी राजनयिक अड़चन में बदलने की अनुमति मिल सकती है।

आगे की राह:

- अद्वितीय खुली सीमा परंपरा का उपयोग: दोनों देशों को अपनी खुली सीमा प्रणाली से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो 1,700 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और 1962 के संघर्ष से पहले पूरी तरह से काम करती थी।
- मजबूत संस्थागत सेना-से-सेना संबंधों का लाभ उठाना: एक व्यावहारिक सीमा समाधान पर चुपचाप बातचीत करने और समर्थन करने के लिए भारतीय और नेपाली सेनाओं के बीच गहरे, पारस्परिक रूप से भरोसेमंद संस्थागत संबंधों का उपयोग करें।
- मल्टी-मॉडल आर्थिक और ऊर्जा समझौतों को प्राथमिकता देना: सीमा पार ब्रिड, डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क और परिवहन लिंक को द्विपक्षीय वार्ता के केंद्र में रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सीमा विवाद क्षेत्रीय विकास को न रोकें।
- रचनात्मक संयुक्त सीमा प्रबंधन की ओर बढ़ना: संप्रभु दावों को बदले बिना विवादित क्षेत्रों को संभालने के लिए साझा पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र या संयुक्त सीमा प्रशासन गलियारों जैसे अभिनव मॉडल का पता लगाएं।
- प्रत्यक्ष, उच्च-स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से जुड़ना: दोनों देशों के नेताओं को कठोर नौकरशाही की आदतों से आगे बढ़ना चाहिए, कठिन नीतिगत चुनौतियों को पारदर्शी रूप से हल करने के लिए सीधे संचार चैनलों का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष:

काठमांडू में एक नए, युवाओं के नेतृत्व वाले प्रशासन का उद्भव भारत और नेपाल के बीच एक आधुनिक, प्रबुद्ध साझेदारी बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। अति-राष्ट्रवादी रुख से दूर जाकर और एक वस्तुनिष्ठ लेंस के माध्यम से सीमा प्रबंधन को देखकर, दोनों राष्ट्र अपने गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने मूल सुरक्षा हितों की रक्षा कर सकते हैं।

भारतीय चालक दल के साथ जहाजों पर अमेरिका का हमला

संदर्भ:

भारत ने ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय नाविकों द्वारा संचालित तेल टैंकरों पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) द्वारा किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है।

भारतीय चालक दल के साथ जहाजों पर अमेरिका का हमला

भारतीय चालक दल के साथ जहाजों पर अमेरिकी हमलों के बारे में:

यह क्या है?

- इन घटनाओं में अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा ईरानी ऊर्जा निर्यात के खिलाफ सख्त समुद्री नाकाबंदी करने वाली आक्रामक नौसैनिक प्रवर्तन कार्रवाई शामिल है। नाकाबंदी शुरू करने के बाद से, यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के साथ क्षेत्रीय जल को पार करने का प्रयास करने वाले गैर-अनुपालन वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया है, रोका है और उन पर गोलीबारी की है।

हमला किए गए जहाजों का अवलोकन:

- एम/टी जलवीर: गिनी-बिसाऊ ध्वज वाले एक टैंकर को ओमान की खाड़ी के माध्यम से ईरान से तेल ले जाते समय निशाना बनाया गया। चालक दल के कथित तौर पर रेडियो निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद, एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन कक्ष में सीधे दो हेलफायर मिसाइलें दागीं, जिससे जहाज निष्क्रिय हो गया। इसके 20 चालक दल के सदस्यों में से पांच को गुजरने वाले जहाजों द्वारा बचाया गया और ओमान लाया गया।
- सेटेबेलो: पलाऊ के झंडे वाले एक तेल टैंकर को अमेरिकी सेना ने ओमानी तट पर कथित तौर पर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने का प्रयास करते हुए निशाना बनाया। हमले में बड़े पैमाने पर आग लग गई, और तीन भारतीय राष्ट्रीय चालक दल के सदस्यों को मृत या लापता घोषित कर दिया गया।
- एमटी मारिवेक्स: 24 भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक तेल टैंकर में अमेरिकी नौसैनिकों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिण में आग लग गई।

संघर्ष को नियंत्रित करने वाले राजनयिक और समुद्री कानून:

- नेविगेशन की स्वतंत्रता (UNCLOS): UNCLOS तटस्थ वाणिज्यिक जहाजों को अंतरराष्ट्रीय जल और प्रमुख जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्दोष मार्ग के अधिकार की गारंटी देता है, वैध समुद्री व्यापार और नागरिक शिपिंग की रक्षा करता है।
- प्रतिबंध प्रवर्तन बनाम प्रत्यक्ष युद्ध: जबकि राज्य निरीक्षण या नाकाबंदी के माध्यम से प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं, तटस्थ नागरिक जहाजों के खिलाफ घातक बल का उपयोग करना स्थापित समुद्री कानून के तहत विंता पैदा करता है।
- राजनयिक डिमार्श प्रोटोकॉल: एक विदेशी राजनयिक को बुलाना एक औपचारिक राजनयिक विरोध है, जो शांतिपूर्ण बातचीत और विवाद समाधान के लिए चैनलों को संरक्षित करते हुए गंभीर विंता का संकेत देता है।

मुख्य निहितार्थ:

- यह घटना रणनीतिक सहयोग और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत के दायित्व के बीच तनाव पैदा करके भारत-अमेरिका संबंधों को जटिल बनाती है।
- पश्चिम एशियाई जल में बढ़ते जोखिम नाविकों को असाइनमेंट स्वीकार करने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे कार्यबल की कमी और उत्त्व शिपिंग लागत हो सकती है।
- संघर्ष से संबंधित जोखिम युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई शुल्क को बढ़ाते हैं, संभावित रूप से वैश्विक ऊर्जा परिवहन और आयात लागत को बढ़ाते हैं।

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ:

भारत और फ्रांस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीस यात्रा के दौरान 13 प्रमुख परिणामों का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, एआई, रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग को गहरा करना है।

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के बारे में:

यह क्या है?

- भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 1998 में स्थापित एक व्यापक द्विपक्षीय संबंध है, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंध शामिल हैं।



भारत-फ्रांस शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम:**भारत-फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030:**

- एआई, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, नवाचार इकोसिस्टम और शैक्षणिक गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक ढांचा अपनाया।
- वैश्विक चुनौतियों के लिए उद्योग-अकादमिक साझेदारी और संयुक्त तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देता है।

भारत-फ्रांस एआई कार्य समूह का संयुक्त

- एआई शासन के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित किया।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान सहयोग, स्टार्टअप साझेदारी, क्षमता निर्माण और नीति समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।

वैमानिकी में कौशल के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र

- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में स्थापित किया जाएगा।
- एयरोस्पेस विनिर्माण, विमानन रखरखाव और कार्यबल विकास को मजबूत करता है।

फ्रांस में UPI का विस्तार

- यूपीआई सेवाओं का विस्तार पेरिस हवाई अड्डे और नीस तक किया गया।
- भारतीय पर्यटकों, छात्रों, व्यवसायों और प्रवासी समुदायों के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा को बढ़ाता है।

स्टेशन एफ के माध्यम से स्टार्टअप सहयोग

- यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप हब स्टेशन एफ में दस अतिरिक्त भारतीय स्टार्टअप इनक्यूबेट किए जाएंगे।
- निवेशकों, सलाहकारों, बाजारों और प्रौद्योगिकी नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है।

भारत-फ्रांस डिजिटल विज्ञान केंद्र

- डीएसटी और फ्रांस के आईएनआरआई द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, प्रतिभा गतिशीलता और कौशल विकास का समर्थन करता है।
- पेरिस-सैवले विश्वविद्यालय में आईसीसीआर इंडिया की अध्यक्षता
- एआई, नवाचार और संस्कृति पर नई अकादमिक कुर्सी।
- शैक्षिक सहयोग, अनुसंधान आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करता है।

स्वास्थ्य डेटा और एआई अनुसंधान सहयोग

- आईसीएमआर और फ्रांस के हेल्थ डेटा हब के बीच साझेदारी।
- सुरक्षित स्वास्थ्य-डेटा साझाकरण, एआई-संचालित चिकित्सा अनुसंधान और डिजिटल स्वास्थ्य शासन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की व्यवस्था
- एक वार्षिक उत्त्व-स्तरीय तंत्र का निर्माण।
- पांच वर्षों के भीतर भारत-फ्रांस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य।

आर्थिक सुरक्षा वार्ता

- महत्वपूर्ण खनिजों, अर्धचालकों, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों को कवर करने वाला नया मंच।
- आर्थिक लचीलापन और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाता है।

रेलवे और हाई-स्पीड रेल सहयोग

- रेलवे आधुनिकीकरण के लिए आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बुनियादी ढांचे के विकास और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण का समर्थन करता है।

वर्गीकृत सूचना संरक्षण पर समझौता

- संवेदनशील जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- रक्षा-औद्योगिक सहयोग और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है।

उन्नत अंतरिक्ष सहयोग

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सेंटर नेशनल डीएट्यूड्स स्पेशियल्स के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- मानव अंतरिक्ष उड़ान, माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान, गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शामिल करता है।

ब्रिक्स इंदौर घोषणा**संदर्भ:**

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का समापन जून 2026 में इंदौर में आयोजित कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्रिक्स इंदौर घोषणा को अपनाने के साथ हुआ।

ब्रिक्स इंदौर घोषणा**ब्रिक्स इंदौर घोषणा के बारे में:****यह क्या है?**

- ब्रिक्स इंदौर घोषणा मध्य प्रदेश के इंदौर में 2026 कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया एक सर्वसम्मति संयुक्त कृषि चार्टर है।
- यह खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि, कृषि व्यापार, नवाचार और जलवायु लचीलापन पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक किसान-केंद्रित ढांचे के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

- ब्रिक्स देशों के बीच गहरे सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और किसान कल्याण को बढ़ावा देना।
- किसानों को नीति-निर्माण के केंद्र में रखते हुए नवाचार, डिजिटल कृषि, जलवायु-अनुकूल खेती और कृषि व्यापार को मजबूत करना।

घोषणा की मुख्य विशेषताएं:

- कृषि-पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि पर उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क:
- प्राकृतिक, जैविक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण और ज्ञान-साझाकरण के लिए एक सहयोगी मंच स्थापित करता है।
- ब्रिक्स देशों में जलवायु-अनुकूल कृषि और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क:

- एआई, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और डेटा-संचालित कृषि समाधानों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में तेजी लाना और डिजिटल नवाचार के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।

बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच:

- स्वदेशी बीजों, पारंपरिक ज्ञान और बीज संसाधनों पर किसानों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- जैव विविधता संरक्षण का समर्थन करता है और जलवायु चुनौतियों के बीच खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है।
- ब्रिक्स एग्रीएन (कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क):
- कृषि आदानों, आनुवंशिक संसाधनों, सर्वोत्तम बीज किस्मों और तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- क्षमता निर्माण को बढ़ाता है और कृषि अनुसंधान और नवाचार में सहयोग को मजबूत करता है।

महत्व:

- बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त, पौष्टिक और किफायती भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में एक समन्वित ब्रिक्स दृष्टिकोण बनाता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए पुनर्योजी खेती, टिकाऊ भूमि प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को बढ़ावा देता है।

संयुक्त क्रेडिट तंत्र (जेसीएम)

संदर्भ:

भारत और जापान की सरकारों ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त ऋण तंत्र (JCM) के लिए 'कार्यान्वयन के नियम' को अपनाया।

- यह परिचालन मील का पत्थर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत एक द्विपक्षीय कार्बन बाजार ढांचे को सक्रिय करता है।

संयुक्त क्रेडिट तंत्र (जेसीएम)

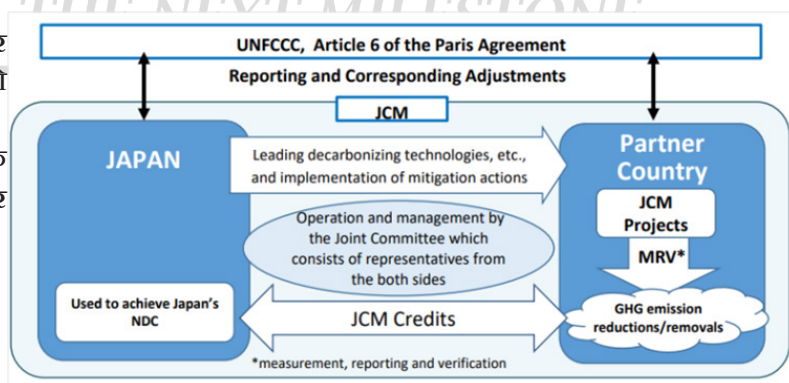
संयुक्त क्रेडिट तंत्र (JCM) के बारे में:

यह क्या है?

- संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) जापान द्वारा विभिन्न भागीदार देशों के साथ स्थापित एक औपचारिक द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट प्रणाली है।
- यह विकासशील या संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में उन्नत डीकार्बोनाइजिंग प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और श्रमण प्रणालियों को तैनात करके ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- कानूनी जनादेश: JCM को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, जो सहकारी दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित श्रमण परिणामों (ITMOs) के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

उद्देश्य:

- जेसीएम का उद्देश्य भागीदार देशों में उत्त्व-प्रदर्शन, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रसार में तेजी लाना है।



- निजी और सार्वजनिक पूंजी का लाभ उठाकर, यह तंत्र सतत विकास को बढ़ावा देते हुए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या हटाने का प्रयास करता है और दोनों सहयोगी देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्राप्त करने में मदद करता है।

यह कैसे काम करता है और प्रमुख विशेषताएं:

- निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: जापानी संस्थाएं भारत में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में सीधे निवेश करती हैं। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन बुनियादी ढांचे में अग्रणी जापानी हरित नवाचारों का उपयोग करती हैं।
- मानात्मक ऋण अधिग्रहण: किसी परियोजना द्वारा प्राप्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी या निष्कासन की गणना मानात्मक तरीके से की जाती है। परिणामी कार्बन क्रेडिट को जापान और भारत के बीच उनके जलवायु लक्ष्यों की ओर गिनने के लिए आवंटित किया जाता है।
- दोहरी समिति शासन: नए अपनाए गए नियमों के तहत, भारत और जापानी दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और पारदर्शी अनुमोदन बनाए रखने के लिए प्रणाली की देखरेख करेगी।
- सख्त सत्यापन और सत्यापन: परियोजना चक्र को स्वतंत्र, तृतीय-पक्ष सत्यापन और सत्यापन की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सर्जन में कमी वास्तविक, स्थायी और अतिरिक्त है।
- राष्ट्रीय रजिस्ट्री एकीकरण: यह तंत्र क्रेडिट को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने, जारी करने और स्थानांतरित करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों पर निर्भर करता है। यह संरचना दोहरी गिनती को रोकती है और उच्च पर्यावरणीय अखंडता बनाए रखती है।
- मल्टी-चैनल फंडिंग सहायता: परियोजनाओं को कई फंडिंग चैनलों द्वारा समर्थित किया जाता है, जिसमें जापान के पर्यावरण मंत्रालय (एमओईजे), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ट्रस्ट फंड और नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) द्वारा प्रबंधित प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से जेसीएम मॉडल परियोजनाएं शामिल हैं।

महत्व:

- जेसीएम भारत और जापान को सत्यापित कार्बन-क्रेडिट उत्पादन के माध्यम से पेरिस समझौते के उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।
- जेसीएम जापानी वित्त और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करता है, जिससे स्वच्छ-ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाएं अधिक किफायती हो जाती हैं।

यूएस पैसिफिक कमांड (USPACOM)

संदर्भ:

संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विभाग ने घोषणा की कि यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (यूएसआईएनडीओपीओसीओएम) ने आधिकारिक तौर पर यूएस पैसिफिक कमांड (यूएसपीएसीओएम) को अपना मूल नाम बहाल कर दिया है।

यूएस पैसिफिक कमांड (USPACOM)

US पैसिफिक कमांड (USPACOM) के बारे में:

यह क्या है?

- USPACOM संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के छह भौगोलिक एकीकृत लड़ाकू कमांडों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। हवाई में मुख्यालय, यह दुनिया भर में अमेरिकी अग्रेषित सैन्य उपस्थिति और रक्षा वास्तुकला की आधारशिला के रूप में खड़ा है।

स्थापना और इतिहास:

- स्थापना: कमान की स्थापना 1 जनवरी, 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी।
- नाम टाइमलाइन: यह मई 2018 तक 70 से अधिक वर्षों तक मूल USPACOM नाम के तहत संचालित हुआ, जब हिंद महासागर क्षेत्र के बढ़ते महत्व को उजागर करने के लिए इसे USINDOPACOM में बदल दिया गया।
- 16 जून, 2026 को, वर्तमान प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर अपने पारंपरिक नाम को बहाल कर दिया।
- उद्देश्य: USPACOM का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके लोगों और इसके विशाल रंगमंच में उसके संप्रभु हितों के क्षेत्र की रक्षा और रक्षा करना है।

महत्वपूर्ण कार्य:

- जिम्मेदारी का विशाल क्षेत्र (AOR): पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से को शामिल करने वाले एक विशाल भौगोलिक थिएटर में संचालित होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से भारत की पश्चिमी सीमा तक और उत्तरी ध्रुव से अंटार्कटिका तक फैला हुआ है।
- संयुक्त बल एकीकरण: प्रशांत थिएटर के भीतर तैनात अमेरिकी सेना, नौसेना, वायु सेना, मरीन कॉर्प्स और अंतरिक्ष बल की परिसंपत्तियों की लड़ाकू तत्परता को निर्देशित और सिंक्रनाइज़ करता है।



- रंगमंच सुरक्षा सहयोग: खुले समुद्री मार्गों और मुक्त व्यापार गलियारों को बनाए रखने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, रणनीतिक क्षमता-निर्माण और अंतर-संचालनीयता कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय सेनाओं के साथ लगातार साझेदारी करता है।
- मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर): अंतरराष्ट्रीय आपदा-प्रतिक्रिया नेटवर्क का नेतृत्व करता है, पूरे एशिया में विनाशकारी मौसम की घटनाओं या मानवीय संकटों के दौरान तत्काल रसद, चिकित्सा सहायता और खोज और बचाव टीमों को तैनात करता है।

निहितार्थ:

- एशिया-प्रशांत शब्दावली पर लौटना स्पष्ट रणनीतिक टकराव पर चीन के साथ राजनयिक जुड़ाव को प्राथमिकता देने का संकेत दे सकता है।
- यह कदम ववाद पर भविष्य में जोर देने और दक्षिण क्षेत्रीय रणनीति में हिंद महासागर की भूमिका के बारे में संदेह पैदा करता है।
- भारत को छोड़ने से प्रतीकात्मक रूप से एकीकृत हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचे में भारत की केंद्रीयता पर ध्यान कम हो जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 14-खंड समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक ऐतिहासिक 14-खंड समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- यह समझौता अंतिम शांति संधि के लिए 60-दिवसीय सख्त बातचीत की खिड़की स्थापित करता है, जो पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में एक गहरा मोड़ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने 14-खंड समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बारे में 14-खंड समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए:

यह क्या है?

- 2026 समझौता जापन एक विस्तृत राजनयिक ढांचा है जो 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) की संकीर्ण परमाणु सीमाओं से काफी आगे बढ़ता है।
- केवल अप्रसार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह समझौता मूल अमेरिका-ईरान राजनीतिक संबंधों को व्यापक रूप से नया आकार देने का प्रयास करता है।
- यह तेहरान को पश्चिम एशिया में अपनी पारंपरिक सैन्य और आर्थिक स्थिति के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत, पुनर्निर्माण निधि और भू-राजनीतिक स्थान प्रदान करता है।

14-खंड समझौता जापन की मुख्य विशेषताएं:

- खंड 1: शत्रुता की स्थायी समाप्ति: सभी मोर्चों पर सभी सक्रिय सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने का आदेश देता है, स्पष्ट रूप से लेबनान को व्यापक युद्धविराम वास्तुकला में एकीकृत करता है।
- खंड 2: आंतरिक मामलों में पूर्ण गैर-हस्तक्षेप: आधिकारिक तौर पर वाशिंगटन के "शासन परिवर्तन" के पिछले तर्क को हटा देता है, जो ईरान की आंतरिक राजनीतिक संप्रभुता का सम्मान करने के लिए अमेरिका को कानूनी रूप से बाध्य करता है।
- खंड 3: समरसेखा विस्तार के लिए आपसी सहमति: एक लचीला प्रशासनिक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है जो दोनों संप्रभु राज्यों को आपसी सहमति के माध्यम से 60-दिवसीय अंतरिम वार्ता अवधि का विस्तार करने की अनुमति देता है।
- खंड 4: अमेरिकी नौसेना नाकाबंदी को पूरी तरह से हटाना: ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिकी वाहक हड़ताल समूहों की भौतिक वापसी को मान्य करता है।
- खंड 5: होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से बिना शर्त पारगमन: ईरान वैश्विक वाणिज्यिक शिपिंग के लिए खुले पारगमन मार्ग की गारंटी देता है, लेकिन नेविगेशन और पर्यावरण सेवाओं के लिए भविष्य के शुल्क-संग्रह ढांचे को परिभाषित करने के लिए ओमान के साथ काम करने का अधिकार सुरक्षित करता है।
- खंड 6: \$ 300 बिलियन की ईरानी पुनर्निर्माण योजना: ईरान की युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय कोष स्थापित करता है, जिससे वैश्विक रियल एस्टेट और औद्योगिक डेवलपर्स के लिए वाणिज्यिक प्रवेश बिंदु बनते हैं।
- खंड 7: पूर्ण प्रतिबंध हटाने का मार्ग: ईरान के ऊर्जा, बैंकिंग और शिपिंग क्षेत्रों पर एकतरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को व्यवस्थित रूप से उठाने के लिए रूपरेखा स्थापित करता है, जिससे वार्षिक तेल राजस्व में अनुमानित \$ 60 बिलियन का लाभ होता है।
- खंड 8: परमाणु हथियारों की खरीद पर औपचारिक सीमा: परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए ईरान की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जबकि तेहरान को किसी तीसरे देश को स्थानांतरित किए बिना अपने अत्यधिक समृद्ध 60% यूरेनियम भंडार को बनाए रखने देता है।

- खंड 9: रणनीतिक यथास्थिति बनाए रखना: बातचीत सक्रिय होने के दौरान तनाव बढ़ने से रोकने के लिए 60 दिनों के दौरान सभी सैन्य उन्नयन और प्रगति को रोक देता है।
- खंड 10: अंतरिम प्रतिबंध छूट: मानवीय व्यापार और बैंकिंग संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल, अस्थायी प्रतिबंध राहत प्रदान करता है, जबकि खंड 7 को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- खंड 11: विदेशी संप्रभु परिसंपत्तियों को मुक्त करना: जमे हुए ईरानी होल्डिंग्स में \$ 100 बिलियन से अधिक की व्यवस्थित वापसी शुरू करता है, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में बैंकों ने तुरंत बैंक-लॉग किए गए सार्वजनिक वेतन का भुगतान करने के लिए शुरुआती \$ 12 बिलियन का भुगतान किया।
- खंड 12: संयुक्त कार्यान्वयन निगरानी तंत्र: अनुपालन की निगरानी और सद्भावना निष्पादन का प्रबंधन करने के लिए एक समर्पित, द्विपक्षीय कार्यकारी समिति का गठन करता है।
- खंड 13: पारस्परिक प्राथमिकताओं का पदानुक्रम: वार्ताकारों के लिए 60-दिवसीय अवधि में राजनीतिक, वित्तीय और तकनीकी मुद्दों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए एक संरचित, चरण-दर-चरण एजेंडा स्थापित करता है।
- खंड 14: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन: यह अनिवार्य करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी वैधता को अधिकतम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत अंतिम समझौते को एक औपचारिक UNSC प्रस्ताव में संहिताबद्ध किया जाए।

समझौता जापान के सकारात्मक परिणाम

- तत्काल वाणिज्यिक स्थिरीकरण: होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने से उत्तम जोखिम वाले समुद्री बीमा प्रीमियम को हटा दिया जाता है, जिससे एक वैश्विक व्यापार धमनी सुरक्षित होती है जो दुनिया के 20-25% तेल और 20% गैस को संभालती है।
- नागरिकों के लिए तत्काल आर्थिक राहत: कतर और संयुक्त अरब अमीरात में बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से शुरुआती 12 बिलियन डॉलर को अनफ्रीज करने से तेहरान को अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में तुरंत तरलता इंजेक्ट करने और लंबित सार्वजनिक वेतन का भुगतान करने की अनुमति मिलती है।
- क्षेत्रीय फ्लैशपाइंट का डी-एस्केलेशन: युद्ध-समाप्ति ढांचे में लेबनान का स्पष्ट एकीकरण सीमा पार बमबारी में तत्काल विराम प्रदान करता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य शांत हो जाता है।

अनुसलझे मुद्दे और रणनीतिक ब्लाइंड स्पॉट:

- बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिबंधों की चूक: 14-खंड के पाठ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, राष्ट्रपति ट्रम्प का अर्थ है कि क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन ईरान को इन हथियारों को रखने की अनुमति देता है।
- क्षेत्रीय गैर-राज्य अभिनेताओं के लिए कोई नियम नहीं: समझौता जापान ईरान के लंबे समय से चले आ रहे गठबंधनों और क्षेत्रीय गैर-राज्य प्रावसी नेटवर्क के साथ वित्तीय संबंधों के संबंध में नियमों या प्रतिबंधों को पूरी तरह से दरकिनारा करता है।
- प्रत्यक्ष निगरानी प्रोटोकॉल का अभाव पुनः जुड़ाव: यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के "ज्ञान की निरंतरता" प्रोटोकॉल को तुरंत बहाल करने में विफल रहता है, जिससे सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग में अंतर रह जाता है।
- एकतरफा अमेरिकी वापसी के लिए भेद्यता: जबकि खंड 14 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का आह्वान किया गया है, पाठ में भविष्य के अमेरिकी प्रशासन को एकतरफा चलने से रोकने के लिए एक अचूक भौतिक तंत्र का अभाव है, जैसा कि 2018 में हुआ था।

आगे की राह:

- सख्त सत्यापन समयसीमा लागू करना: दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए खंड 12 निगरानी तंत्र का उपयोग करना चाहिए कि वित्तीय परिसंपत्तियों को फ्रीज करना होर्मुज जलडमरूमध्य में ऑन-द-ग्राउंड डी-माइनिंग कार्रवाइयों से मेल खाता है।
- IAEA निगरानी सुरक्षा उपायों को फिर से शामिल करना: 60-दिवसीय वार्ता के भविष्य के दौर को ईरान के नागरिक परमाणु अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए IAEA तक पूर्ण, अप्रतिबंधित पहुंच बहाल करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- बहुपक्षीय विफल-सुरक्षित आर्थिक संधियों का मसौदा तैयार करना: ईरान को अपने आने वाले \$ 300 बिलियन के पुनर्निर्माण कोष को बहु-राष्ट्र वाणिज्यिक अनुबंधों से जोड़ने के लिए काम करना चाहिए, जिससे भविष्य के एकतरफा प्रतिबंधों को शामिल सभी पक्षों के लिए आर्थिक रूप से महंगा बना दिया जाए।
- पारंपरिक हथियार नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना: पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, बाद की वार्ताओं को बैलिस्टिक मिसाइलों और सीमा पार सुरक्षा लाइनों पर स्पष्ट क्षेत्रीय समझौते स्थापित करने के लिए परमाणु मुद्दों को देखना चाहिए।

निष्कर्ष:

ईरान के 60% समृद्ध यूरेनियम भंडार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को बरकरार रखकर, यह सौदा होर्मुज जलडमरूमध्य में वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित करते हुए तेहरान के बदलते क्षेत्रीय प्रभाव को स्वीकार करता है। अंततः, इस परिवर्तन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या दोनों देश अस्थायी 60-दिवसीय युद्धविराम को एक स्थायी क्षेत्रीय संधि में बदलने के लिए आवश्यक संस्थागत विश्वास का निर्माण कर सकते हैं।

विवाटेक 2026

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मानव-केंद्रित एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को उजागर करने और द्विपक्षीय डिजिटल सहयोग का विस्तार करने के लिए पेरिस में विवाटेक 2026 में भाग लिया।



विवाटेक 2026

विवाटेक 2026 के बारे में:

यह क्या है?

- विवा टेक्नोलॉजी (वीवाटेक) यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है और डिजिटल परिवर्तन के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है।
- एक ओपन-इनोवेशन हब के रूप में काम करते हुए, यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए डीप-टेक स्टार्टअप, उद्योग जगत के नेताओं, प्रमुख निगमों, उद्यम पूंजीपतियों और वैश्विक निवेशकों को जोड़कर वाणिज्यिक और तकनीकी सफलताओं को गति देता है।

होस्ट और टाइमलाइन

- स्थान: पेरिस, फ्रांस में पेरिस एक्सपो पोर्टे डी वर्साय में सालाना आयोजित किया जाता है।
- संस्थापक और आयोजक: फ्रांसीसी मीडिया और संचार दिग्गज पब्लिसिस ग्रुप और लेस इकोस-ले पेरिसियन द्वारा सह-स्थापित और आयोजित।

में स्थापित: 2016

विवाटेक 2026 की मुख्य विशेषताएं:

- बड़े पैमाने पर संस्थागत पैमाना: 2026 संस्करण लगभग 180,000 उपस्थित लोगों, 14,000 स्टार्टअप, 4,000 भागीदारों और 450 वैश्विक वक्ताओं को एक साथ लाता है, जो 30 से अधिक विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
- भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल: भारत की उपस्थिति में अब तक का सबसे बड़ा मंडप पदविह्व है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य-तकनीक, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, उन्नत कंप्यूटिंग और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) में घरेलू डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करता है।
- डीप-टेक कॉर्पोरेट घुसपैठ: 80 से अधिक भारतीय डीप-टेक कंपनियां और इनोवेटर्स उद्योग, स्वास्थ्य देखभाल, हरित गतिशीलता और जलवायु स्थिरता के लिए निर्मित वास्तविक दुनिया, स्केलेबल उत्पाद पेश कर रहे हैं।
- ओपन इनोवेशन इनक्यूबेशन: सिग्नेचर विवाटेक स्टार्टअप चैलेंजेज की सुविधा है, एक एप्लिकेशन फ्रेमवर्क जहां विजेता स्टार्टअप को कुलीन वैश्विक उद्यम भागीदारों द्वारा इनक्यूबेट किया जाता है।

महत्व:

YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

- विवाटेक 2026 में भारत की भागीदारी बढ़ते द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी संबंधों पर आधारित फ्रांस के साथ नवाचार और स्टार्टअप सहयोग को मजबूत करती है।
- भारत ने लोक कल्याण, पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल समावेशन पर केंद्रित एक नैतिक, ओपन-सोर्स एआई दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
- भारतीय मंडप ने विकासशील देशों के लिए डिजिटल भुगतान, कृषि, शासन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मापनीय समाधान प्रदर्शित किए।

आयुष्मान सारथी चैटबॉट

संदर्भ:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैटबॉट 'आयुष्मान सारथी' लॉन्च किया।

आयुष्मान सारथी चैटबॉट

आयुष्मान सारथी चैटबॉट के बारे में:

यह क्या है?

- आयुष्मान सारथी एक सुरक्षित, एपीआई-आधारित डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य इंटरफ़ेस है जो व्हाट्सएप पर काम करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा विकसित, यह नागरिकों को अपने मोबाइल फोन पर सरल, स्वचालित संदेश आदान-प्रदान के माध्यम से PM-JAY सिस्टम के साथ सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाता है।

नोडल मंत्रालय:

- मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार
- निष्पादन निकाय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा विकसित और निगरानी की जाती है।

उद्देश्य:

- एक अत्यधिक सुलभ, संवादात्मक मंच प्रदान करना जो नागरिकों को बुनियादी कार्ड प्रबंधन के लिए सरकारी कार्यालयों या कॉल सेंटर पर जाने की आवश्यकता को दूर करता है।
- प्रत्येक पात्र परिवार को नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षित, वास्तविक समय पर डिजीटरी सुनिश्चित करना, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण जनसांख्यिकी पर ध्यान केंद्रित करना।

आयुष्मान सारथी की मुख्य विशेषताएं:

- व्यापक कार्ड प्रबंधन: उपयोगकर्ता तुरंत योजना पात्रता की जांच कर सकते हैं, नए आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपने सक्रिय डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आवश्यक ईकेवाईसी सत्यापन को फिर से कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से अपनी आधिकारिक पहचान प्रोफाइल लिंक कर सकते हैं।
- डायनेमिक सिव्योरिटी ब्रिड: लाभार्थियों को पहचान के दोहराव या दुरुपयोग से बचाने के लिए सीधे व्हाट्सएप से अपने पीएम-जेएवाई कार्ड को अस्थायी रूप से लॉक या अनलॉक करने की अनुमति देता है।
- वरिष्ठ नागरिक देखभाल एकीकरण: आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए एक समर्पित मॉड्यूल पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने विशेष स्वास्थ्य देखभाल लाभों को निर्बाध रूप से प्रबंधित कर सकें।
- वास्तविक समय वित्तीय और नैदानिक लुकअप: लाभार्थी अपने शेष बीमा वॉलेट बैलेंस की जांच कर सकते हैं, अपने चिकित्सा उपचार इतिहास के रिकॉर्ड को ब्राउज़ कर सकते हैं और आस-पास के सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पतालों की खोज कर सकते हैं।
- स्वचालित निवारण और फीडबैक लूप: नागरिकों को आधिकारिक प्रशासनिक शिकायतों को सुरक्षित रूप से पंजीकृत करने, ट्रैक करने या वापस लेने, सीधे कॉलबैक समर्थन का अनुरोध करने और अस्पताल देखभाल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए उनके डिस्चार्ज के बाद की प्रतिक्रिया लॉग करने में सक्षम बनाता है।
- त्वरित सक्रियण प्रोटोकॉल: किसी भी स्मार्टफोन पर आधिकारिक एनएचए क्यूआर कोड स्कैन करके या समर्पित व्हाट्सएप नंबर +91 72908 23838 पर नमस्ते भेजकर 24x7 तक पहुंच योग्य है।

महत्व:

- व्हाट्सएप का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान, ऐप-मुक्त पहुंच को सक्षम बनाता है, जिससे डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद मिलती है, खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।
- चैटबॉट वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया और शिकायत डेटा एकत्र करता है, जिससे अधिकारियों को खराब प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों की पहचान करने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद मिलती है।



प्रोजेक्ट ब्रह्मांक

संदर्भ:

सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने 29 जून, 2026 को अरुणाचल प्रदेश के राणाघाट में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया।

प्रोजेक्ट ब्रह्मांक

प्रोजेक्ट ब्रह्मांक के बारे में:

यह क्या है?

- प्रोजेक्ट ब्रह्मांक एक अत्यधिक विशिष्ट, फॉरवर्ड-डिप्लॉयड इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूनिट है। चरम भौगोलिक परिस्थितियों में काम करते हुए, यह एक मुख्य आधारभूत संपत्ति के रूप में कार्य करता है जिसे भारत की सीमा रेखाओं के साथ भारी-भरकम सड़कों, बहु-टन सामरिक पुलों और सैन्य-ब्रेड विमानन परिसंपत्तियों के निर्माण का काम सौंपा गया है।
- मूल संगठन: यह सीधे सीमा सड़क संगठन (BRO) के तहत कार्य करता है।

उद्देश्य:

- भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तेजी से आगे बढ़ने को सुनिश्चित करने के लिए संचार की सभी मौसम में परिचालन लाइनों का निर्माण, उन्नयन और रखरखाव करना।
- सीमांत क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाना, कट-ऑफ सीमा चौकियों और दूरदराज के स्वदेशी सीमावर्ती गांवों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना।

मुख्य विशेषताएं और संचालन:

- उत्तरदायित्व का क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश के पांच जिलों और असम के आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विकास और रखरखाव करता है।
- बुनियादी ढांचा नेटवर्क: सीमा कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली 811 किमी रणनीतिक सड़कों और 86 प्रमुख पुलों का रखरखाव करता है।
- हाल की उपलब्धियां (वित्त वर्ष 2025-26): 13 पुलों (कुल 390 मीटर) को पूरा किया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग डबल लेन (एनएचडीएल) मानकों के अनुसार 61 किमी सड़कों को ब्लैकटॉप किया गया।
- विमानन सहायता: भारतीय वायु सेना रसद और आपातकालीन निकासी के लिए सामरिक हेलीपैड विकसित करता है।
- इतिहास: 29 जून 2011 को राणाघाट में स्थापित किया गया और 3 दिसंबर 2011 को चालू हो गया।

महत्व:

- प्रोजेक्ट ब्रह्मांक सभी मौसम में रणनीतिक सड़कों के माध्यम से वास्तविक कॉन्ट्रो की रेखा (LAC) तक सैनिकों, तोपखाने और सैन्य उपकरणों की तेजी से आवाजाही में सुधार करता है।
- यह परियोजना भूस्खलन, भारी वर्षा और दूरदराज की स्थितियों पर काबू पाने के लिए कठिन हिमालयी इलाकों में जटिल पुलों और सड़कों को वितरित करती है।

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल

संदर्भ:

ग्रामीण विकास मंत्री ने पूना कैंपस, नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान एआई-सक्षम 'ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल' का शुभारंभ किया।

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल

ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल एक एआई-संचालित, एकीकृत क्लाउड-आधारित डिजिटल इकोसिस्टम है जिसे सार्वजनिक आंतरिक ऑडिट के पूरे जीवनचक्र का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) के कार्यालय द्वारा परिकल्पित, यह एक मानकीकृत, डेटा-संचालित ढांचे के साथ खंडित, कागज-गहन और मैनुअल ऑडिटिंग को बदल देता है।
- नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में।
- विकास भागीदार: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ सक्रिय सहयोग से निर्मित और वास्तुकला।



उद्देश्य:

- संस्थागत जवाबदेही को अधिकतम करने और प्रणालीगत वित्तीय रिसाव को खत्म करने के लिए आंतरिक सार्वजनिक लेखा परीक्षा को डिजिटाइज, मानकीकृत और सरल बनाना।
- उन्नत भविष्य कहनेवाला मॉडलिंग का उपयोग करके सरल अनुपालन चेक-सूचियों से डेटा-संचालित, जोखिम-आधारित ऑडिट योजना में संक्रमण करना।
- ऐतिहासिक ऑडिट ट्रेन्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) का एक केंद्रीय भंडार स्थापित करना, जबकि पूरी तरह से कागज रहित और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ शासन की ओर बढ़ रहा है।

पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

- एंड-टू-एंड डिजिटल फ्लो: पूरे ऑडिट चक्र को ऑनलाइन कवर करता है, जिसमें टीम पंजीकरण, योजना, ऑडिट झापन जारी करना, अवलोकन दर्ज करना और रिपोर्ट जनरेट करना शामिल है।
- डिजिटल एटीआर ट्रैकिंग और पैरा सेटलमेंट: ऑडिटी डिजिटल एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) और सहायक प्रमाण सीधे पोर्टल पर अपलोड करते हैं। लेखा परीक्षक प्रकटीकरण की समीक्षा करते हैं और वास्तविक समय में डिजिटल रूप से ऑडिट पैराग्राफ को व्यवस्थित या स्पष्ट करते हैं।
- भू-स्थानिक निगरानी (मानचित्र दृश्य): एक सहज ज्ञान युक्त जीआईएस-आधारित मानचित्र इंटरफ़ेस को एकीकृत करता है जो चल रहे ऑडिट को नेत्रहीन रूप से ट्रैक करता है, सक्रिय टीमों को मैप करता है, और स्पष्ट रूप से ग्रामीण इकाइयों को उजागर करता है जिनका संसाधन परिणियोजन को अनुकूलित करने के लिए कभी ऑडिट नहीं किया गया है।
- एआई और प्रेडिक्टिव रिस्क एनालिटिक्स: उच्च जोखिम वाली संस्थाओं को चिह्नित करने, आवर्ती प्रणालीगत विसंगतियों को अलग करने और साक्ष्य-आधारित निर्णय सहायता प्रदान करने के लिए मशीन लर्निंग और स्वचालित पैटर्न पहचान का उपयोग करता है।
- भूमिका-आधारित शासन ढांचा: लेखा परीक्षकों, स्थानीय लेखा परीक्षकों, अनुमोदन प्राधिकरणों और जिला या राज्य-स्तरीय प्रशासनिक प्रभागों के लिए अनुकूलित अलग, सुरक्षित इंटरफ़ेस की सुविधा है।
- मजबूत तकनीकी सुरक्षा: आधुनिक CI/CD माइक्रो-सेवाओं पर निर्मित, भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण, सुरक्षित API एकीकरण और पूर्ण स्वचालित आपदा रिकवरी प्रोटोकॉल के साथ NIC द्वारा सुरक्षित रूप से होस्ट किया गया।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना 2026**संदर्भ:**

शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना 2026 के लिए आवेदन शुरू किए हैं।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना 2026**प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026 के बारे में:****यह क्या है?**

- पीएमआरसी योजना एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतिभा-प्रत्यावर्तन और अनुसंधान संरचना है। यह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालयों, निजी प्रयोगशालाओं और तकनीकी उद्योगों में काम करने वाले भारतीय मूल के शीर्ष स्तरीय शोधकर्ताओं के लिए प्रीमियम भारतीय संस्थानों के भीतर उच्च-स्तरीय अनुसंधान पदों को लेने के लिए एक सीधा मार्ग स्थापित करता है।
- मंत्रालय: इस योजना की अवधारणा, वित्त पोषण और प्रशासित उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (MoE), भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य उच्च कुशल प्रतिभाओं के बहिर्वाह को रोकने के लिए विश्व स्तरीय भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और तकनीकी नेताओं को आकर्षित करना, प्रोत्साहित करना और बनाए रखना है।
- भारत की वैज्ञानिक पाइपलाइन में अपनी वैश्विक विशेषज्ञता को एकीकृत करके, यह परियोजना महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में घरेलू सफलताओं में तेजी लाने, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और भारत को एक उन्नत वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है।

मुख्य विशेषताएं और मुख्य वास्तुकला:

- पीएमआरसी का परिचालन ढांचा तीन संरचनात्मक परतों पर बनाया गया है और सख्त संस्थागत मानदंडों द्वारा शासित है:

जुड़ाव के तीन स्तर:

- कार्यक्रम आने वाले अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों को तीन आयु और कैरियर-विशिष्ट ट्रैक में वर्गीकृत करता है:
- युवा रिसर्च फेलो: शुरुआती कैरियर के वैज्ञानिकों और पोस्टडॉक्टोरल विद्वानों की ओर तैयार किया गया है जो अभिनव परियोजनाओं को बीज देने के लिए तैयार हैं।



- वरिष्ठ रिसर्च फेलो: मध्य-कैरियर शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों के उद्देश्य से गहरी क्षेत्र विशेषज्ञता है।
- अनुसंधान अध्यक्ष: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अकादमिक नेताओं, प्रयोगशाला प्रमुखों और वैश्विक प्रौद्योगिकी अग्रदूतों के लिए आरक्षित।

प्राथमिकता वाले रणनीतिक विषयगत क्षेत्र

- आने वाले अनुसंधान प्रस्तावों को भारत के विकास और सुरक्षा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण तेरह प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ सख्ती से संरेखित किया जाना चाहिए:
- कंप्यूटिंग और तकनीक: उन्नत कंप्यूटिंग (एआई, क्वांटम और सुपरकंप्यूटिंग), सेमीकंडक्टर, अगली पीढ़ी के संचार और साइबर सुरक्षा।
- औद्योगिक और बुनियादी ढांचा: विनिर्माण और उद्योग 4.0, उन्नत सामग्री और महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और रक्षा, और परमाणु ऊर्जा।
- स्थिरता और जीव विज्ञान: ऊर्जा, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और मेडटेक, कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकियां, और नीली अर्थव्यवस्था।

सब्सिडीयरी पात्रता

- मेजबान मानदंड: केवल एनआईआरएफ समग्र/इंजीनियरिंग श्रेणियों के शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, या एनआईआरएफ अनुसंधान श्रेणी के शीर्ष 50 संस्थानों को ही फेलो लेने की अनुमति है। यह डीएसटी, डीबीटी, आईसीएमआर और सीएसआईआर के तहत काम करने वाली चुनिंदा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा पूरक है।
- 7 प्रमुख हब: बहु-विषयक निष्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिए, सात प्रमुख संस्थानों को प्रमुख केंद्रों के रूप में नामित किया गया है: आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद और आईआईएससी बेंगलुरु।
- कठोर स्वतंत्र शासन: फेलो और प्रस्तावों दोनों का मूल्यांकन और चयन पूरी तरह से भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- फंडिंग और स्थानांतरण पैकेज: प्रारंभिक बजटीय अनुमान आने वाले समूह के लिए बहु-वर्षीय अनुसंधान अनुदान, मजबूत स्थानांतरण भत्ते, प्रतिस्पर्धी संस्थागत फेलोशिप और अत्याधुनिक प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की लक्षित तैनाती को दर्शाते हैं।

भव्या पोर्टल

संदर्भ:

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया।

यह रोलआउट 33,660 करोड़ रुपये की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) के औपचारिक संचालन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 100 विश्व स्तरीय, निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना है।

भव्या पोर्टल

BHAVYA पोर्टल के बारे में:

यह क्या है?

- भव्य पोर्टल भारत के नए औद्योगिक पार्क के संपूर्ण जीवनचक्र की देखरेख के लिए विकसित एक उन्नत, एंड-टू-एंड सिंगल-विंडो डिजिटल प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। यह राज्य परियोजना प्रस्तुतियों, वास्तविक समय निर्माण ट्रैकिंग और दूरस्थ निवेशक मानचित्रण के लिए प्राथमिक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
- मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
- नोडल निष्पादन निकाय: राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी)।

उद्देश्य:

- फ्रेमवर्क का उद्देश्य पूरी तरह से विकसित, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक भूखंड प्रदान करके घरेलू और वैश्विक विनिर्माण कंपनियों के लिए बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटना है।
- भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी की पारंपरिक बाधाओं को दूर करके, इसका उद्देश्य व्यापार सेटअप में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर औद्योगिक रोजगार पैदा करना है।

ढांचे की मुख्य विशेषताएं:

- निष्पादन मॉडल संघीय प्रतिस्पर्धा को एक अनुकूलित, स्तर-आधारित भूमि आवंटन रणनीति के साथ जोड़ता है:
- चुनौती-आधारित चयन मॉडल: राज्यों को स्वचालित रूप से धन प्राप्त नहीं होता है। उन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करके प्रतिस्पर्धा करने के लिए पोर्टल का उपयोग करना चाहिए जो उनकी विशिष्ट भूमि उपलब्धता, स्थानीय औद्योगिक ताकत और निवेशक रुचि को प्रदर्शित करता है।



- चर, स्तरीय पार्क आकार: क्षेत्रीय इलाके से मेल खाने के लिए, पार्कों को तीन परिचालन पैमानों में विभाजित किया गया है:
- पहाड़ी क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर: 25 एकड़ के छोटे पैमाने के क्षेत्र।
- मध्यम आकार के राज्य: 100 से 500 एकड़ के बीच के औद्योगिक क्षेत्र।
- शहरी परिधि: प्रमुख शहरों के करीब 1,000 एकड़ तक फैले मेगा-पार्क।
- 51:49 वित्तीय खाई: राज्य सरकारें कच्ची भौतिक भूमि प्रदान करती हैं, जबकि केंद्र सरकार 51:49 संयुक्त साझेदारी मॉडल के तहत एनआईसीडीसी के माध्यम से प्राथमिक बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करती है।
- चरणबद्ध रोलआउट समयरेखा: 1 जून से 31 जुलाई, 2026 के बीच जमा किए गए आवेदन 20 पार्कों के पहले बैच के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, इसके बाद 30 सितंबर तक प्राप्त डोजियर के आधार पर अतिरिक्त 30 पार्क होंगे।
- विशिष्ट हाई-टेक एन्वलेव: पार्कों के भीतर स्थान विशेष रूप से डीप-टेक उद्यमों, स्टार्टअप, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए निर्धारित किए जाएंगे।
- इन-हाउस गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं: नियामक अनुपालन बाधाओं को जल्दी से दूर करने के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) और एफएसएसआई के साथ सीधी साझेदारी में पार्कों के अंदर आधुनिक परीक्षण सुविधाएं बनाई जाएंगी।
- वैश्विक प्रवासी केंद्र: यह नीति जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड जैसे विदेशी निवेश भागीदारों के लिए तैयार किए गए समर्पित अंतरराष्ट्रीय एन्वलेव बनाने के लिए जगह छोड़ती है, जिसमें श्रमिक आवास और एकीकृत सामाजिक बुनियादी ढांचा शामिल है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

संदर्भ:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) की 10वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए PMSMA के 10 वर्ष – देखभाल का एक दशक विषय के तहत राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के बारे में:

यह क्या है?

- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) एक राष्ट्रीय प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसे पूरे भारत में सभी गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से आश्वस्त, व्यापक और पूरी तरह से मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- एक अद्वितीय सिंगल-विंडो हेल्थकेयर डिलीवरी मैकेनिज्म के माध्यम से काम करते हुए, यह योजना प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) रणनीति के तहत सरकार के देखभाल निरंतरता दृष्टिकोण के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है।
- इस योजना को आधिकारिक तौर पर 9 जून, 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
- शामिल मंत्रालय: कार्यक्रम को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), भारत सरकार द्वारा डिजाइन, वित्तपोषित और निष्पादित किया जाता है।
- उद्देश्य: पीएमएसएमए उत्तम जोखिम वाले गर्भधारण की प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन के माध्यम से रोकी जा सकने वाली मातृ और शिशु मृत्यु को कम करने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक विशेषज्ञ प्रसवपूर्व जांच मिले।

PMSMA परिस्थितिकी तंत्र की मुख्य विशेषताएं:

- महीने की 9 तारीख: हर महीने के 9वें दिन, सभी नामित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं विशेष पीएमएसएमए सत्र आयोजित करती हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसवपूर्व देखभाल तक अनुमानित और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित होती है।
- सिंगल-विंडो न्यूनतम देखभाल पैकेज: गर्भवती महिलाओं को एक ही यात्रा के तहत नैदानिक जांच, परामर्श, दवाएं, प्रयोगशाला परीक्षण और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन सहित मुफ्त सेवाओं का एक पूरा पैकेज मिलता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वयंसेवा: निजी स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट स्वेच्छा से सरकारी सुविधाओं का समर्थन करते हैं, जिससे विशेषज्ञों की कमी को पूरा करने और मातृ स्वास्थ्य देखभाल कवरेज में सुधार करने में मदद मिलती है।
- ग्रीन स्टिकर (सामान्य गर्भावस्था): बिना किसी पहचानी गई जटिलताओं वाली महिलाओं के एमसीपी कार्ड पर एक हरे रंग का स्टिकर लगाया जाता है, जो एक सामान्य गर्भावस्था का संकेत देता है जिसके लिए नियमित निगरानी की आवश्यकता होती है।
- लाल स्टिकर (उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था): एक लाल स्टिकर उच्च जोखिम वाली गर्भधारण वाली महिलाओं की पहचान करता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को करीबी पर्यवेक्षण, समय पर रेफरल और प्रसव की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सचेत करता है।



ई-पीएमएसएम सुविधाओं के बारे में:

- नाम-आधारित लाइन लिस्टिंग: ई-पीएमएसएम ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड और ट्रैक करता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा वास्तविक समय की निगरानी की जा सकती है।
- विस्तारित देखभाल बैठकें: स्वास्थ्य सुविधाएं प्रति माह चार पीएमएसएम सत्र आयोजित कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि छूटे हुए लाभार्थियों और उच्च जोखिम वाले मामलों को समय पर देखभाल मिले।
- 45-दिवसीय स्वस्थ परिणाम खिड़की: निगरानी प्रणाली गर्भावस्था से प्रसव के 45 दिन बाद तक मां और नवजात दोनों को ट्रैक करती है, जिससे व्यापक मातृ और नवजात देखभाल सुनिश्चित होती है।
- वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त परिवहन सहायता: JSSK के तहत, गर्भवती महिलाओं को परिवहन सहायता प्रदान की जाती है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, जिससे संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बाधाएं कम हो जाती हैं।

गर्भनिरोधक उपयोग और प्रजनन एजेंसी

संदर्भ:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023-24) के हालिया जारी आंकड़ों ने भारत में महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चाओं को गति दी है।

गर्भनिरोधक उपयोग और प्रजनन एजेंसी

गर्भनिरोधक उपयोग और प्रजनन एजेंसी के बारे में:

यह क्या है?

- प्रजनन एजेंसी - सुरक्षित रूप से यह तय करने की स्वतंत्रता कि क्या, कब और कितनी बार बच्चे पैदा करने हैं - महिला सशक्तिकरण का एक मूलभूत स्तंभ है। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य इतिहास में, गर्भनिरोधक को लंबे समय तक मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय लक्ष्य-निर्धारण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में माना जाता था।
- हालांकि, आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे इसे एक महिला की शारीरिक स्वायत्तता और एक आर्थिक चालक के एक आवश्यक मार्कर के रूप में देखते हैं जो असमान सामाजिक वास्तुकला को दूर करने में मदद करता है।

NFHS-6 से मुख्य डेटा और सांख्यिकी:

- प्रारंभिक विवाह सीमा: राष्ट्रीय स्तर पर, 20-24 आयु वर्ग की 20.1% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले हो गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में मीट्रिक बढ़कर 23.3% हो गई (एनएफएस-5 से पूरी तरह से अपरिवर्तित रही)।
- किशोर गर्भावस्था का बोझ: प्रारंभिक विवाहों के प्रत्यक्ष परिणाम को दर्शाते हुए, सर्वेक्षण के समय 15-19 वर्ष की आयु की 6.7% युवा लड़कियां पहले से ही मां या गर्भवती थीं, जो ग्रामीण भीतरी इलाकों में 7.9% पर पहुंच गई थीं।
- नसबंदी लिंग विषमता: महिला नसबंदी भारत में भारी प्रमुख गर्भनिरोधक विधि बनी हुई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी गर्भनिरोधक उपयोग का 36.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 38.1% है, जबकि पुरुष नसबंदी के लिए यह नगण्य 0.5% है।
- पारंपरिक तरीकों में बदलाव: आधुनिक प्रतिवर्ती तरीकों में 56.4% (NFHS-5) से 52.7% तक मामूली गिरावट देखी गई, जबकि कम प्रभावी, पारंपरिक परिवार नियोजन विधियों का उपयोग 10.3% से बढ़कर 16.4% हो गया।

मजबूत प्रजनन स्वायत्तता की अनिवार्य आवश्यकता:

- विस्तारित प्रजनन विंडो को छोटा करना: जब एक लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, तो उसकी प्रजनन खिड़की काफी लंबी हो जाती है। यह सुनिश्चित करना कि लड़कियों की शादी बाद में हो जाए, जिससे जल्दी, बार-बार गर्भधारण से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं।
- गंभीर मातृ स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना: स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता की कमी के कारण युवा दुल्हनों को उच्च मातृ जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक गर्भधारण को रोकने से सीधे गंभीर एनीमिया, प्रसूति संबंधी जटिलताओं और मातृ मृत्यु दर के शारीरिक बोझ कम हो जाते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक उन्नति को सक्षम करना: विवाह और प्रसव को स्थगित करने से महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने, सशुल्क कार्यबल में प्रवेश करने और वित्तीय सुरक्षा का निर्माण करने की अनुमति मिलती है।
- खतरनाक स्थायी संचालन को सुरक्षित विकल्पों से बदलना: कम वित्त पोषित ग्रामीण अस्पतालों में बड़े पैमाने पर सर्जिकल प्रक्रियाओं पर निर्भरता से दूर जाने से पोस्ट-ऑपरेटिव संक्रमण, एनेस्थीसिया से जटिलताओं और दीर्घकालिक बीमारियों को रोका जा सकता है।
- परिवार नियोजन के विषम बोझ को संतुलित करना: भारी असंतुलन को ठीक करना जहां महिलाएं गर्भनिरोधक के लिए लगभग सभी जिम्मेदारी वहन करती हैं, परिवार नियोजन में समान साझेदारी और साझा जवाबदेही बनाने के लिए आवश्यक है।



पहल और ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1952 परिवार नियोजन का शुभारंभ: भारत ने एक आधिकारिक, राज्य-प्रायोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर एक वैश्विक ऐतिहासिक बेंचमार्क स्थापित किया।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA): बाल विवाह को दंडित करने, नाबालिगों की सुरक्षा करने और युवा लड़कियों के अधिकारों की कानूनी रूप से रक्षा करने के लिए एक सख्त वैधानिक ढांचा अधिनियमित किया गया है।
- एनएफएचएस फ्रेमवर्क की शुरुआत: सभी राज्यों में स्वास्थ्य, पोषण और परिवार नियोजन मापदंडों को व्यवस्थित रूप से पकड़ने के लिए बहु-दौर, जनसंख्या-पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण तैनात किए गए।
- ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार: ग्रामीण सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क बनाया गया जो कम आय वाले परिवारों को रियायती प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

परिवार नियोजन में प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ:

- कानूनी विवाह की उम्र की लगातार अवहेलना: गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक प्रथाओं का मतलब है कि सभी ग्रामीण लड़कियों में से लगभग एक चौथाई अभी भी 18 से पहले शादी कर रही हैं, जिससे उनकी शिक्षा और करियर की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
- स्थायी महिला नसबंदी पर अत्यधिक निर्भरता: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां अक्सर प्रतिवर्ती, आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों के विविध मिश्रण की पेशकश करने के बजाय स्थायी ट्यूबेक्टोमी के लिए डिफ़ॉल्ट होती हैं।
- कम वित्त पोषित और भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं: ग्रामीण सरकारी अस्पतालों को उत्तम रोगी संख्या, कम प्रशिक्षित कर्मचारियों और सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ता है, जो सर्जिकल देखभाल की गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप संक्रमण हो सकता है।
- अप्रभावी पारंपरिक तरीकों के लिए एक अट्श्य बदलाव: नसबंदी में गिरावट ने महिलाओं को आधुनिक, वैज्ञानिक रूप से मान्य प्रतिवर्ती विकल्पों के बजाय अनौपचारिक, कम विश्वसनीय पारंपरिक तरीकों की ओर प्रेरित किया है।
- पुरुष गर्भनिरोधक भागीदारी में एक जिद्दी कमी: गहरे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और लक्षित जागरूकता अभियानों की कमी पुरुष नसबंदी दर को नगण्य 0.5% पर स्थिर छोड़ देती है।

आगे की राह:

- कम उम्र में विवाह को एक मुख्यसार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में मानना: बाल विवाह निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू करना और ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों को बनाए रखने के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन तैयार करना।
- आधुनिक प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक की ओर धुरी रणनीति: विश्वसनीय, वैज्ञानिक प्रतिवर्ती तरीकों (जैसे कॉपर-टी, इंजेक्शन और मौखिक गोलियां) तक मुफ्त पहुंच का विस्तार करने की दिशा में स्थायी नसबंदी अभियानों से दूर राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिकताओं को स्थानांतरित करें।
- समुदाय-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का उन्नयन: अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, अस्वास्थ्यकर स्थितियों को खत्म करने और उत्तम गुणवत्ता, रोगी-केंद्रित देखभाल की गारंटी देने के लिए ग्रामीण सरकारी क्लिनिकों में समर्पित धन उपलब्ध कराना।
- पुरुष भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोग्रामेटिक अभियान शुरू करना: पुरुष नसबंदी के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने और परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी में सुधार करने के लिए सक्रिय, समुदाय-स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान तैयार करना।
- सूचना-विकल्प परामर्श ढांचे को संस्थागत बनाना: सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक प्रजनन देखभाल तक पहुंचने वाली प्रत्येक महिला को उसके लिए उपलब्ध अस्थायी और स्थायी गर्भनिरोधक विकल्पों के पूर्ण सूट पर निष्पक्ष, व्यापक परामर्श प्राप्त हो।

निष्कर्ष:

एनएफएचएस-6 की अंतर्दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भारत में परिवार नियोजन को महिलाओं की प्रजनन एजेंसी के सक्रिय रूप से निर्माण की दिशा में बुनियादी जन्म-सीमित संख्याओं को विकसित करना चाहिए। एक कम वित्त पोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क के भीतर महिला नसबंदी पर बहुत अधिक भरोसा करना महिलाओं पर एक अनुचित, असुरक्षित बोझ डालता है।

FCRA विधेयक - नागरिक समाज पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार**संदर्भ:**

लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (FCRA) विधेयक, 2026 को पेश करने से पूरे भारत में गहन संवैधानिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है।

FCRA विधेयक**FCRA विधेयक के बारे में - नागरिक समाज पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार:****यह क्या है?**

- विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, एक विधायी उपाय है जिसे 2010 के मूलभूत FCRA अधिनियम में संशोधन करने के लिए डिज़ाइन



किया गया है। जबकि सरकार इसे नियामक अंतराल को बंद करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए एक वैधानिक कदम के रूप में प्रस्तुत करती है, नागरिक समाज समूह इसे एक संरचनात्मक तंत्र के रूप में देखते हैं जो कार्यकारी शक्ति का विस्तार करता है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की मुख्य विशेषताएं:

- पंजीकरण की समाप्ति के लिए विस्तारित आधार: पंजीकरण को बंद माना जाएगा यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है, या समाप्ति से पहले प्राप्त नहीं किया जाता है।
- एक नामित प्राधिकरण का निर्माण: एक केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नामित प्राधिकरण पंजीकरण को रद्द करने, आत्मसमर्पण करने या समाप्त करने के बाद विदेशी योगदान और संबंधित संपत्ति का प्रबंधन करेगा।
- परिसंपत्तियों का अंतिम निहितीकरण: विदेशी निधियों से पूरी तरह या आंशिक रूप से सृजित विदेशी योगदान और परिसंपत्तियां अस्थायी रूप से पर्यवेक्षण और रखरखाव के लिए नामित प्राधिकारी में निहित होंगी।
- बहाली तंत्र: अप्रयुक्त विदेशी योगदान और संपत्ति वापस की जा सकती है यदि पंजीकरण नवीनीकृत किया जाता है, बहाल किया जाता है, या एक नया पंजीकरण प्रदान किया जाता है।
- परिसंपत्तियों का स्थायी निहित करना: परिसंपत्तियां और विदेशी योगदान स्थायी रूप से नामित प्राधिकारी में निहित हो सकते हैं यदि निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण बहाल नहीं किया जाता है या इकाई निष्क्रिय हो जाती है।
- सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों का उपयोग: स्थायी रूप से निहित संपत्ति को सरकारी निकायों को हस्तांतरित किया जा सकता है या भारत की संचित निधि में जमा आय के साथ निपटारा जा सकता है।
- विस्तारित अनुपालन दायित्व: संगठनों और प्रमुख पदाधिकारियों को रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, संपत्ति को संरक्षित करना चाहिए और प्राधिकरण की देखरेख में काम करना चाहिए।
- अपील का अधिकार: पीड़ित व्यक्ति 90 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष नामित प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
- सरकारी छूट शक्ति: केंद्र सरकार कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं को सार्वजनिक हित में निहित प्रावधानों से छूट दे सकती है।
- विदेशी वित्त पोषण पर व्यापक प्रतिबंध: विदेशी योगदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध समाचार उत्पादन, प्रकाशन या करंट अफेयर्स के प्रसारण में लगे किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाता है।
- आपराधिक दंड में कमी: उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास को पांच साल से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है, जबकि जुर्माने के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।
- जांच के लिए पूर्व केंद्रीय अनुमोदन: अधिनियम के तहत अपराधों की किसी भी जांच के लिए केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
- आंशिक रूप से विदेशी वित्त पोषित परिसंपत्तियों का कवरेज: निहित प्रावधानों में अब स्पष्ट रूप से विदेशी योगदान के माध्यम से आंशिक रूप से बनाई गई संपत्ति शामिल है।
- केंद्रीय निरीक्षण: विधेयक विदेशी वित्त पोषित संस्थाओं और उनकी संपत्तियों से संबंधित प्रबंधन, निगरानी, जांच और निपटान शक्तियों को केंद्रीकृत करता है।

सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- प्रक्रियात्मक लालफीताशाही से नागरिक समाज की रक्षा करना: उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है, इसलिए देरी से कागजी कार्रवाई या लंबित नवीनीकरण गलत काम किए बिना गैर-सरकारी संगठनों को स्वचालित रूप से अपंग नहीं करते हैं।
- उदाहरण: धारा 14B लंबित नवीनीकरण के दौरान पंजीकरण को स्वचालित रूप से बंद करने की अनुमति देती है, जिससे प्रशासनिक देरी के कारण परिचालन पक्षाघात का खतरा होता है।
- जमीनी स्तर पर कल्याण वितरण की निरंतरता सुनिश्चित करना: गैर सरकारी संगठनों द्वारा कमजोर समुदायों को दी जाने वाली सेवाओं में अचानक व्यवधान को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता है।
- उदाहरण: फंडिंग रुकावटें सीधे बाल कल्याण, टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल-विकास कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती हैं।
- दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण निश्चितता प्रदान करना: स्थिर नियामक समयसीमा गैर सरकारी संगठनों को आत्मविश्वास के साथ बहु-वर्षीय विकास परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने में मदद करती है।
- उदाहरण: निश्चित अनुमोदन समयसीमा की अनुपस्थिति निरंतर विदेशी धन पर निर्भर परियोजनाओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
- अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों को मनमाने ढंग से पूछताछ से बचाना: अल्पसंख्यक द्वारा संचालित शैक्षणिक और धर्मार्थ संस्थानों की चयनात्मक जांच को रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ मानक आवश्यक हैं।
- उदाहरण: हजारों मिशन स्कूलों, अस्पतालों और अनाथालयों को अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
- संपत्ति के अधिकारों और उचित प्रक्रिया का संरक्षण: संवैधानिक सुरक्षा की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच के बाद ही संपत्ति की जब्ती होनी चाहिए।
- उदाहरण: धारा 16A पूर्व न्यायिक समीक्षा के बिना सरकारी अधिकारियों में संपत्ति के अंतिम निहित करने की अनुमति देती है।

प्रमुख पहल और पहले से मौजूद हांचे

- 1976 की आपातकालीन आधारेखा: मूल FCRA को आपातकाल के दौरान विदेशी फंडिंग को विनियमित करने और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था।
- समेकित 2010 अधिनियम: 2010 के कानून ने सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की निगरानी को मजबूत किया।
- कड़े 2020 संशोधन: संशोधनों ने प्रशासनिक व्यय सीमा को कम कर दिया और धन के उपयोग पर सख्त नियंत्रण लागू किया।
- गृह मंत्रालय डिजिटल डैशबोर्ड: एक केंद्रीकृत पोर्टल गैर-सरकारी संगठनों के पंजीकरण, वार्षिक फाइलिंग, अनुपालन रिकॉर्ड और रद्दीकरण अपडेट को ट्रैक करता है।

2026 विधेयक में प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ:

- नामित प्राधिकारी को दी गई व्यापक शक्तियाँ: विधेयक संगठनात्मक परिसंपत्तियों और संचालन में हस्तक्षेप करने के लिए व्यापक शक्तियों के साथ एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाता है।
- उदाहरण: प्राधिकरण संपत्तियों पर कब्जा कर सकता है, प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव कर सकता है और परिसंपत्ति निपटान की देखरेख कर सकता है।
- समेकित निधि में निजी परिसंपत्तियों का परिसमापन: पंजीकरण पुनः प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप संगठनात्मक संपत्ति सरकार को स्थायी रूप से हस्तांतरित हो सकती है।
- उदाहरण: भवन या भूमि बेची जा सकती है, आय को भारत की संचित निधि में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- व्यक्तिपरक "सार्वजनिक हित" मानक: व्यापक और अपरिभाषित सार्वजनिक हित खंड पंजीकरण के मनमाने ढंग से रद्द करने की अनुमति दे सकते हैं।
- उदाहरण: जनजातीय अधिकारों, पर्यावरण, या मानवाधिकार संगठनों को अस्पष्ट व्याख्याओं के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- पदाधिकारियों की व्यापक व्यक्तिगत देयता: विस्तारित अनुपालन जिम्मेदारियाँ ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को अधिक कानूनी जोखिमों के लिए उजागर करती हैं।
- उदाहरण: निदेशकों और प्रमुख पदाधिकारियों को प्रक्रियात्मक अनुपालन विफलताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- जांच शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण: जांच प्राधिकरण केंद्र सरकार के साथ केंद्रित है, जिससे राज्य स्तरीय स्वायत्तता कम हो जाती है।
- उदाहरण: धारा 43 के तहत राज्य एजेंसियों को जांच शुरू करने से पहले पूर्व केंद्रीय अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

- लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निश्चित वैधानिक समय-सीमा शुरू करना: पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य 90-दिन की खिड़की पेश करने के लिए विधेयक में संशोधन करना, यह सुनिश्चित करना कि लंबित स्थिति के परिणामस्वरूप स्वचालित समाप्ति न हो।
- परिसंपत्ति निहित करने से पहले स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा को अनिवार्य करना: किसी संगठन की संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण लेने से पहले उच्च न्यायालय या स्वतंत्र न्यायाधिकरण से स्पष्ट मंजूरी प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकारी की आवश्यकता होती है।
- "सार्वजनिक हित" के लिए स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ परिभाषाओं की स्थापना: वैध सार्वजनिक वकालत या मानवाधिकारों के काम को दबाने के लिए कानून का उपयोग करने से रोकने के लिए सटीक, कानूनी रूप से परिभाषित श्रेणियों के साथ व्यक्तिपरक रद्दीकरण खंड को बदलें।
- स्थानीय रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों को राज्य अधिग्रहण नियमों से छूट देना: यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 16A के दायरे को स्पष्ट करें कि घरेलू दान का उपयोग करके बनाई गई संपत्ति को अनंतिम निहित करने से पूरी तरह से छूट दी गई है, जो स्कूलों, अस्पतालों और पूजा स्थलों की रक्षा करती है।
- हितधारक परामर्श के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन: अधिनियमन से पहले नागरिक समाज हितधारकों, गैर-लाभकारी और अल्पसंख्यक संस्थानों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए 2026 विधेयक को एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजें।

निष्कर्ष:

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, विदेशी नकदी प्रवाह को विनियमित करने से नागरिक समाज की संपत्ति पर व्यापक राज्य नियंत्रण शुरू करने के लिए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। एक केंद्रीकृत नामित प्राधिकरण को पूर्व न्यायिक समीक्षा के बिना संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति प्रदान करके, विधेयक एक द्रुतशीतन प्रभाव पैदा करने का जोखिम उठाता है जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक नेटवर्क को बाधित कर सकता है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए उपचार की समानता

संदर्भ:

विशेषज्ञों ने एक समान राष्ट्रव्यापी पेंशन प्रणाली स्थापित करके भारत के विकलांगता कल्याण ढांचे के आमूल-चूल पुनर्गठन का आह्वान किया है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए उपचार की समानता

विकलांग व्यक्तियों के लिए उपचार की समानता के बारे में:

यह क्या है?



- जबकि भारत डिजिटल इंडिया मिशन, आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और यूपीआई के माध्यम से एक डिजिटल कल्याणकारी राज्य के वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है, पीडब्ल्यूडी इस सार्वभौमिक आउटरीच से काफी हद तक बाहर हैं।
- वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, विकलांगता पेंशन किसी व्यक्ति की विकलांगता की चिकित्सा प्रकृति या शारीरिक सीमा द्वारा समान रूप से निर्धारित नहीं की जाती है।

संवैधानिक और कानूनी अनिवार्यता:

- विकलांगता पेंशन को राज्य दान और प्रशासनिक विवेक के मामले से पूर्ण नागरिकता अधिकार में बदलना कई कानूनी आदेशों की प्रत्यक्ष पूर्ति है:
- संविधान का अनुच्छेद 41: राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24: दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और गैर-भेदभावपूर्ण पेंशन लाभ की कानूनी रूप से गारंटी देती है।
- गरिमा के साथ जीने का अधिकार: भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में पुष्टि की गई है।

विकलांगता कल्याण पर प्रमुख डेटा और सांख्यिकी:

- बढ़ती PwD जनसांख्यिकीय: जबकि 2011 की जनगणना में 2.68 करोड़ PwD दर्ज किए गए थे, बदलते रोग प्रोफाइल और जनसंख्या वृद्धि के कारण वर्तमान रुढ़िवादी अनुमान 4.5 करोड़ से 6 करोड़ नागरिकों तक है।
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का खर्च: भारत पेंशन सहित विकलांगता कल्याण पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मुश्किल से 0.02% खर्च करता है। इसके विपरीत, दक्षिण अफ्रीका 0.12%-0.15% खर्च करता है, ऑस्ट्रेलिया 0.35%-0.40% खर्च करता है, ब्राजील 0.45%-0.50% और ओईसीडी देश सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 2.2% खर्च करता है।
- अपर्याप्तस्थानीय पेंशन भुगतान: केंद्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में दिव्यांगजनों के केवल एक छोटे से हिस्से को ही शामिल किया गया है, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में आधारभूत राज्य पेंशन राशि मात्र ₹300 से ₹500 प्रति माह तक होती है।
- उच्च आर्थिक गुणक: प्रो बोनो इकोनॉमिक्स (2025) इस बात पर प्रकाश डालता है कि विकलांगता पेंशन का सामाजिक-आर्थिक रिटर्न उनकी लागत से लगभग 48% अधिक है, जिससे 1.4 से 1.6 के संरचनात्मक राजकोषीय गुणक प्राप्त होते हैं।

न्यूनतम सार्वभौमिक विकलांगता पेंशन फ्लोर रेट (MUDPFR) की अनिवार्य आवश्यकता:

- भौगोलिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना: एक नागरिक का बुनियादी उत्तरजीविता समर्थन स्थानीय राज्य के बजट या राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। MUDPFR की स्थापना देश भर में एक पूर्ण न्यूनतम आधार रेखा सुनिश्चित करती है, जबकि अभी भी प्रगतिशील राज्यों को अतिरिक्त टॉप-अप की पेशकश करने की अनुमति देती है।
- पर्याप्त व्यापक आर्थिक रिटर्न को अनलॉक करना: सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार से PwD को बाहर करने से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित 3% से 7% का नुकसान होता है। सार्वभौमिक आय दर परिवारों को स्थिर करके और ग्रामीण खपत को बढ़ावा देकर एक आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है।
- लाभार्थियों को उत्तरजीविता से उत्पादक श्रम की ओर ले जाना: संरचित रोजगार प्रोत्साहनों के साथ एक समान आधारभूत पेंशन के संयोजन से दिव्यांगजनों को सक्रिय बाजार सहभागियों में बदलने में मदद मिलती है।
- वैश्विक सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना: एक मजबूत पेंशन नेटवर्क को लागू करने से भारत की वैश्विक शासन स्थिति और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए इसकी दावेदारी मजबूत होती है। यह घरेलू नीति को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 28, आईएलओ सिफारिश संख्या 202 और जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुरूप है।

वर्तमान सेटअप में प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियाँ:

- एक खंडित और विभाजित प्रशासनिक वास्तुकला: ग्रामीण विकास मंत्रालय और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के बीच निगरानी बिखरी हुई है, जिससे नौकरशाही में देरी और जवाबदेही धुंधली हो गई है।
- अन्य क्षेत्रों की तुलना में गंभीर वित्तीय अंडरफंडिंग: विकलांगता कल्याण के लिए दिए गए सूक्ष्म आवंटन अन्य राष्ट्रीय व्ययों, जैसे खाद्य सब्सिडी (₹2.05 लाख करोड़) या बुनियादी ढांचे (₹11.11 लाख करोड़) से भारी रूप से आगे निकल गए हैं।

- एक खंडित विकलांगता रोजगार प्रोत्साहन योजना: मौजूदा कार्यस्थल एकीकरण प्रणाली कमजोर बनी हुई है और विदेशों में सफलतापूर्वक उपयोग किए जाने वाले मजबूत कर प्रोत्साहन या मजदूरी सब्सिडी की कमी है।
- बोझिलनौकरशाही सत्यापन प्रक्रियाएं: जटिल, गैर-पोर्टेबल पंजीकरण प्रणाली कमजोर नागरिकों को अंतर्हीन लालफीताशाही में फंसा देती है, जिससे वे पूरी तरह से आधुनिक कल्याण सुरक्षा जाल से बाहर हो जाते हैं।

आगे की राह:

- वित्तीय रूप से प्रबंधनीय राष्ट्रीय MUDPFY फ्लोर को लागू करना: बुनियादी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय आधारभूत दर शुरू करना- जैसे कि 40 लाख लाभार्थियों के लिए ₹8,000 प्रति माह (सकल घरेलू उत्पाद का 0.08% लागत) या 65 लाख लाभार्थियों के लिए ₹10,000 (सकल घरेलू उत्पाद का 0.08%-0.2% लागत)।
- एक एकीकृत राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन प्राधिकरण की स्थापना: एक एकीकृत रजिस्ट्री, पोर्टेबिलिटी और डिजिटल एकीकरण की देखरेख के लिए एक एकल स्वतंत्र निकाय के तहत संचालन को केंद्रीकृत करना - दक्षिण अफ्रीका के SASSA या ऑस्ट्रेलिया के NDIA जैसे सफल वैश्विक संस्थानों का मॉडलिंग करना।
- कार्यस्थल प्रोत्साहन के साथ नकद पेंशन को एकीकृत करना: यूके के एक्सेस टू वर्क प्रोग्राम पर आधारित कॉर्पोरेट टैक्स ब्रेक और वेतन सब्सिडी शुरू करके विकलांगता रोजगार प्रोत्साहन योजना को अपग्रेड करें।
- स्थानीय कौशल विकास ढांचे का विस्तार: समावेशी रोजगार चैनलों के साथ कल्याणकारी सहायता को सीधे जोड़ने के लिए PM-DAKSH और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) जैसे मौजूदा जमीनी स्तर के कार्यक्रमों को बढ़ाना।
- उन्नत डीबीटी और डिजिटल पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म की तैनाती: क्षेत्रीय देशी और राज्य-स्तरीय पोस्टकोड को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, लाभार्थियों को तुरंत एक समान पेंशन वितरित करने के लिए भारत के सिद्ध प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ढांचे का उपयोग करें।

निष्कर्ष:

एक विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने की दिशा में भारत का मार्ग अपने सबसे कमजोर नागरिकों को असमान, राज्य-दर-राज्य पेंशन लॉटरी में पीछे नहीं छोड़ सकता है। विकलांगता समर्थन को विवेकाधीन दान से एक स्पष्ट, कानूनी रूप से समर्थित नागरिकता अधिकार में बदलना एक संवैधानिक कर्तव्य और एक प्रभावी आर्थिक निवेश दोनों है।

अवैतनिक घरेलू श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का आदेश

संदर्भ:

एक ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें गृहणियों को केवल निष्क्रिय देखभाल करने वालों के बजाय राष्ट्र निर्माता और आर्थिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई।

अवैतनिक घरेलू श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का आदेश

अवैतनिक घरेलू श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय के 2026 के आदेश के बारे में:

यह क्या है?

- सुप्रीम कोर्ट का जून 2026 का फैसला भारतीय मुआवजा कानून में एक संरचनात्मक अंधे स्थान को संबोधित करता है, जो ऐतिहासिक रूप से एक गृहिणी के दैनिक घरेलू योगदान पर एक ठोस मौद्रिक मूल्य रखने के लिए संघर्ष करता है।
- अदालत ने एक नया स्टैंडअलोन कानूनी प्रतिपूरक प्रमुख पेश किया जिसे घरेलू देखभाल का नुकसान कहा जाता है, जो एक घर के ठोस आर्थिक प्रबंधन को साहचर्य के भावनात्मक नुकसान से पूरी तरह से अलग करता है।

घरेलू देखभाल पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- जीडीपी योगदान मैट्रिक्स: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 2019 टाइम यूज सर्वे का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाओं की अवैतनिक देखभाल भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुमानित 15% से 17% का योगदान देती है।
- बड़े पैमाने पर दैनिक समय असंतुलन: डेटा से पता चलता है कि 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों पर प्रतिदिन औसतन 7 घंटे से अधिक खर्च करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह 3 घंटे से कम है।
- संस्थागत मुकदमेबाजी अड़चन: 120 से अधिक मोटर दुर्घटना अपीलों के सर्वेक्षण में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय स्तर पर लगभग 8 वर्षों की औसत लंबित स्थिति पाई, यह देखते हुए कि इससे पहले के विशिष्ट मामले को हल करने में आश्चर्यजनक रूप से 25 साल लग गए।
- मल्टी-फोल्डमुआवजा पुनर्गठन: पुराने गणित को आधुनिक मैट्रिक्स से बदलकर, न्यायालय ने निर्भरता के संरचनात्मक नुकसान के लिए 35 वर्षीय मृत गृहिणी के लिए आधारभूत मुआवजे को संशोधित कर ₹60.48 लाख कर दिया, जिससे पारंपरिक खर्चों को जोड़ने के बाद अंतिम भुगतान ₹62.77 लाख हो गया।

अवैतनिक घरेलू श्रम को महत्व देने की अनिवार्य आवश्यकता:

- जीडीपी फ्रेमवर्क में प्रणालीगत कम आकलन को सुधारना: अवैतनिक घरेलू श्रम को नियमित रूप से औपचारिक राष्ट्रीय लेखांकन से



बाहर रखा जाता है क्योंकि व्यापक अर्थव्यवस्था की छिपी नींव के रूप में कार्य करने के बावजूद इसे पारंपरिक उत्पादक गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

- प्रथम शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना: एक माँ या गृहिणी भाषा, रचनात्मक कौशल और मूलभूत मूल्यों का दैनिक प्रसारण प्रदान करती है जिसे कोई भी व्यावसायिक या सशुल्क व्यवस्था दोहरा नहीं सकती है।
- अंतर्निहित घरेलू बुनियादी ढांचे को पहचानना: एक गृहिणी एक घरेलू प्रणाली स्थापित करती है जो सीधे कमाने वाले जीवनसाथी को बाहरी काम और करियर की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है।
- आर्थिक प्रबंधन को भावनात्मक हानि से अलग करना: इस फैसले से पहले, कानून केवल कंसोर्टियम के नुकसान की पेशकश करता था, जो प्रति आश्रित ₹40,000 तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कंसोर्टियम केवल भावनात्मक अनुपस्थिति (सांत्वना और साहचर्य) को संबोधित करता है, जो घर के प्रबंधन के ठोस आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखने में पूरी तरह से विफल रहता है।

कानूनी ढांचे का विकास:

- लता वाधवा बेसलाइन (2001): टाटा स्टील के एक कार्यक्रम में एक दुखद आग से उत्पन्न होकर, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना कि एक गृहिणी की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, 34-59 आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रति माह ₹3,000 की एक मामूली अनुमानित आय शुरू करने की स्थापना की।
- मोटर वाहन अधिनियम अनुमान (2001): दुर्घटना दावों की गणना करने के लिए देश भर में सभी गैर-कमाई वाले व्यक्तियों के लिए केवल ₹15,000 की मनमानी वार्षिक आय आधार रेखा लागू की।
- अरुण कुमार अग्रवाल बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (2010): सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से कहा कि एक मां का योगदान खाना पकाने या सफाई से कहीं आगे तक फैला हुआ है, निचली अदालतों को एक अमूल्य गृहिणी को एक मानक भुगतान वाले घरेलू कामगार के साथ बराबर करने के खिलाफ चेतावनी दी।
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017): एक संविधान पीठ ने अंतिम संस्कार के खर्च, संपत्ति के नुकसान और भविष्य के संभावित गुणकों के लिए पारंपरिक प्रमुखों को तय करके गणित को मानकीकृत किया, हालांकि अदालतों में अभी भी दैनिक घरेलू श्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक स्पष्ट तंत्र का अभाव है।

नया अनिवार्य मुआवजा तंत्र:

- सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू देखभाल के नुकसान की गणना करने के लिए एक सख्त, समान ढांचा स्थापित किया :
- तीन अनिवार्य ट्रिगर शर्तें: नया मुआवजा सिर स्वचालित रूप से लागू होता है जब एक दुर्घटना के दावे में एक गृहिणी शामिल होती है जिसने घर के कामकाज में योगदान दिया, जिसके बच्चों ने मातृ मार्गदर्शन खो दिया, और जिसके पति या पत्नी या माता-पिता ने महत्वपूर्ण दैनिक समर्थन खो दिया।
- नई बेसलाइन इनकम फ्लोर रेट: जहां तीन शर्तें पूरी होती हैं, ₹30,000 प्रति माह आधार आय के रूप में खड़ा होता है, जिससे आयु-आधारित भविष्य की संभावनाओं और गुणकों की गणना की जाती है, जो पूरी तरह से पुरानी मनमानी काल्पनिक आय को बदल देती है।
- पेड-एम्प्लॉयमेंट टॉप-अप नियम: यदि मृत गृहिणी भी घर के बाहर एक सक्रिय, भुगतान वाली नौकरी रखती है, तो ₹30,000 की आधार रेखा सीधे उसकी वास्तविक सत्यापित आय के ऊपर जोड़ दी जाती है।
- स्वचालित मुद्रास्फीति सूचकांक: मूल्य को स्थिर होने से रोकने के लिए, बेसलाइन दर को हर तीन साल में स्वचालित रूप से 10% ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा, जो कंसोर्टियम के नुकसान के लिए उपयोग किए जाने वाले शेड्यूल से मेल खाता है।

आगे की राह:

- सारांश से मानकीकृत दावा न्यायाधिकरण में परिवर्तन: राज्य सरकारों को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) को सुप्रीम कोर्ट के ₹30,000 बेसलाइन फ्रेमवर्क के साथ सामान्य काल्पनिक आय को तुरंत बदलने का निर्देश देना चाहिए।
- बड़े पैमाने पर लंबित मामलों को निपटाने के लिए सारांश प्रक्रियाओं को लागू करना: उत्तम न्यायालयों को सबसे पुराने लंबित मोटर दुर्घटना मामलों को प्राथमिकता देने, समर्पित पीठों का विस्तार करने और सामान्य 8 साल की देरी को दूर करने के लिए त्वरित सारांश प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लागू करना चाहिए।
- दावों के प्रसंस्करण के लिए डिजिटल डेटाबेस को एकीकृत करना: सुनिश्चित करें कि बीमा रजिस्ट्रियां और स्थानीय न्यायाधिकरण विशेष डिजिटल ढांचे के माध्यम से आसानी से इंटरफेस करते हैं ताकि परिवार की पीड़ा को बढ़ाए बिना आयु-आधारित गुणकों की जल्दी से गणना की जा सके।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का निर्णय अवैतनिक घरेलू श्रम के वास्तविक वित्तीय मूल्य को पहचानकर आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ा कदम है। गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता के रूप में तैयार करके और घरेलू देखभाल के लिए 30,000 रुपये मासिक आधार रेखा स्थापित करके, कानून ने महिलाओं के काम को मामूली दान या भावनात्मक भावना के रूप में मानने से आगे बढ़ गया है।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69(ए)

संदर्भ:

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अनुरोध के बाद भारत में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को 22 जून, 2026 तक ब्लॉक कर दिया है।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69(ए)

IT अधिनियम, 2000 की धारा 69(A) के बारे में:

यह क्या है?

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) एक शक्तिशाली वैधानिक प्रावधान है जो केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी डिजिटल जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- यह भारत में राष्ट्रीय डिजिटल सेंसरशिप, वेबसाइट ब्लॉकिंग और प्लेटफॉर्म प्रतिबंध के लिए प्राथमिक कानूनी तंत्र के रूप में कार्य करता है।



धारा 69(A) के मुख्य प्रावधान:

- इस धारा के तहत, केंद्र सरकार या उसका कोई भी विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकता है।
- इस शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सरकार संतुष्ट हो कि विशिष्ट आधारों के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता।
- भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा।
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- सार्वजनिक आदेश या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए उकसाने को रोकने के लिए।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उद्देश्य: मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का व्यापक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य माध्यमों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की मुख्य विशेषताएं:

- इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता: डिजिटल अनुबंधों, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों और डेटा लॉग को मान्य करता है, उन्हें कानूनी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भौतिक, कागज-आधारित दस्तावेजों के बराबर रखता है।
- डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण: ऑनलाइन लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर (असममित क्रिप्टो-सिस्टम का उपयोग करके) के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- मध्यस्थ दायित्व और सुरक्षित बंदरगाह (धारा 79): ऑनलाइन मध्यस्थों (जैसे सोशल नेटवर्क, वेब होस्ट और टेलीकोस) की कानूनी देनदारियों को परिभाषित करता है। यह उन्हें तृतीय-पक्ष डेटा सामग्री से प्रतिरक्षा (सुरक्षित बंदरगाह) प्रदान करता है, बशर्ते वे सख्त परिश्रम करते हैं और सरकारी निष्कासन या डेटा अवरोधन आदेशों का तुरंत पालन करते हैं।
- व्यापक साइबर अपराध और दंड: अनधिकृत हैकिंग, स्रोत कोड छेड़छाड़, पहचान की चोरी, अश्लील सामग्री प्रकाशित करना, डिजिटल धोखाधड़ी और डेटा गोपनीयता उल्लंघनों सहित डिजिटल अपराधों को दंडित करने के लिए एक समर्पित दंड प्रणाली बनाता है।
- साइबर अपीलीय बुनियादी ढांचे की स्थापना: तकनीक से संबंधित नागरिक विवादों, डेटा उल्लंघनों और कॉर्पोरेट वैधानिक उल्लंघनों को निपटाने के लिए निर्णायक अधिकारियों और साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण सहित एक प्रशासनिक और नियामक पदानुक्रम बनाता है।

यूपीएससी ईडब्ल्यूएस कोटा जांच

संदर्भ:

द इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण कोटा के घोषित कल्याणकारी उद्देश्यों और सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2025 में उत्तीर्ण होने वाले कई उम्मीदवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल के बीच एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर का पता चला है।

यूपीएससी ईडब्ल्यूएस कोटा जांच

UPSC EWS कोटा जांच के बारे में:

यह क्या है?



- द इंडियन एक्सप्रेस ने 2025 परीक्षा चक्र में चुने गए कुल 958 उम्मीदवारों में से 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले सभी 104 उम्मीदवारों की सोशल मीडिया, कोचिंग रजिस्ट्री और संस्थागत ट्रैकिंग जांच की।

जांच से मुख्य निष्कर्ष:

- प्रीमियम सिविल सेवा कोचिंग तक पहुंच: कम से कम 67 उम्मीदवारों (64.4%) ने दिल्ली और अन्य प्रमुख केंद्रों में कुलीन कोचिंग केंद्रों में भाग लिया, जहां वार्षिक ट्यूशन ₹2.65 लाख तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर, 104 उम्मीदवारों में से 84 ने औपचारिक, निजी कोचिंग नेटवर्क का उपयोग किया।
- उच्च लागत वाली निजी स्कूली शिक्षा पृष्ठभूमि: कम से कम 46 उम्मीदवारों (44.4%) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के प्रसिद्ध निजी स्कूलों और लखनऊ, जयपुर और रायपुर जैसे राज्यों की राजधानियों में अपनी शिक्षा पूरी की, जहां वार्षिक शुल्क ₹45,000 से ₹1.5 लाख के बीच है।
- वाणिज्यिक और व्यावसायिक पारिवारिक समर्थन: कम से कम 28 उम्मीदवारों (26.9%) के माता-पिता के पास सक्रिय व्यवसाय हैं, जो एनसीआर, राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों में कपड़े के व्यापार, स्टील फैब्रिकेशन, कन्फेक्शनरी और खुदरा दुकानों में फैले हुए हैं।
- पूर्व उच्च-भुगतान वाले कॉर्पोरेट क्षेत्र के रोजगार: कम से कम 10 उम्मीदवार (9.6%) बहुराष्ट्रीय निगमों, बड़े सॉफ्टवेयर फर्मों या निर्माण समूहों में निजी क्षेत्र में कार्यरत थे, जो अपनी बहु-वर्षीय यूपीएससी तैयारी शुरू करने से पहले पर्याप्त कॉर्पोरेट वेतन प्राप्त कर रहे थे।
- एलीट इंस्टीट्यूशनल ब्रेजुएशन क्रेडेंशियल्स: कम से कम 14 उम्मीदवार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक या स्नातकोत्तर हैं, 3 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), 27 दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से और 3 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से।
- ववालीफायर की क्षेत्रीय एकाग्रता: 104 सफल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश (25), बिहार (17), मध्य प्रदेश (14), हरियाणा (9) और राजस्थान (8) से हैं।

EWS कोटा का इतिहास:

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण ढांचा जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।
- इस ऐतिहासिक संशोधन ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को शामिल किया, जिससे राज्य को उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% तक आरक्षण प्रदान करने और आर्थिक रूप से वंचित नागरिकों के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक रोजगार नियुक्तियां प्रदान करने में सक्षम बनाया गया, जो पहले से मौजूद किसी भी आरक्षण श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।
- अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार के परिवार की सकल वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए, जो कृषि भूमि के स्वामित्व, आवासीय प्लॉट आकार और शहरी भूखंड होलिंग्स के संबंध में विशिष्ट परिचालन बहिष्करण के अधीन है।

EWS कोटा के लिए संरचनात्मक आवश्यकता:

- सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए कानूनी सुरक्षा जाल प्रदान करना: कोटा यह सुनिश्चित करता है कि सामान्य श्रेणी से संबंधित संरचनात्मक रूप से हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक अवसरों तक समान पहुंच मिले।
- कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना आर्थिक नुकसान की ओर: यह सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक वैध कानूनी मार्कर के रूप में आर्थिक स्थिति का परिचय देता है, जो भारत की पारंपरिक जाति-आधारित आरक्षण नीतियों का पूरक है।
- शैक्षिक और रोजगार असमानताओं को कम करना: यह नीति कम आय वाले परिवारों के लिए उच्च शिक्षा और सिविल सेवाओं के द्वार खोलती है जो प्रीमियम शैक्षिक सामग्री का खर्च नहीं उठा सकते।
- ग्रामीण और कृषक परिवारों के लिए वित्तीय तनाव को कम करना: कोटा छोटे पैमाने के किसानों और कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है।
- समावेशी विकास के दायरे को व्यापक बनाना: यह यह सुनिश्चित करके सबका साथ, सबका विकास के संवैधानिक वादे को संस्थागत बनाने में मदद करता है कि कोई भी कमजोर समूह राज्य की सामाजिक सुरक्षा छतरी से पूरी तरह से बाहर न रह जाए।

EWS फ्रेमवर्क से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- अत्यधिक व्यापक आय पात्रता सीमा: सकल पारिवारिक आय सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष निर्धारित करने से मानदंड बहुत व्यापक हो जाते हैं, जिससे मध्यम आय वाले परिवारों को पूर्ण गरीबी में रहने वाले परिवारों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है।
- कमजोर ऑन-ग्राउंड सत्यापन और उचित परिश्रम: स्थानीय प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी अक्सर पूरी तरह से परिसंपत्ति ऑडिट किए बिना स्व-घोषणा और बुनियादी आयकर रिटर्न पर भरोसा करते हैं।
- समृद्ध उम्मीदवारों द्वारा लाभ की कॉर्नरिंग: समृद्ध सामान्य श्रेणी के व्यक्ति जो निजी स्कूली शिक्षा और कुलीन कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, वे वास्तव में वंचित उम्मीदवारों को बाहर कर सकते हैं।
- बहु-वर्षीय यूपीएससी तैयारी का उच्चवित्तीय बोझ: नई दिल्ली जैसे महंगे केंद्रों में बहु-वर्षीय तैयारी चक्र को बनाए रखने की क्षमता वित्तीय स्थिरता के स्तर को इंगित करती है जो आर्थिक कमजोरी कोटा के मूल इरादे के विपरीत है।
- रीयल-टाइम एसेट ट्रैकिंग एकीकरण की कमी: राजस्व विभागों के पास सीमा पार संपत्ति होलिंग्स, शहरी प्लॉटों और अनौपचारिक व्यापार राजस्व को सत्यापित करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल रजिस्ट्री का अभाव है, जिससे अनुपालन स्वामियां पैदा होती हैं।

आगे की राह:

- आय पात्रता सीमा को युक्तिसंगत बनाना और कम करना: वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड का पुनर्मूल्यांकन करें और वर्तमान ₹8 लाख आधार रेखा से कम करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण वास्तव में गरीब परिवारों को लक्षित करता है।
- सत्यापन के लिए कठोर परिश्रम को अनिवार्य करना: स्थानीय राजस्व अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सरल स्व-घोषणाओं से आगे बढ़ने और पारिवारिक संपत्ति और जीवन शैली संकेतकों का गहन सत्यापन चलाने का निर्देश दें।
- केंद्रीय डेटाबेस में आय डेटा को एकीकृत करना: गैर-पात्र आवेदकों को स्वचालित रूप से विहित करने के लिए ईडब्ल्यूएस आवेदनों को सीधे आयकर विभाग, ईपीएफओ रजिस्ट्रियों और कॉर्पोरेट पेट्रोल डेटाबेस से लिंक करें।
- एक केंद्रीकृत क्रॉस-बॉर्डर एसेट रजिस्ट्री की स्थापना: EWS मानदंडों का उल्लंघन करने वाली छिपी हुई शहरी अचल संपत्ति होल्डिंग्स की पहचान करने के लिए राज्यों में एक एकीकृत डिजिटल संपत्ति और भूमि ट्रैकिंग नेटवर्क का निर्माण करें।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सालाना ईडब्ल्यूएस चयन प्रोफाइल का ऑडिट करने और परिसंपत्ति-स्वामित्व नियमों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाना चाहिए।

निष्कर्ष:

कठोर ऑन-ग्राउंड परिसंपत्ति सत्यापन के बिना बुनियादी आय स्व-घोषणाओं पर भरोसा करना इस सकारात्मक कार्यवाई नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का जोखिम उठाता है। अंततः, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अखंडता की रक्षा के लिए, राज्य को सख्त परिश्रम लागू करना चाहिए और पात्रता नियमों को अद्यतन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सच्चा आर्थिक न्याय सबसे कमजोर नागरिकों तक पहुंचे।



LK ACADEMY[®]
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE

एयर कुशन वाहन (ACVs)s

संदर्भ:

छह स्वदेशी रूप से निर्मित एयर कुशन वाहनों (ACV) में से पहले को आधिकारिक तौर पर गोवा में एक समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक बल (ICG) में शामिल किया गया था।

एयर कुशन वाहन (ACVs)

एयर कुशन वाहनों (ACVs) के बारे में:

यह क्या है?

- एक एयर कुशन वाहन (एसीवी), जिसे आमतौर पर होवरक्राफ्ट के रूप में जाना जाता है, एक उभयचर शिप है जिसे पानी, मडपलैट्स, सैंडबार और उथले समुद्र तटों सहित कई सतहों पर आसानी से यात्रा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह अपने पतवार के नीचे हवा का एक उच्च दबाव वाला कुशन उत्पन्न करके संचालित होता है , जो एक लचीली खर स्कर्ट द्वारा निहित होता है, जिससे जहाज सतह से पूरी तरह से ऊपर तैर सकता है और पानी के प्रतिरोध को खत्म कर सकता है।
- इस हाई-टेक पोत का निर्माण चौंगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।
- उद्देश्य: इन ACV को शामिल करने का उद्देश्य तटीय सुरक्षा, उथले पानी की निगरानी, खोज और बचाव, और समुद्री कानून प्रवर्तन कार्यों के लिए भारतीय तटरक्षक बल की तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है।



आईसीजी एसीवी की मुख्य विशेषताएं:

- उभयचर ऑल-टैरेन पैटर्नबाज़ी: शून्य ड्राफ्ट के साथ डिज़ाइन किया गया, होवरक्राफ्ट गहरे समुद्र के चैनलों, ज्वारीय मडपलैट्स और रेतीले तटों के बीच निर्बाध रूप से संचरण कर सकता है जहां पारंपरिक पतवार फंस जाएंगे।
- छह-पोत अनुबंध बेड़ा: यह डिलीवरी क्रमिक रूप से निर्मित और आईसीजी बेड़े में एकीकृत किए जाने वाले छह नियोजित स्वदेशी एसीवी में से पहला है।
- उन्नत पतवार और सामग्री डिज़ाइन: मलबे या उबड़-खाबड़ तटीय इलाके पर रिकमिंग करते समय संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए एक टिकाऊ खर स्कर्ट सिस्टम के साथ जोड़े गए हल्के, समुद्री-ग्रेड सामग्री का उपयोग करके बनाया गया।
- आधुनिक नेविगेशन और संचार सूट: घने कोहरे या शून्य-दृश्यता की स्थिति में चौबीसों घंटे संचालन को सक्षम करने के लिए विशेष समुद्री रडार, नाइट-विजन थर्मल इमेजिंग और सुरक्षित संचार प्रणालियों से लैस।
- अनुकूलित पेलोड स्थान: एक बहुमुखी डेक लेआउट के साथ इंजीनियर किया गया जो सशस्त्र बोर्डिंग पार्टियों, चिकित्सा प्रतिक्रिया टीमों या तेजी से हस्तक्षेप उपकरण ले जाने में सक्षम है।

महत्व:

- एसीवी कच्छ और सुंदरबन जैसे दलदल, खाड़ियों और मडपलैट्स में कुशलतापूर्वक गश्त कर सकते हैं, जिससे तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार होता है।
- समुद्र से किनारे तक जाने की उनकी क्षमता चक्रवात, बाढ़ और समुद्री आपात स्थितियों के दौरान तेजी से बचाव कार्यों और सहायता वितरण को सक्षम बनाती है।

आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस शोधक और आईएनएस अग्रे को त्रि-कमीशन

संदर्भ:

भारत के प्रधानमंत्री ने कोलकाता में आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे के ऐतिहासिक त्रि-कमीशन की अध्यक्षता की।

आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस शोधक और आईएनएस अग्रे को त्रि-कमीशन

आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे के त्रि-कमीशनिंग के बारे में:

यह क्या है?

- त्रि-कमीशनिंग तीन अलग-अलग नौसैनिक प्लेटफार्मों के एक साथ शामिल होने को संदर्भित करता है, जिनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से अलग रणनीतिक थिएटर के लिए इंजीनियर किया गया है। साथ में, वे क्षमता का विस्तार करने के लिए भारतीय नौसेना के



स्तरित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं: दूर के संचालन के लिए बड़े युद्धपोतों का निर्माण, समुद्री इलाके का नक्शा बनाने के लिए गहरे पानी के सर्वेक्षण जहाजों और आधुनिक खतरों के खिलाफ स्थानीय समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए फुर्तीले तटीय शिकारी।

व्यक्तिगत जहाज प्रोफाइल और रणनीतिक भूमिकाएं:

आईएनएस दूनागिरी (ब्लू-वाटर कॉम्बैटेंट)

- यह क्या है: एक भारी, स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट जो नौसेना के उन्नत प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। यह एक विध्वंसक से छोटा है लेकिन गहरे समुद्र में दूर तक नौकायन और लड़ने के लिए काफी बड़ा है।
- द्वारा विकसित: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता।
- उद्देश्य: नीले पानी के वातावरण में स्वतंत्र रूप से काम करना, दूर के समुद्री गलियारों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों दुश्मन खतरों का मुकाबला करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- उन्नत रडार-चोरी संरचनात्मक चुपके डिजाइन ज्यामिति के साथ निर्मित, जिससे शत्रुतापूर्ण सेंसर के लिए इसका पता लगाना असाधारण रूप से मुश्किल हो जाता है।
- ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएम) रक्षा नेटवर्क सहित लंबी दूरी के स्ट्राइक हथियारों से लैस।
- मल्टी-फंक्शन सर्विलांस, ट्रैक एंड गाइडेड रडार (MFSTAR), एंटी-सबमरीन वारफेयर रॉकेट और एकीकृत सोनार पतवारों सहित एक अत्यधिक उन्नत सेंसर सूट है।
- यह एक विशिष्ट फ्रिगेट परिवार का हिस्सा है जिसमें बहन जहाज आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं।

आईएनएस संशोधक (गहरे पानी का सर्वेक्षक)

- यह क्या है: एक सर्वेक्षण पोत - लार्ज (एसवीएल), विशेष संधायक-श्रेणी के बेड़े के चौथे और अंतिम जहाज के रूप में कार्य करता है।
- द्वारा विकसित: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता।
- उद्देश्य: समुद्र विज्ञान के इलाके को मापने, निरीक्षण करने और डिजिटल रूप से मानचित्रण करने के लिए, पानी के नीचे की नौसैनिक इकाइयों को नागरिक शिपिंग और आपदा राहत के लिए चार्ट प्रदान करते हुए सुरक्षित रूप से मार्गों की योजना बनाने में मदद करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- हाइड्रोग्राफिक डेटा एकत्र करने, समुद्र तल की विशेषताओं का विश्लेषण करने, पानी की गहराई निर्धारित करने और जटिल बंदरगाह दृष्टिकोण चैनलों का मानचित्रण करने का काम सौंपा गया है।
- गहरे समुद्र में अनुसंधान तकनीक से लैस, जिसमें स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन (एयूवी), दूर से संचालित पानी के नीचे के वाहन (आरओवी), और मल्टी-बीम इको साउंडर शामिल हैं।
- 2018 में हस्ताक्षरित नौसेना के आधुनिक बड़े हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण बेड़े के अनुबंध को पूरा करने के लिए अपने सहयोगी जहाजों-आईएनएस संधायक, निर्देशक और इक्षक का अनुसरण करता है।

आईएनएस एग्रा (द कोस्टल सबमरीन हंटर)

- यह क्या है: एक पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी का जहाज (ASW SWC) जो विशेष अर्नाला-वर्ग से संबंधित है। यह तीन प्लेटफार्मों में सबसे छोटा लेकिन सबसे चुस्त है।
- द्वारा विकसित: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता।
- उद्देश्य: व्यस्त, शोर और उथले तटीय (तटीय) पानी के भीतर छिपने का प्रयास करने वाली शत्रुतापूर्ण पनडुब्बियों का पता लगाना, ट्रैक करना और बेअसर करना।

प्रमुख विशेषताएं:

- वाणिज्यिक बंदरगाहों, नौसैनिक ठिकानों और रणनीतिक तटीय दृष्टिकोणों सहित महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए तैयार।
- मछली पकड़ने की नौकाओं, व्यापारी शिपिंग यातायात और असमान चट्टानों जैसे उथले पानी की अव्यवस्था से ध्वनिक गड़बड़ी को फ़िल्टर करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित।
- हल्के पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो, स्थानीयकृत पतवार सोनार और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट लांचर के साथ करीबी दूरी के समुद्री युद्ध के लिए भारी रूप से सशस्त्र।

भारत के परमाणु त्रय में रणनीतिक बदलाव

संदर्भ:

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) ने अपनी वार्षिक वैश्विक आयुध वार्षिक पुस्तक जारी की, जिसमें एक हड़ताली मूल्यांकन पेश किया गया: भारत के आधुनिक रणनीतिक इतिहास में पहली बार, इसके अनुमानित 190 परमाणु हथियारों में से 12 को परिचालन रूप से तैनात के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत के परमाणु त्रय में रणनीतिक बदलाव

भारत के परमाणु त्रय में रणनीतिक बदलाव के बारे में:

यह क्या है?

- भारत द्वारा 12 ऑपरेशनल परमाणु हथियारों की तैनाती आक्रामक परमाणु मुद्रा की ओर बदलाव का संकेत नहीं देती है। इसके बजाय, यह भारत की दूसरी बार क्षमता को धीरे-धीरे मजबूत करने का प्रतीक है - पहले हमले को अवशोषित करने के बाद भी परमाणु हथियारों से जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता। यह भारत के लंबे समय से नो फर्स्ट यूज (NFU) सिद्धांत और विश्वसनीय न्यूनतम निवारण रणनीति को पुष्ट करता है।

मुख्य डेटा और सांख्यिकी (SIPRI 2026):

संकेतक	स्थिति (2026)
कुल परमाणु हथियार	190 (180 में 2025 से ऊपर)
परिचालन रूप से तैनात	12 हथियार
रिजर्व भंडार	178 डी-मेटेड वॉरहेड
भारत का रक्षा व्यय (2025)	यूएस\$92.1 बिलियन (+8.9%)
चीन का परमाणु शस्त्रागार	620 हथियार (34 तैनात)
पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार	170 हथियार

ऐतिहासिक "Recessed Deterrent" आधार रेखा:

- पोस्टरन-II परमाणु परीक्षणों (1998) के बाद, भारत ने आक्रामक प्रक्षेपणों को रोकने और रक्षात्मक परमाणु मुद्रा बनाए रखने के लिए मिसाइलों से अलग परमाणु हथियार जमा किए।
- मजबूत नागरिक नियंत्रण: परमाणु हथियारों को तैनात करने के किसी भी निर्णय के लिए नागरिक नेतृत्व वाले परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) के माध्यम से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध: धँसे हुए निवारक ने हथियारों को निरंतर सतर्क रखे बिना एक जीवित प्रतिशोधी क्षमता बनाए रखकर भारत की नो फर्स्ट यूज (NFU) नीति का समर्थन किया।

शांतिकाल की तैयारी की ओर आधुनिक बदलाव:

- मजबूत समुद्र-आधारित निवारक: परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों (SSBN) को शामिल करने से भारत की दूसरी स्ट्राइक क्षमता में सुधार हुआ है, क्योंकि भूमि-आधारित मिसाइल स्थलों की तुलना में पनडुब्बियों का पता लगाना कहीं अधिक कठिन है।
- कनस्तरिकृत मिसाइलों की तैनाती: अग्नि-V और अग्नि-P जैसी आधुनिक मिसाइलों को सीलबंद कनस्तरों में संग्रहीत किया जाता है, जिससे न्यूनतम तैयारी के साथ तेजी से चलने, लंबे समय तक भंडारण और तेजी से प्रक्षेपण किया जा सकता है।
- सीमित परिचालन तैनाती: भारत ने अपने NFU सिद्धांत को छोड़े बिना प्रतिरोध को मजबूत करते हुए, बहुमत को रिजर्व में रखते हुए परिचालन रूप से तैनात वॉरहेड्स की एक छोटी संख्या को बनाए रखना शुरू कर दिया है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- वैश्विक हथियार नियंत्रण ढांचे को कमजोर करना: नई START संधि की समाप्ति ने प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों को कम कर दिया है। इससे अनिश्चितता बढ़ती है और वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ तेज होती है।
- उदाहरण: कोई भी उत्तराधिकारी संधि वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित नहीं करती है।
- दो-मोर्चों पर रणनीतिक सुरक्षा माहौल: भारत को पाकिस्तान की सामरिक परमाणु क्षमता और चीन के लंबी दूरी के परमाणु शस्त्रागार के विस्तार के खिलाफ विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखना चाहिए। इसके लिए दो सक्रिय रणनीतिक मोर्चों पर संसाधनों को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- उदाहरण: चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 हथियार हैं।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकी जोखिम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियाँ संकट के दौरान निर्णय

लेने के समय को कम करती हैं और आकरिमक वृद्धि की संभावना को बढ़ाती हैं। ये प्रौद्योगिकियां रणनीतिक स्थिरता के लिए नई चुनौतियाँ पेश करती हैं।

- उदाहरण: परमाणु कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम या एआई-आधारित गलत गणना पर साइबर हमले अनपेक्षित संघर्ष को ट्रिगर कर सकते हैं।
- पनडुब्बी रोधी युद्ध में प्रगति: उपग्रह निगरानी, पानी के नीचे सेंसर और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रौद्योगिकियों में सुधार के कारण बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का पता नहीं चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए निरंतर आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- उदाहरण: भारत आईएनएस वर्षा जैसी रणनीतिक सुविधाओं को मजबूत कर रहा है और एसएसबीएन स्टील्थ प्रौद्योगिकियों को बढ़ा रहा है।

आगे की राह:

- नागरिक नियंत्रण को संरक्षित करना: भारत को यह सुनिश्चित करना जारी रखना चाहिए कि सभी परमाणु निर्णय नागरिक नेतृत्व वाले परमाणु कमान प्राधिकरण (एनसीए) के अधीन रहें।
- उदाहरण: प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली राजनीतिक परिषद को परमाणु हथियार रोजगार पर विशेष अधिकार बनाए रखना चाहिए।
- समुद्र-आधारित प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना: लंबी दूरी की पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) का विस्तार करने से भारतीय पनडुब्बियों को शत्रुतापूर्ण जल से सुरक्षित रूप से दूर तक संचालित करने की अनुमति मिलेगी।
- उदाहरण: K-4 SLBM ($\approx 3,500$ किमी रेंज) और भविष्य की K-5/K-6 मिसाइलों का तेजी से प्रेरण।
- साइबर और अंतरिक्ष-आधारित सुरक्षा का उन्नयन: भारत को परमाणु कमांड नेटवर्क की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों और अंतरिक्ष-आधारित प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए।
- उदाहरण: स्वदेशी उपग्रह निगरानी और सुरक्षित कमांड-एंड-कंट्रोल संचार प्रणाली।
- वैश्विक परमाणु जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना: भारत को विश्वसनीय न्यूनतम निवारण की अपनी नीति को बनाए रखते हुए बहुपक्षीय हथियार-नियंत्रण पहलों का समर्थन करना जारी रखना चाहिए।
- उदाहरण: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु विश्वास-निर्माण और रणनीतिक जोखिम कम करने वाले संवादों में सक्रिय भागीदारी।

निष्कर्ष:

भारत के 12 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स पर SIPRI की रिपोर्ट एक परिपक्व परमाणु त्रय के विकास को दर्शाती है, न कि आक्रामक मुद्रा की ओर बदलाव। अपनी दूसरी स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करके, भारत बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल के बीच अपनी नो फर्स्ट यूज नीति, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करता है।

ब्रह्मोस मिसाइल

संदर्भ:

सिंगापुर में शांगरी-ला वार्ता में बोलते हुए, भारतीय रक्षा सचिव ने पुष्टि की कि भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए 5,800 करोड़ रुपये के रणनीतिक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के साथ इसी तरह का निर्यात समझौता पूरा होने के अंतिम चरण में है।

ब्रह्मोस मिसाइल

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:

यह क्या है?

- ब्रह्मोस एक अत्याधुनिक, सार्वभौमिक, लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, समुद्र, उप-समुद्र और हवाई प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करता है, अपने पूरे उड़ान लिफाफे में उच्च सुपरसोनिक गति बनाए रखता है, जिससे आधुनिक वायु-रक्षा नेटवर्क के लिए इंटरसेप्ट करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है।

द्वारा विकसित:

- इस मिसाइल का निर्माण ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा किया गया है, जो भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओ माशिनोस्ट्रॉयेनिया के बीच 1998 में स्थापित एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम है।
- इसका नाम दो प्रमुख नदियों से लिया गया एक पोर्टमैन्ट्यू है: भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा।

उद्देश्य:

- ब्रह्मोस हथियार प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य उच्च-मूल्य वाली सतह और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ विनाशकारी सटीकता-प्रहार क्षमता प्रदान करना है, जो परिचालन बलों के लिए पूर्ण समुद्री इनकार और रणनीतिक प्रतिरोध की गारंटी देता है।



प्रमुख तकनीकी और प्रदर्शन विशेषताएं:

- दो-चरण प्रणोदन: इसमें प्रारंभिक त्वरण और पृथक्करण के लिए अपने पहले चरण के रूप में एक ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन है , इसके बाद एक तरल रैमजेट दूसरा चरण है जो मच 2.8 के पास एक उत्तम क्रूज गति बनाए रखता है।
- बेजोड़ काइनेटिक प्रदर्शन: पारंपरिक सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में, ब्रह्मोस के पास 3 गुना वेग, उड़ान सीमा का 3 गुना तक और लक्ष्य प्रभाव पर 9 गुना अधिक विनाशकारी गतिज ऊर्जा होती है।
- उड़ान प्रक्षेपवक्र और ऊंचाई: मिसाइल 200 किलोग्राम तक का पारंपरिक वारहेड ले जाती है। यह दुश्मन के रडार से बचने के लिए 15 किमी तक की ऊंचाई पर क्रूज कर सकता है या 5 मीटर (सी-स्कमिंग टर्मिनल चरण) जितना कम उड़ान भर सकता है।
- यूनिवर्सल लॉन्च कॉन्फिगरेशन: यह सभी तैनाती विकल्पों में एक समान आंतरिक मिसाइल कॉन्फिगरेशन का उपयोग करता है। यह एक ट्रांसपोर्ट लॉन्च कनस्टर (टीएलसी) का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित भंडारण कंटेनर, परिवहन माध्यम और लॉन्च ट्यूब के रूप में कार्य करता है।

मल्टी-प्लेटफॉर्म परिनियोजन:

- भूमि: एक मोबाइल स्वायत्त लांचर (एमएएल) से लंबवत निकाल दिया गया।
- समुद्र: अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर ऊर्ध्वाधर या झुके हुए विन्यास में स्थापित।
- वायु: Su-30MKI लड़ाकू विमान बेड़े में अनुकूलित और एकीकृत।

वैश्विक पदचिह्न और अंतर्राष्ट्रीय खरीदार:

- फिलीपींस (पहला खरीदार): सिस्टम खरीदने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया, जिसने अपनी तटीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 2022 में तट-आधारित एंटी-शिप वेरिएंट के लिए \$ 375 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए।
- वियतनाम: तटीय रक्षा बैटरी, मिसाइल, प्रशिक्षण और रसद सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग ₹5,800 करोड़ मूल्य के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इंडोनेशिया: जल्द ही एक निर्यात अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए रक्षा वार्ता अंतिम चरण में है।

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला

संदर्भ:

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह के दौरान आधिकारिक तौर पर भारत के नए नौसेना प्रमुख (सीएनएस) के रूप में पदभार ग्रहण किया।

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कार्यभार संभाला

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला:



वह कौन है?

- एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के एक उत्तम अलंकृत ध्वज अधिकारी हैं। समुद्री बल के शीर्ष पद पर पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एफओसी-इन-सी) की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अरब सागर में नौसेना की तलवार शाखा के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख उपलब्धियां और प्राथमिकताएं:

- आला प्रौद्योगिकी प्रेरण: उन्होंने खुद को असममित युद्ध क्षमताओं के लिए एक मजबूत वकील के रूप में स्थापित किया है, जो नौसेना प्रणालियों में स्वदेशी उभरती प्रौद्योगिकियों और एआई प्लेटफॉर्मों की तैनाती को तेजी से बढ़ाने का वादा करता है।
- परिचालन तैयारी: अपनी कमांड संरचनाओं के तहत, उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में जटिल समुद्री डकैती विरोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा तैनाती का नेतृत्व किया है, अस्थिर क्षेत्रीय अनिश्चितताओं और अस्थिर समुद्री चोक पॉइंट्स को संभाला है।
- आधुनिकीकरण की गति: वह सक्रिय रूप से नौसेना के संरचनात्मक आत्मनिर्भरता ब्लूप्रिंट (आत्मनिर्भरता) को चला रहे हैं, चल रहे स्वदेशीकरण जहाज और पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रमों के समेकन की देखरेख कर रहे हैं।

भारतीय नौसेना पदानुक्रम:

- भारतीय नौसेना के संगठनात्मक मैट्रिक्स को एक स्पष्ट, पिरामिडनुमा सैन्य कमांड ढांचे के रूप में संरचित किया गया है जिसे तेजी से सामरिक निष्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है:
- एपेक्स: एडमिरल के चार सितारा रैंक वाले चीफ ऑफ नवल स्टाफ (सीएनएस) भारतीय नौसेना के सर्वोच्च ऑपरेशनल कमांडर और प्रशासनिक प्रमुख हैं, जो सीधे रक्षा मंत्रालय और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को रिपोर्ट करते हैं।
- ऑपरेशनल कमांड: बल को संरचनात्मक रूप से तीन स्थानीय कमांडों में विभाजित किया गया है, जिसका नेतृत्व तीन सितारा वाइस एडमिरल (फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ) करते हैं:
- पश्चिमी नौसेना कमान (मुख्यालय: मुंबई): अरब सागर और पाकिस्तान सीमा पर समुद्री हिटों की रक्षा करता है।

- पूर्वी नौसेना कमान (मुख्यालय: विशाखापत्तनम): बंगाल की खाड़ी की रक्षा करता है और मलक्का जलडमरूमध्य में चीनी गतिविधियों पर नज़र रखता है।
- दक्षिणी नौसेना कमान (मुख्यालय: कोच्चि): मुख्य रूप से प्रशिक्षण और संस्थागत कमांड ढांचे के रूप में कार्य करता है।

भारतीय नौसेना के प्रमुख कार्य:

- सैन्य भूमिका: युद्ध क्षमताओं, निगरानी, पनडुब्बी रोधी संचालन और वायु रक्षा के माध्यम से समुद्र में खतरों को रोककर और हराकर भारत के समुद्री हितों की रक्षा करता है।
- राजनयिक भूमिका: नौसैनिक अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और रक्षा सहयोग के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ता है।
- कांस्टेबुलरी भूमिका: समुद्री कानून को लागू करता है और समुद्री डकैती विरोधी, तस्करी विरोधी, मादक पदार्थों का मुकाबला और समुद्री सुरक्षा संचालन करके समुद्री मार्गों को सुरक्षित करता है।
- सौम्य और मानवीय भूमिका (HADR): प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष स्थितियों के दौरान आपदा राहत, खोज और बचाव सहायता, चिकित्सा सहायता और नागरिकों की निकासी प्रदान करता है।

रुद्रम-II मिसाइल

संदर्भ:

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रुद्रम-II हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया।

रुद्रम-II मिसाइल

रुद्रम-II मिसाइल के बारे में:

यह क्या है?

- रुद्रम-II एक उन्नत, उत्तम गति, स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी-रेडिएशन मिसाइल है। इसे दुश्मन के रडार, संचार नेटवर्क और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) साइटों का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- द्वारा विकसित: मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत (RCI), हैदराबाद के नेतृत्व में एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र के तहत विकसित किया गया है, जो नोडल DRDO प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

- रुद्रम-II का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय वायुसेना को दुश्मन की वायु रक्षा (एसईएडी) क्षमता का दमन प्रदान करना है।
- संघर्ष के शुरुआती चरणों के दौरान दुश्मन के जमीन-आधारित रडार और वायु रक्षा बुनियादी ढांचे को नष्ट करके, यह दोस्ताना स्ट्राइक विमानों के लिए सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएं:

- हाइपरसोनिक वेग: मिसाइल मैक 5.5 के चरम वेग तक पहुंचने में सक्षम है, जिससे यह एक अविश्वसनीय रूप से तेज़ हथियार बन जाता है जो लक्ष्य की प्रतिक्रिया और अवरोधन समय को कम करता है।
- विस्तारित स्टैंड-ऑफ रेंज: इसमें लगभग 300 किमी की स्ट्राइकिंग रेंज है, जो भारतीय लड़ाकू विमानों को दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों के लिफाफे में प्रवेश किए बिना सुरक्षित हवाई क्षेत्र के भीतर से हथियार लॉन्च करने की अनुमति देता है।
- पेलोड क्षमता: 200 किलोग्राम तक वजन वाले पारंपरिक वारहेड को ले जाने के लिए सुसज्जित, कठोर रडार प्रतिष्ठानों और कंक्रीट कमांड बंकरों को नष्ट करने के लिए अनुकूलित।
- डायनेमिक लॉन्च लिफाफा: बहु-ऊंचाई लचीलेपन के लिए डिज़ाइन किया गया, इसे 3 किमी और 15 किमी के बीच कहीं भी ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हवाई प्लेटफॉर्मों (जैसे Su-30MKI) से सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है।
- हाइब्रिड गाइडेंस आर्किटेक्चर: एक अत्यधिक संवेदनशील पैसिव होमिंग हेड (PHH) के साथ एक जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम (INS) और GPS को मिलाकर एक अत्याधुनिक नेविगेशन सूट को एकीकृत करता है। PHH एक रेडियो कान और आंखों की प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो एक बहुत व्यापक आवृत्ति बैंड में दुश्मन रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन का पता लगाता है और लॉक करता है।

महत्व:

- रुद्रम-II ने भारत की बढ़ती स्वदेशी मिसाइल क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे हवा से सतह पर मार करने वाले आयातित हथियारों पर निर्भरता कम हो गई।
- मिसाइल पुरानी रूसी मूल की Kh-31 मिसाइलों को बदलने के लिए तैयार है, जो बेहतर रेंज, गति, सटीकता और मार्गदर्शन प्रणाली प्रदान करती है।



भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस)

संदर्भ:

भारत के केंद्रीय गृह मंत्री आज नई दिल्ली में आधिकारिक तौर पर भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस) का शुभारंभ करेंगे।

भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस)

भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (LPMS) के बारे में:

यह क्या है?

- लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (एलपीएमएस) एक अत्याधुनिक, केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर संचालन को डिजिटल और एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह एक बुद्धिमान डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है जो सीमा पार डेटा ट्रैकिंग को मानकीकृत करता है, जिससे भूमि बंदरगाहों को प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से ही संचालित उत्तम दक्षता वाली डिजिटल प्रणालियों के बराबर लाया जा सकता है।
- शामिल संगठन: LPMS की अवधारणा और विकास भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (LPAI) द्वारा किया गया है।

उद्देश्य:

- एलपीएमएस का उद्देश्य व्यापार और लॉजिस्टिक्स डेटा के एंड-टू-एंड डिजिटल आदान-प्रदान के माध्यम से एक सुरक्षित, स्मार्ट सीमा प्रबंधन प्रणाली बनाना है, जो तेजी से कार्गो और यात्री आवाजाही, कम लागत को सक्षम करता है और विकसित भारत 2047 विजन का समर्थन करता है।

सिस्टम की मुख्य विशेषताएं:

- एकीकृत ऑनबोर्डिंग फ्रेमवर्क: एलपीएमएस एकल पंजीकरण अनुरोध (एसआरआर) प्रणाली का उपयोग करता है जहां हितधारक केवल एक बार जानकारी जमा करते हैं, दोहराए जाने वाले कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और निर्बाध डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।
- पूर्वानुमानित स्लॉट और निवास प्रबंधन: प्लेटफॉर्म एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर वास्तविक समय की क्षमता के आधार पर अग्रिम स्लॉट बुकिंग को सक्षम बनाता है और रसद योजना में सुधार के लिए वाहन प्रतीक्षा समय का पूर्वानुमान लगाता है।
- स्वचालित सुरक्षा और गेट संचालन: एलपीएमएस सीमा सुरक्षा और कार्गो निगरानी को मजबूत करने के लिए फुल बॉडी ट्रक स्कैनर के साथ एकीकृत करते हुए शिपमेंट विवरण, परिवहन मैनिफेस्ट और गेट आंदोलनों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है।
- बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) एनालिटिक्स: बिल्ट-इन एनालिटिक्स डैशबोर्ड हितधारकों को कार्गो मूवमेंट, कंटेनर स्टेटस, ट्रांजिट प्रदर्शन और परिचालन दक्षता पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं।
- सीधे ICEGATE सीमा शुल्क फाइलिंग: सिस्टम सीधे ICEGATE से जुड़ता है, जिससे शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री स्वचालित रूप से जमा करने की अनुमति मिलती है, त्रुटियों को कम किया जाता है और सीमा शुल्क निकासी में तेजी आती है।
- अनुकूलित संसाधन और गोदाम नियंत्रण: समर्पित यार्ड और गोदाम प्रबंधन मॉड्यूल भंडारण स्थान को कुशलतापूर्वक आवंटित करने, भीड़भाड़ को कम करने और सीमा रसद केंद्रों पर कार्गो हैंडलिंग में सुधार करने में मदद करते हैं।
- एकीकृत सिंगल-विंडो भुगतान: व्यापारी एकल डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क, पार्किंग शुल्क, वेटब्रिज शुल्क और टर्मिनल शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जिससे वित्तीय लेनदेन सरल हो जाएगा और देरी कम हो जाएगी।

नेत्र एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली

संदर्भ:

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली को अंतिम परिचालन मंजूरी (FOC) प्रदान की है।

नेत्र एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल

नेत्र एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) प्रणाली के बारे में:

यह क्या है?

- आमतौर पर भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के "आई इन द स्काई" के रूप में जाना जाता है, नेत्रा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हवाई निगरानी, कमांड-एंड-कंट्रोल और युद्ध प्रबंधन मंच है। यह एक अत्यधिक मोबाइल, उड़ान रडार स्टेशन के रूप में कार्य करता है जो पारंपरिक जमीन-आधारित रडार सिस्टम की सीमा से परे हवाई क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों को स्कैन करता है।



विकसित : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)

- उद्देश्य: नेत्र परियोजना की स्थापना हवाई निगरानी बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भर घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को संवेदनशील सीमाओं की निगरानी करने, शत्रुतापूर्ण घुसपैठ को ट्रैक करने और जटिल नेटवर्क-केंद्रित हवाई युद्ध मिशनों का समन्वय करने के लिए एक लचीला, अत्यधिक कुशल सामरिक बल गुणक प्रदान करना है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- उच्च ऊंचाई वाली स्कैनिंग: 40,000 फीट से अधिक की क्लोज़ छत से काम करते हुए, विमान का पृष्ठीय फिन-माउंटेड सक्रिय रडार लगातार नीचे और उसके आसपास के हवाई क्षेत्र को स्कैन करता है, जो इलाके की रुकावटों को बायपास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दातों का उत्सर्जन करता है जो जमीन इकाइयों को अंधा कर देता है।
- सिग्नल फ़िल्टरिंग और पहचान: ऑनबोर्ड मिशन कंप्यूटर तौटाए गए रडार संकेतों को संसाधित करते हैं, स्वचालित रूप से मित्र-या-दुश्मन (आईएफएफ) हस्ताक्षरों की पहचान करते हैं, विमान श्रेणियों को छांटते हैं, और शत्रुतापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन को टैग करते हैं।
- डेटा लिंक वितरण: इस डेटा को स्थानीय रूप से रखने के बजाय, नेत्रा अत्यधिक सुरक्षित, जाम-प्रतिरोधी डेटा लिंक का उपयोग करता है ताकि वास्तविक समय के लक्ष्य डेटा को एक साथ लड़ाकू जेट कॉकपिट और ब्राउंड कमांड सेंटर में स्ट्रीम किया जा सके।
- कमांड एंड कंट्रोल इंटरफ़ेस: ऑनबोर्ड ऑपरेटर सामरिक नियंत्रकों के रूप में कार्य करने के लिए अपने डिस्टले कंसोल का उपयोग करते हैं, जो क्षेत्रीय वायु रक्षा विन्यास का आयोजन करते समय मित्र लड़ाकू समूहों को आने वाले खतरों को रोकने के लिए निर्देशित करते हैं।

नेत्र प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

- एयरफ्रेम बेस: ब्राजील से आयातित एक संशोधित, जुड़वां इंजन एम्ब्रेयर EMB-145 क्षेत्रीय जेट एयरफ्रेम पर निर्मित। प्लेटफॉर्म में रडार इलेक्ट्रॉनिक्स को शक्ति प्रदान करने के लिए अनुकूलित इन-प्लाइंट ईंधन भरने वाली जांच, उन्नत विद्युत जनरेटर और उच्च क्षमता वाली जलवायु शीतलन प्रणाली है।
- सक्रिय ईईएसए रडार पावर: प्राथमिक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सरणी (ईईएसए) रडार से लैस। सिस्टम 250 किलोमीटर की रेंज तक देख सकता है और साथ ही साथ 200 से अधिक अलग-अलग हवाई वस्तुओं (विमान, मिसाइलों और मानव रहित हवाई वाहनों सहित) को ट्रैक कर सकता है।
- व्यापकसेंसर फ्यूजन: मानक ट्रैकिंग से परे, प्लेटफॉर्म दुश्मन के रडार पदों और रेडियो नेटवर्क को रोकने, मैप करने और इंगित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय (ईएसएम) और संचार सहायता उपाय (सीएसएम) को एकीकृत करता है।
- पूर्ण नेटवर्क-केंद्रित युद्ध एकीकरण: आने वाली शत्रुतापूर्ण मिसाइलों को स्पूफ़ करने के लिए एक मजबूत आत्म-सुरक्षा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट की सुविधा है। यह भारत की लंबी दूरी की IL-76-आधारित फाल्कन AWACS के साथ मिलकर एक स्तरीय, बहुस्तरीय वायु रक्षा निगरानी छाता बनाता है।

रक्षा दशक परिवर्तन (2014-2026)

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने 2014 और 2026 के बीच भारत के रक्षा परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए द डिफेंस डिडेड: एन्हांस्ड कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी शीर्षक से एक व्यापक पृष्ठभूमि जारी की है।

रक्षा दशक परिवर्तन (2014-2026)

रक्षा दशक परिवर्तन (2014-2026) के बारे में:

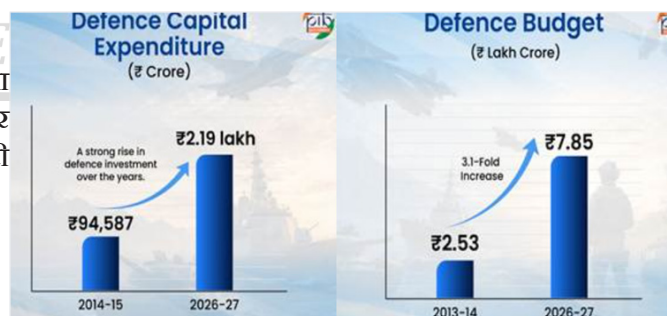
यह क्या है?

- पिछले बारह वर्षों में, भारत ने एक बुनियादी रणनीतिक बदलाव को अंजाम दिया है जो ऊपर से नीचे विदेशी सैन्य उपकरण खरीदार से एक स्वदेशी औद्योगिक निर्माता के रूप में बदल गया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के मूलभूत दृष्टिकोण से निर्देशित, रक्षा मंत्रालय ने एक पारदर्शी, सह-प्रबंधित और नवाचार-संचालित विनिर्माण इकोसिस्टम शुरू करने के लिए विरासत नौकरशाही ढांचे को ध्वस्त कर दिया है।

पैमाने और विस्तार की ओर इशारा करने वाले प्रमुख डेटा और आंकड़े:

वृहद राजकोषीय आवंटन और पूंजीगत व्यय:

- कुल बजटीय छलांग: बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ हो गया।
- तीव्र पूंजीगत व्यय: दीर्घकालिक सैन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और निर्माण के लिए आवंटित धन 2014-15 में ₹94,587.95 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में ₹2.19 लाख करोड़ हो गया।

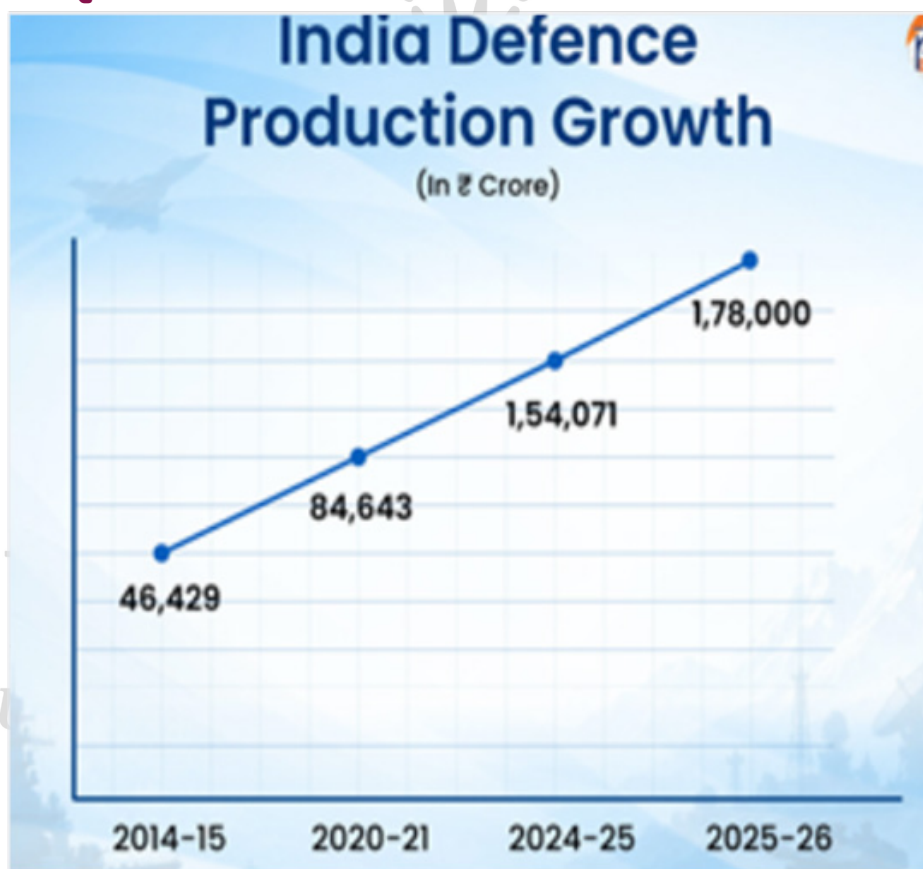


- अनुसंधान एवं विकास खर्च को दोगुना करना: रक्षा अनुसंधान और विकास वित्त पोषण में 112% से अधिक की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2014-15 में ₹13,716.14 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में ₹29,100.25 करोड़ हो गई।

औद्योगिक गहराई, उत्पादन और पुनर्गठन:

- चौंका देने वाली मूल्य वृद्धि: स्वदेशी रक्षा उत्पादन का शुद्ध वित्तीय मूल्य 2014-15 में ₹46,429 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹1.78 लाख करोड़ हो गया, जो 2020-21 के बाद से 110% की वृद्धि दर्शाता है।
- निजी क्षेत्र का पदचिह्न: जबकि डीपीएसयू ने कुल विनिर्माण उत्पादन में 76% का योगदान दिया, निजी क्षेत्र की भागीदारी कुल औद्योगिक मिश्रण में 24% तक बढ़ गई।
- ट्रिपलिंग औद्योगिक लाइसेंस: जारी किए गए सक्रिय, कानूनी रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की कुल मात्रा 2015 में 258 से बढ़कर मार्च 2026 तक 834 हो गई , ताकि व्यापार करने में आसानी हो सके।
- आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को भंग करना: अक्टूबर 2021 में, सरकार ने 200 साल पुराने OFB को भंग कर दिया, व्यवस्थित रूप से अपने 41 विरासत आयुध कारखानों को सात चुस्त, कॉर्पोरेट DPSU में पुनर्गठित किया।
- विदेशी प्रवाह (FDI) को आकर्षित करना: स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक और सरकारी मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देने वाले नीतिगत परिवर्तनों के बाद, भारत ने मार्च 2026 तक प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह में ₹6,670.59 करोड़ दर्ज किए।

औद्योगिक गहराई, उत्पादन और पुनर्गठन



वैश्विक निर्यात पदचिह्नों का विस्फोट:

- 5500% निर्यात वृद्धि: प्रतिस्पर्धी घरेलू वैकल्पिक प्लेटफार्मों द्वारा प्रेरित, भारत का वैश्विक रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में ₹686 करोड़ की न्यूनतम आधार रेखा से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया।
- एक विस्तृत गंतव्य मैट्रिक्स: निर्मित वस्तुएं और युद्ध के मैदान के लिए तैयार उप-प्रणालियां अब सक्रिय रूप से 80 से अधिक संप्रभु देशों को निर्यात की जाती हैं।
- कॉर्पोरेट निर्यातक आधार का विस्तार: वैश्विक अनुबंधों में भाग लेने वाली घरेलू विनिर्माण फर्मों की सक्रिय आधार रेखा का विस्तार 145 विशिष्ट संस्थाओं तक हो गया।
- आयात निर्भरता को उलटना: ऐतिहासिक रूप से अपने 65%-70% उपकरणों के लिए बाहरी बाजारों पर निर्भर भारत ने अपनी रक्षा इन्वेंट्री का लगभग 65% घर पर निर्माण करने के समीकरण को उलट दिया है।

पिछले 12 वर्षों में भारतीय रक्षा शासन में प्रमुख रुझान:

- पृथक अनुसंधान से सह-प्रबंधित नवाचार (iDEX) में बदलाव: इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX) पहल ने मार्च 2026 तक 551 विशिष्ट डिजाइन अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए सक्रिय रूप से MSME और स्टार्ट-अप को शामिल किया।
- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (पीआईएल) में चरणबद्धता: विदेशी वस्तुओं की खरीद को समाप्त करने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने पांच पीआईएल ट्रैक लागू किए, 5,012 विशेष भागों पर आयात को रोक दिया और सृजन पोर्टल के माध्यम से घरेलू ऑर्डर में ₹9,782 करोड़ का सृजन किया।

- क्षेत्रीय गलियारों के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करना: समर्पित रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना से अप्रैल 2026 तक उत्तर प्रदेश में ₹42,057 करोड़ और तमिलनाडु में ₹32,699 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिली।
- सृजन दीप के माध्यम से सुरक्षित आपूर्ति डेटाबेस का केंद्रीकरण: रक्षा प्रतिष्ठानों और उद्यमियों के मंच का शुभारंभ आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को सुरक्षित करने के लिए एक अद्वितीय संदर्भ संख्या (URN) के साथ 41,000 से अधिक सत्यापित आपूर्तिकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से लॉग करता है।
- निजी एयरोस्पेस उद्यमों के लिए राज्य अनुसंधान प्रयोगशालाएं खोलना: एकीकृत रक्षा परीक्षण पोर्टल के माध्यम से निजी उद्योगों के लिए उन्नत डीआरडीओ परीक्षण सुविधाएं खोलने से क्रॉस-सत्यापन अत्यधिक पारदर्शी हो गया है।

सकारात्मक संकेतक और सफल तकनीकी मील के पथर:

- मिशन शक्ति (2019): भारत ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक लक्ष्य उपग्रह को नष्ट करके उत्तम ऊंचाई वाले एंटी-सैटेलाइट (ASAT) क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
- मिशन दिव्यास्त्र (2024): मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRV) से लैंस लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- हाइपरसोनिक मिसाइल एडवांसमेंट्स (2026): हैदराबाद में एक नई हाइपरसोनिक विंड टनल द्वारा समर्थित सक्रिय रूप से कूल्ड स्क्रीमजेट फुल-स्केल कम्बस्टर का 12 मिनट का सफल ब्राउंड टेस्ट किया।
- अगली पीढ़ी के उत्पादन अनुमोदन: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 97 स्वदेशी तेजस Mk-1A लड़ाकू विमान (₹62,000 करोड़) और 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (₹62,700 करोड़) सहित ₹6 लाख करोड़ से अधिक की आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्रदान की।
- प्रोजेक्ट 75 माइलस्टोन (2025): फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित सभी छह कलवरी-श्रेणी की स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की डिलीवरी पूरी हो गई।

भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:

- असंगत वाणिज्यिक तकनीक-अवशोषण समयसीमा का प्रबंधन: डीआरडीओ द्वारा विकसित जटिल प्रयोगशाला प्रोटोटाइप को निजी एमएसएमई द्वारा बड़े पैमाने पर निर्मित प्रणालियों में बदलने से औद्योगिक देरी का सामना करना पड़ सकता है।
- पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता के साथ वैश्विक सह-उत्पादन अनुबंधों को संतुलित करना: विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ संवेदनशील प्रौद्योगिकी-साझाकरण समझौतों पर बातचीत करने के लिए बौद्धिक संपदा को स्वतंत्र रखने के लिए गहरी नियामक जांच की आवश्यकता होती है।
- हाई-टेक सब-सिस्टम के लिए औद्योगिक कौशल घाटे को पाटना: सटीक सैन्य विनिर्माण के लिए एक स्थिर कार्यबल का निर्माण प्रवेश स्तर के तकनीशियनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण अपडेट की मांग करता है।
- अंतर-राज्यीय गलियारों में स्थानीय अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करना: जबकि केंद्रीय स्तर पर मेगा निवेश प्रतिबद्ध हैं, कारखानों का भौतिक निर्माण राज्य-स्तरीय भूमि रूपांतरण और नगरपालिका मंजूरी के कारण गति बाधाओं को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह:

- 2029 निर्यात मील का पथर प्राप्त करना: 2029 तक वार्षिक रक्षा निर्यात में केंद्र सरकार के ₹50,000 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आक्रामक वैश्विक पहुंच बनाए रखें।
- डीएपी 2026 के माध्यम से उत्तम स्वदेशी सामग्री को लागू करना: पूंजीगत खरीद में 60 प्रतिशत न्यूनतम स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता को अनिवार्य करने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2026 के मसौदे को शीघ्रता से अंतिम रूप देना और लागू करना।
- प्रौद्योगिकी विकास कोष के माध्यम से डीप-टेक अनुदान को बढ़ाना: टीडीएफ के तहत नए स्वीकृत ₹500 करोड़ के कोष को स्पष्ट रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और स्वायत्त ड्रोन स्वार्म जैसी उभरती रक्षा लाइनों के लिए आवंटित करें।
- लघुपक्षीय और समुद्री सुरक्षा ढांचे का विस्तार: भारत को इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में स्थापित करने के लिए भारत-अमेरिका ट्रस्ट पहल और महासागर सिद्धांत जैसे गहरे ढांचे का लाभ उठाएं।

निष्कर्ष:

एक ऊपर से नीचे के विदेशी सैन्य आयातक से एक आत्मनिर्भर विनिर्माण राष्ट्र के रूप में भारत का संरचनात्मक परिवर्तन इसकी आधुनिक आर्थिक और सुरक्षा वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है। आयुध कारखानों और विशेष क्षेत्रीय औद्योगिक गलियारों के निगमिकरण जैसे संस्थागत सुधारों के साथ कई गुना पूंजीगत व्यय में वृद्धि का समर्थन करके, देश ने रणनीतिक स्वायत्तता के साथ आर्थिक विकास को सफलतापूर्वक जोड़ा है।

भारत और शहरी अग्निकांड: मालवीय नगर घटना

संदर्भ:

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगने से 12 विदेशी नागरिकों सहित 21 लोगों की मौत हो गई।

भारत और शहरी अग्निकांड: मालवीय नगर घटना

भारत और शहरी आग दुर्घटनाओं के बारे में: मालवीय नगर घटना

यह क्या है?

- शहरी आग दुर्घटनाएं उच्च तीव्रता, विनाशकारी आग हैं जो घनी आबादी वाले नगरपालिका क्षेत्रों, वाणिज्यिक संरचनाओं, ऊंची इमारतों, कारखानों या अनौपचारिक बस्तियों में होती हैं। जंगल की आग के विपरीत, शहरी आग आमतौर पर निर्मित पर्यावरण की कमजोरियों से शुरू होती है, जैसे कि दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली, अनधिकृत संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक भीड़, और कार्यात्मक अग्नि-सुरक्षा बुनियादी ढांचे की कमी।



भारत में आग दुर्घटनाओं पर मुख्य डेटा और आंकड़े:

- उच्च मौतें: भारत में आग दुर्घटनाएं प्रतिदिन लगभग 35 लोगों की जान ले लेती हैं, जिससे वे आकस्मिक मौतों का एक प्रमुख कारण बन जाते हैं।
- वाणिज्यिक स्थान सबसे अधिक प्रभावित: आग से होने वाली 40% से अधिक मौतें बाजारों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में होती हैं।
- विद्युत दोष प्रमुख कारण: लगभग 70% शहरी वाणिज्यिक आग दोषपूर्ण वायरिंग, शॉर्ट सर्किट या अतिभारित प्रणालियों से उत्पन्न होती है।
- खराब सुरक्षा अनुपालन: 60% से अधिक छोटे और मध्यम वाणिज्यिक भवनों में वैध अग्नि एनओसी या पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी है।

भारत में प्रमुख अग्नि दुर्घटनाएँ: एक ऐतिहासिक घटनाक्रम

- वीनस सर्कस फायर (बैंगलोर, 1981): सर्कस शो के दौरान आग लगने से 56 बच्चों सहित कुल 92 लोगों की मौत हो गई, जिससे जलती हुई कैनवास की छत 4,000 से अधिक की भीड़ पर गिर गई।
- डबवाली टेंट फायर (हरियाणा, 1995): एक स्कूल समारोह के दौरान 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर बच्चे और माता-पिता थे, जब बिजली के शॉर्ट सर्किट ने सिंथेटिक पंजाल को प्रज्वलित कर दिया, जिससे एक संकीर्ण निकास के पास भगदड़ मच गई।
- उपहार ब्रैंड सिनेमा त्रासदी (दिल्ली, 1997): भूतल के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण थिएटर एयर कंडीशनिंग नलिकाओं के माध्यम से घना धुआं फैल गया, जिससे बालकनी के मेहमान बंद निकास दरवाजों के पीछे फंस गए, जिससे जहरीले धुएं से कुल 60 लोगों की मौत हो गई।
- कुंभकोणम स्कूल में आग (तमिलनाडु, 2004): फूस की छत वाली रसोई से एक चिंगारी में आग लगने से कुल 94 नर्सरी स्कूली बच्चों की मौत हो गई, जहां बच्चे एक अनुपस्थित संस्थागत प्रतिक्रिया ढांचे के कारण फंस गए थे।
- एएमआरआई अस्पताल आपदा (कोलकाता, 2011): बेसमेंट में सुबह-सुबह आग लगने से कुल 89 मरीजों और कर्मचारियों की मौत हो गई - जिसे अवैध रूप से अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था - सात मंजिला इमारत के माध्यम से जहरीला धुआं उठता था।

आग दुर्घटनाओं के आवर्ती कारण:

- अतिभारित और दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली: पुरानी वायरिंग और ट्रांसफार्मर को अक्सर आधुनिक जलवायु नियंत्रण और औद्योगिक गियर द्वारा उनकी क्षमता से आगे धकेल दिया जाता है, जिससे गंभीर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं।
- अवैध वाणिज्यिक विस्तार और भीड़भाड़: संपत्ति के मालिक अक्सर अतिरिक्त कमरे जोड़ते हैं या अपनी अनुमत क्षमता से अधिक फर्श को संशोधित करते हैं, जिससे प्राकृतिक वायु वेंटिलेशन और आपातकालीन रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण: रसायनों, प्लास्टिक या गैस सिलेंडर को स्टोर करने के लिए बेसमेंट, सीढ़ियों और पार्किंग संरचनाओं का नियमित रूप से दुरुपयोग किया जाता है, जो मामूली आग को बड़े पैमाने पर विस्फोटों में बदल सकता है।

- सरत, ज्वलनशील निर्माण सामग्री का व्यापक उपयोग: प्लास्टिक की चादरें, सिंथेटिक तिरपाल, या फूस की छत का उपयोग करने से आग मिनटों में तेजी से बढ़ने की अनुमति मिलती है।
- ऑन-साइट सुरक्षा नियंत्रण की पूर्ण अनुपस्थिति: कई इमारतों में फायर अलार्म, वॉटर स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्टर या अग्निशामक यंत्र जैसे बुनियादी, कार्यात्मक सुरक्षा बुनियादी ढांचे का भी अभाव होता है।

शहरी अग्नि सुरक्षा में प्रमुख चुनौतियाँ:

- केवल एक प्रवेश और निकास बिंदु की कमी: कई वाणिज्यिक सेटअप प्रवेश और निकास दोनों के लिए एक ही सीढ़ी या गलियारे के साथ काम करते हैं, जिससे संकट के दौरान निकासी लगभग असंभव हो जाती है।
- कमजोर कानूनी प्रवर्तन और गैर-अनुपालन भवन: भ्रष्ट या आलसी निरीक्षण दिनचर्या अवैध होटलों, कोचिंग सेंटरों और छोटे कारखानों को आग की मंजूरी के बिना खुले तौर पर संचालित करने की अनुमति देती है।
- जमीनी स्तर पर सुरक्षा जागरूकता में एक गंभीर कमी: अधिकांश भवन प्रबंधकों, कर्मचारियों और किरायेदारों को कभी भी आपातकालीन प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, जिससे घबराहट और घातक भगदड़ हो सकती है।
- भीड़भाड़ वाले शहरों में विलंबित आपातकालीन प्रतिक्रिया समय: संकरी शहरी सड़कें, भारी यातायात और खराब नगरपालिका योजना फायर ट्रकों को फंसा सकती है, जिससे जीवन रक्षक सहायता में देरी हो सकती है।
- उल्लंघनकर्ताओं के लिए कमजोर आपराधिक जवाबदेही ढांचे: लापरवाह मालिकों को अक्सर कमजोर जुर्माना या लंबी अदालत की देरी का सामना करना पड़ता है, जो सुरक्षा कानूनों की अनदेखी के खिलाफ एक मजबूत निवारक बनाने में विफल रहता है।

आगे की राह:

- स्वचालित फायर एनओसी सत्यापन चैनलों को अनिवार्य करना: नगरपालिका वाणिज्यिक लाइसेंसिंग पोर्टलों को सीधे अग्निशमन विभाग के डेटाबेस से लिंक करें, वैध फायर एनओसी के बिना संचालित होने वाले किसी भी भवन के लिए व्यापार परमिट को तुरंत रद्द कर दें।
- सख्त मल्टी-एजेंट स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मानदंडों को लागू करना: सभी वाणिज्यिक संरचनाओं, होटलों और स्कूलों को इमारत के विपरीत किनारों पर कम से कम दो चौड़ी, अनब्लॉक और आग प्रतिरोधी निकास सीढ़ियों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- गैर-अनुपालन संपत्ति मालिकों के लिए भारी दंड लगाना: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 जैसे सख्त आपराधिक प्रावधानों के तहत मामलों को स्थानांतरित करना - ताकि लापरवाह मालिकों को टाली जा सकने वाली मौतों के लिए सीधे जवाबदेह ठहराया जा सके।
- नियमित शहर-व्यापी सुरक्षा ऑडिट का संचालन: कोचिंग सेंटर, नर्सिंग होम और भीड़-भाड़ वाले बाजारों जैसे कमजोर स्थानों में सुरक्षा अनुपालन की जांच करने के लिए निरंतर, महीने भर चलने वाले निरीक्षण अभियान शुरू करें, जो विफल होने वाली संपत्तियों को सील कर दें।
- स्मार्ट अर्बन रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन: भीड़भाड़, संकरी शहर की गलियों के भीतर भी तेजी से, प्रभावी बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए उन्नत, कॉम्पैक्ट अग्निशमन इकाइयों और स्वचालित धुआं-चेतावनी नेटवर्क में निवेश करें।

निष्कर्ष:

मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग शहरी सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाती है। प्रतिक्रियाशील, आपदा के बाद की जांच से सख्त, सक्रिय प्रवर्तन की प्रणाली की ओर बढ़ना परिहार्य नुकसान के इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आवश्यक है।



LK ACADEMY[®]
YOUR GUIDE TO THE NEXT MILESTONE
